राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का उनतीसवां दिवस |संख्या: 18

सोमवार,

05 मार्च 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। होली की खुमारी है कि नहीं अभी तक? नमस्कार, नमस्कार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका आशीर्वाद प्रतिपक्ष पर बना रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) चुनाव के परिणाम ने उतार दी खुमारी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका क्या हुआ श्रीमान्? (व्यवधान) तालियां बजा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: होली का खुशनुमा वातावरण है आज। विधान सभा भी उसी खुशनुमा वातावरण के हिसाब से चलनी चाहिये शाम तक, यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी के घर में बेटा जन्मा है, खुशी ये मना रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। देखो, क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। (व्यवधान) नहीं, अभी नहीं, बैठो आप। बाद में, अभी बैठो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ओलों से फसल बर्बाद हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर, अलवर में सैकड़ों-सैकड़ों गांव चौपट हो गये। किसान का सब कुछ बर्बाद हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। बैठो, आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। 90-90 परसेंट फसल खराब हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कुछ किसान का चौपट हो गया।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। नो-नो, नहीं। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो। आज का खुशनुमा वातावरण है, पर एक आदत पड़ी हुई है। नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल में व्यवधान करना चाहते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नियम में आओ न।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में संचालित विद्युत यूनिटों के लिये कोयले की आपूर्ति

313. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोयले पर आधारित विद्युत यूनिटें भी संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त यूनिटों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी मेगावाट है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण उक्त यूनिटें अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त यूनिटों के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(5) क्या सरकार अब कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां। राज्य में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयां मुख्य रूप से कोयले पर आधारित हैं। निम्न तापीय विद्युत परियोजना कोयले पर आधारित हैं:-

1. कोटा तापीय विद्युत परियोजना की सात इकाइयां
2. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना की छह इकाइयां

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

3. छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की चार इकाइयां

4. कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना की दो इकाइयां

5. गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड परियोजना की दो इकाइयां।

(2) तापीय विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता (मेगावाट) का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में कोयला आधारित विद्युत गृहों की इकाइयां पूर्ण क्षमता पर काम कर रही हैं एवं इन इकाइयों को प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक कोयले की आपूर्ति हो रही है। इन इकाइयों का संचालन राज्य भार सम्प्रेषण केन्द्र, जयपुर के निर्देशानुसार एवं ग्रिड की आवश्यकतानुसार पूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता पर किया जा रहा है।

(4) वर्तमान में उक्त तापीय विद्युत परियोजनाओं की इकाइयों को प्रतिदिन उत्पादन के लिये आवश्यक कोयले की आपूर्ति हो रही है, परन्तु कोल इंडिया लिमिटेड एवं रेलवे के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मानक स्तर पर कोयले का भण्डारण नहीं हो पा रहा है।

(5) वर्तमान में उक्त इकाइयों को प्रतिदिन उत्पादन के लिये आवश्यक कोयले की आपूर्ति हो रही है तथापि सी.ई.ए. के मानकों के अनुसार कोयले के भण्डारण हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास जारी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आप कोयले का प्रोक्योरमेंट किस मैकेनिज्म से करते हैं, आपको कहां-कहां से कोल प्राप्त होता है? क्या आपकी कुछ कैप्टिव माइंस भी हैं और अगर कैप्टिव माइंस हैं तो उनके लिये आप खुद एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ आपने कोई कांट्रेक्ट या अनुबंध कर रखा है और जो आप यह प्रोक्योरमेंट करते हैं कोयले का, इसकी जो प्रक्रिया है, क्या वह पब्लिक डोमेन में है और जो आप वाश्ड कोल लेते हैं, उसके लिये क्या हाई कोर्ट ने आपको कोई दिशा-निर्देश दिये हैं और कितनी मात्रा में कोयला आप प्रति माह लेते हैं और कितने दिन का आपके पास स्टाक है? आपकी 21 इकाइयां हैं, जो कोल पर आधारित हैं और उनकी क्षमता है लगभग 4400 मेगावाट। पिछले सितम्बर-अक्टूबर में भी आपकी 10

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

दिन से एक महीने तक यह बंद रही और एक तरफ यह कह रहे हैं कि कोल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तो आप यह बताएं फिर मैं दूसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कोल आपके कहां से आता है? हमारे यहां कोटा है, छबड़ा है, कालीसिंध है या सूरतगढ़ है, यह जितने भी प्लांट्स हैं, ज्यादातर कोल इंडिया के मार्फत एच.सी.सी.एल. और एन.सी.एल. के फील्ड से कोयले का ब्लाक आबंटन हुआ है। जैसे कोटा में एच.सी.सी.एल. से लगभग 33 लाख मीट्रिक टन आबंटन हुआ है और एन.सी.एल. से 36 लाख मीट्रिक टन हमें आबंटन हुआ है, जो कोटा में कुल 69.58 लाख मीट्रिक टन कोयल प्रत्येक वर्ष आबंटन हुआ है। सूरतगढ़ में एच.सी.सी.एल. से 73.04 लाख मीट्रिक टन हमको आबंटन हुआ है कोल इंडिया के मार्फत। छबड़ा में एक नम्बर और दो नम्बर यूनिट में 23.12 लाख मीट्रिक टन हमारे एच.सी.सी.एल. से आबंटन हुआ है और छबड़ा व कालीसिंध थर्ड व नंबर फोर्थ, यह दोनों यूनिट हमको पारसा और कान्ता बेसिन, जो राजस्थान उत्पादन निगम को जो उत्पादन हुआ है, उसके मार्फत हमको 18 लाख मीट्रिक टन, छबड़ा में तीन और चार नंबर के लिये और कालीसिंध के लिये लगभग 40.90 मीट्रिक टन कोल आबंटन हुआ है। जहां तक अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे फीगर्स हैं कि दिसम्बर से लेकर आज दिन तक हमारे पास कभी भी ऐसी हालत नहीं रही कि जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, उसमें छह-सात दिन का कोयला का स्टाक हमेशा हमारे पास एडवांस पडा रहा जिससे कभी भी कोयले की कमी नहीं रहे। किसी भी प्रकार की डिमांड के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इकाइयां जब चलाते हैं, हम हमारे पास जो स्टेट, जो डिस्पैच सेंटर हमको कहता है कि इसमें डिमांड बढ़ जाती है तो हम आपके थर्मल को चालू करते हैं, आवश्यकतानुसार हम चालू करते हैं। परन्तु दिसम्बर से लेकर आज दिन तक डिमांड के अनुरूप हमारे यहां कभी भी कोयले की कमी के कारण कोई भी थर्मल बंद नहीं पड़ा रहा। हमारे पास पूरा स्टाक है और पांच-सात दिन का स्टाक सभी इकाइयों में हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2017 के सितम्बर-अक्टूबर में आपके बंद रहे हैं कि

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
नहीं रहे हैं और आप वाश्ड कोयला लेते हैं और वह लगभग 2 लाख मीट्रिक टन हर महीने लेते हैं, उसको आप किस तरह से लेते हैं और क्या कोई बिडिंग कमेटी है क्या? आपका उसमें कोई मैकेनिज्म है क्या और क्या उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी जो प्रक्रिया है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या? लगाया है तो क्या लगाया है और उसके लिये आपने क्या कदम उठाये हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, एनवायर्नमेंट की जो गाइड लाइंस हैं, उसके अनुसार, जहां भी कोल पिट मतलब थर्मल स्टेशन पर जहां भी कोल पहुंचता है, अगर उसकी लैंथ 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो यह अनिवार्य है, हमको वाश कोल लाना जरूरी है। वाशिंग के तहत, मतलब वाश करके फिर ही उसका जो एस कंटेट है, वह लगभग 42 से 43 परसेंट ऊपर जो एस कंटेंट है, उसको हम कम करते हैं। 42 परसेंट से ऊपर जितने भी एस कंटेंट है, उसको कम करते हैं। वाश कोल को हम ब्रोशरीज के माध्यम से इस कोयले को हम लाते हैं। बाकायदा हमने इसकी टेंडरिंग की है। टेंडर प्रोसेस के थ्रू ही हम कोयला लाये हैं।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में जो वाश कोल आ रहा था, उसकी रेट की तुलना में, मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम वन थर्ड प्राइस टेंडरिंग के प्रोसेस से हमने और कम की है। मैं समझता हूं कि बहुत कम रेट पर, आज की तारीख में हमको टेंडर प्रोसेस के थ्रू जो वाश कोल मिल रहा है, हमने जिस तरीके से टेंडर बनाये, जिस तरीके से टेंडर हुआ है, जो प्राइस आपके टाइम 2013-14-15 में आपने जो टेंडर किया, उससे वन थर्ड प्राइस घटी है जिससे सस्ता कोयला आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राजस्थान उत्पादन निगम, जो आपके कार्यकाल में 2600 करोड़ रुपये के लोस में चल रहा था, पिछले साल-डेढ़ साल में जितने भी हमारे उत्पादन निगम हैं, लगभग हमारे 400 करोड़ के प्रोफिट में हम एक साल में आ गये हैं। जो आपके कार्यकाल में 2600 करोड़ के लोस में था, आज हम 400 करोड़ के प्रोफिट में आ गये।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कंपाउडिंग सेस, मतलब जो एनवायर्नमेंट सेस है, लगातार बढ़ रहा है,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट बढ़ रहा है, कोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और हमारे उत्पादन निगम और हमने मिलकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले से ज्यादा मंहगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट इतना मंहगा होता है कि यह कोयले की कोस्ट से भी ऊपर होता है।

हमने शापिंग की है। जो डिस्टेंस, हमको लगा कि इस थर्मल से कोल फील्ड नजदीक पड़ता है तो हमने शापिंग करके अलाटमेंट वहां करा दिया और हमने देखा कि जिसकी जीसीबी वैल्यू, कोल इण्डिया हमको जी-4, जी-5 की बिलिंग करती थी, जहां 3500-3600 रुपये लेती थी और कोल की क्वालिटी है, वह 1800-1900 रुपये की क्वालिटी में थी, उसको केन्द्र सरकार ने सिम्फर लगाकर, उसकी जो रिसीव वैल्यू है, जहां से लदान होता है और जहां उतरता है, दोनों तरफ से सिम्फर लगाकर कोल की एक्चुअल गुणवत्ता के कारण उत्पादन निगम का लगभग 70-80 करोड़ रुपये हमने बचाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उत्पादन में हकीकत में प्राइज बढ़नी चाहिए। आपके कार्यकाल में प्रति यूनिट 4 रुपये 26 पैसे जो यूनिट थी, आज की तारीख में, हमारे कार्यकाल में, इन तीन सालों में ट्रांसपोर्टेशन, कोयले के भाव बढ़ने के उपरान्त और कम्पाउण्डिंग सैस लगने के बावजूद भी आज यूनिट की कोस्ट 4 रुपये 06 पैसे पर आ गयी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के मानक स्तरों पर कोयले का भण्डारण क्या है? आज की तारीख में इन पांचों यूनिट्स में कितना स्टाक है? इसके साथ-साथ ही, कोयले पर आज की तारीख में कितने प्रतिशत खर्चा आता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि सीईए की गाइडलाइन्स क्या हैं, सीईए की गाइडलाइन्स यह बोलती है कि पिट्स हैड पर अगर कोई भी थर्मल है तो उसके पास 15 दिन का स्टाक होना चाहिए और पिट हैड से जो दूर हैं, उसके पास 30 दिन का स्टाक उपलब्ध होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पिट्स हैड से दूर होने वाले के पास 30 दिन का कोयले का स्टाक होना चाहिए, परन्तु हमारे पास कोयले का स्टाक इसलिए

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

नहीं है कि कोल इण्डिया का उत्पादन भी कम हो गया है, कोल का उत्पादन कम हुआ है और रेगुलर रेलवे की जो रैक्स हमको मिलनी चाहिए, वह हमको उपलब्ध नहीं हो रही हैं। हमारे जो एनर्जी सैक्रेटरी हैं, उत्पादन के सीएमडी हैं, मुख्य मंत्रीजी ने, हमने बार-बार वार्ता की है दिल्ली में, और यह मैं आपको कह सकता हूं कि आज अगर 16 रैक्स की रोज की खपत है तो 17-18 रैक्स की हमारे यहां प्रतिदिन आपूर्ति हो रही है। मैं हाउस को यह विश्वास दे सकता हूं कि कोयले की आपूर्ति के कारण राजस्थान में हम बिजली की कटौती नहीं करेंगे। आज की तारीख में प्रत्येक यूनिट में...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आज की तारीख में पांचों यूनिट्स में स्टाक की क्या स्थिति है?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह है कि कोटा में हमारे पास लगभग 06 दिन का स्टाक है। सूरतगढ़ में हमारे पास 06-07 दिन का स्टाक है। कालीसिंध में हमारे पास 05 दिन का स्टाक है और छबड़ा में हमारे पास लगभग 05 दिन का स्टाक है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि कोयले के कारण बिजली की डिमाण्ड में किसी प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होगी। मैं आपको विश्वास देता हूं कि पूरे प्रदेश में कोयले के कारण या कोई रैक्स नहीं मिलने के कारण दिसम्बर से लेकर खास तौर से किसानों का मेन टाइम है, जब बिजली की सबसे ज्यादा खपत होती है राजस्थान में, आज दिन तक हमने कटौती नहीं की है। पर्याप्त मात्रा में बिजली हमको उपलब्ध है। हम सभी थर्मल्स से बार-बार वार्ता भी कर रहे हैं ताकि कोयले की आपूर्ति हम सुचारु रूप से कर सकें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान) नहीं, मैंने शंकर सिंह राजपुरोहित को पुकारा है। इनके बाद आपको अलाउ करूंगा। (व्यवधान)

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने पूरा उत्तर दे दिया, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एडवांस कोयला रखने की, सीईए के दिशा-निर्देश हैं, बन्द कर दिया, उसको

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

वापस प्रारम्भ करवाने के लिए, क्योंकि आपको एडवांस में कोयला तो रखना ही पड़ेगा, आप भले ही कहें दिसम्बर से, लेकिन अक्टूबर, सितम्बर से पहले एकाध बार सूरतगढ़ वगैरह कोयले की कमी के कारण बन्द हुई थीं, यही कारण है तो सीईए के दिशा-निर्देशों को चेन्ज करवाने के लिए जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने नोर्म्स बदल दिये थे, एडवांस इलेक्ट्रिसिटी परचेज का और कोयले का। इसको दूर करने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किये और क्या-क्या करोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपको बताया। आहौर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सीईए की गाइडलाइन्स यह हैं कि पिट हैड से कोई भी थर्मल पावर स्टेशन यदि दूर है तो 30 दिन का स्टॉक अनिवार्य है। इसके लिए 22.09.2017 को प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा, राजस्थान सरकार ने हमारे यहां से पत्र लिखा। 04.10.2017 को भी हमने वापस चिट्ठी लिखी और 09.10.2017 को हमने मीटिंग भी की। हमारे जो चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक हैं, उन्होंने भी माइनिंग कोल मंत्रालय के प्रबन्ध निदेशक से वार्ता की है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इसमें पहले करते हुए कोल मंत्रालय के मंत्रीजी पीयूष गोयलजी से मिले हैं। उसके बाद राजस्थान में नवम्बर, दिसम्बर में कोल की प्रतिदिन जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप और उससे ज्यादा कोल हमारे पास आ रहा है और अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजस्थान की ही बात नहीं है, पूरे देश में 113 थर्मल पावर स्टेशन हैं। इनमें से सुपर क्रिटिकल प्राब्लम है, जिनमें 29 पावर प्लांट में चार दिन से कम स्टॉक है। पूरे देश में लगभग 22 क्रिटिकल प्लांट्स हैं जिनमें कोयला 06 और 07 दिन का है। फिर भी राजस्थान की पोजीशन हमारी वार्ताओं और मुख्य मंत्रीजी की पहल के कारण, उनके बार-बार दिल्ली जाकर बात करने के कारण, कोयले की वजह से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। हम निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे पास पूरा स्टाक मिले।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, इन इकाइयों में गत वर्षों में 114 में 20 परसेंट तक भी उत्पादन रहा है। पिछले एक साल में

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

पूर्ण क्षमता के साथ कितना उत्पादन होना था और कितना हुआ? कम हुआ तो किस वजह से?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्मल चलाना स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर के ऊपर है। जैसे डिमाण्ड बढ़ती है, वैसे ही पूरे पीएलएफ को चलाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थर्मल अगर पूरे पीएलएफ पर नहीं चलता, अगर हीट रेट वैल्यू को अगर हमने मेन्टेन नहीं किया होता, पूर्ववर्ती सरकार के समय आपने कभी मेन्टेन किया नहीं, जहां 2400 हीट रेट वैल्यू थी, वहां 2800-2900 हीट रेट वैल्यू पर आपने चलाया जिससे आपको लोसेज हुए। हमने इस हीट रेट को मेन्टेन करने की कोशिश की है जिससे उत्पादन की कोस्ट भी कम हो और स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर उसकी ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार ही हम थर्मल चलाते हैं। कभी हो सकता है कि हम थर्मल चला रहे हैं, उसका लोड कम करना पड़ता है, लोड डिस्पैच सेन्टर के कारण लोड मेन्टेन करना पड़ता है। उसको पूरा चलाना, उस ग्रिड में ज्यादा बिजली देकर, उस बिजली को फालतू करना, खर्च करना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपको कहना चाहता हूं हमने अच्छे ढंग से इस पूरे सिस्टम को चलाया तब जाकर हम प्रोफिट में आये हैं, नहीं तो हम 2600 करोड़ के लोस में चल रहे थे। 2013-14 में, 2015-16 में हमने घटाया। आज 2017 में हम 400 करोड़ पर आये हैं और नेक्स्ट आडिटिंग में लगभग 700-800 करोड़ के प्रोफिट में उत्पादन आयेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

भीम में कृषि बीमा के दर्ज परिवाद

314. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवाद दर्ज हुए? क्या उक्त सभी दर्ज परिवादों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कृषि बीमा योजना के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों में कोई परिवाद दर्ज नहीं हुए हैं। विधान सभा क्षेत्र भीम में विगत तीन वर्षों में संचालित की गई कृषि बीमा योजना के तहत बीमित कृषक, बीमा क्लेम व लाभान्वित कृषकों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कृषि बीमा योजना के तहत पृथक से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित कृषि बीमा योजना के प्रीमियम में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 8 व 9 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों से बैंक ऋण ले रखा है, उनका बीमा तो कर दिया जाता है, ऐसे किसानों को, जिनकी अत्यधिक बरसात की वजह से या शीतलहर की वजह से नुकसान होता है लेकिन उन्होंने बीमा नहीं कराया है, क्या सरकार ऐसे किसानों को भी बीमा का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया क्या उनको भी नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान बीमा में है, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अभी 2016 में लागू हुई है, इसमें बीमा करने वाले स्वैच्छिक किसानों को भी सम्मिलित करने के प्रावधान किये हुए हैं और जिन किसानों ने ऋण लिया है सुओमोटो ही उनको बीमा हो जाता है। लेकिन जिन किसानों ने स्वैच्छिक बीमा भी नहीं कराया है या उनकी फसलें नुकसान हुई हैं तो आपदा राहत के नियमों के अन्तर्गत यदि 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होता है तो ऐसे किसानों को उस योजना में सम्मिलित करने के प्रावधान हैं, बीमा योजना में इस प्रकार के किसानों को किसी का प्रोत्साहन देने के प्रावधान नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग ने एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं लघु कृषकों को प्रोत्साहन हेतु ग्रीन हाउस या शेडनैट के यह योजना लागू की है। कृषि मंत्रीजी, मेरे जिला राजसमंद में ...

श्री अध्यक्ष: आप भीम तक सीमित रहो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सर, यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: हां तो भी का ही है, आप भीम का कीजिए। आप उधर मत ले जाइये, भीम का कीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सर, उसी में पूछ रहा हूं। राजसमंद जिले में जिसमें भीम भी आता है।

श्री अध्यक्ष: हां, भीम, भीम।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों ने ग्रीन हाउस और शेडनैट का आवेदन किया है, कब से किया है? क्या उन आवेदकों को आप यह शेडनैट तत्काल देने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। भीम के बारे में जानकारी हो तो दे दीजिए अन्यथा नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो भीम जिला होगा भीम आयेगा, सर।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न तो फसल बीमा का ही पूछा है। खण्ड-1 और खण्ड-2 में फसल बीमा की बात कही है।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि आनलाइन आवेदन पत्र चाहे वो संरक्षित खेती से जुड़े ग्रीन हाउस हो, पाली हाउस हो, नेट हाउस हो, यदि उन्होंने आनलाइन आवेदन किये हैं तो लक्ष्य के मुताबिक निश्चित रूप से उन किसानों को उसी जिले के लक्ष्य और उसी तहसील के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: भादू साहब, यह भीम से सम्बन्धित है आप क्या पूछेंगे? भीम से सम्बन्धित है। अगला सवाल। डा. मंजू बाघमार।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): यह फसल बीमा से ही सम्बन्धित है, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, भीम से सम्बन्धित। (व्यवधान)

जायल को अपराध मुक्त करने की कार्ययोजना

315. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल को अपराध मुक्त करने हेतु एक सकारात्मक पहल की गई थी? यदि हां, तो कब व इस हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र को अपराध मुक्त करने की पहल से अपराधों में कमी आई है? यदि हां, तो गत 04 वर्षों में थानेवार विभिन्न श्रेणी के अपराधों का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल के केवल ग्राम जायल को अपराध मुक्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के कार्यालय आदेश क्रमांक 33213-27 दिनांक 15.08.15 से अपराध मुक्त ग्राम बनाने का संकल्प लेने का निर्णय लिया गया था। इस हेतु उठाये गये कदमों का विवरण उक्त आदेश में अंकित है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ पर है।

(2) जी हां यह सही है कि ग्राम जायल में उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2015 में 70 प्रकरण, वर्ष 2016 में 41 प्रकरण व वर्ष 2017 में 32 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जायल में अपराधों में काफी कमी आई है। विधान सभा क्षेत्र जायल में भी गत 04 वर्षों में दर्ज प्रकरणों में वर्षवार कमी रही है। विधान सभा क्षेत्र जायल के सभी पुलिस थानों का गत 04 वर्षों में थानेवार दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जायल विधान सभा का जो क्षेत्र है गांव जायल उसमें एक अभिनव पहल की गयी, तत्कालीन थाना अधिकारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा जन सहभागिता से जायल को अपराध मुक्त घोषित करने के लिए जो पहल की गयी, उसके लिए धन्यवाद।

(डा. मंजू बाघमार)

लेकिन फिर भी मुझे जो कुछ जानकारी मिली है कि जो जायल थाना क्षेत्र है वहां पर कुछ लूटपाट, डकैती, भू-माफिया, आपसी रंजिश और वन्य जीवों की शिकार की घटनाएं तो कुछ बढ़ी हैं, आंकड़ों में जरूर थोड़े बहुत अपराध कम हुए हैं। जायल को अपराध मुक्त करने के लिए जो सकारात्मक कदम उठाया गया है, यदि उसको वास्तव में अपराध मुक्त घोषित करना है तो अब तक अधिकारियों और वृत्ताधिकारियों द्वारा जो इसका एक उद्देश्य था कि जायल में घटित अपराधों की समीक्षा और उसका निरोधात्मक उपाय किया जाए या जागरूकता फैलाने का काम किया जाए, यूथ क्लब बनाया जाए, छोटे-छोटे विवादों का चिन्हीकरण किया जाए, तो इस दिशा में अब तक, जो 2015 में जायल को अपराध मुक्त घोषित करने का कार्य उससे लेकर अभी तक जो कार्य किये गये हैं, उसके बारे में जरूर मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना जायल में अपराध में विभिन्न अपराधों में यह स्थिति रही:-

हत्या- 2014 में 1, 2015 में 3, 2016 में 2, 2017 में 2. हत्या का प्रयास- 2014 में जीरो, 2015 में जीरो, 2016 में 4 और 2017 में जीरो। लूट- 2014 में जीरो, 2015 में 1, 2016 में जीरो, 2017 में जीरो। अपहरण- 2014 में 1, 2015 में 2, 2016 में जीरो और 2017 में 5. बलात्कार- 2014 में 1, 2015 में 2, 2016 में जीरो और इस साल 5. नकबजनी- 2014 में 1, 2015 में 5, 2016 में 4 और इस साल 1. चोरी- 14, 5, 8, 3.

टोटल आई.पी.सी. अपराध पूरे जायल थाने में 2014 में 167, 2015 में 128, 2016 में 72 और 2017 में 86. लगभग सभी हैड में अपराध घटा है, 2017 में किसी-किसी में एकाध अपराध बढ़ा है।

जो आपने अपराध मुक्त गांव के बारे में कहा था, जायल में एक गांव आपका रामपुरा है, वो अपराध मुक्त हुआ है और पूरी विधान सभा में आपके 8 गांव अपराध मुक्त हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आप और पूरक प्रश्न करेंगी? जवाब तो आ गया।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि 2017 में जरूर अपराधों में वृद्धि हुई है और 2015 और

(डा. मंजू बाघमार)

2016 में जब अपराध मुक्त घोषित किया था, तब जरूर कमी आयी थी। 2017 में जो अपराधों में वृद्धि हुई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो अधिकारी लोग कार्य कर रहे हैं, अपराध मुक्त के लिए आंकड़े जरूर उन्होंने कम बताये हैं लेकिन फिर भी यदि अपराधियों को शह देने का छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, उन्हें यदि आप आदेशित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जायल को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जायल ने जो पहल की और वहां के एस.पी. श्रीवास्तव ने अपराध मुक्त गांव करने के लिए 15 अगस्त, 2015 को जो आदेश जारी किया कि हर ब्लाक में कम से कम एक गांव अपराध मुक्त हो और इसी कारण से पूरे नागौर में 88 गांव अपराध मुक्त हुए हैं और सारे राजस्थान में भी हमने पहल की, वो 2016 तक 2234 गांव अपराध मुक्त राजस्थान में हुए हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हर गांव अपराध मुक्त हो और पंचायत राज मंत्रीजी साथ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि जो गांव हम अपराध मुक्त करते हैं उसको कोई विशेष आपकी योजना में किसी न किसी प्रकार का लाभ उस गांव को और उस पंचायत को ताकि लोगों में इस ओर आगे बढ़ने का और एक तरह से उत्साह जागे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री भागीरथ चौधरी के स्थान पर श्री शंकर सिंह रावत।

अजमेर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के स्वीकृत कार्य

316. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) (श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) के स्थान पर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में अजमेर जिले को अब तक कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार, पंचायत समितिवार तथा स्वीकृत कार्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(3) प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितने भामाशाहों द्वारा उक्त योजनान्तर्गत राशि प्रदान की गई है? विधान सभा क्षेत्रवार, पंचायत समितिवार व भामाशाह के नाम मय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के किस-किस ग्राम को किन-किन जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों व एजेन्सियों द्वारा गोद लिया गया है तथा इनका इस योजना में अब तक क्या योगदान रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जलग्रहण (केचमेन्ट) क्षेत्र उपचार के कार्य, लघु सिंचाई योजना के कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, जलसंग्रहण ढांचों की क्षमता बढाने के कार्य, पेयजल स्रोतों को सुद्ढीकरण करने के कार्य, चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि कार्य स्वीकृत किये जा सकते है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत अजमेर जिले में अब तक क्रमश: प्रथम चरण में 1785.38 लाख रुपये एवं दितीय चरण में 771.11 लाख रुपये राज्य मद से उपलब्ध कराये गये। विभिन्न विभागों द्वारा उनके विभागीय मदों से कन्वर्जेन्स कर भी कार्य सम्पादित करवाये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्रवार प्रथम चरण एवं दितीय चरण में स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पंचायत समितिवार प्रथम चरण एवं दितीय चरण में स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

एजेन्सीवार प्रथम चरण एवं दितीय चरण में स्वीकृत कार्यो की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम एवं दितीय चरण में कुल 24 भामाशाहों (औद्योगिक प्रतिष्ठान/धार्मिक संगठन, जन प्रतिनिधि/दानदाता) द्वारा अब तक 40.42 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है, जिसका भामाशाहवार, विधान सभा क्षेत्रवार, पंचायत समितिवार प्राप्त की गयी राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(4) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम एवं दितीय चरण के अन्तर्गत अजमेर जिले में जन प्रतिनिधियों, भामशाहों/एजेन्सियों द्वारा कोई भी ग्राम गोद नहीं लिया है।

जन प्रतिनिधियों, भामाशाहों/एजेन्सियों द्वारा योजनान्तर्गत प्रदान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर 1, श्री शंकर सिंह जी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जल स्वावलम्बन योजना जब से शुरू हुई है, राजस्थान में एक बहुत अच्छी योजना पानी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी लाई हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो वहां अधिकारी लगे हुए हैं, ये अपनी मनमर्जी से कार्य ...(व्यवधान) जिस जगह पर पानी का अच्छा भराव हो और पानी की उपलब्धता ज्यादा हो, जिस प्रकार अजमेर जिले की ही पंचायत समिति जवाजा के राजड़ा बांध और कोटा बांध, दोनों का सर्वे 2 बार करवा लिया गया है, उसके बावजूद वे अधिकारी यह कह देते हैं कि साहब, यह कैचमेंट एरिया में नहीं आ रहा है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि वन विभाग को भी एजेंसी बनाकर उस एरिये को ले सकते हैं। क्या उनको आप लेंगे या नहीं, कैचमेंट एरिया में पुल बनवाने के लिए? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में जो गांवों का चयन है, उसके मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के मेरे उत्तर में कहा कि इस योजना में राज्य मद के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस करके यह एक अनूठा अभियान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चलाया है। इनमें जिन गांवों का चयन किया जाता है, उनमें प्राथमिकता उनको दी जाती है जो IWMP में या अन्य जलग्रहण योजनाओं में या four water concept आदि में स्वीकृत हों या ऐसे गांव जहां पीने योग्य पानी न हो यानी Flouride, nitrous आदि हों उस गांव में या विगत 5 वर्षों से टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा हो उस गांव में या 5 वर्षों में ये गांव अकालग्रस्त या अभावग्रस्त घोषित किये गये हों।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन गांवों को भी प्राथमिकता दी जाती है, जहां 70 फीसदी भूमि बारानी हो और अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो गांव प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना या मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना में या सांसद अथवा विधायकों के द्वारा गोद लिए जाते हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है और उन गांवों को भी प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें भामाशाह आगे बढ़कर यह कहें कि इस योजना में वे अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। इसलिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निर्धारित मापदण्डों के आधार पर यह चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, क्योंकि IWMP योजना भारत सरकार की योजना है, जो कई वर्षों से चल रही है, उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में जो धनराशि आती थी, उस समय उस भूमि का उपचार पूर्णत: नहीं होता था, इसलिए इस योजना को कन्वर्जेंस के माध्यम से चलाया गया है।

आप जवाजा के जिस गांव की बात कर रहे हैं, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं, पर अगर इन मापदण्डों में वह गांव आता है तो निश्चित तौर पर उसे शामिल किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, उन मापदण्डों के अन्दर ही है और विधायक कोष से भी अगर आवश्यकता होगी तो मैं पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए उसमें देने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ वहां कार्य चालू करवाने या स्वीकृत करवाने के लिए कृपा करें। उस कैचमेंट एरिया के अन्दर ही है। वहां के एक्सईएन ने भी बताया, तो वह शुरू करवाने के लिए कृपया आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, आश्वस्त कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस तरह पहले कहा, गांवों के चयन के मापदण्ड बने हुए हैं और इसमें मुख्य रूप से क्लस्टर और माइक्रो वाटर शेड, इसके आधार पर कौन-से पानी को surface water को बरसात के पानी को trap किया जा सकता है, उसके आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य जिस बात के लिए कह रहे हैं, मैं उस गांव की विस्तृत DPR वगैरह दिखवा लूंगा। अगर वे सारे मापदण्ड पूरे कर रहे हैं तो उस गांव को निश्चित तौर पर IIIrd phase में शामिल करने की अनुशंसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक, श्रीमती शकुंतला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का उद्देश्य तो यही है कि पानी भरे, चाहे वह कन्वर्जेंस योजना से, किसी से भी हो...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जिस जगह पर पानी का भराव क्षेत्र है और गहरा है, जहां सच में पानी भर सकता है और उस बांध से चाहे पंचायत समिति जड़वासा, श्रीनगर हो, चाहे पुष्कर में पहाड़ी क्षेत्र हो, मसूदा हो, किशनगढ़ हो, मैं अजमेर का ही पूछ रही हूं, अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी गहराई से नहीं देखें। वहां जल स्वावलम्बन की योजना के तहत ऐसी जगहों पर क्यों नहीं कार्य किया गया, मैं यह पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब दीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का तीसरा चरण है। पहले चरण में पूरे राजस्थान में 3529 गांवों का चयन किया गया था और उसके अंतर्गत 95192 जल ढांचों को बनाया गया था और मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन शत प्रतिशत ढांचों के अन्दर पानी आया और ये ढांचे आज भी पानी से लबालब भरे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा चरण इसके बाद प्रारम्भ किया गया और उसमें 4213 गांव और 1 लाख 29 हजार 588 ढांचे बनाए गए और यह तीसरा चरण है, जिसमें 4300 गांव लिए गए हैं और 1 लाख 50 हजार से अधिक ऐसे ढांचे बनाए जाएंगे, जिनमें वर्षा का जल और स्थायी जल का संग्रहण करके हम कोशिश करेंगे कि गांव जल की दृष्टि से स्वावलंबी हों। इस योजना को इस दृष्टि से आगे बढ़ाया गया है।

माननीय सदस्या जो कह रही हैं कि कुछ गांव के अन्दर, जहां जल है या पहाड़ी है, जहां से पानी बहकर आता है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि इस योजना के पीछे हेतु यह है कि हर ब्लाक के अन्दर इस प्रकार की गतिविधियां चलें ताकि लोगों में जन-जागृति आए। गांव के अन्दर पहली बार जल बजट की बात भी... जल बजट माने गांव में कितना जल उपलब्ध है... (व्यवधान)... अंडरग्राउंड वाटर किस प्रकार का है, उसके आधार पर उसमें कितने पानी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मनुष्यों को, जानवरों को आवश्यकता है, पहली बार राजस्थान में जल बजट की बात हुई...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, घुमा-फिराकर जवाब दे रहे हैं। एक भी बांध का सुदृढ़ीकरण इस योजना में नहीं कराया गया, कहीं पानी भरा नहीं है, गांवों में, खेतों में खोद दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी, ऐसे नहीं। बैठिए, बैठिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभी जगह यही हाल है, पूरे राजस्थान का हाल है।

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने भी बांध हैं, सारे बांधों की मरम्मत करके उन बांधों को इसमें लिया जाए, यह सम्भव नहीं है। यह तो एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो चयनित गांव हैं, जिनको मापदण्ड के अनुसार चयनित किया गया है, अगर उनमें से किसी गांव का चयन किया गया हो और उसमें कोई जलग्रहण ढांचा लिया गया हो या उसमें कोई एनीकट लिया गया हो और उसमें पानी नहीं आया हो तो आप मुझसे शिकायत कर सकती हैं, मैं उसकी जांच करवाऊंगी, ...(व्यवधान) और यह पहली योजना है अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) हां कराऊंगा, कराऊंगा। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए...असर आ गया आपका उन पर, असर आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं उनकी तरफ आकर्षित होकर बोल रहा था, इसलिए 'गी' निकल गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, होली का असर आ गया और होली के असर में इन्होंने अपने आपको नारी रूप में ग्रहण कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: बात कुछ ऐसी ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हरसोरा का बांध है, रामपुर के हैं, धीरपुर के बांध हैं, जो इतने भारी हैं, पानी की कमी है तो, इसलिए उनका करवा दें उद्धार। (व्यवधान) एक का भी करवा दो, साहब, मैं मान जाऊं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, अगर इसमें चयनित कोई गांव है और उस चयनित गांव में कोई भी चैक-डैम या एनीकट बना है और उसमें पानी नहीं आया हो तो उसकी निश्चित तौर पर जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला पूरक प्रश्न, श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की जो प्रदेश में एक साथ एक ही दिन शुरुआत की जाती है और जो इस योजना की शुरुआत का जो पहला दिन होता है, उसमें सभी पंचायत समितिवार जिन ग्राम पंचायतों में काम चालू होता है, वहां एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें क्या जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है और क्या विधायक के द्वारा उस कार्यक्रम का लोकार्पण किए जाने का प्रावधान है या नहीं? यदि है तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो तीसरे फेज में काम चालू हुआ, उसमें विधायक होते हुए और मेरे खुद की ग्राम पंचायत में काम होते हुए मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, क्या मंत्री महोदय, जो अधिकारी हैं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ...उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का विचार रखते हैं, मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान है। अभियान कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, अध्यक्ष महोदय। यह जनता का कार्यक्रम है, जनता के लिए कार्यक्रम है, जनता को समर्पित कार्यक्रम है। इस अभियान में वे सब लोग सम्मिलित हुए, जो वास्तव में जागरुक हों और जो चाहते हैं राजस्थान में जल समस्या जो कि आने वाले समय के लिए बहुत चुनौती वाली है, हमारे डार्क जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 248 ब्लाक हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें से 164 ब्लाक आज अति-दोहित हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य जागरूक सदस्य हैं। इसमें किस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत थी? लोग चल-चलकर 'साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे' कहते हुए गांव के गांव, जत्थे के जत्थे के जत्थे चले गए, आपाको खुद को आना चाहिए था, ...(व्यवधान) अगर आप नहीं आए तो...अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर माननीय विधायक उसके अन्दर नहीं गए, III[rd] phase का कार्यक्रम इनके विधान सभा क्षेत्र में चला और एक मापदण्ड के अनुसार चला, कोई राजनीतिक आधार पर गांव का चयन नहीं हुआ और उसके बाद भी आप नहीं गए तो आपको खुद को अपने आप में अफसोस करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह अधिकारों का हनन है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। नहीं, जवाब आ गया। (व्यवधान) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। भंवरसिंह जी का अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री अध्यक्ष: यह दो-दो बार नहीं होता है। पूरक प्रश्न आपने एक कर लिया और उसका जवाब आ गया। (व्यवधान) भंवरसिंह जी, कृपया विराजिये। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। भंवरसिंह जी, कृपया विराजिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। यह क्या तरीका है? पूरक प्रश्न एक होता है, बैठिये आप। (व्यवधान) जवाब जो आप चाहो वो नहीं आ सकता। जो आएगा वह जवाब आएगा। आप बैठिये, मैं कह रहा हूं। नहीं, बैठिये आप। मिस्टर भंवरसिंह, बैठिये आप। (व्यवधान) भूत और वर्तमान की बात मत कीजिये, बैठिये। मैं आपसे कह रहा हूं, बैठिये। आदेश नहीं है, व्यवस्था है कि एक पूरक प्रश्न कर लिया उसका जवाब आ गया, दूसरा आप नहीं कर सकते। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान ने राजस्थान में एक आंदोलन का रूप लिया है तो इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक जिले में दूसरे जिले के अधिकारियों को भेजकर जांच कराकर इस काम को और सही तरीके से आंदोलन के रूप में करें, यह कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: सुझाव है माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पहली योजना है और इसमें जितने काम होते हैं उसके 10 परसेंट काम रेंडम से लिए जाते हैं और थर्ड पार्टी से उसका इंस्पेक्शन कराया जाता है। फर्स्ट फेज में अजमेर के अन्दर कुल मिलाकर जो गांव थे उन गांवों की संख्या 4483 थी और 450 गांवों में जो काम हुए उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्दर निर्धारित मापदण्ड और मानकता के साथ हो, इसलिए पहले से ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का इसमें प्रावधान डाला गया है।

प्रश्न संख्या 317

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री रमेश।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल श्री चन्द्रभान सिंह।

प्रदेश में गैर सरकारी संस्थाओं को खेलों के लिए अनुदान

318. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में क्रीड़ा क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं को खेलों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत 4 वर्षों में (31 दिसम्बर, 2017 तक) कितनी अनुदान राशि किस-किस संस्था को कब-कब, किस-किस मद से दी गई? वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में उक्त अनुदान राशि हेतु किस-किस संस्था द्वारा आवेदन किये गये तथा कितनों को अनुदान राशि आबंटित की गई एवं कितनों को किस कारण से अनुदान राशि दिया जाना लम्बित है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनुदान राशि से वंचित संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(5) क्या सरकार क्रीड़ा क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

युवा मामले एवं खेल मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2016 में विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत क्रीड़ा क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न है।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में अनुदान नियमों के तहत गत 4 वर्षो में निम्न संस्था ने अनुदान हेतु आवेदन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**संस्था का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1	2016-17	जौहर स्मृति संस्थान	50000
2	2017-18	जौहर स्मृति संस्थान	50000

वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि संस्था को बैंक खाते में आनलाइन भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम-2016 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त खेल संस्थाओं को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के पश्चात् आवेदन करने पर नियमानुसार अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

(5) जी नहीं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्कूल के खिलाड़ी भी खेलते हैं और ओपन के भी खेलते हैं पर, अध्यक्ष महोदय, उन खिलाड़ियों को किस अनुपात में टी.ए., डी.ए. मिलता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल का बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट खेलने जाता है उसको 70 रुपये मिलते हैं, वही बच्चा स्टेट खेलने जाता है उसको 100 रुपये मिलते हैं और वही बच्चा नेशनल खेलने जाता है तो उस राजस्थान के बच्चे

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

को 225 रुपये मिलते हैं। एक बच्चा खेलने जाता है तो 70 रुपये में उसको चाय-पानी मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा तो यह कैसे क्या हो सकता है और उनको किट मिलने का तो काम ही नहीं है। नेशनल जाएगा तो नेशनल के बच्चे को भले ही 1250 रुपये मिलेंगे उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। मैं आपको दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर बता सकता हूं कि जैसे हरियाणा में......

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सवाल यही है अध्यक्ष महोदय। आज हरियाणा का बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलने जाता है उसको 125 रुपये मिलते हैं, स्टेट खेलने जाता है उसको 250 रुपये मिलते हैं और वही नेशनल खेलने जाता है तो उसको 250 रुपये मिलते हैं। महाराष्ट्र का बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट खेलने जाता है तो उसको 150 रुपये मिलते हैं, स्टेट खेलने जाता है उसको 150 रुपये मिलते हैं और नेशनल खेलने जाता है उसको 280 रुपये मिलते हैं।

वही बच्चा अगर ओपन खेलता है तो डिस्ट्रिक्ट में उसको कुछ भी नहीं मिलता है, स्टेट खेलने जाता है तो 300 रुपये मिलते हैं और नेशनल खेलने जाता है तो उसको 500 से 550 रुपये मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से राजस्थान का खिलाड़ी कम्पीटिशन में भाग ले, एशियाड खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले तो उनके लिए आने वाले दिनों में माननीय मुख्य मंत्री महोदया से भी मैं रिक्वैस्ट करता हूं, माननीय मंत्री महोदय से भी रिक्वैस्ट करता हूं और यह क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसी बजट में जो स्कूल से डिस्ट्रिक्ट खेलने जाता है उसको कम से कम 200 रुपये डिस्ट्रिक्ट में मिले, 300-400 रुपये स्टेट में मिले और कम से कम 700-800 रुपये नेशनल खेलने के लिए मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी डी.ए. की बात की। जो टी.ए. है वो तो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

एक्चुअल्स पर ही पेमेंट दिया जाता है और जो डी.ए. है वह स्टेट लेवल के गेम्स में 2015-16 में 200 रुपये प्रतिदिन था जिसको हमने बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ओपन का बढ़ाया है, स्कूल का नहीं बढ़ाया है।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): नेशनल गेम्स का 300 से 500 रुपये कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है इसमें दो डिपार्टमेंट इन्वाल्व हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स इवेंट्स के अन्दर सपोर्ट देता है वो स्टेट कम्पीटिशन में 50 रुपये प्रतिदिन देते हैं और 150 रुपये नेशनल गेम्स के लिए देते हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज के जो बच्चे हैं, जिनकी एक एपेटाइट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कैलोरीज इतना बर्न करते हैं, कीर्तिमान लाते हैं हमारे स्टेट के लिए और बढ़ती मुद्रा स्फीति के स्तर को देखते हुए हम दोनों मिलकर फाइनेंस को अवश्य प्रपोजल भेजेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका खाली टी.ए., डी.ए. का है। जहां बच्चों को प्रोत्साहित करने का मामला है उसके अन्दर हमारे पास आठ कैटेगिरीज हैं। इसके अन्दर प्राइस मनी है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेटवाइज। उसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर को डिवाइड किया हुआ है, ब्रांस, गोल्ड, सिल्वर को डिवाइड किया हुआ है। अचीवर्स जो हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कीर्तिमान स्थापित किया है, उनको एक से 5 लाख रुपये इक्विपमेंट के लिए दिए जाते हैं। जो स्टेट लेवल के हैं उनको 30 हजार रुपये सालाना ट्रेनिंग और ट्रेवलिंग के लिए दिया जाता है, नेशनल गेम्स के लिए 75 हजार रुपये दिये जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं। कोचिंग में फ्री कोचिंग है, हमारी एकेडमीज हैं, हमारे महाराणा प्रताप अवार्ड्स है, गुरु गोलवलकर अवार्ड्स हैं, हमारी जितनी भी एसोशिएशन टूर्नामेंट्स होल्ड करती हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उनको एक लाख से दस लाख रुपये हम देते हैं। आपके टी.ए., डी.ए. का मैंने आपको बताया कि बढ़ाया है। इसके अलावा टेलेंट सर्च जो है उसमें हर साल और अभी पिछले साल 145 खिलाड़ियों को सलेक्ट किया, एक लाख रुपये सालाना चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे डाइट हो उसके लिए इनको दिया है तो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने युवा पीढ़ी के लिए 9-10 अलग-अलग हैड्स बनाए हैं जिनसे इनको बैनेफिट मिले।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने ओपन में बढ़ाया उसके लिए तो मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा पर जो स्कूल का बच्चा, पैराइशी बच्चा, 5वीं तक का, 8वीं तक का, 12वीं तक का स्कूल से खेलता है और स्कूल का टी.ए., डी.ए. पिछले कम से कम 8-10 साल से नहीं बढ़ा है इसलिए स्कूल के बच्चे का टी.ए., डी.ए. बढाएं। उसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में जो खिलाड़ी स्टेट खेलता है, नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है उसको 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 10 परसेंट पासिंग में ग्रेस मिलता है तो क्या राजस्थान में भी अपन ऐसा करना चाहते हैं? मंत्री महोदय, इस तरह का भी करें और आज आप यह बताएं कि स्कूल का टी.ए., डी.ए. भी हण्डरेड परसेंट बढ़ेगा, ओपन का भी बढ़ेगा। आपने बात घुमाकर बता दिया कि हम पारितोषिक देंगे, यह देंगे, यह नहीं, आप तो स्कूल का बताओ कि स्कूल का बढ़ाएंगे और ओपन का कितना बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और है, अपन नेहरू युवा केन्द्र द्वारा पैसा देते हैं और गांवों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): तो नेहरू युवा केन्द्र के अलावा भी हम राजस्थान में ऐसी कुछ फैकल्टी आगे के लिए करना चाह रहे हैं क्या? इस तरह का भी बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): और अपन स्कूल का टीए डीए बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे और 10 परसेंट मार्क्स जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? इतना स्पष्ट क्लियर बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, शिक्षा मंत्रीजी से मैं बैठकर बात करूंगा क्योंकि स्कूल के गेम्स हैं, वह शिक्षा विभाग से संबंधित है। हम बैठकर, दोनों डिपार्टमेंट्स इसमें चर्चा करके, हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के अन्दर रिकमण्ड करें इनका डी ए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): 10 परसेंट वाला, 10 परसेंट वाला ग्रेस जो दूसरे राज्यों में मिलता है, वह अपने राज्य में मिलता है या नहीं, बताएं।

श्री अध्यक्ष: नो नो नो, बैठिये, बैठिये आप। मिस्टर बैठिये। जवाब आ गया। श्री मानवेन्द्र सिंह, पूरक प्रश्न नम्बर एक। मानवेन्द्र सिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): यह गलत दब गया। हुकुम, यह गलत दब गया।

श्री अध्यक्ष: गलत दब गया तो सही दबाना चाहिए। मानसिंहजी, आप कर लीजिये मानवेन्द्र सिंह जी का।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी हैं, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन की योजना रखते हैं कि उस प्रकार से गांवों के खिलाड़ियों को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ-साथ में मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे गांवों के अन्दर जितने भी नेहरू युवा केन्द्र हैं, जिनमें सरकारी सहायता से लोगों ने निजी परिसम्पत्तियां बना ली हैं, क्या ऐसे संस्थानों की आप जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के जितने भी गेम्स हैं, ये एसोसिएशन्स करती हैं। हमारा विभाग है, खाली कोचिंग फेसेलिटीज और इन्फ्रास्ट्रकचर हम प्रोवाइड करते हैं। ग्रामीण स्पोर्ट्स हो चाहे शहरी स्पोर्ट्स हो, उसके अन्दर एसोसिएशन्स ही टूर्नामेंट्स करती हैं और उनको आर्गनाइज करती हैं। हम ग्रांट-इन-एड देते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे राज्य क्रीड़ा परिषद का स्टेट का बजट कितना है? अगर बजट पर्याप्त है तो हमारे इस राज्य की कितनी प्रतिभाओं को अभी तक हम उभार पाये हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दीजिये हो तो।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एग्जेक्ट फीगर्स तो नहीं हैं पर लगभग पिछले सात-आठ साल से जो महाराणा प्रताप और गुरु गोलवलकर अवार्ड्स नहीं दिये गये थे लगभग 2008 से, हमने माननीया मुख्य मंत्रीजी के कर-कमलों से करीबन लगभग 200-250 अवार्ड्स बैकलाग करके फुलफिल किये हैं और अब जो मार्च का महीना यह शुरू हो गया है, हम 2017-18 का भी, मार्च 31 से पहले उनको हम अवार्ड दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा, करेंगे? यह है भी सवाल, कीजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि मैं और शिक्षा मंत्रीजी बैठकर, हम तय करके जो भी उचित प्रयास हो सकेगा, वह करेंगे। आपका दोनों का बैठना कब होगा, वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला सवाल, श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठकर भी क्या कर लेंगे? रिकमण्ड ही करेंगे। बैठकर भी ठन-ठन ही है।

जालौर में राशन सामग्री का वितरण

319. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में गत चार वर्षों में राशन डीलरों द्वारा कितने राशन कार्डों पर कौन-कौनसी राशन सामग्री वितरित की गई? ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने स्थानों पर राशन डीलर हैं व उनमें से गत चार वर्षों में कितने राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में गत चार वर्षों में राशन डीलरों द्वारा निम्न राशनकार्डों (संख्या) पर राशन सामग्री (गेहूं, चीनी एवं केरोसिन) वितरित की गई हैं:-

सामग्री/वर्ष	2014	2015	2016	2017
गेहूं	43,810	43,810	43,810	43,810
चीनी	14,753	14,753	14,753	4,059
केरोसिन	64,582	64,088	65,601	51,303

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

वितरित की गई राशन सामग्री का ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्तमान में 112 राशन डीलर हैं एवं गत चार वर्षों में चार राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न नम्बर एक। अलकाजी, अपने स्थान पर जाइये, आपस में बात मत कीजिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि जो लाइसेंस रद्द किये गये हैं, उनकी नई निविदा कब तक निकालेंगे और अगर निकालेंगे तो कब तक वह स्वीकृत करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन हमने नई दुकानों का 2015-16 में निकाला था। उसमें 13 दुकानों की हमने वेकेंसी निकाली थी, उनमें से 13 दुकानें अनुमोदित कर दी गई हैं, जिनमें सात में हमने प्राधिकृत-पत्र भी जारी कर दिये गये हैं और जो छह दुकानें बाकी हैं, उनमें कुछ प्रक्रिया का पार्ट बाकी है। उसमें किसी ने जो आवश्यक दस्तावेज थे, वह दस्तावेज नहीं दिये। किसी में हमने उनको सूचना की, सूचना करने के बाद वह लोग आये नहीं। जैसे ही वह लोग आएंगे तो जिन दुकानों के लिए हमने विज्ञापन निकाला है, उनमें निश्चित रूप से हम लोग दुकानें जल्दी ही जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि जिन पंचायतों में आबादी बढ़ गई हैं, उन जगह पर डीलर्स की संख्या है, वह बढ़ाने का विचार रखते हैं? अगर रखते हैं तो कब तक इन रिक्त पदों पर आप स्वीकृतियां निकालेंगे? बताइये।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंहजी, बातचीत नहीं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन डीलर की नई दुकानों के लिए सरकार ने कुछ नोर्म्स तय किये

(श्री बाबूलाल वर्मा)

हैं, जैसे कि उस क्षेत्र में 500 राशन कार्ड होने चाहिए और 2,000 यूनिट होना आवश्यक है और हम इस पर भी सोच रहे हैं, जहां डीलर के पास ज्यादा राशन कार्ड है, तो उनको भी चैक करवाकर इस रेशो में यदि कोई नियमानुसार आवश्यकता होगी तो नई दुकानों के आबंटन के लिए हम लोग विज्ञापन भी जारी करेंगे और उसके हिसाब से कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, श्री नारायण सिंह जी देवल। (व्यवधान) नहीं, बैठिये। नारायण सिंह जी देवल, फिर आपका है। यह जालौर से संबंधित है, जालौर विधान सभा क्षेत्र।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में 2014 में चीनी इन्होंने अलाट की है 14,753 किलोग्राम और अगर 2017 में देखें तो इन्होंने चीनी अलाट की है 4,059 किलोग्राम। अब 2014 से 2017 की तुलना करें तो 2017 में इन्होंने 10,694 किलोग्राम कम चीनी अलाट की है और इसी तरह से भी केरोसिन में भी 2014 से 2017 का देखें तो 13,279 लीटर कम केरोसीन दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चीनी और केरोसिन कम अलाट किया है, उसको आगे पूरा करने का विचार रखते हैं और अगर रखते हैं तो कब तक करेंगे? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जो यह 4,059 का आपने जिक्र किया है, अब वर्तमान में केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार हम लोग अन्त्योदय परिवारों को ही चीनी देते हैं। पहले यह चीनी बीपीएल प्लस अन्त्योदय, दोनों परिवारों को मिला करती थी, इसलिए ज्यादा अलाट होती थी। वर्तमान में जितने अन्त्योदय परिवार हैं, उनको न केवल जालौर विधान सभा क्षेत्र में, बल्कि पूरे राजस्थान में हम लोग चीनी बंटवा रहे हैं। इसमें एक किलो प्रति परिवार के हिसाब से हम लोग चीनी बांटते हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने केरोसीन की बात बताई है, इसमें जिन लोगों के पास, जिन पात्र परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं हैं, उन

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लोगों को हम लोग केरोसिन देते हैं। ढाई लीटर प्रति परिवार हम लोग लगातार इनको केरोसिन दे रहे हैं आज की तारीख में। गेहूं का जहां तक सवाल है, मैं गेहूं के बारे में आपके माध्यम से निवेदन कर दूं, एनएफएस में चयनित परिवार हैं, उनको पांच किलो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देते हैं और जो अन्त्योदय परिवार हैं, अन्त्योदय परिवार को हम लोग 35 किलो पर फैमिली के हिसाब से गेहूं का आबंटन करते हैं। वर्तमान में पूरे राजस्थान में चयनित परिवारों की जितनी संख्या है, उसके हिसाब से गेहूं का आबंटन कर रहे हैं और उसी प्रकार से चीनी और केरोसिन का भी हम लोग आबंटन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा, श्री प्रताप सिंह।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: वह आ गया, जवाब आ गया। आप और पूछ लेना बाद में। श्री प्रताप सिंह। वैसे भी प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है। हां, प्रताप सिंहजी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो चयन समिति राशन डीलर का चयन करती है...

श्री अध्यक्ष: यह जालौर से संबंधित है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यह जालौर से ही संबंधित है, पूरे राजस्थान से ही संबंधित है साहब। जालोर की ही बात है। चयन समिति जिसको चयन करती है, उसको छोड़कर जो चयन किया गया है, उसको नहीं देकर, क्या दूसरे का भी चयन कर लिया जाता है?

श्री अध्यक्ष: सवाल अलग से करें। प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिए 01 अप्रैल, 2018 से नियम AIS 113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विद्युत कनेक्शनों एवं बिल वितरण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से पंजाब व हरियाणा द्वारा सतलज एवं व्यास नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़ने से नहरी क्षेत्रों में बसे लोगों को हो रही जानलेवा बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जालौर जिले में पिछले कुछ समय से रात्रिकालीन हैल्पलाइन बंद होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग की वर्ष 2016-17 की डी.पी.सी. में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति ठण्डी, खाटा व लखा टीब्बा बरानी क्षेत्र में अस्थायी आबंटित भूमि को स्थायी रूप से आबंटित करने के संबंध में।

(7) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में DRDA से छंटनीशुदा कार्मिकों को ग्राम सेवक के पदों पर समेकित वेतन पर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी, माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह, श्रीमती सोनादेवी, श्री मनोज कुमार एवं श्री हीरा लाल दरांगी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत भुवाणा की चरागाह एवं नाड़ी क्षेत्र की जमीन को पेसिफिक एजूकेशन सोसायटी, उदयपुर को रिजर्व प्राइस पर आबंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत बसवा को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(3) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ जिले की भुड़वाई नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी राजकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद में हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना से पेयजल आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

(6) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मण्डाना क्षेत्र में कोटा बैराज से पानी पहुंचाकर किसानों को राहत पहुंचाये जाने के संबंध में।

(7) डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातौली कस्बे में स्थित राजकीय अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावास में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

(9) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थान एवं तीर्थ स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

(10) श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से नागौर जिले की जायल और खींवसर तहसील के लाइम स्टोम खनन हेतु किसानों की

(श्री अध्यक्ष)

जमीन अवाप्त कर औद्योगिक घरानों को आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम देवता के खसरा नं. 70 रकबा 1.44 भूमि को कचरा प्रबन्धन हेतु नगरपालिका को आबंटित करने के संबंध में।

(12) श्रीमती कामिनी जिंदल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 05 मार्च, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री शंकर लाल शर्मा, विधान सभा क्षेत्र दौसा में बिजली सुधार हेतु जी.एस.एस., सहायक अभियंता कार्यालय खोलने एवं वी.सी.आर. भरने में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

(2) मास्टर मामन सिंह यादव, ग्राम खिजूरीवास, तहसील तिजारा नगर परिषद भिवाड़ी के गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 148 पर मैसर्स स्टार रायजन लैण्डमार्क सोसायटी, भिवाड़ी द्वारा अवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री जगदीश नारायण, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जयपुर से भानपुर कला वाया साइवाड तक लो-फ्लोर बस चलाने के संबंध में।

(4) श्री पब्बा राम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप एवं राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने एवं पी.एच.सी. केशवनगर (फलौदी) हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटन के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह।

अनुरोध एवं मांग

ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के बारे में वक्तव्य की मांग

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे ओलावृष्टि हो गयी, पूरे प्रदेश में किसान की फसलें बर्बाद हुई हैं। गूंगी-बहरी सरकार बैठी है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कुछ किसान का बर्बाद हो गया। पहले तो ...(व्यवधान) दे दिया, कर्ज माफी को लेकर ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलों से सब कुछ बर्बाद हो गया, और सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारी ओले पड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झेंप मिटा रहे हैं, मुख्य मंत्री ने कल ओलावृष्टि हुई, ...(व्यवधान) गिरदावरी के आदेश मुख्य मंत्रीजी ने कल दे दिये, ये झेंप मिटाने का काम कर रहे हैं। हम कहीं पीछे न ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, आपने 11 हजार करोड़ का पैकेज मांगा था, दो साल पहले...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आज दिन तक कभी ऐसा हुआ है क्या। कल बारिश हुई और कल के कल ये आदेश कर दिये कि गिरदावरी कर दी जाए, इससे ज्यादा और मुख्य मंत्रीजी क्या कर सकती हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, आपदा राहत मंत्रीजी, आपने 11 हजार करोड़ का पैकेज पहले भी मांगा था केन्द्र से, दो साल पहले। लेकिन, 11 सौ करोड़ रुपये मिले...(व्यवधान) सरकार सक्षम नहीं है, केन्द्र से पैसा लेने के लिए ...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ... क्या कर सकती है? आप बताओ? गिरदावरी के लिए सरकार ने कल का कल आदेश कर दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? केवल चिल्लाना आपका काम है, आपको किसान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की मदद करने की इच्छा थोड़े ही है, कल का कल आदेश मुख्य मंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के लिए और क्या कर सकते हैं, गिरदावरी आने के बाद ही तो मदद ...(व्यवधान)

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: वाक आउट करना है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 00

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

श्री अध्यक्ष: आपदा प्रबंधन मंत्रीजी इस विषय पर अपना वक्तव्य देने को तत्पर हैं इसलिए आप सब अपनी सीटों पर चले जाइये। आपदा प्रबंधन मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय जिस गम्भीरता से, इस प्रदेश की जनता और किसान के साथ जो हुआ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। मैंने उन्हें पुकारा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसके बाद में आपदा राहत मंत्रीजी जवाब देंगें तो अच्छा रहेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बात सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप सुनना ही नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने देख लिया। मैंने इनसे कहा, बैठिये, बयान दिलवाता हूं। फिर भी हंगामा कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं इस विधान सभा में। मैं इसकी निन्दा करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं। (व्यवधान) आपके आपसी झगड़े हैं ...(व्यवधान) या तो आप इनको बैठाओ ...(व्यवधान) मैं बयान दिलवाता हूं...(व्यवधान) बैठ जाइए, बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) आप सब आइए, हंगामा कीजिए, राजस्थान की जनता देख रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) यह विधान सभा में हाका करने के लिये आये हैं, इनको हाका करने दो, हाका करके थक जाएंगे तब अपनी कार्यवाही चालू करेंगे, आप शांति से बैठिए, करो हाका करो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: कोई दो मिनट की बात नहीं, अपनी सीटों पर जाइए, यहां से नहीं, सीटों पर जाइए। पहले नियमों का पालन कीजिए, गेट आउट। (व्यवधान) नो, नो। आपका कंट्रोल नहीं है ...(व्यवधान) आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, यह कोई आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बैठा नहीं सकते, बैठ जाइए आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, नो, नो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) एक भी शब्द अंकित नहीं हो, एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हीरा लाल (निवाई): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

बहिर्गमन

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कल जो ओलावृष्टि हुई उससे कई जिलें प्रभावित हुए, कई किसान और कई गांव प्रभावित हुए। इतनी बड़ी समस्या है, सबने कम से कम रात को टेलीविजन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं देखा तो कोई बात नहीं, सवेरे अख़बार तो सबने पढ़ा था और पढ़ने के बाद कांग्रेस ने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं, उसको अगर राजस्थान की जनता पढ़े तो शर्म, शर्म करके इनको एक तरह से नाक डुबो लेनी चाहिये कि इस प्रकार की घटना पर तो इनको साढ़े नौ बजे आकर पर्ची डालने तक की फुर्सत नहीं। एक भी प्रस्ताव होता और आसन स्वीकार नहीं करता, तब तो समझ में आ सकता था कि इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई और आसन ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इनको एक भी प्रस्ताव लिखने की फुर्सत नहीं थी और केवल यह कि हमसे भारी भूल हो गई, उस भूल को सुधार करने के लिये इस सदन का बिना नियमों से जिस प्रकार से इन्होंने हुड़दंग की, यह इस लोकतंत्र के लिये शर्मनाक है और राजस्थान की मुख्य मंत्री को सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहिये, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के, केवल जो ट्रेजडी हुई और उनको जानकारी मिली, कल कि कल उन्होंने स्पेशल गिरदावरी के आदेश इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना क्विक एक्शन होकर गिरदावरी की सूचना हो गई। गिरदावरी के आने के बाद ही तो पता लगेगा कि कहां कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ और उसमें सरकार को क्या भरपाई करनी है और क्या इमिजिएट सहायता देनी है। जब तक इसके आंकड़े नहीं आएंगे तब तक हम कैसे देंगे। जो भी तुरन्त देना होगा, देंगे। लेकिन इनको तो इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि इनमें से कोई बंदा आकर साढ़े नौ बजे राजस्थान के उस किसान के साथ प्रकृति ने जो किया, उसके लिये यहां आकर कम से कम एक प्रस्ताव तो डाल देते। अब केवल अपनी झेंप मिटाने के लिये, राजस्थान के किसान को क्या जवाब देंगे। प्रतिपक्ष है या मजाक है? इतनी बड़ी समस्या के बारे में इनको प्रस्ताव डालने की फुर्सत नहीं है और यहां आकर हल्ला करते हैं। सुखराम जी ने जो प्रस्ताव पेश किया, जिसको आपने स्वीकार नहीं किया, सुनकर आश्चर्य होता है। यहां चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं किसान के पक्ष में, कहते हैं जालौर जिले में पिछले कुछ समय से रात्रिकालीन हैल्प लाइन बंद होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। यह तो महत्वपूर्ण है, किसान का प्रस्ताव इनके लिये महत्वपूर्ण नहीं था। शकुन्तला जी ने कहा कि विधान सभा बानसूर में विद्युत कनेक्शनों और बिल वितरण में हो रही अनियमितता के संबंध में, यह है इनके प्रस्ताव। किसान के ऊपर इनको अधिकार था, आसन इसको 100 परसेंट स्वीकार करता, हमारी जिम्मेदारी थी। जो कुछ भी वस्तु स्थिति हम इकट्ठी कर पाते, उसका हम यहां आकर जवाब देते, लेकिन यह उस जनता को शक्ल क्या दिखाएं, शक्ल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिखाने के लिये यहां वैल में आकर हल्ला करके एक न्यूज बनेगी कि हमने किसान के लिये किया, यह पहली बार इनकी पोल खुली है। इतनी बड़ी ट्रेजडी किसान के साथ होने के बाद भी, मैं आसन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि बिना एक मिनट भी व्यर्थ किये हुए, उन्होंने गिरदावरी की सूचना लेकर आंकड़े मंगाने के लिये सब जगह सूचना भेज दी है, आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर यह चर्चा करना चाहें तो आप समय दे दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। प्रकृति का प्रकोप न मेरे हाथ में है, न इनके हाथ में है। इन्होंने 52-53 साल राज किया, अगर किसी ओलावृष्टि के दूसरे दिन इन्होंने गिरदावरी की घोषणा कर दी तो वह साल निकालकर बताएं। वह तारीख निकालकर बताएं जब इन्होंने गिरदावरी की घोषणा की हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन कर रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता जिम्मेदार पद पर हैं, इन्होंने आपको इंगित करते हुए कहा कि +++ मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान के इतिहास में पहली बार किसी प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी सीट से खड़े होकर इस प्रकार इंगित किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह रिकार्ड पर नहीं आया। यह रिकार्ड पर नहीं आया। मैंने उसको रिकार्ड पर नहीं लिया है। वह रिकार्ड का पोर्शन नहीं है, इसलिए आपका आब्जेक्शन भी कोई मायने नहीं रखता है।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, इनको तो यह दु:ख है कि इनकी कहीं सरकार नहीं बनी है, इनको किसानों का दु:ख नहीं है। उत्तर-पूर्व में इनकी सरकार कहीं नहीं बनी। एक राज्य में तो खाता भी नहीं खुला। (व्यवधान) तीन राज्यों में सरकार गयी।

श्री अध्यक्ष: हीरालाल जी बैठिए। श्रीमती सोनादेवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रायसिंहनगर की पंचायत समितियों में भूमि का स्थायी आबंटन

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद साहब जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना

(श्रीमती सोनादेवी)

चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का लगभग आधा एरिया, जिसमें ठण्डी, ठाकरी, खाटा, लखा टीबा, बरानी की चार पंचायतें ऐसी हैं, इनमें अभी तक बहुत से किसानों को सैकड़ों मुरब्बों का अभी तक स्थाई रूप से आबंटन नहीं मिला है। मैं इनका स्थायी आबंटन करने के लिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिन किसानों की जमीन को डी-कालोनाइज्ड घोषित कर दिया गया है, वह रकबा 1950 से 1988 तक किसानों को अस्थाई आबंटित हो रहा है। तत्पश्चात 1988 से डी-कालोनाइज्ड घोषित हुआ। ऊंचा रकबा होने से किसानों को नि:शुल्क आबंटन राज्य सरकार को किया जाना था। 1988 से पहले रकबा टी.सी. पर था, उसके बाद सरकार के आदेश रकबा राज घोषित कर दिया गया, जिस पर तवान व नीलामी की प्रक्रिया राजस्व वसूली के लिये होती रही है, जिसे डी-कालोनाइज्ड के पीड़ित किसान 30 वर्षों से जमा करवा रहे हैं, जबकि रकबा डी-कालोनाइज्ड घोषित है, जिसकी कभी भी सिंचाई नहीं हो सकती। इन 30 वर्षों के दौरान किसानों ने अपनी जमीनों की दोगुनी कीमत राजस्व वसूली में तवान व नीलामी के रूप में जमा करवा दी है। मगर आज दिनांक तक सरकार द्वारा पुख्ता आबंटन के आदेश नहीं दिये गये हैं। सन् 1988 के बाद न तो किसानों को रकबा का अस्थायी आबंटन किया गया और न ही पुख्ता आबंटन किया गया है, बल्कि नाजायज काश्तकार के कार्यवाही कर, कुर्की व तवान की कार्यवाही की जाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। बीच में ही ऐसी जमीन जैसी ठाकरी और ठण्डी के किसानों की सोसाइटी भूमि, जिसके पूरे रिकार्ड की फाइल हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एडीएम साहब के यहां से आपके सैक्रेटरी आई हुई है। पूरा रिकार्ड है, सिर्फ आपके जवाब का इंतजार है, वहां के किसान, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान आस लगाये बैठे हैं। जो सोसाइटी भूमि का है और डी-कोलोनाइज्ड है, उसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: रिपीट मत कीजिए। जवाब दे रहे हैं। राजस्व मंत्री जी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): सम्माननीय अध्यक्ष जी, रायसिंहनगर से आने वाली माननीया सदस्या ने जो बात रखी है। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति के चक, लखा टीबा, ठण्डी, खाटा के बारानी को अधिसूचना दिनांक 17.05.1988 से डी-कमांड घोषित किया गया। जबकि अधिसूचित रकबे को तत्समय आबंटन अधिकारियों द्वारा उपनिवेशन

(श्री अमराराम)

नियमों में आबंटन कर आबंटी गैर-खातेदार दर्ज हैं। आबंटितों के द्वारा किश्तें जमा कराने के बावजूद भी रकबा डी-कालोनाइज्ड होने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं। ठण्डी, खटा लखा, टीबा और बारानी क्षेत्र में अस्थाई भूमि का स्थाई आबंटन करने के संबंध में परीक्षणोपरांत गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर गंगानगर को निर्देशित किया जा रहा है। धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सोसाइटी भूमि का और आदेश कर देते तो...। इसी में है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बात कर लेना। विराजिए। श्री मनोज कुमार।

DRDA के छंटनीशुदा कार्मिकों की ग्राम सेवक पद पर नियुक्ति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से छंटनीशुदा कार्मिक, जिनकी पुनर्नियुक्ति समेकित वेतनमान पर ग्राम सेवक पदों पर की गयी। नियुक्ति को नियमित वेतनमान पर स्वीकृत करने के बाबत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 से लेकर 2018 तक छंटनीशुदा कार्मिक लगातार एक निर्धारित वेतनमान 4000 रुपये पर कार्य कर रहे हैं। ये नियमित कर्मचारी थे, नियमित होते हुए पंचायती राज विभाग में इनको पदस्थापित किया गया, लेकिन उस दिन से लेकर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। इन सरकारों ने इन कर्मचारियों को लगातार फाइलों में भोला राम का जीव बनाकर इनको घुमाने का काम किया है। वर्तमान पंचायती राज मंत्री महोदय ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी मीटिंग 27.12.16 को हुई और 06.01.17 को इनकी कमेटी की मीटिंग द्वारा निर्णय पारित किया गया और इस निर्णय में पांच नंबर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के छंटनीशुदा कार्मिकों को, जिनकी पुनर्नियुक्ति समेकित वेतनमान पर ग्राम सेवकों के पदों पर की गयी, को नियमित वेतन मान श्रृंखला स्वीकृत करने के संबंध में उप समिति द्वारा सिफारिश की गयी कि प्रशासनिक विभाग वर्ष 2001 से उक्त कार्मिकों को नियमित वेतनमान श्रृंखला प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का परीक्षण कर वित्त विभाग को सहमति हेतु भिजवाने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, उस समय आप इस विभाग के मंत्री नहीं थे। तब तो आप इस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में आप इसी विभाग के मंत्री हो, इसलिए आप

(श्री मनोज कुमार)

से गुजारिश करता हूं कि इन कर्मचारियों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उनके पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। उसके बाद सरकार अनदेखी न करे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1992 में डीआरडीएम में उपयोजना की जब समीक्षा हुई। राजेन्द्र जैन कमीशन बना, उसमें डीआरडीएम में काम करने वाले 338 पदों को समाप्त किया गया था और 112 पद सृजित किये गये थे। उसके अनुसार ये बायो गैस के मिस्त्री, जिनका जिक्र राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। बायो गैस मिस्त्री - सैकिण्ड के 47 पद समाप्त किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, इनमें 7 स्नातक स्तर के थे, 17 सैकण्डरी स्तर की क्वालीफिकेशन थी और 23 मिडल स्तर की शिक्षा ग्रहण किये हुए थे। इनमें जो स्नातक स्तर के थे, चूंकि ग्राम सेवक की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी की है, इसलिए ये जो 7 स्नातक स्तर के थे, इनको तो ग्राम सेवकों के पद पर समायोजित कर दिया पर बाकी सब लोगों को, जो सैकण्डरी और मिडल पास ही थे, इनको एक समेकित वेतन पर। आप जो कह रहे है वह निश्चित तौर पर सही है, ये अभी भी समेकित वेतन पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं। कैबिनेट सब-कमेटी बनी, कैबिनेट सब-कमेटी ने इन 40 कर्मचारियों के बारे में ग्राम सेवक, कनिष्ठ लिपिक और वाहन चालकों को प्रथम नियुक्ति करण की दिनांक से बिना वार्षिक वृद्धि पुन: नियुक्ति के लिए एक अभिशंसा परीक्षण के लिए वित्त विभाग की समीक्षा के लिये भेजी। वित्त विभाग ने उसमें सहमति नहीं जताई। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार फिर मैं मेरी अभिशंसा के साथ इसको भेजूंगा और वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने पर निश्चित रूप से कोई कार्यवाही की जाएगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। माननीय

श्री अध्यक्ष: नो नो नो। श्री हीरालाल दरांगी, एब्सेंट।

295, श्री मानिक चन्द सुराना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज सत्ता पक्ष की तरफ से 33 माननीय सदस्य शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने वाले हैं और लगभग 11 उधर से हैं, 295 को पढ़ा हुआ मान लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

295 को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची के माध्यम से, श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मुझे तो पढ़ने का अवसर दीजिए। औरों के हैं, दूसरे पढ़ेंगे, इसलिए मुझे भी पढ़ना है। मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी।

श्री अध्यक्ष: मानिक जी, यह पढ़ा हुआ मान लिया गया है। सहमति हो गयी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): या तो सबको पढ़ा हुआ मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष: सबको पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है, रिकार्ड पर आ जाये।

श्री अध्यक्ष: 295 की जितनी भी सूचनाएं हैं, सबको आज पढ़ा हुआ मान लिया गया। पर्ची के माध्यम से। श्री शंकर लाल पर्ची एब्सेंट, मास्टर मामन सिंह, एब्सेंट। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। सदन मैं चला रहा हूं। स्प्रिंग लग रही हो तो हटा दीजिए। हां, शंकर लाल जी आ गये। शंकर लाल जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

दौसा में नवीन जी एस एस की स्थापना

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के

(श्री शंकर लाल शर्मा)

माध्यम से बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो चार साल से जब से सरकार आई है, दौसा के अन्दर कनेक्शनों में सुधार हुए हैं। हमारे झारड़ा, तितरवाड़ा, सिन्डौली, सिविल लाइन 33 केवी के जीएसएस बनाए गए। 132 केवी का नांगल राजावतान में भी जीएसएस बनाया और शहर में पहली बार 18.50 करोड़ की लागत से भूमिगत केबल का कार्य भी किया। हमारे दौसा की हालत यह थी कि ए.सी. तो कभी चलता ही नहीं था लेकिन 70 नये ट्रांसफार्मर लगाकर दौसा की विद्युत सप्लाई को बेहतर तरीके से दिया। ट्रिपिंग की समस्या खतम हुई। खासतौर से जिला चिकित्सालय, दौसा में भी गांव की, देहात की लाइन से जुड़ा हुआ था। पहली बार उसको भूमिगत केबल करके डायरेक्ट जीएसएस से जोड़ा। हमें आदर्श ग्राम पंचायत में भी 24 घंटे बापी को विद्युत आपूर्ति दी, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। सभी कार्यों के लिए मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बिजली के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था कर रखी है। पूर्णत: बिजली सप्लाई दी जा रही है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमारे एरिया के अन्दर कुछ एरिया ऐसा है जहां पर जीएसएस होना जरूरी है। आदरणीय मंत्री महोदय, जब दौसा के अन्दर पधारे थे तब भी हमने अवगत कराया था और मंत्रीजी ने आश्वस्त भी किया था कि हमारे सिंगवाड़ा, चूड़ियावास और दौसा के आगरा रोड़ पर नए जीएसएस देंगे। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां का कुछ एरिया ऐसा है कि दूरी के कारण हर समय लाइन में डिफेक्ट आता रहता है। इसके कारण वहां के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है। साथ ही दौसा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 हजार से ऊपर कनेक्शन हैं। उसके अन्दर दौसा शहर है, जहां निरन्तर आबादी बढ़ रही है, क्योंकि जिला बना और जिला बनने के बाद में दौसा जिले के ही नहीं बल्कि आस-पड़ौस के करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर तक के लोग दौसा में मकान बना रहे हैं। ऐसे में निरन्तर दौसा की आबादी बढ़ रही है और आज की तारीख में 80 हजार से ऊपर कनेक्शन हैं। इसके अन्दर शहर और देहात में एक ही एईएन है। एक नांगल राजावतान में है और एक सैकिण्ड है। हमने आपसे मांग की है कि दौसा को सुचारु रूप से चलाने के लिए कम से कम एक एईएन आफिस और एक नया एईएन दिया जाए ताकि जिस व्यवस्था को आप बेहतर तरीके से चला रहे हैं, उसकी समुचित व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है मेरा। खासतौर से वीसीआर। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा वीसीआर बहुत बढ़िया तरीके से चलाई गई। आपकी घाटापूर्ति भी हुई है और अभी भी आपने सदन को बताया है कि हम 400 करोड़ के लाभांश में चले। इसके साथ-साथ इस वीसीआर में खासतौर से लाइन में टैक्निकल हैल्पर और वे ही लोग गांवों के अन्दर, देहात में जाकर डरा-धमका कर वीसीआर का झांसा देकर आम उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रहे हैं। खासतौर से एक बात और बतलाना चाहूंगा कि वीसीआर का उपभोक्ता को मालूम भी तब पड़ता है, जब बिल आता है, चार महीने बाद में, तीन महीने बाद में। न उसको मालूम कि मेरा वीसीआर कब भरा, सही भरा या गलत भरा। कम से कम इस तरीके से जो वीसीआर भरा जा रहा है, टैक्निकल हैल्पर, लाइनमैन, जेईएन अकेला पहुंचकर, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी है और उपभोक्ता के साथ अन्याय भी है। इसी तरीके से आपके द्वारा लोड के कारण वीसीआर भरा जा रहा है। आज कोई भी मकान बना रहा है। दुकान, शोरूम चलाता है, शुरू में जब मकान बनाता है तो बिजली कनेक्शन इतना लगा लेता है कि लाइट खूब हो जाती है। उसको मालूम नहीं है कि मेरे मकान के अन्दर कितना लोड होना चाहिए? मेरे शोरूम में कितना लोड होना चाहिए? लोड कम ले रखा है, मीटर भी है और ईमानदारी से वह बिल पे कर रहा है। लेकिन लोड के अन्दर कि साहब आपने चार हार्स पावर का ले रखा है, आपने कनेक्शन लगा रखे हैं पांच हार्स पावर के। आज अपनी विधान सभा में भी इतने कनेक्शन होंगे कि मालूम नहीं कितना लोड होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): हुकुम मैं इसी के ऊपर बोल रहा हूं। आम उपभोक्ताओं को मालूम नहीं है। ऐसे में वीसीआर भरने वाले वहां जाते हैं और सीधे ही उसको डराते हैं। ईमानदार आदमी को भी डराते हैं कि यह कनेक्शन ज्यादा ओवरलोड है इसलिए तुम्हारी वीसीआर भरी जाएगी। इसकी आड़ में वह लाख रुपए का, डेढ़ लाख रुपए का बताते हैं और फिर सौदा करते हैं कि तू पचास हजार रुपया दे तो तेरा वीसीआर नहीं भरा जाएगा। ऐसे हालात हैं, मंत्री महोदय जबकि आप सही तरीके से सुचारु रूप से कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे ये तीन जीएसएस, एक

(श्री शंकर लाल शर्मा)

एईएन आफिस और खासतौर से जो वीसीआर भर रहे हैं। ये अकेले-अकेले जाकर जो भर देते हैं, इस पर कुछ किया जाए। एक कमेटी बनाई जाए और उसी समय जब वीसीआर भरा जाए, उपभोक्ता को नोटिस दे दें या उसके साइन करवा लें। उसी समय उसकी जानकारी में आ जाए कि आप चोरी कर रहे हो। हम मना नहीं कर रहे हैं कि चोरी का वीसीआर भरो। लेकिन अननेसेसरी जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, आपका टैक्निकल हैल्पर, जेईएन और एक साधारण कर्मचारी जाकर उसको डराता है, उससे कम से कम हमारे उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाएं। यही अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो बात की है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 33/11 केवी के तीन सब-स्टेशन चावरियावास, ख्वारावजी और लाडली का बास में स्थापित कर चालू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 33 केवी के 3 सब-स्टेशन एक सिविल लाइंस, दौसा के पास, सिन्दौली और तितरवाड़ा में बनाए जा रहे हैं। यह कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी इसको पूर्ण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने चूडियावास और सिंगवाड़ा के लिए नये जीएसएस के प्रस्ताव भेजे हैं। निश्चित रूप से मैं इसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालकर और कोस्ट-बेनेफिट रेशो निकालकर और अगर कोस्ट-बेनिफिट रेशो में अगर आता है तो निश्चित रूप से आपने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनको स्वीकृत कराएंगे। इन्होंने एक नया एईएन आफिस खोलने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद में पहले बजट भाषण में घोषणा की थी कि हम पांच साल के कार्यकाल में लगभग 30 लाख से ऊपर डोमेस्टिक कनेक्शन देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हमने हमारे कार्यकाल में लगभग 30 लाख कनेक्शन दे दिए हैं और दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से तथा पावर फार आल जो हमने मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू योजना के तहत शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल के अन्दर हम लगभग 7 लाख नए कनेक्शन, जो गैर-आबादी, आबादी और जो ढ़ाणी नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत जल्दी विद्युत कनेक्शन देने जा रहे हैं। माननीया मुख्य

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मंत्रीजी ने अपने बजट भाषणा में घोषणा की है कि हमारे इस कार्यकाल में अभी कुछ दिनों में, विधान सभा खतम होने के बाद लगभग पूरे राजस्थान में 93 सब-डिवीजन खोलने जा रहे हैं और लगभग 23 डिवीजन खोलने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में तीनों डिस्काम के...

आम उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके। दूर-दराज से आते हैं, कोई भी समस्या होती है तो एईएन आफिस बहुत दूर पड़ता है, कंजूमर्स की संख्या बढ़ गई है। हम नये डिवीजन भी खोल रहे हैं, नये 93 सब डिवीजन भी खोल रहे हैं। हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि शहरी क्षेत्र में 25 हजार कंजूमर्स का एक सब डिवीजन रखेंगे। लगभग 70-80 हजार के ऊपर हम एक डिवीजन रखेंगे, हमने यह क्राइटेरिया बनाया है। इस क्राइटेरिया के तहत, हमने डिस्कॉम के माध्यम से भी हमने वर्कआउट किया है। पश्चिमी राजस्थान, जहां पर कंजूमर्स की कमी है, एईएन आफिस में जाने के लिए व्यक्ति को 120 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, उसका भी हमने विशेष प्रावधान रखा है, इनके लिए हमने कम रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 20 हजार कंजूमर्स के लिए एक सब डिवीजन आफिस खोलने का प्रावधान किया है। लगभग 70 हजार पर एक डिवीजन खोलने का प्रावधान रखा है। पूरे राजस्थान में आने वाले समय में 93 सब डिवीजन खोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा शहर में दो एईएन आफिस हैं। एईएन प्रथम में लगभग 44 कनेक्शन हैं। एईएन द्वितीय में लगभग 19 हजार कनेक्शन हैं। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में एक एईएन आफिस खोलने की बात की है, इनकी इच्छा है कि एक नया एईएन आफिस खुले, निश्चित रूप से मैं इसका वर्क आउट करके, पूरी कोशिश करके, इसको खुलवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा।

दूसरी बात इन्होंने वीसीआर की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेडा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वीसीआर से एलर्जी है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वीसीआर के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। सभी माननीय सदस्य जब यह बात कहते हैं तो हमने इसके बारे में काफी विचार-विमर्श किया है। विचार-विमर्श करके वीसीआर की मानीटरिंग कमेटी भी बनाई है। सुबह से लेकर रात तक,10 बजे से पहले-पहले उसकी जितनी भी वीसीआर काट रहे हैं, 10 बजे से पहले, एम डी आफिस में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कितनी वीसीआर हुई है, किस सब डिवीजन में, किस डिवीजन में कितनी वीसीआर हुई है, शाम 10 बजे तक पूरी रिपोर्ट एम डी आफिस तक पहुंचेगी। अगर लेट किया तो उससे हमें यह मालूम चल जाएगा कि व्यक्ति का कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेन्शन है इसलिए उसने रिपोर्टिंग एम डी आफिस को नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, हमने इसके लिए 22.02 को, 25.02 को हमने यह कहा कि एक व्यक्ति स्वयं, जेईएन, एईएन, खुद अकेला जाकर विजिलेंस भी करेगा। उसके साथ टेक्निकल टीम होगी। उसके साथ सहायक अभियंता एमएनपी होगा, एक एईएन या जेईएन, एक कमेटी के साथ, पुलिस के साथ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति जाता है और वह विजिलेंस करके आता है, हो सकता है कि उसका मेलाफाइड इंटेन्शन हो या हो सकता है कि उसके साथ उसकी अनबन हो, उसी कारण वह विजिलेंस कर रहा है। इन सबको दूर करने के लिए हमने एक कमेटी फोर्म की है। इस कमेटी में 5-7 या 8 आदमी होंगे। वह साथ चलेंगे तभी वह विजिलेंस करेगा। शाम 10 बजे से पहले पहले एम डी आफिस में उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मामन सिंह।

भिवाड़ी की तहसील तिजारा के ग्राम खिजूरीवास में एक फर्म द्वारा रास्ते पर अवैध कब्जा

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्ची के माध्यम से मैं माननीय यूडीएच मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। भिवाड़ी शहर की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। विश्वप्रसिद्ध औद्योगिक इकाइयां भी वहां पर हैं। बड़े-बड़े बिल्डर्स ने वहां आवासीय परियोजनाओं के साथ बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। दिल्ली और हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों से लोग वहां पर आवास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भिवाड़ी शहर मेरे तिजारा क्षेत्र के अन्दर आता है। लगभग 3 लाख के आस-पास वहां आबादी है। कुछ बिल्डर्स विकासशील योजनाओं की आड़ में वहां के सौंदर्यीकरण के साथ और वहां के ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी हैं, किसान हैं, वहां की जनता है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका रास्ता रोककर, पौराणिक संस्कृति, धर्म स्थल को नष्ट करने, संस्कृति को नष्ट करने पर तुले

(मास्टर मामन सिंह यादव)

हुए हैं। गांव खिजूरीवास उसी नगर परिषद भिवाड़ी में ही आता है। उसमें गैर मुमकिन खसरा नम्बर 148 है, ब्रिटिश शासन के समय से नक्शे में रास्ता है, आजादी से पहले 200 साल पुराना रास्ता है। उस रास्ते को यूआईटी के, भिवाड़ी के अधिकारियों से, मिलीभगत करके 20211-12 में यूआईटी ने बिल्डर को बेच दिया या अवैध कब्जा करा दिया, यह तो मंत्री महोदय ही जानकारी देकर बताएंगे। पूरे रास्ते को जाम करके 10 फुट की चारदीवारी बना दी गई।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उस दीवार को हटवा कर, लोकायुक्त के यहां भी ग्रामीणों ने दावा किया। दावा करने के बाद यूआईटी का जवाब यही था कि हमने रास्ते पर अवैध कब्जे की कोई परमीशन नहीं दी, अन्य जगह की हमने परमीशन दी है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, विराजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): साहब यह तो अभी भूमिका है।

श्री अध्यक्ष: भूमिका इतनी लंबी है तो फिर क्या है?

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, पहली बार तो मुझे पर्ची पर बोलने का मौका मिला है, अभी एक मिनट भी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): होली पर बाबा मोहन राम का मेला भरता है। 15 लाख अनुयायी 8-10 स्टेट से आते हैं। वह रास्ता भी मूल रूप से, पुराने समय से, खिजूरीवास से ही गुजरता था, वह रास्ता रोक दिया गया है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उस रास्ते की जांच कराई जाए। चरागाह भूमि भी उसी बिल्डर ने दबा ली। अवैध रूप से रास्ता दबा लिया। लोकायुक्त के आदेश के बावजूद भी रास्ता दबा दिया गया, उसको तुरन्त खुलवाया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि 2011-12 में यूआईटी के जिस अधिकारी की मिली भगत थी, या अब आदेश के बावजूद भी जिसने पालना नहीं की, उनके ऊपर भी कार्यवाही हो, बिल्डर्स पर कार्यवाही हो।

दूसरी बात, 8-8, 10-10, 14-14 मंजिलों की बिल्डिंग्स बन रही हैं, निर्माणाधीन हैं, वहां लोग आवास करने आते हैं, यूआईटी से न तो कम्पलिशन सर्टिफिकेट लेते हैं, पैसे ले-लेकर बेच देते हैं। कोई सुविधा नहीं होती, नोर्म्स है कि यह-यह सुविधा होनी चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, अग्निशमन होना

(मास्टर मामन सिंह यादव)

चाहिए आगजनी बुझाने के लिए, पार्किंग होनी चाहिए, यह सब एग्रीमेंट में देते हैं, उनमें एक भी नहीं होता। जो भी वहां पर आवास करने आ रहे हैं समझ लेते हैं कि फंस गए। उनका पैसा बटोर लिया। जितनी भी सोसाइटियां बनी हुई हैं, बहुत इमारतें वहां बनी हुई हैं, भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए कि यूआईटी ने, सरकार ने उनको परमीशन दी थी, स्वीकृति दी थी क्या नोर्म्स के आधार पर फिजिकल रूप से उनकी सोसाइटियां बनी हुई हैं, नोर्म्स के आधार पर बिल्डिंग बनी हुई है, फिजिकल जांच कराई जाए, अगर गलत है तो कार्यवाही की जाए।

खिजूरीवास का खसरा नम्बर 148, पुराना रास्ता है, आपको यह दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसको शीघ्र खुलवाया जाए। जनता में काफी आक्रोश है। माननीय मंत्रीजी हेमसिंह भडाना जी, श्रम मंत्री जसवंत यादव जी, और भी कई, 5-6 नेतागण उस गांव में, उस क्षेत्र में गए, पूरे क्षेत्र वालों ने इनका कड़ा विरोध किया था। अगर यह रास्ता नहीं खुलवाया गया तो हम जबरन तोड़-फोड़ करके, वहां अशांति भी हो सकती है। यह मेरा निवेदन है, कोई धमकी मत समझना। जांच करके हर हालत में इसको खुलवाया जाए। चरागाह भूमि को भी दबा लिया गया। 2011-12 में रोक दिया गया था। लोकायुक्त के आदेश के आधार पर रोक दिया गया था, 2011-12 में मिलीभगत करके ....

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): यूआईटी अधिकारियों से मिलीभगत करके उसको रोक दिया गया। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि डंडा तुड़वाकर रास्ता खुलवाया जाए, बहुत ही आवश्यक है। जनता खुद तोड़ेगी तो उसमें अशांति होगी, इससे हमें भी दिक्कत आएगी, सरकार को भी दिक्कत आएगी, लॉ एंड आर्डर खराब होगा।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस रास्ते का जिक्र किया है, हालांकि यह मैटर बहुत पुराना मैटर है, ग्राम खिजूरीवास में मैसर्स स्टार रायसन की आवासीय परियोजना राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 11.09.2007 को अनुमोदित की गई। इस आवासीय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
परियोजना में खातेदारी भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 148, क्षेत्रफल 0.14, किस्म और गैर मुमकिन रास्ता, व खसरा नम्बर 200, क्षेत्रफल 0.03 हैक्टेयर किस्म बीड़ के रूप में राजकीय भूमि के रूप में स्थित थी।

मामनसिंहजी, तहसीलदारजी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 148 गैर मुमकिन रास्ते पर आवागमन नहीं होने की रिपोर्ट दी गई थी, तहसीलदार द्वारा, तथा राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार इसका स्वतंत्र उपयोग भी सम्भव नहीं था। अत: राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार खसरा नम्बर 148 व 200, कुल क्षेत्रफल 0.17 हैक्टेयर अनुपयोगी राजकीय भूमि को डी.एल.सी. दर पर मैसर्स स्टार रायसन को आबंटित करने का, जो हमारी राज्य स्तरीय समिति बनी हुई है, उसने निर्णय ले लिया। उसके बाद जिला कलेक्टर, अलवर ने अपने आदेश दिनांक 15.04.2008 द्वारा डी.एल.सी. दर की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को जमा कराने की शर्त पर यह भूमि नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को आबंटित की। नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा मैसर्स स्टार रायसन से डी.एल.सी. की राशि वसूल कर उसकी खातेदारी की भूमि के साथ-साथ खसरा नम्बर 148 व 200 का आबंटन पत्र दिनांक 16.042008 को जारी कर दिया गया। विकासकर्ता ने अनुमोदित परियोजना के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना ली, जिसमें खसरा नम्बर 148 व 200 भी सम्मिलित है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 148, रकबा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के नाम पर दर्ज है। अध्यक्ष महोदय, विभागीय परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के अनुसार इस प्रकार के आबंटन, नियमन सरकार कर सकती है। इस तरह के नियम बने हुए हैं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, यह जो रिपोर्ट दी है कि रास्ता अवरुद्ध था, आज भी आधा किलोमीटर रास्ता तो उस बिल्डर के डण्डे तक पहुंच रहा है, वह तो अब भी चालू है। वह तो रास्ता अवरोध किया गया है। यह तो रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट तो मेरे पास ही है। आप उसकी जांच कराएं। (व्यवधान) आप मौके की जांच कराइये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी नहीं, पुरानी रिपोर्ट है, 2008 की रिपोर्ट है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मैं फिर भी माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो शंका है, आप लिखित रूप में, आपने आज मामला यहां उठाया है, इसकी मैं जांच कराऊंगा और नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी, निश्चित रूप से हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

जयपुर से भानपुर कलां वाया साईवाड़ लो-फ्लोर बस का संचालन

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने की इजाजत दी, उसके लिये आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक विशेष महत्वपूर्ण समस्या, जिसको मैं पर्ची के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जयपुर, बड़ी चौपड़ से भानपुर कलां, वाया साईवाड़, यह जो सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग के दोनों तरफ से लगभग नौ ग्राम पंचायतें हैं। उन पंचायतों के कम से कम 50 गांव इस सड़क मार्ग के दोनों तरफ बसे हुए हैं। सड़क मार्ग भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। विभाग के माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बढ़िया, फर्स्ट क्लास सड़क बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से तीन कस्बों के बारे में काफी समय से लो-फ्लोर बसें लगाने की मांग लगातार चली आ रही थी। जिसमें से नायला और जमवारामगढ़ में मुख्य मंत्रीजी ने और विभागीय मंत्री महोदय ने लो-फ्लोर बसें चला दी हैं। वे बसें आज जनता की भरपूर सेवा कर रही हैं। उस क्षेत्र को काफी सुविधा मिल रही है और सरकार को उन बसों के माध्यम से अच्छी इनकम भी हो रही है।

इन दो कस्बों के अलावा एक कस्बा भानपुर कलां, जो जयपुर से साईवाड़ होता हुआ सड़क मार्ग जा रहा है और इसी मार्ग पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय कालोनी नारदपुरा में बसी हुई है। उस नारदपुरा कालोनी में लगभग 2500 फ्लैट्स बने हुए हैं, और सारे 2500 फ्लैट्स ही अलाटेड हैं। सबमें लोग रह रहे हैं। उस क्षेत्र की लगभग दस हजार की आबादी है।

(13.05 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जगदीश नारायण)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग दस हजार लोगों की आबादी वाला यह जे.डी.ए. कालोनी क्षेत्र है, जिसमें मजदूरी पेशा और नौकरी पेशा लोग रहते हैं। उसके आगे साईवाड़ ग्राम पंचायत पड़ती है। इस रोड पर छह ग्राम पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की लगी हुई हैं और तीन ग्राम पंचायतें विधान सभा क्षेत्र आमेर की लगी हुई हैं। कुल मिला करके 50 गांवों की आबादी का क्षेत्र है। आज तक इस रोड पर किसी प्रकार की कोई सरकारी बस की सुविधा नहीं है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से इस रोड पर लो-फ्लोर बस चलाई जाये, ताकि उस क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल सके। इस क्षेत्र में जो लो-फ्लोर बसें चल रही हैं, इसमें गाड़ी नम्बर-एक कूकस से सांगानेर तक जाती है। दूसरी, गाड़ी नम्बर-पांच, यह आमेर नोलखा स्टेडियम से मानसरोवर तक जाती है। ये बसें भरी हुई आती हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरी पेशेवर लोगों को और नौकरी पेशेवर लोगों को आने-जाने की सुविधा देने हेतु इस रोड पर लो-फ्लोर बस चलाई जाये, ताकि इस क्षेत्र का, क्योंकि यह क्षेत्र जयपुर से लगा हुआ क्षेत्र है। अधिकांश, हजारों की तादाद में लोग यहां आ करके, मजदूरी करके रोजाना अपना भरण-पोषण करते हैं। इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करुंगा कि इस क्षेत्र में यह लो-फ्लोर बस चला करके मेरे क्षेत्र के लगभग 50 गांवों की जनता को राहत पहुंचाने की मेहरबानी करें। धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर द्वारा वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्ग संख्या तीस, बड़ी चौपड़ से रामगढ़ वाया सड़वा नाई की थड़ी, सायपुरा, प्रति बीस मिनट की फ्रिक्वेंसी पर सात बसों का संचालन किया जा रहा है। माननीय सदस्य, जो जमवारामगढ़ से आते हैं, उन्होंने जिस समस्या के बारे में कहा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमान में जमवारामगढ़ से भानपुर कलां वाया साईवाड़ मार्ग पर लो-फ्लोर बसों का संचालन प्रस्तावित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस मार्ग का सर्वेक्षण करके संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लेने का मैं पूरा प्रयास करुंगा। हम जल्दी इसका सर्वेक्षण करवा लेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से वहां बस चलाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बारामजी।

बाप के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति व केशवनगर पी.एच.सी. हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटन

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं पर्ची के माध्यम से सम्माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो क्षेत्र बाप है, वह जोधपुर से कम से कम 160 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां के लोग अपना ज्यादा अच्छा इलाज कराने के लिये जोधपुर के बजाय बीकानेर जाना पसंद करते हैं क्योंकि एक तरफ बीकानेर लगता है और एक तरफ जैसलमेर लगता है। बीकानेर और जैसलमेर के लोग भी बाप में आते हैं। अब उस सी.एच.सी. की हालत क्या है, जिसका मैं जिक्र आपको कर रहा हूं। उस सी.एच.सी. के अन्दर कुल जो स्वीकृत पद हैं, वे कनिष्ठ विशेषज्ञ के पांच हैं, वे पांचों के पांचों रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी के दो हैं, उनमें से एक रिक्त है। चिकित्सा अधिकारी, दंत का एक है, जो कि रिक्त नहीं है। कहने का मतलब चिकित्सा अधिकारियों के आठ पद हैं, उनमें से एक दंत चिकित्सक सहित, दो चिकित्सक ही वहां पर मौजूद रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस सी.एच.सी. की हालत क्या है। नेशनल हाई-वे उस पर आता है। वहां पर दो बड़े मेले लगते हैं, दो नहीं, तीन। दो बार तो रामदेवरा के मेले में वहां पर पैदल यात्री आते हैं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कभी एक्सीडेंट होते हैं और कभी चलता राहगीर बीमार पड़ जाता है। उसके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। रात्रि के समय तो वहां पर किसी प्रकार का इलाज हो ही नहीं सकता।

यह परिस्थिति है कि इस हास्पिटल की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर हर महीने कोई न कोई प्रदर्शन जरूर होता है। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक तो यह निवेदन है कि आप कम से कम इस बाप क्षेत्र की सी.एच.सी. की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें और यही स्थिति रही तो निश्चित तौर से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, 500 की ओ.पी.डी. वहां पर है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक चिकित्सक 500 की ओ.पी.डी. को किस प्रकार से डील करता होगा और रात्रि के समय में भी किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती होंगी?

(श्री पब्बाराम)

इसी प्रकार से कुल जो 29 पद हैं, उनमें से 15 पद रिक्त बोल रहे हैं और एम.एन.जे.वाई. के तहत लैब टेक्निशियन, क्लिनिकल रिकार्ड सहायक, वार्ड ब्वाय, यह 8 पद हैं और आठों के आठ ही रिक्त हैं।

अब यह सी.एच.सी. खुद बीमार है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस बीमार सी.एच.सी. को कुछ ठीक करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। उनको वहां से 125 किलोमीटर दूर बीकानेर जाना पड़ता है, इधर 160 किलोमीटर जोधपुर आना पड़ता है तो आप इनके दर्द को अवश्य सुनेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं।

इसी प्रकार से हमारी फलौदी की जो सी.एच.सी. है, उसके अन्दर भी रिक्त पदों की भरमार है। वरिष्ठ विशेषज्ञ दो हैं और दो के दो ही पद खाली हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ 7 हैं, उसमें से 2 पद खाली हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 2 हैं और दोनों के दोनों पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी के 8 पद हैं और 6 कार्यरत हैं और 2 रिक्त है। इसी प्रकार से नर्स ग्रेड प्रथम है, उसके 9 पदों में से 5 खाली हैं और यह कुल-मिलाकर परिस्थिति है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन पदों को भरिए और विशेषकर, बाप की सी.एच.सी. की दशा सुधार दीजिए अन्यथा रोजाना के रोजाना धरने प्रदर्शन होते हैं और सरकार की छवि खराब होती है और आखिर जाकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और उनको आश्वासन दिया जाता है और उस आश्वासन पर आश्वासन के नाम पर कुछ नहीं मिलता।

इसी प्रकार से फलौदी के अन्दर एक सिटी डिस्पेंसरी दो साल पहले स्थापित की है। उस सिटी डिस्पेंसरी के लिए अभी तक जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ है। कई बार प्रयास कर लिया गया, उसकी जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ है तो कृपया जमीन अलाटमेंट हो जाए। आपने उसके भवन निर्माण का बजट जारी कर दिया है परन्तु जमीन अलाटमेंट हो जाएगी तो भवन निर्माण भी हो जाएगा और सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। मेरा आपसे निवेदन है विशेषकर, बाप क्षेत्र के लिए कि उन मेलों के अन्दर आने वाले उन धार्मिक यात्रियों के लिए और रोजाना की 400 की जो ओ.पी.डी. है उसको राहत प्रदान करने के लिए, रोजाना के धरने-प्रदर्शनों को अवाइड करने के लिए कृपया इसके अन्दर डाक्टर भेजिए। मात्र एक डाक्टर के सहारे एक सी.एच.सी. चल रही है।

(श्री पब्बाराम)

आठ पद हैं, एक दंत चिकित्सक है जो सिर्फ दांत ही देख सकता है और कोई काम नहीं कर सकता है। आप विशेष तौर से मुझे बताने की कृपा करें कि आप कब तक वहां पर डाक्टर्स लगा देंगे? यह मुझे आश्वासनों की तो हमेशा टोकरी भर कर आपने उठाई है परन्तु कभी भी वहां पर, हम लोग टेल पर बसते हैं और टेल पर नहर का पानी भी नहीं आता है और यही स्थिति हमेशा हमारे सी.एच.सी. की रहती है तो कृपया इसके ऊपर थोड़ा अपना बयान दें और केवल बयान ही न दें, इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ऐसा मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पर्ची के माध्यम से मामला उठाया है मैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में चिकित्सकों के 10 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 4 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं और राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में चिकित्सकों के 26 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 16 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पी.जी. पूर्ण करने के पश्चात् उपलब्ध होने वाले चिकित्सकों से भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 894 तथा चिकित्सा अधिकारी दंत के 113 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के 14 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं और राजकीय चिकित्सालय, फलौदी में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के 50 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 32 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के पदोन्नति के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के उपरांत भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

सीधी भर्ती के पदों में प्रयोगशाला सहायक एवं ए.एन.एम. के पदों को भरने जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष पदों को नियमानुसार कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

और, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र केशव नगर, फलौदी, जोधपुर हेतु नगरपालिका फलौदी, जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7340, दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा भूमि का नि:शुल्क

(श्री कालीचरण सराफ)

आबंटन कर दिया गया है। भवन निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे के सारे डेपुटेशन के माध्यम से चलता है और डेपुटेशन वाला आता नहीं है और यह चार पद जो बता रहे हैं, मात्र एक परमानेंटली है और बाकी डेपुटेशन के माध्यम से आप लगाते हैं और वह कभी आता है और कभी नहीं आता है तो यह परिस्थितियां हैं। आप परमानेंट हमारे वहां पर लगाइए, डेपुटेशन छोड़िए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी स्थानांतरण पर रोक है, जैसे ही स्थानांतरण से रोक हटेगी परमानेंट लगा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करने में विलम्ब से सदस्यों के अधिकारों का हनन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ पुन:, किसी को लगता होगा कि बार-बार मैं यह प्रश्न उठाता हूं लेकिन यह बार-बार प्रश्न उठाना आवश्यक है इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके सामने तीन प्रतिवेदन रखे जाएंगे। एक, माननीय गृह मंत्रीजी रखेंगे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वह किस विभाग में आता है लेकिन इतनी जानकारी है कि अब किसी भी विभाग पर चर्चा नहीं होगी, मुख- बंद पर पारित होगा, एक।

इसलिए उनका जो सूचना के अधिकार का अधिनियम की जो, सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं उसके बारे में भी सदन में अब कोई चर्चा नहीं हो पाएगी।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यह दो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। एक, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का जो केवल वर्ष 2016-17 का होगा और 2017-18 का उसमें शामिल नहीं है।

दूसरा प्रस्तुत कर रही हैं- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का उसमें 2016-17 एवं 2017-18, दोनों का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या-24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं पारण है।

तीन प्रश्न इसमें से उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि दिनांक 26 तारीख को जब कृषि और सहकारिता की बहस हो रही थी, उस समय मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्रीजी ने क्षमा-याचना भी की थी बार-बार और उसके बाद में 27 तारीख को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन आपका आभारी है और राज्य की जनता आपकी आभारी रहेगी कि आपने एक ऐतिहासिक व्यवस्था पिछले सारे रिकार्ड को देखकर एक अंतिम व्यवस्था दी जिसके अंतर्गत सरकार को वह काम करने जरूरी थे।

उस तारीख को, 26, 27, 28, 01, 02, 03, 04 और आज 05 तारीख हो गयी। इस पीरियड में सरकार ने यह दोनों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर इनके प्रतिवेदन न आने को, मंगाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की, क्या पत्र लिखा, किसको फोन किया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय का यह निर्णय आ चुका है और हमको इसको देना है, एक तो सदन को इस बात की जानकारी चाहिए।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा समाचार-पत्रों में छपा, '72 प्रतिवेदन नहीं आने पर उपाध्यक्ष सख्त, अब सरकार मांगेगी माफी' और दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भास्कर के फ्रंट पेज पर छपा- 'शर्मसार' चार बड़े मंत्रियों की इसमें फोटो है कि इन मंत्रियों के डिपार्टमेंट के वह आए नहीं। अब इतना सारा होने के पश्चात्, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के पश्चात् 3 बातों का हनन है।

पहला इसमें माननीय विधायकों के इस अधिकार का हनन है कि सदन के बारे में जो उनको बोलना है, उच्च शिक्षा के बारे में, वह उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जानकारी प्राप्त हो और इस पर वह अपनी बात रख सकें। दूसरा, उपाध्यक्ष जी, आसन की व्यवस्था का हनन है और तीसरा, इस बात का अहम है कि चाहे आसन कोई भी व्यवस्था करे, चाहे विधान सभा कोई व्यवस्था करे, हम तो हमारी मर्जी से चलेंगे और जैसे मन में आएंगे, वैसे रखेंगे और सदन को भी एक तरह से गिरवी रख लिया है इन मंत्रियों ने। मंत्रियों की अगर नहीं चलती है और अफसर मंत्रियों की नहीं मानते हैं तो भी मंत्रियों को रहने का अधिकार नहीं है और सदन की बात अस्वीकार करके इस प्रकार की हठधर्मिता से काम करें तो फिर सदन में हमको रहने का कोई नैतिक अर्थ नहीं निकलता है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस बात की जितनी बड़ी व्यवस्था के बाद इतनी बड़ी गलती सरकार कर रही है, उसके बारे में सदन को जानकारी दी जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी का, लेकिन जब विभाग का मंत्री उपस्थित हो और विभाग का मंत्री स्वयं प्रस्तुत करने वाला हो, उस समय संसदीय कार्य मंत्री को आवश्यकता नहीं होती नियमों के हिसाब से। संसदीय कार्य मंत्री प्रक्रियाओं के बारे में और ज्ञान-विज्ञान के बारे में वह तो इस तरह जानते होंगे। मंत्री प्रजेंट है और मंत्री बताएगा कि उन्होंने क्या कार्यवाही की उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद में। आप क्यों बताएंगे?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने भी तो इनको पुकारा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने किसको पुकारा, यह मेरी और उनकी बात है। हर बात में खड़े होकर बोलना जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसन की उस व्यवस्था के बारे में, जो 27.02.2018 को आसन ने दी थी, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा कि एक बार फिर पुनरावृत्ति हुई है। आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, दोनों के वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017, 2017-2018 और एक माननीय गृह मंत्रीजी के द्वारा राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 रखे जा रहे हैं, यह विलम्ब से हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी थी, आपकी व्यवस्था 27 तारीख को हुई थी। मैंने 28 तारीख को ही राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर यह लिखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, आपरेटिंग पैरा पढ़कर सुना दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखा था कि आसन ने व्यवस्था दी है कि मुख्य सचिव संलग्न सूची का अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न करने के लिये कौन-कौन अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव जिम्मेवार हैं, उन सभी से लिखित में आसन के प्रति क्षमा-याचना प्राप्त कर अपने साथ प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य मंत्री को साथ में लाएं और यह सारी बातें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में 12 मार्च को 11.00 बजे यह सब चीजें, अब तक आपने जिन 72 वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के बारे में सूचित किया था, आपने ही यह कहा था कि 3.1.2018 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके माध्यम से यह सारी की सारी सूचनाएं 325 के अन्दर 5.2.2018 से पहले आनी चाहिए। मैं इसको स्वीकार करता हूं। आपकी आसन की व्यवस्था की अवहेलना करना सरकार का कतई मन्तव्य नहीं है। हम आसन का आदर करते हैं। आपने किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल कर ली कि हम सारी विधान सभा को गिरवी रख दें, हम यह करें। हम लोकतांत्रिक आस्थाओं में पूरी आस्था रखने के साथ-साथ नियमों के अनुसार, पूरे कार्य को करना, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। उसी के अनुसार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो तारीख फर्माई है 12 मार्च को, उस 12 मार्च को 11.00 बजे मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। सारे स्पष्टीकरण के साथ में उपस्थित होंगे और उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना प्रारम्भ हो गया है। मुख्य सचिव को मेरे लिखे पत्र के पश्चात् और मैं सारी चीजों से अवगत करा दूंगा। अगर इससे पहले आप आदेश फर्माएंगे तो पहले हाजिर हो जाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं पहले क्षमा-याचना कर चुका हूं, आज यह विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, मैं दोनों मंत्रीगणों को भी निवेदन करूंगा कि इसके जरिये आज ही स्पष्टीकरण मांगेंगे कि यह विलम्ब क्यों हुआ, जबकि उनको परिपत्र के द्वारा संसदीय कार्य विभाग ने पहले से सूचित कर दिया था कि समय पर यह प्रतिवेदन आने चाहिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बात अलग हो गयी। मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपके आदेश के बाद में पत्र भेज दिया, चला गया। मैंने प्रश्न यह उठाया है कि इसके बाद में आज जब बहस हो रही है तो जिम्मेदार मंत्रियों ने इसके लिये क्या कार्यवाही की? यह मंगाये क्यों नहीं, इसका कौन जवाब देगा? इसके लिये या तो मंत्री दोषी हैं, या जिसको उन्होंने लिखा वह दोषी है। कोई दोषी नहीं है और केवल आपका पत्राचार-पाठ्यक्रम चलेगा, वह जरूरी नहीं है। इसके लिये सदन को बताना पड़ेगा इन मंत्रियों को, कि यह काम इन्होंने गलत क्यों किया? इनकी रेस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है? इस सदन के प्रति अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? इस सदन के प्रति मंत्री जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आर्टिकल 208 के तहत संविधान सभा के संचालन के नियम बने हैं, जिम्मेदारी मंत्रीगण की है, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से हम काम कर रहे हैं और मैंने आपके सामने खड़े होकर जो अनुनय किया है, वह कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में किया है और मैं आसन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो विलम्ब हुआ है, संबंधित विभाग इसके बारे में संबंधित लोगों से स्पष्टीकरण भी लेंगे और 12 तारीख को जब आपके सामने वह प्रस्तुत होंगे तब उनको भी लेकर आएंगे कि किसकी गलती से क्यों समय पर प्रतिवेदन नहीं आये। इसके उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उस पर कार्यवाही करने के लिये मैं आसन से निवेदन करूंगा, निश्चित तौर पर करें।

व्यवस्था

प्रतिवेदन नियत समय पर सदन में उपस्थित होने चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि एक बार सांगानेर से आने वाले सम्मानित सदस्य ने जिस व्यवस्था का प्रश्न उठाया है We are now in a corrective mode. जो पीछे कुछ गलतियां हो गयीं या कुछ In corrective mode, naturally now in the due course you will get all these prativedans. मैं टाइम स्केल और टाइम फ्रेम को वापस पीछे तो ले जा नहीं सकता, इस सदन के सैशन के एडजोर्नमेंट से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें I'll be very specific. आप यह सुनिश्चित कर लें कि जितने भी प्रतिवेदन आने थे, वे कम से कम इस सैशन के दौरान आ जाएं। लेट आ रहे हैं, इस पर आप कोग्नीजेंस लेंगे। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वह उस

(श्री उपाध्यक्ष)

मीटिंग में तय हो जाएगा, But in case even after that, if there are certain documents which were supposed to be placed on the Floor of the House, have not been placed then we will take cognizance accordingly. That will be clear I think so, that will settle your queries.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद में मंत्रीगण यहां बैठे हैं और वह कार्यवाही करके नहीं आये। यह कैसे होगा, यह दे देंगे डाकूमेंट्स लाकर दो दिन में, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सारी व्यवस्था है, इससे मैं आहत हूं। हम यहां सदन में आकर बैठते हैं। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यहां पर भत्ता लेते हैं और हम यहां पर यह देखने के लिये बैठे हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करके आज के दिन मैं बाहर जाना चाहता हूं ताकि यह प्रतीक के रूप में रजिस्टर हो, इस बात के लिये कि हम यहां जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और आसन की व्यवस्था को इस प्रकार मखौल नहीं बनाएं। इसलिये मैं आज का भत्ता भी नहीं लूंगा और मैं आज बोलने के लिये बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन आज मैं मन से, अंतरात्मा से आहत हूं कि इस प्रकार का लगातार करते रहना उचित नहीं है। इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करते हुए आज के दिन मैं पश्चाताप करना चाहता हूं कि हमारी सरकार खुद की है और हमारे खुद हैं, वह इस प्रकार का व्यवहार लगातार करते रहें, यह उचित नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो अध्यक्षीय व्यवस्था की अवहेलना हो गयी। यह तो एक तरह से आसन का अपमान करके सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य जा रहे हैं। आपने व्यवस्था दे दी और व्यवस्था पर सरकार गम्भीर है और सरकार की तरफ से प्रत्युत्तर दे दिया। मैंने आपसे यह भी निवेदन कर दिया कि यह तीनों जो प्रतिवेदन हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण लेकर मैं 12 मार्च को आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह तो पिछले वालों का था, आज का क्या है? आज का क्या जवाब है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आसन का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन का अपमान नहीं है, आसन का अपमान आप कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): संसदीय प्रक्रियाओं का अपने आपको ज्ञाता समझते हो। यह आसन का अपमान है। यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आसन की व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन, यह पहली बार मैं देख रहा हूं। आसन की व्यवस्था के खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आसन के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ बहिर्गमन कर रहा हूं। आपने आसन का अपमान किया, इसलिये बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम आसन के सम्मान के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कुछ भी नहीं कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने 12 मार्च को राजस्थान के मुख्य सचिव सहित, उन सारे विभागों को, जो आपने सूची साथ में दी है, उनको ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसके लिये मैंने धन्यवाद दे दिया आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। यह आसन का अपमान है। यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह अपनी-अपनी खाल बचाने का प्रयत्न मत करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह कौनसी परम्परा डाल रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपनी खाल बचाने का प्रयत्न आसन पर मत डालो। गलती आपकी है और आसन पर डाल रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बहिर्गमन करके आसन का अपमान करके नहीं जाओगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आसन का सम्मान कर रहा हूं, मैं राजस्थान की जनता का सम्मान कर रहा हूं और सरकार द्वारा आसन की अवहेलना की गयी है, इसलिये बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, अगर मंत्री महोदय इसके ऊपर जवाब दे देंगे तो इनकी भी बात रह जाएगी, आसन की भी रह जाएगी और संसदीय कार्य मंत्री की भी रह जाएगी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप तो आग में घी डालने का काम करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आपको स्मरण रहे कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संबंध में एक प्रतिवेदन पहले भी प्रस्तुत किया गया था। उस वक्त सम्माननीय मंत्री महोदय ने यह बात कह दी थी कि बाकी, जो भी रह गये हैं, उनके संबंध में हम कार्यवाही कर रहे हैं और जब आसन की तरफ से स्पष्ट निर्देश आ जाते हैं।

अब यह बात तो बिलकुल सही है कि जो समय पर नहीं आया, वह समय पर नहीं आया। कम से कम आइन्दा समय पर आ जाए। हमारा अब करेक्टिव प्रोसीजर यह है कि आइन्दा समय पर आ जाए। इसलिए आइन्दा समय पर तब आएंगे, जो पहले समय पर नहीं आये, वह आ जाएं और उसके बाद बजट सैशन आयेगा तब सारे प्रतिवेदन उसमें आ जाएं। हम इस पर कठोरता से कार्यवाही करेंगे, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसमें आसन की अवमानना का सवाल नहीं है, सदन की अवमानना का सवाल है। It is the right of this House to seek information. यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कांस्टीट्यूशनल लॉ का इनबिल्ट सेलिएन्ट करेक्टर है। इसीलिए कई बार हम यह मानते हैं कि जब हमारी डिबेट्स होती है तो डिबेट्स हो किस विषय पर रही है और हम बहस कुछ और कर रहे हैं क्योंकि सूचना और जानकारी हमारे पास नहीं है। सूचना और जानकारी प्राप्त करने का यह एक माध्यम है। यह एक ऐसा डाकूमेंट है कि जो सदन के पटल पर झुठलाया नहीं जा सकता। अगर उस डाकूमेंट के आधार पर कोई माननीय सदस्य अपनी बात कह रहा है, कुछ वाद-विवाद के अन्दर अगर अपनी बात रख रहा है तो वहां कोई भी माननीय मंत्री यह नहीं कह सकता कि यह डाकूमेंट है, बाकी सारे डाकूमेंट्स हैं, उन पर कहीं न कहीं विवाद हो सकता है। इस डाकूमेंट पर विवाद नहीं हो सकता क्योंकि पटल पर रखा हुआ डाकूमेंट है और उसकी सत्यता अपने आप में प्रमाणित है। इसलिए मैं बहुत कठोर शब्दों में आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, Parliamentary Affairs Minister, because you are the one who will guide this. Let us see if we can correct

(श्री उपाध्यक्ष)

this thing and henceforth, it will not be allowed and we will try to make rules so strict that those who would be careless enough to do it, will be put to tasks through Lawful means even that could be ensured. The Hon'ble Speaker has lot of other powers which are not declared in print but the Hon'ble Speaker can deliberate on to it and this deliberation will take place on 12th. I assure the entire House that your privilege and your sanctity will be protected to that extent. Thank you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिये हैं, आपने जो व्यवस्था दी, उसका उद्योग मंत्रीजी से हिन्दी में अनुवाद करवा लूंगा और उसकी पालना करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इससे और टेंशन बढ़ता उसके अन्दर। इनसे कहिए कि शांत होकर बैठ जाएं। क्षमा मांगें ये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके अंग्रेजी समझ में आयी नहीं इसलिए रिपीट कर रहे हैं पहले वाला बयान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं उद्योग मंत्रीजी से इसका अनुवाद करवा लूंगा, आपने जो अंग्रेजी में व्यवस्था दी है। उसकी पालना सुनिश्चित करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब विलम्ब हो गया और आपने उस पर सख्त रवैया अपना कर निर्देश दे दिये तो विलम्ब से जो आ रहे हैं वह आएंगे तो सही सदन में। जब-जब भी आएं सदन में, विलम्ब से पेश करें तो उस समय ही यदि ये प्रश्न उठाना शुरू कर दें तो यह तो मैं सोचता हूं ठीक बात नहीं है। एक बार आपने निर्देश दे दिये, जो पीछे रह गये, वह आएंगे तो सही सदन में। पेश तो करने ही पड़ेंगे और जब भी पेश करें तब ही ये व्यवधान करें। यह तो ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का प्रतिवेदन 2016-17

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं:-

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का प्रतिवेदन 2016-17

1- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रतिवेदन 2016-17 एवं 2017-18

2- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-37 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018.

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र. सं. 255 से 260)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2017-18 के निम्नांकित छह प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या-2.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 255वां प्रतिवेदन।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या-3.8 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 256वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या-3.3 एवं 3.11 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 257वां प्रतिवेदन।

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या-3.10 एवं 3.13 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 258वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या-3.12 एवं 3.19 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 259वां प्रतिवेदन।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट प्रतिवेदन संख्या-2 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या-7.1 से 7.7.15 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 260वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारीलालजी सिंघल।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (क्र. सं. 32 से 36)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2017-18 के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, सूचना एवं जन सम्पर्क, मंत्रीमण्डल सचिवालय, उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि विपणन, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 32वां प्रतिवेदन;

2. गृह, नगरीय विकास एवं आवासन, आबकारी, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, सामान्य प्रशासन, उपनिवेशन, कृषि, परिवहन, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 33वां प्रतिवेदन;

3. उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि विपणन, कार्मिक, खाद्य एवं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

नागरिक आपूर्ति, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, प्रशासनिक सुधार, परिवहन, भू-जल, महिला एवं बाल विकास, युवा मामले एवं खेल, वन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, सिंचित क्षेत्र एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 34वां प्रतिवेदन;

4. अल्पसंख्यक मामलात, आयुर्वेद, ऊर्जा, कृषि, कृषि विपणन, कारागार, ग्रामीण विकास रोजगार गारण्टी योजना, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जन अभाव अभियोग निराकरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, तकनीकी शिक्षा (कृषि), नागरिक उड्डयन, पंचायती राज, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजकीय उपक्रम, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, श्रम एवं रोजगार एवं सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 35वां प्रतिवेदन; एवं

5. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, देवस्थान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वित्त, आबकारी, कारागार, निर्वाचन एवं भू-जल विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 36वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री विवेक धाकड़ (अनुपस्थित), श्री भागीरथ चौधरी (अनुपस्थित), श्री नवनीत लाल।

याचिका

घाटोल की पंचायत समितियों के ग्रामों में सिंचाई की सुविधा

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र घाटोल, जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समितियों के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

आहौर की पंचायत समिति जालौर के अडवाड़ा से नांगणी गांव तक सड़क निर्माण

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र आहौर की पंचायत समिति जालौर के अडवाड़ा से नांगणी गांव को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 (द्वितीय अवस्था), अनुदान की मांग पर विचार। श्री वासुदेव देवनानी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अब आप विराजो। that is absolute dereliction of duty.

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 286,59,19,42,000/- (दो सौ छियासी अरब उनसठ करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: Your 3 Ministers will participate in this issue. We will have 3 Ministers....

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह आज नहीं हैं। उन्होंने मुझे दिया है। उनका जवाब मैं ही दूंगा, कला एवं संस्कृति का भी।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि 50 से ज्यादा माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। अगर दस मिनट की समय सीमा का निर्धारण हो जाए, क्योंकि आज बाकी मांगों का पारण भी है, इसलिये दस मिनट में स्वत: ही आप अनुशासित होकर विराज जाएं अन्यथा दस मिनट बाद में वह अंकित नहीं होगा This has to be very followed strictly.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फर्स्ट वाले के लिये तो 15-20 मिनट हों। वह भी बोलेंगे, यह भी बोलेंगे। (व्यवधान) अब आपको घबराहट क्यों हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले वाले के सुर्खाब के पर लगे हुए हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्षजी से निवेदन कर रहा हूं। आसन का आदेश होगा, वह शिरोधार्य होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट का समय निर्धारित है और दस मिनट के बाद में आप अपना वाक्य पूरा कमप्लीट कर लें, तब तक आपको अधिशेष समय देंगे। पूरा वाक्य कमप्लीट नहीं किया तो फिर उस व्याकरण की त्रुटि के साथ ही आपका अंकन खतम हो जायेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा।

मांग संख्या 24 पर विचार

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर वाद-विवाद है, यह समाज और राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के माध्यम से ही हम संस्कृति के भी दर्शन करते हैं और उसमें कला शब्द भी साथ में जुड़ा हुआ है। विद्वान कहते हैं कि शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा ऐसा एलीमेंट है जो केवल और केवल व्यक्ति को प्राप्त होता है लेकिन देता समाज है। इतिहास में भी और आज भी शिक्षा, या तो सरकार व्यवस्था करती है या समाज करता है लेकिन मिलता व्यक्ति को है। परिवार के कोई भी व्यक्ति उसका बंटवारा नहीं कर सकते। इसकारण से हमारे देश में आदिकाल से ही शिक्षा का महत्व रहा और यही कारण था कि हम जगद्गुरु कहलाये।

18वीं शताब्दी में भी एक अंग्रेजी डाकूमेंट से यह प्रकट होता है कि 1883-84 में एक कमेटी बनी। उतनी शिक्षण संस्थाएं आजाद भारत के 1990 तक भी नहीं थीं। प्रत्येक गांव में चट पाठशाला होती थी। 1990 के बाद में जब राजस्थान में आठ साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसमें शिक्षा को नयी दिशा मिली और जब अटलजी प्रधान मंत्री बने तो सर्वशिक्षा के माध्यम से इस देश में एक-एक किलोमीटर पर शिक्षण संस्थाएं बनीं लेकिन पहले जो हमारी चट पाठशालाएं थीं, वे संगठित और व्यवस्थित रूप में नहीं थीं लेकिन हर जगह हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था थी। इस कारण से हम

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जगद्गुरु कहलाये और शिक्षा का उच्च स्थान था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहां पंचपति शिक्षा थी जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कला शिक्षा, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और भाषा शिक्षा, जिसको हम उस समय देववाणी कहते थे। यह पंचपति शिक्षा थी।

अंग्रेजों के आने के बाद में, मैकाले के आने के बाद में यह पंचपदी शिक्षा नष्ट होने के कारण से संस्कारयुक्त शिक्षा, शिक्षा में संस्कार होना चाहिए और संस्कृति का दिग्दर्शन होना चाहिए, धीरे-धीरे करके नष्ट होता चला और उसके कारण से आज देश में दुर्व्यसन आते हैं, या समाज में जो विकृतियां आयी हैं उनका कारण ही यह है कि हमने शिक्षा से संस्कारों को विमुख कर दिया। कुछ 76 के बाद में एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष संविधान की रचना करने के बाद और ज्यादा बंटाढार कर दिया। ऐसी स्थिति शिक्षा की हो गयी।

जब हम राजस्थान की शिक्षा का विचार करते हैं तो पुरुष शिक्षा में राजस्थान का 27वां स्थान है, टोटल शिक्षा में 33वां स्थान है। राज्य तो कम हैं, केन्द्र शासित प्रदेश मिलाकर 35 इकाई हैं, 33वां स्थान है। लेकिन जब हम महिला शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा स्थान 35वां है, आखिरी स्थान है। हालांकि बीच में हम महिला शिक्षा में 27वें स्थान पर आ गये थे, दुर्भाग्य था शासन बदल गया, इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन आज की स्थिति भी मैं बताऊं, आपके सामने निवेदन करूं, 50 परसेंट महिला शिक्षा में केवल 16 जिले आते हैं। अभी भी हमारे 17 जिले ऐसे हैं जो 50 परसेंट साक्षरता महिला शिक्षा में नहीं है।

ऐसे ही एक इतिहास की घटना है, 2002 में इस सदन में भी शायद उस समय प्रशंसा की गयी होगी, मैं तो सदस्य नहीं था लेकिन शिक्षक था, कांग्रेस शासन के द्वारा एक जश्न मनाया गया, डूंगरपुर को 100 परसेंट साक्षर बना दिया गया। सारे विश्व में एक ही चर्चा रही कि राजस्थान का डूंगरपुर शिक्षा में 100 परसेंट पारंगत हो गया लेकिन अभी 2011 की जो रिपोर्ट है उसमें हम डूंगरपुर को पीछे से 13वें स्थान पर पाते हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं क्योंकि ज्यादातर, 52 साल तक शासन कांग्रेस का रहा। इस कारण से शिक्षा के बारे में कभी ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। इस राज्य का सौभाग्य यह रहा कि बीच-बीच में सरकारें बदलती रहीं। जैसे 1977 में सरकार

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बदली तो उस समय शिक्षा का अन-बैलेंस था, कांग्रेस के लोग जिसको चाहते थे शिक्षण संस्थाएं खुल जाती थीं, बड़े-बड़े गांव रह जाते थे। जब माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बने, माननीय भंवर लाल जी शर्मा जब बने, उन्होंने एक ही आदेश में यह निकाला कि हम इस राजस्थान में संतुलित शिक्षा का विकास चाहते हैं, उन्होंने एक ही आदेश निकाल दिया कि 2017 में जिसकी आबादी तीन हजार है, उन सबमें सैकण्डरी स्कूल खोल दिया जाय, खोल दिया गया। इस कारण से वहां से हमारा थोड़ा शिक्षा का बैलेंस शुरू होता है।

दोबारा जब वो 1990-91 में शासन में आये तब उन्होंने एक साथ फिर शिक्षा को चरणबद्ध विकास देने का प्रयास किया। उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा में एक ही आदेश से 4600 मिडल स्कूल खोलकर के यह साबित किया कि प्रत्येक पंचायत को आठवीं तक की शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। यह ऐतिहासिक कार्य किया माननीय भैरोंसिंह जी ने, आपके माध्यम से आज मैं उनको नमन करता हूं। इतना ही नहीं किया, उन्होंने उसी कार्यकाल में, 1993 से लेकर 1998 के कार्यकाल में उन्होंने प्रत्येक विकास खण्ड में एक सैकण्डरी स्कूल, एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और उसमें भी देखिये, जब भैरोंसिंह जी 1977 में मुख्य मंत्री थे तो जितने विकास खण्ड थे उनमें ट्राइबल के नाम पर, ट्राइबल डिपार्टमेंट लगभग उस समय बना था, तो तीन विकास खण्ड बांसवाड़ा में ज्यादा लेकर आये इस कारण से सबसे ज्यादा सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें खुलीं तो वो बांसवाड़ा जिले में खुलीं। पांच विधायक थे लेकिन आठ पंचायत समिति होने के कारण से ज्यादा खुलीं और यही कारण है कि आज बांसवाड़ा शिक्षा में एक सम्मानजनक स्थिति में है।

उस समय इतना ही नहीं किया, भैरोंसिंह जी ने बालिका शिक्षा के लिए एक ऐसा काम किया जिसको आज हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शान से बालिकाओं को पुरस्कृत करते हैं, जिसको गार्गी पुरस्कार कहते हैं। यह उस समय स्थापित हुआ। बालिका फाउंडेशन की स्थापना की, एक करोड़ रुपये शासन के बजट से दिये गये और बाद में जो निजी शिक्षण संस्थाओं की एफ.डी. होती है, उसके ब्याज से वो चलता है और आज इतना बड़ा परिवर्तन, उसके कारण से 1 लाख 26 हजार बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एक वर्ष में दिया गया। इतना ही नहीं, 1993 से 1998 में केवल प्रारम्भिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा में भी महिला शिक्षा का एक स्वर्ण काल था जब केवल 10 स्थानों

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पर महिला शिक्षा की कालेज थीं, उस एक कार्यकाल में 22 कालेज और आखिरी वर्ष में 4 कालेज, ऐसे 26 गर्ल्स कालेज, जिसमें से दो जिले बचे थे, केवल हनुमानगढ़ और सीकर, वहां प्राइवेट कालेज थे, मान्यता प्राप्त थे, एडेड थे। बाकी सब में वो महिला शिक्षा की कालेज खोलकर गये। यह इस प्रकार का स्वर्ण युग कहलाता है।

उसका एक प्रमाण भी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं। जब हम 1951 में आये थे तो हमारी राजस्थान की शिक्षा 8.95 थी लेकिन महिला शिक्षा 3 परसेंट ही थी। उसके बाद में 52 वर्ष तक हम कांग्रेस को ढोते रहे, तो कभी भी 10 परसेंट ग्रोथ रेट नहीं हुई। लेकिन 1991 से 2001 तक, 10 साल का कार्यकाल था उसमें दो साल तक माननीय गहलोत साहब ने शासन किया, मुख्य मंत्री रहे लेकिन उसके पहले माननीय भैरोंसिंह जी रहे, तो उस कार्यकाल की जो ग्रोथ रेट है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। 21.85 तो जो टोटल शिक्षा थी उसमें वृद्धि हुई, पहले तीन परसेंट, चार परसेंट, आठ परसेंट, मैक्सिमम आठ परसेंट थी लेकिन पहली बार 10 साल में जो विकास दर हुई वो 21.85 परसेंट और पुरुष शिक्षा में 20.71 लेकिन महिला शिक्षा में जिसमें महिला कालेज भी खोलना था, हर पंचायत में मिडल स्कूल खोली, इस कारण से मान लीजिए 23.41 परसेंट। इंडिया में किसी भी स्टेट की ग्रोथ रेट इतनी नहीं इस महिला शिक्षा की 10 वर्षो की 23.41 हमने अचीव की, मैं इसको बी.जे.पी. शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उस समय हमारी महिला शिक्षा का स्थान 27वां हो गया था, वापस 35वां हो गया। यह एक दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन हम महिला शिक्षा में इतना कुछ कर पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राथमिक का सवाल है, एक बार इस सदन में भी आरोप लगा, बाहर भी आरोप लगे कि राजीव गांधी जी के नाम पर हमने जो स्कूलें खोली थीं, बी.जे.पी. शासन ने उनको नष्ट कर दिया। मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार को अनुदान लेने के लिए, सर्व शिक्षा का अनुदान देने के लिए लिखकर दिया, हम जितनी पाठशालाएं राजीव गांधी पाठशालाएं हैं उनको सरकारी प्राथमिक विद्यालय घोषित करते हैं, हमें एड दो। झोली फैलाकर गये तब राजीव गांधी का नाम हटकर के सरकारी विद्यालय बने। यह आरोप का उत्तर दे रहा हूं कि इस प्रकार का आरोप लगा। कोई भी प्रधान मंत्री था, हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है लेकिन इस प्रकार का आरोप लगा।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से आज प्राथमिक शिक्षा में अभी भी आलोचना की जाती है कि हमने स्कूलें बंद कर दीं लेकिन 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, 1 से 5, इस प्रकार का आप फाइव सैक्टर माडल कह दीजिए, इस प्रकार की स्थिति है।

मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। इस कारण से यह जो स्थिति है, इसके कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि गांव में प्राइमरी स्कूल लगती ही नहीं थी। 1 से 12 तक जब विद्यालय हो गये तो प्राइमरी स्कूल को भी टीचर मिल गया। जो व्याख्याता है वो दसवीं को पढ़ाने लग गया और सैकिण्ड ग्रेड वाला प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने लग गया। इस कारण से आज जो 12 लाख नामांकन बढ़ा है उसका एक मात्र कारण है कि यह सिस्टम हमने लागू किया। मैं यह नहीं कहता कि यह परफैक्टली हो गया। अभी पद बहुत खाली हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, मैंने तो शुरू ही किया है, उसमें चार हैं, संस्कृत शिक्षा भी है। चलो, मैं छोटा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप लिखित में दे दें न। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): साहब, थोड़ा सा, पहली बार बोल रहा हूं। थोड़ी सी दया दिखाइये, थोड़ी सी दया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह हमारे पड़ौसी नहीं हैं शाहपुरा के ही हैं, यह गलतफहमी भी आप दूर कर लो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं छोटा कर देता हूं। बिलकुल छोटी-छोटी बातें रखूंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम एक घंटा तो दें। पहली बार शिक्षा के मामले में कोई शिक्षाविद् अपनी बात रख रहा है पहले इसलिए इनको कम से कम 60 मिनट तो...

श्री उपाध्यक्ष: आप अगर सब इस बात को तय कर लें तो आखिरी वक्ता के बाद में फिर हम इनको एक घंटा दे देते हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं शोर्ट करूंगा। निश्चित तोर पर आसन का पालन करूंगा।

इतना ही नहीं हमने केवल विद्यालयों को ही व्यवस्थित नहीं किया, हमने रिजल्ट को भी व्यवस्थित किया है। 2015 में हमारा सैकण्डरी स्कूल का

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

73 परसेंट परिणाम था और निजी स्कूल का 82 था लेकिन हम आगे बढ़े, अभी 2017 का है उसमें 75.66, मतलब 75 परसेंट से ऊपर निकल गये जबकि प्राइवेट सैक्टर का जो रिजल्ट है वो 82 परसेंट ही है। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, हम 80 परसेंट 88 परसेंट पर चले गये और उसमें भी 91 परसेंट चले गये सीनियर हायर सैकण्डरी कला में तो जहां प्राइवेट सैक्टर केवल 89 पर रह गया, हम उससे भी आगे निकल गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को, दोनों को ही धन्यवाद दूंगा क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं।

इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में कई परिवर्तन हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी बैलेंस के हिसाब से।

बैलेंस इस रूप में कि हमारे यहां जो उच्च शिक्षा में कालेजों की स्थिति है जनसंख्या पर, मैं पूरे सदन को धन्यवाद दूंगा की इंडिया में उच्च शिक्षा में सबसे आगे हम हैं, औसत के रूप में। सबसे आगे हैं और उसमें भी सीकर और झुंझुनूं वालों को तो और दूंगा, 12000 पर ही एक कालेज है झुंझुनूं में, 14 हजार पर सीकर में है, लेकिन संभागों की जब बात करते हैं तो अजमेर संभाग 49 हजार पर है, बीकानेर 28 हजार पर है, इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर का बहुत बड़ा योगदान है प्राइवेट सैक्टर का। जयपुर का 21 हजार ही है और जोधपुर, जहां 4-4 मुख्य मंत्री रहे हैं सर, वहां 65900 है अभी भी, लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी...दूंगा कि अभी उन्होंने ...(व्यवधान) 8-10 कालेज खोल दिए हैं 2 साल में जोधपुर में। पहले के मुख्य मंत्रियों ने नहीं खोले। (व्यवधान) अब कई बार हो जाता है लगातार बोलने के दौरान।

कोटा संभाग में भी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, 71 हजार पर है। भरतपुर में 40 हजार पर है। मेरा निवेदन है, 62 कालेज तो हमने खोल दिए। 4-5 साल में 62 कालेज खोले हैं। 224 में से 62 कालेज खोलना अपने आप में रिकार्ड है। वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। इस कारण से जो हमारा 2008 में 78 हजार औसत था उच्च शिक्षा का, उसको आज आप 36 हजार पर ले आए, बिल्कुल आधे से भी नीचे ले आए। मैं तो कहूंगा कि झुंझुनूं और सीकर ने तो हमारा जो वर्ल्ड का रिकार्ड है उच्च शिक्षा का, उसको भी तोड़ दिया। वर्ल्ड रिकार्ड से भी आगे निकल गये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सुझाव दे देता हूं मैं आपको, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। एक तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां 2 विकास खण्ड हैं- पावटा और विराटनगर। दोनों में ही सरकारी कालेज नहीं हैं। शिक्षा मंत्रीजी यहां हैं। मेरे यहां ITI भी नहीं है। दोनों जगह ही ITI नहीं हैं। इसी प्रकार से मेरे यहां 4 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हैं लेकिन एक भी कालेज नहीं है। कालेज के लिए हमने जमीन भी रिजर्व की हुई है विराटनगर में आपके टाइम से ही। इसी प्रकार से संस्कृत के ऐसे 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है। उनको अगर प्रवेशिका वहां खोल दिया जाए...क्योंकि पिछले 15 साल में तो कोई प्रवेशिका स्कूल खुला नहीं, कोई वरिष्ठ उपाध्याय खुला नहीं, संस्कृत की जो दुर्गति पिछले 10-15 साल में हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई, वर्ना हम सम्मान देकर संस्कृत को विकसित करते थे, जिसमें हमारा आंतेला, बड़नगर, जयसिंहपुरा, खेड़ा और चेचावाला, 35 वर्ष से एक ही कालेज है चिंपा में, जिसमें कृषि संकाय 35 वर्ष से चल रहा है।

राजस्थान में 10-12 कालेज खुल गए नए। वहां कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। केवल प्रिंसिपल का पद देना है। 11 टीचर हैं, 11 सब्जेक्ट हैं वहां, अगर प्रिंसिपल का पद देकर के कालेज की शुरुआत कर दी जाए तो ICR का बजट भी मिल सकता है और पीजी कालेज भी हो सकता है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कोटा और नौगांवा में खोला है, तो जयपुर जिले में भी खोल दें, क्या दिक्कत है? ऐसे ही मेरे यहां 335 पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षा में, उनको भरा जाए। एक हैडमास्टर के पदों की भी मिडिल स्कूलों में संख्या तो बढ़ी है। इसी प्रकार से विराटनगर क्षेत्र में विवेकानंद विद्यालय नहीं है एक भी। वह भी खोला जाए।

सरकारी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है, उसमें या तो नरेगा से या सर्व शिक्षा से बनाई जाए। इसी प्रकार से एक विशेष निवेदन करूंगा कि RMSA से पैसा आ रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और इस कारण से निर्माण को PWD को दिया जाए और शिक्षा मंत्री को उसका नोडल बनाया जाए, क्योंकि अभी अधिकारी नोडल हैं उसके। इसी प्रकार से मेरा एक यह भी सुझाव है। निजी विश्वविद्यालयों और कालेजों की मानिटरिंग के लिए कंट्रोलिंग की यहां घोषणा हुई है 2 साल पहले, अभी वह कमेटी बनी नहीं है। इस कारण से मैं इतना ही आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंह जी।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24- कला, शिक्षा, संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि आपने समय का राइडर लगाया है, मैं उसका पालन करूंगा और माननीय भिण्डा जी ने जिन बातों को बोल दिया, उन्हें रिपीट नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद में प्रथम प्रधान मंत्री को जिस प्रकार का औद्योगीकरण का एक जुनून था, देश के पहले बजट में ही vernacular education के बजट को कम कर दिया गया। शायद दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि शिक्षा के बजट को कम कर दिया जाए। यह पहला उदाहरण इस देश में देखने को मिला।

आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का विचार एक गरीब को गरीब रखने का, एक अमीर अमीर चलता रहे, उस खाई को नहीं पाटने का उनका जो विचार था और जिस प्रकार की सफेद चमड़ी का जो जुनून था, वह इस देश में चलता रहा और उसके बाद जिस प्रकार के हालात...राजस्थान के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पिछले 5 साल में जो शिक्षा के हालात थे, उसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सुधार किए हैं। उच्च शिक्षा को जब हम देखते हैं तो उसके अन्दर नए कालेज खोलकर के एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो हमने बी.एड. में शुरू किया है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। Higher education में भी मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि हमारी higher education में भी technical education और normal education अगर अलग-अलग कर दी जाएं तो हमारे बच्चों का जो बहुत समय खराब होता है, वह नहीं हो।

मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं, इसको नोट करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हम इसको पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देखते? मैं कांग्रेस के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा देश की मूल बुनियाद है। इस पर अगर हम अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर विचार करेंगे तो आप और हम यह सोचने को मजबूर होंगे कि किस प्रकार से जो हालात पिछले 5 साल में थे, उनमें किस प्रकार का सुधार हुआ है और आज जिन सुधारों की आवश्यकता है, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, मैं उसका भी निवेदन करूंगा।

(श्री मानसिंह किनसरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने जिस प्रकार से 44 हजार 135 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा पर दिया है, वह सरकार की सहृदयता, शिक्षा के प्रति उसकी जवाबदेही को प्रदर्शित करता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से बच्चों के लिए हमारे स्कूलों में दूध की व्यवस्था की जो बात कही है, एक गरीब के बच्चे को पौष्टिक आहार देकर स्कूल के प्रति जो भाव दिखाया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दूध की जो व्यवस्था की है, वह बहुत अच्छा कदम है।

इसी के साथ-साथ सरकार ने जिस प्रकार से हमारे 17 उपखण्डों में महाविद्यालय खोले हैं और करीब 500 मरदसों का चयन करके आदर्श मदरसा बनाने की जो बात कही है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर उस वर्ग को भी इस प्रकार से ट्रेनिंग देने का काम सरकार के जो मन में है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े और वह केवल दीनी तालीम नहीं लेकर, दुनिया की तालीम लेवे और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ें, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देने का काम करूंगा।

इसी के साथ-साथ मैं आगामी वर्ष में हमारे महाविद्यालयों में वाइ-फाई की सुविधा है, सरकार ने जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं कि 77 हजार जो नई नौकरियां हैं, वे भी हमारे युवाओं को इस शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती लाने का काम करेंगी और शिक्षा के इस बीड़े को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर कुछ सुझाव देना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो primary education है, उसमें पिछले 5 साल में कांग्रेस की जिस प्रकार से फेल नहीं करने की व्यवस्था थी, उसके कारण जो नुकसान हो रहा था, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे primary स्कूलों में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी हो गई है। इस पर आप विचार करें, क्योंकि अगर स्टाफ की कमी रहेगी तो हमारी primary education मजबूत नहीं होगी।

इसका हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टाफ हमारा पूरा हो और जो हमने इसमें पीईओ की व्यवस्था की है सीनियर स्कूल को, जो पीईओ को हमने जिम्मेदारी दी है, उस पीईओ का क्या बीईओ के बराबर का व्यवहार है क्या? जिस प्रकार से बीईओ की मानिटरिंग चल रही थी, उस प्रकार से पीईओ

(श्री मानसिंह किनसरिया)

कर रहा है क्या? क्या आपकी bio-metric जो हाजिरी है, उस प्रकार से उसको कभी आपने चैक किया कि पीईओ ने आपके छोटे स्कूल में कितने मास्टरों को किस दिन भेजा, कौन-सी क्लास खाली थी, किसको भेजा, इसको अगर आप चैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक रूप से जो हमारे primary schools हैं, primary education है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, यह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बेसिक रूप से हमारी primary education में आज की तारीख में आपने जिस प्रकार से स्टाफिंग पैटर्न का समानीकरण के जितने काम किए हैं, वे सराहनीय हैं, आपने जितनी DPC के माध्यम से क्रमोन्नति दी है, वह भी आज तक के इतिहास में शायद ही कोई दे पाया, लेकिन primary education में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि क्या कारण हैं कि हमारे सरकारी महाविद्यालय UGC ग्रांट लेने में फेल रहते हैं। आज हमारे अधिकारी इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते कि जितने भी प्राइवेट कालेजेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर उनकी जो नोर्म्स हैं, उनके जो तरीके हैं, वे सारे fulfil करके UGC का सबसे बड़ा ग्रांट वे लेते हैं। हमारे सरकारी महाविद्यालयों में UGC का ग्रांट कम मिलता है। इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इसकी पालना होती है।

(14.00 बजे)

इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा जो थ्री ईयर डिग्री कोर्स है जिसमें बच्चा सिम्पल बी.ए. करता है उसमें वो तीन साल का उसका पढ़ाई का काम है उसमें जीवन का महत्वपूर्ण समय उसका बर्बाद हो जाता है और हमने इसके बारे में कहीं भी नहीं सोचा। इसके लिए हमें उनके लिए किसी न किसी प्रकार की इंटर्नशिप की व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे आप उनको नरेगा के काम से ही जोड़ दीजिए, पंचायत समिति के नरेगा के आफिस में अगर 45 दिन वो बच्चा बैठेगा तो निश्चित रूप से वो सीखेगा कि किस प्रकार से मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का विकास हो सकता है, इस पैसे का समायोजन कैसे होता है, व्यवस्था कैसे चलती है। उनको शुरूआती तौर पर जो एडमिशन का समय होता है, अगर 45

(श्री मानसिंह किनसरिया)

दिन का इंटर्नशिप का समय देंगे तो हमारी इस कालेज व्यवस्था में सुधार होगा नहीं तो बच्चा केवल एडमिशन लेता है और एडमिशन के बाद वो जिस प्रकार से अपनी तैयारियों के बहाने से तैयारी करता रहता है, हाज़िरी चलती रहती है और एक तरह से इससे शिक्षा का नुकसान हो रहा है। इसकी ओर मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विषय के बारे में सोचें। आपने जो बी.एड. का कोर्स किया है वो बहुत शानदार है, उससे हमारे बच्चे का टाइम खराब नहीं होगा और उससे उसको लाभ मिलेगा तो हम लोगों को इस प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए आई.टी.आई. की हमने व्यवस्था की है उसमें आई.टी.आई. के साथ-साथ आई.टी.आई. की जगह टैक्निकल हाई-स्कूल अगर शुरू से होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो बच्चा पहले 12वीं तक पढ़ता है और उसके बाद में फिर वो तय करता है कि मुझे इसमें जाना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है इसलिए अगर शुरू में हमारे गरीब का बच्चा है, कोई खाती का बच्चा है और वो कारपेंटर का काम करना चाहता है तो अगर वो टैक्निकल स्कूल में होता तो उसको शुरू से ही ट्रेनिंग मिल जाती। आज जितनी भी आपकी आई.टी.आई. हैं उनमें कोई भी प्लम्बिंग का काम नहीं करना चाहता लेकिन प्लम्बिंग का काम इतना महत्वपूर्ण है कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लेकिन उसको आई.टी.आई. के कोर्स में कोई नहीं करना चाहता। इसके लिए हमको चाहिए कि हमारे ट्रेडिशनल वर्कर्स को जो आप स्किल डवलपमेंट के माध्यम से करने जा रहे हो और पिछली बार जो 700 सेंटर खोले उनकी मानीटरिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और स्किल के काम पर और ध्यान देकर ट्रेडिशनल काम को मजबूत करने का काम करना चाहिए क्योंकि यह तीनों विभागों का काम है और तीनों विभागों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवा को हम अच्छी राह दिखाने का काम कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, समय आपका होता जा रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो मेरा राजकीय महाविद्यालय है उसमें अभी 1700 बच्चियों ने एडमिशन लिया है और 4200 बच्चियां प्राइवेट रजिस्टर्ड हैं जिससे आप अंदाज लगा लें कि लगभग 5900 बच्चियों ने एग्जाम

(श्री मानसिंह किनसरिया)

दिया है। जो प्राइवेट कालेज हैं उन दोनों में मिलाकर करीब 8 हजार बच्चियों ने वहां से एग्जाम दिया और वहां पर सरकारी महाविद्यालय नहीं है। प्राइवेट की तो फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब की बच्ची एडमिशन ले नहीं सकती और 1700 के बाद में 4200 बच्चियां नान कालेजिएट हैं तो मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि गंगापुर में महिला महाविद्यालय की आवश्यकता है। वहां पर सारे नोर्म्स पूरे होते हैं, वहां बिल्डिंग भी है, स्थान भी है इसलिए इस बारे में आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि इसकी वहां पर आवश्यकता है।

इसी के साथ-साथ, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समानीकरण का जो काम हुआ था उस समानीकरण के काम में भी कई स्कूलों की हमने शिकायतें की थीं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। उस बारे में एक समय सीमा तय होनी चाहिए थी कि कुछ स्कूल जो रह गये, मैं उदाहरण के तौर पर आपको फिर कहना चाहूंगा कि मेरे यहां ग्राम पंचायत अहमदपुर का जो स्कूल है उस अहमदपुर और अलीगंज दोनों के बीच में रेलवे लाइन है, दोनों गांव रेवेन्यू विलेज हैं, अहमदपुर पंचायत हैडक्वार्टर है और उस पंचायत हैडक्वार्टर के स्कूल को अलीगंज में मिला दिया। उसके लिए कई बार लिखकर दिया लेकिन समझ में नहीं आया तो ऐसे स्कूलों के मामले में जो हमारे मापदण्ड हैं उन मापदण्डों की सख्ती से पालना हो। क्या कारण है कि उनकी पालना नहीं हो रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी जो त्रुटि है उसको दुरुस्त किया जाए और उस स्कूल के समानीकरण का जो निर्णय है उसको निरस्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक लास्ट अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा महत्व रखता है। वहां पर जो कापी चैक करने का सिस्टम है उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कापी जो बाहर जाती है उस बाहर जाने के सिस्टम को कभी तो हमको बन्द करना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी स्टेट में नहीं है। यह कापी को हम वहीं पर चैक कराने का काम करें जिससे इस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगे और इस व्यवस्था के अन्दर और सुधार हो। इसी के साथ-साथ हमारी जो गोपनीय शाखा है, उसका जो निदेशक होता है वो प्रमोशन से नहीं हो। वो जीरो से चलने वाला आदमी डायरेक्टर बनता है और वो जब पूरी सर्विस वहां पर गुजारता है तथा गोपनीय शाखा का अध्यक्ष बनता

(श्री मानसिंह किनसरिया)

है तो कई बार सवाल खड़े होते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि इस पोस्ट को कम से कम इस प्रकार से नहीं भरा जाना चाहिए और ऐसी पोस्ट पर दूसरा होना चाहिए। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। आपने सबको समय सीमा में बांध दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, स्वयं विद्वान हैं, यहां आपके माध्यम से शिक्षा में हम क्या चाहते हैं उसकी बात कई सालों से रख रहे हैं और मैं यह भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि वो जो हम चाहते हैं वो यहां बिना रखे भी सम्भव होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास साक्षी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि कहीं सभासद् बैठे हैं और किसी विषय पर चर्चा हुई है तो विषय विशेष पर 6-6 महीने, साल-साल भर तक चर्चा के उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं और मैं उन पर नहीं जाना चाहता।

शिक्षा, कला और संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण मांग, जिस पर यह सदन आज चर्चा कर रहा है, किसके लिए? वो मनुष्य जो राजस्थान का 6 करोड़ 84 लाख और अब सात-सवा सात करोड़ हो गया होगा, जो प्रकृति की अमूल्य निधि है हमारे लिए और राष्ट्र की एक बेशकीमती सम्पदा है, उसका सृजन कैसे हो, उसका निर्माण कैसे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब लोग, हमारे से पहले वाले लोग भी इसी कल्पना के साथ मौजूदा पीढ़ी में जब रहे होंगे, जीते होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होना चाहिए, उसका निर्माण, उसका सृजन किस प्रकार का होना चाहिए और जब हम यह चिंतन करते हैं तो उसके पीछे बेसिक थीम क्या आती है? आने वाली पीढ़ी, उसका भविष्य सुखद हो, संयमित और सृजनात्मक विचार के साथ जीवन जिये तथा स्वयं और मानव कल्याण के रास्ते पर वो आगे बढ़े, यह विचार और यह चिंतन, जिसको हमने शिक्षा, कला के बाद जो संस्कृति शब्द जोड़ा है, उस संस्कार के साथ उसको मिल सकते हैं और वो संस्कार आखिर उसको मिलेगा किससे? वो संस्कार शिक्षा से मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो विरासत का संक्रमण करता है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विरासत का संवर्धन करता है, हमारी विरासत कैसी थी, हमको उसे आगे कैसे बढ़ाना है। हमने इस हाउस में कई बार नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला की चर्चा की और तब दुनिया के 10-11 हजार लोग जापान से, फ्रांस से, दुनियाभर से हमारे यहां पढ़ने आते थे उस विरासत को हम कैसे साउण्ड करें, संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसका संरक्षण कैसे करें। यह महत्वपूर्ण चर्चा जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, मुझे 3 विद्यालय चाहिए और मुझे 5 विद्यालय चाहिए, अगर यहीं तक यह चर्चा सीमित है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा के बंटवारे में सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार करेंगे। किसी को दो विद्यालय चाहिए तो वो भी मिलेंगे, किसी को तीन विद्यालय चाहिए तो वो भी मिलेंगे और उससे हटकर काम नहीं कर सकते इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। आसन की अवमानना का उद्देश्य कतई नहीं है, 10 मिनट में अपनी बात करूंगा लेकिन आज मैं उस बेसिक बात पर, जिस पर शिक्षा की बात मुझे करनी थी, नहीं जाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रकृति का अनुपम उपहार जो राजस्थान का आम आदमी है पूरे विश्व का, इस अमूल्य संसाधन का सृजन कैसे करें और सृजन के लिए शिक्षा और संस्कार और उसमें भी कला का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा से कला डवलप होती है और जब कला डवलप होती है तो जिसके लिए हम संस्कार डालकर, उसको हम राष्ट्र की सृजनात्मक अमूल्य निधि तैयार करना चाहते हैं, वह क्रियाशील बनती है और हम उसको कितना क्रियाशील बनाएं कि वह आने वाली पीढ़ी देश और समाज के लिए सृजनात्मक तौर-तरीके से काम करे और इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमने आजादी के बाद शिक्षा में बहुत गुणात्मक सुधार किया है। वह अलग विषय है।

मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि अगर हम हमारे 13 विश्वविद्यालयों की बात करें जो प्राचीन काल के थे, तक्षशिला, नालन्दा और भी जो मैं पढ़कर नहीं बताना चाहता, सब लोग उन्हें जानते हैं, तब दुनिया हमारी तरफ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित होती थी। लेकिन आज आजादी के 70 साल बाद हमारे पास दुनिया के प्रथम 200 बेहतरीन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विश्वविद्यालयों में शुमार करने के लिए एक विश्वविद्यालय नहीं है। यह आपको चिंतन का अवसर है। हमने पिछले 70 सालों में, चाहे उसके लिए मैं दोष किसी को नाम लेकर नहीं देना चाहता, हमारी शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया। कभी हम किस विचार को पढ़ाएंगे, कभी हम किस विचार को पढ़ाएंगे और दुनिया से तौर-तरीके उधार लेकर हमें किस दिशा में, किस शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इस पर कभी हमने विचार ही नहीं किया।

मैं अगर भगवान राम के समय से इस बात की उदाहरण के साथ चर्चा करूं, भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र के आश्रम पर गये, 14 साल के वनवास में चित्रकूट से लेकर पंचवटी की नासिक तक गये। हमने केवल एक पक्ष उसका उजागर करके रख दिया। भगवान राम जब वनवास में गये थे, राक्षस आते थे, ऋषि-मुनियों के हवन यज्ञ में नरमुण्ड डालते थे और राम ने यज्ञ विध्वंस करने वाले राक्षसों को मार दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कारण से भारत विश्वगुरु रहा है, दुनिया जिस कारण से भारत का अनुसरण करती रही है, उस उजले पक्ष को हमने राम की उस यात्रा के पक्ष में से निकालकर रख दिया कि तत्समय से हिन्दुस्तान की शैक्षणिक संस्थाएं केवल और केवल ऋषि आश्रम हुआ करती थीं, चाहे वह विश्वामित्र के आश्रम को ताड़का उजाड़ना चाहे और यह तो राम से लेकर मुगलकाल में जब हमारे ऊपर हमले हुए, हम सांस्कृतिक गुलाम हुए तो तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाया जाना भी इस बात का सबूत है कि दुनिया में जब-जब भी लड़ाई हुई है, संस्कृतियों की लड़ाई हुई है। किसकी सभ्यता सर्वोच्च है, किसकी सभ्यता विश्व के कल्याण की बात करती है, किसकी सभ्यता मानव को सृजनात्मक रास्ते पर चलाने की बात करती है? जब इस दिशा में बात करेंगे तो दुनिया को हमने सिखाया है। भगवान राम ने धनुष इसलिए धारण किया कि शिक्षा के केन्द्रों को कोई डिस्टर्ब करेगा, शिक्षा के केन्द्रों को कोई चुनौती देगा, यह उन यज्ञ कुण्डों में नर मुण्ड डालने का सवाल नहीं था। ऋषि आश्रम हमारे शिक्षा के केन्द्र होते थे। उन ऋषि आश्रम शिक्षा के केन्द्रों को कोई विध्वंस करेगा तो वह मृत्यु दण्ड का पात्र होगा। हमारे यहां शिक्षा को लेकर इतने कठोर भी थे। ऐसा हमारा जीवन था और उस जीवन में से हमने हमारी मौजूदा आधुनिक शिक्षा को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? केवल हम उस पर 10 मिनट बोलेंगे,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उसके उजले पक्ष को कांग्रेस ने यह कर दिया था और घनश्यामजी तिवाड़ी जब शिक्षा मंत्री होते थे, मेरे यहां 126 मिडिल स्कूल रामगंजमण्डी एमएलए था, तब और आज जब वासुदेव जी देवनानी शिक्षा मंत्री हैं तो उसमें से 70 बंद हो गये। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। (व्यवधान) मैं जाना चाहता हूं कि राजस्थान में हम शिक्षा से क्या संस्कार लाना चाहते हैं? हम राम की परम्परा के लोग हैं। मुझे अच्छा लगा। मैं आज बहुत लम्बा नहीं बोलूंगा। एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इतिहास भी हमें प्रेरित करता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किस दिशा में जा रहे हैं? देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हमारी विरासत क्या थी? उसका संरक्षण कैसे करेंगे? विरासत से प्रेरित होकर हम हमारी आने वाले भविष्य की नई एक विरासत का निर्माण किस रूप में करेंगे? यह चिंतन होना चाहिए।

देश आजाद हुआ, गुलाम रहा, मेरे पास ये सूची है। 1193 के मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1947 के लार्ड माउंटबेटन तक और अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप को इसीलिए हम गौरव के साथ पढ़ रहे हैं कि उन्होंने संधि-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि 1,000 साल तक राज करने वाले आक्रांताओं का कभी उन्होंने लोहा स्वीकार नहीं किया। लोहा लिया, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन मैं आज इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम इतिहास को पढ़ाना चाहते हैं तो 1193 के पहले का इतिहास पढ़ाओ। 1193 से लेकर 1947 तक के पूरे देश के राजाओं के इतिहास को पढ़ाओ। मेरे पास इण्डियन रूलर्स की सूची है। इनको कहते हैं, भारत के लुटेरे। भारत की अस्मत और दौलत को लूटने का जो नंगा नाच 800 सालों तक किया, यह कहकर अगर मेरे देश के लोगों को पढ़ाया जाता है। उनके देश में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव जागृत होता कि मुझे मेरे देश को अपनी समग्र शक्ति का उपयोग करके, उसको विकसित करके दुनिया का फिर से अगवा देश बनाना है और 800 सालों तक मेरे देश की अस्मत को लूटा है, दौलत को लूटा है और जब हम यह पढ़ा रहे हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं, उस दलित इतिहास को पढ़ाना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कभी मुगलों के साथ संधि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये।

अपनी आखिरी बात कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मंत्रीजी, पढ़ाओ उस दलित इतिहास को। इस हिन्दुस्तान के इतिहास में 12वीं शताब्दी से पहले कोई सफाई कर्म और चर्म कर्म करने वाली जातिगत आधार पर कोई जातियां नहीं थीं। जब 12वीं शताब्दी में 1193 में यह मुल्क आजाद हुआ और मुल्क गुलाम हुआ तो यह समाज कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने आत्म-समर्पण कर दिया और कुछ लोगों ने मरना-मिट जाना मंजूर कर लिया, लड़े और जो लोग युद्ध-बंदी बन गये, उन लोगों के साथ बलात् धर्म परिवर्तन के लिए ज्यादती की गई। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपने आपको मिटाना मंजूर कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनका मान भंग किया। मान भंग करके वाल्मीकि समाज को भंगी बना दिया। जिसने उस समय के इस्लाम की क्रूरता को मैला उठाने से भी अपवित्र समझा और बलात् ज्यादती के बाद भी यह कहा कि दत्त भगवान ने मैले को गुरु बनाया है, हम उसकी पवित्रता मानते हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम के नाम पर बर्बरता कर रहे हैं, हम उनके सामने आत्म-समर्पण नहीं करेंगे।

यह 1193 से लेकर 1947 तक के इतिहास के पहले का भारत तक का इतिहास, जिसने भारत के समाज की शक्लें बिगाड़ दीं। जो देश के लिए लड़े, मर गये, मिट गये, उन लोगों को पढ़ाया जाये और पढ़ाया जाये उन धर्मगुरुओं को, जिनको चर्मकार बना दिया। महर्षि बालीनाथ ने दौसा में जन्म लिया, जिसको भंगी बना दिया, वाल्मीकि बना दिया। सामूहिक सफाई कर्म में लगा दिया। उस जाति में महर्षि नवल ने जन्म लिया। ऐसे महापुरुषों को पढ़ाया जाये। उस दलित के इतिहास को पढ़ाया जाये। दलित भारत का गौरव है। दलित भारत की आत्मा है...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और इसीलिए मैं आज शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, जब जवाब देंगे तो भारत के शासक नहीं, भारत के लुटेरे और भारत के लुटेरों से भारत की आन-बान-शान और इस देश की मर्यादा और अस्मिता के लिए लड़ने वाले लोग जिन्होंने अपना वजूद खो दिया। धर्म, संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं को नहीं बदला, उनके इतिहास का महिमामंडन इस राजस्थान के शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। उसके धर्मगुरुओं, महर्षि नवल और महर्षि बाली जैसे लोगों का महिमामंडन हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हम विरासत से साक्षात्कार करेंगे, तब भविष्य की चुनौतियों से लड़कर एक नये भविष्य का निर्माण करेंगे। एक नये विचार का निर्माण जो इस राष्ट्र की एक मजबूत आधारशिला

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रखेगा और गुलामी की सम्पूर्ण जो आभाएं हैं, उनको उखाड़कर समाज जीवन के विचार में से फेंक देगा, इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कम समय आपने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इस सदन में सभासद बैठे हैं, परम्पराएं अच्छी डलनी चाहिए। औपचारिक रूप से नहीं, यह सभासद 6 करोड़, 7 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में चर्चा करता है। दो स्कूल उसका एजेंडा नहीं रहे। जवाबदेही दो स्कूल खुलाने की नहीं, समूचे राजस्थान के लिए हम क्या करना चाहते हैं, उस समाज में मौलिक परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? उसका चेहरा-मोहरा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सम्पूर्ण विकास, सामाजिक सुविधा, भौतिक सुविधा, कैसे राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए क्या-क्या नजरिया माननीय सभासद का है, वह खुलकर आना चाहिए और इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्पराएं भी सदन में बननी चाहिए। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर चर्चा हो रही है, अनुदान की मांगों पर चर्चा है। आपने 10 मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि 10 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूं। फिर भी, एक-दो मिनट लग जाएं तो आप उदारता बरतेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में आ जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। ये मंत्री हाथ मिलाना बंद कर दें, अपने चैम्बरों में कर लें तो और ठीक रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज उच्च शिक्षा से मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में आपने जो अपना सुराज संकल्प पत्र भाजपा का 2013 राठौड़ साहब, दिया था। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और पढ़ने के बाद में, जो उच्च शिक्षा में आपने वादे किये थे, उसमें से 4-5 बिन्दु बताकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा।

आपने राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। दोनों जगह आपकी सरकार है, आज की तारीख तक आप कर नहीं पाए। आपने प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की थी, आप कर नहीं पाए। आपने नियामक बोर्ड या आयोग बनाने की बात की थी। पहले कालीचरण जी सराफ मंत्री थे, फिर माननीय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किरण माहेश्वरी जी मंत्री आ गयीं, दोनों मंत्रियों का यहां इसी सदन में जवाब है कि हम प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, वो अनियमितता नहीं करें इसके लिए नियामक आयोग बना देंगे। इसी सत्र में आ जाएगा, इसी सत्र में आ जाएगा। आपका सत्र 6 महीने बाद में पूरा होने वाला है, आपकी सरकार जाने वाली है, लेकिन आपकी नीयत में खोट होने के कारण से आज तक नियामक आयोग नहीं बना है।

सरकारी सेवा में एक साल का प्रोबेशन करने का आपने वादा किया था, जब हाई कोर्ट ने यहां से निरस्त कर दिया कि कोई प्रोबेशन नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गये। लेकिन, आपने यह वादा पूरा नहीं किया है।

आपने कहा था प्रत्येक उपखण्ड के ऊपर सरकारी कालेज जहां नहीं है, वहां पर हम सरकारी कालेज करेंगे। आज की तारीख तक केवल जहां उप चुनाव होने थे, उनमें जरूर आपने घोषणा की है और कुल मिलाकर मैं समझता हूं शायद 17 कालेजों की 5-7 पहले की होंगी। 20-22 कालेजों से ऊपर आप घोषणा नहीं कर पाए और वे भी धरातल पर आई नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं लेकिन एक काम बहुत जोरदार तरीके से आप करना चाह रहे हैं कि अब कालेजों में भी आप भगवा ड्रेस कोड अपनाने के लिए जोर देने की बात कर रहे हैं।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, साफा पहनकर आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्होंने पहले साइकिलें काली होती थीं। आज तक किसी ने भगवा साइकिल नहीं बनाई, पूरे हिन्दुस्तान में नहीं बनी, लेकिन इन्होंने बच्चों की साइकिल को ही भगवा कर दिया। आप डरो मत, आराम से पहन कर रखो, हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): साफा आपको बुरा लगता है, आप साफे का अपमान कर रहे हो, राजस्थान की संस्कृति का अपमान कर रहे हो, ये रिकार्ड पर जा रही हैं, सारी बातें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साफे के लिए दो बातें हैं, माननीय राठौड़ साहब। ये राजस्थान की संस्कृति भी है लेकिन सामन्तवादी सोच का परिचायक भी साफा रहा है। तो, कौन सा पहना है, आप जवाब में बता देना।

मैं दूसरा निवेदन करूं विद्यालयों में आपने ड्रेस, जो है वो भगवा कर दी। अब आप कालेज में भी कह रहे हैं वो तय करके बता देंगे। कोई ऐसा प्रिंसिपल आपके ध्यान में है, जो आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आरएसएस की जो विचारधारा है, उससे अलग चलकर यहां नौकरी कर सकता है। वो ही भगवा का ठप्पा लगना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रदेश में आपको 163 का मैंडेट बाबा बनाने के लिए नहीं दिया था। आपको आसाराम और राम रहीम बनाने के लिए नहीं दिया। आपको दिया था अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिस प्रकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे, उसमें आप लोग काम कर नहीं पाए।

आप यूजीसी से ग्रान्ट लेने में छोटे राज्यों से भी पीछे हैं, 100 करोड़ रुपये तक का कम अनुदान हम ले पाए। 5 यूनिवर्सिटी के पास में 75 करोड़ की यूजीसी ग्रान्ट, मिले सिर्फ 8 करोड़ रुपये। ये भी आपके लिए सोचने का विषय है। 11 सरकारी यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं, 4 में तो एक भी पोस्ट स्वीकृत नहीं है और जिस प्रकार से आपने कहा था कि ये चार विश्वविद्यालय खोले थे, हम पद भर देंगे, आपने कुछ नहीं किया, 9 साल के लगभग हो गये, हमने भी बहुत सैंक्शनस कर दीं, भर्ती नहीं कर पाए, लेकिन सवा चार साल से आप भी भर्ती नहीं कर पाए।

सभी सरकारी विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास की दौड़ में शामिल होने से पहली बार बाहर हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, उसकी क्या दशा है। एक और जो आप करने जा रहे हैं गुड एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर एक राइडर लगाकर के जो कालेज लैक्चररों की भर्ती हो रही है, उसमें आप लोग-बाग़ ग्रामीण एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को बाहर करने जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

एक और चीज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, हमने शुरूआत की थी सीकर में। उसका जो एफीलिएशन है, उसका नवीनीकरण किया जाना था। जब प्रदेश के 31 जिलों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफीलिएशन नवीनीकरण हो गया, आज परीक्षा शुरू होने लग गई। परीक्षा की सामग्री वो 600 कालेज हैं, माननीय मंत्री महोदय वे ले नहीं रहे हैं। आपने जो फीसें बढ़ायीं उसको तो छोड़िये, बाद की बात है, लेकिन, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसा क्या वी.सी. आ गया, जो आपकी मुख्य मंत्री झुंझुनूं में गई थीं। उन्होंने निर्देश दिये थे, बुलाकर के कि इसको सबको समान कर दो। इनकी भी एफीलिएशन की जो है, वो रिनुअल कर दो। उसके बावजूद भी आपका वी.सी. आपकी मान नहीं रहा है

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और वी.सी. के खिलाफ जिस प्रकार की जांच यहां जयपुर यूनिवर्सिटी में जब ये थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो आज की तारीख तक जो कमेटी बनी थी उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की, वो आज की तारीख तक भी रिपोर्ट आई नहीं। अगर आ गयी हो तो माननीय मंत्री महोदया, आप बता दें, अपने रिप्लाई में।

लेकिन, मैं निवेदन करना चाहता हूं परीक्षाओं की सामग्री प्राइवेट 600 कालेज हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी शेखावाटी का ही भाग हैं और आप शेखावतों के नाम से ही शेखावाटी का हमारा नाम पड़ा है और हम गौरवान्वित होते हैं, शेखावाटी का नाम लेकर के। आपने शेखावाटी विश्वविद्यालय किया और उसके बाद में दो जिले सीकर और झुंझुनूं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको एफीलिएशन नहीं मिल रहा है और दूसरे 31 जिलों में एफीलिएशन मिल गया।

मैं समझता हूं कि ये वी.सी. की हठधर्मिता है और उसके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगा सकते, नियामक आयोग आप बना नहीं सकते और सरकार अगर असहाय और असक्षम है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं समझता हूं मंत्री महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए। एफेडेविट दे देकर और प्राइवेट कालेज के लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो प्रीक्षा नहीं कराएंगे, हम सामग्री नहीं लेंगे। वहां धमकाये जा रहे हैं, आरएसएस की जिस प्रकार की जो आपकी विंग है, वो काम कर रही है कि नहीं, इनको रगड़ना है, ये कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सपने में भी आरएसएस याद आ रहा है क्या? यहां पर न तो बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी शासन कहो तो ठीक लगता है, लेकिन आरएसएस का बार-बार, यहां पर कोई बात नहीं है। भूत सवार हो रहा तो जरूर आप लोकतंत्र है, कह सकते हो। लेकिन, इतना आरएसएस तो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आरएसएस का क्या लेना देना, जो इनका सदस्य नहीं, कोई है नहीं, उनका नाम बार-बार ले रहे हैं। ऐसे नाम को हटाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हट जाएगा, आठ एक महीने वेट कर लो, हट जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वैसे इनको क्या है, शांति पसन्द नहीं है। इनका उकसाने का एक स्वभाव बन गया है। उकसाओ इनको, उकसाओ इनको...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसको, किसको...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप ऐसा क्यों करते हो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको बाहर करना है यहां से। उकसाना नहीं है... सत्ता से बाहर करना हमारा उद्देश्य है। उकसाना उद्देश्य थोड़े ही है हमारा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके करने से होने वाले नहीं हैं। अभी हो गये पूरे हिन्दुस्तान से तो बाहर हो गए। ये पता नहीं नार्थ-ईस्ट में क्या हालत हुई है, सफाया हो गया और फिर भी बोले जा रहे हो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो अपनी सोचो...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): फिर, भी बोले जा रहे हो। अपनी गिरहबान में झांककर देखो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपना पूत कुवारा डोले और पड़ोसी के बेटे की शादी में डी.जे. पर नाच रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप तो अपनी सोचो। अपनी गिरहबान में झाकों, सत्ता से ...(व्यवधान) आपका हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं शिक्षा विभाग में जिस प्रकार की स्थितियां 14 से 16 साल की 25 फीसदी आज भी बच्चियां स्कूलों से दूर हैं। उसका मुख्य कारण जो है, वो ये है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने 23 हजार के लगभग विद्यालय बंद कर दिये। बच्ची बाहर जा नहीं सकती, वहां पर शौचालय की सुविधा है नहीं और आने-जाने की सुविधा है नहीं, दूर कर दिया, वाउचर का नाटक कर करके वाउचर दे देंगे, कोई वाउचर नहीं देता है और जो साइकिलें दीं, कमीशन का खेल करके वे साइकिलें चल ही नहीं रही हैं शिक्षा मंत्रीजी, दो महीने में ही खराब हो गयीं ...(व्यवधान) आप विराजो, विराजो, मैं आप पर थोड़े ही आरोप लगा रहा हूं आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से 65 फीसदी स्कूलों में साइंस लैब आज भी नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कहा प्रतिबंधित जिलों को हम लोग-बाग़ यहां स्थानांतरण लेकर के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आएंगे। जब सुराज संकल्प यात्रा चल रही थी तो आपने बहुत बड़े-बड़े वादे किये थे। आज 25 और 30 हजार के लगभग थर्ड ग्रेड के टीचर, जो प्रतिबंधित जिलों में बैठे हैं, आप लाये नहीं। भर्तियां आपने की नहीं, जब पहला सत्र चला था तो आपने कहा था 1 लाख 15 हजार थर्ड ग्रेड की भर्ती करेंगे, जब दूसरा सत्र चला था तो आपने कहा 85 हजार की भर्ती करेंगे, तीसरा-चौथा सत्र चला तो आपने कहा 55 हजार की भर्ती करेंगे, फिर मुख्य मंत्रीजी अजमेर में 15 अगस्त मनाने गई 2016 में, तो कहा 35 हजार की भर्ती करेंगे। फिर, आपने कहा 35 हजार की भर्ती करेंगे। आज कह रहे हैं 35 हजार की भर्ती करेंगे फिर पैंतालीस हजार का कह रहे हैं, एक की नहीं। आपसे भर्ती हुई नहीं। फीस चार-पांच बार आपने ले ली। थर्ड ग्रेड की जिस प्रकार से कोई भर्ती आप कर नहीं पाये और स्थानान्तरण, जिनको इंतजार था, आपको बहुत उम्मीद के साथ में इतना बड़ा मेंडेट दिया था, उन लोगों को आप कर नहीं पाये और अब जब विषयवार आपने कर दिया थर्ड ग्रेड के अध्यापक को तो विषयवार जब आपने वेकेंसी निकाल दी पूरे जिलों में तो आप अब उनका स्थानांतरण करके यहां बिना विषय ला नहीं सकते और दूसरी तरफ आपने जो नयी वेकेंसी निकाली है वह नयी वेकेंसी जब तक पूरी नहीं हो जाती, आप ट्रांसफर कर नहीं पाओगे। पीपीपी मोड का बड़ा नाटक चलाया आपने। आपने वापस वो मारवाड़ी में कहावत है 'सौ प्याज खाकर, सौ जूते खाये।' तो वो काम कर लिया आपने। दुबारा वापस ले लेना चाहिए था। आपने वापस लिया ही नहीं। आपने तो कटारिया कमेटी बना दी और कटारिया कमेटी की हर रिपोर्ट का आपको पता है। आठ कमेटियां बन गईं। आज तक एक की भी रिपोर्ट आयी नहीं। कटारिया कमेटी का इस प्रदेश में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ यह हो गया कि कुछ भी नहीं निकलेगा, वो पिटारा बंद हो गया। वो न तो रिपोर्ट देंगे और न उस रिपोर्ट को यहां सदन में किसी प्रकार से रखा जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने पीईओ की व्यवस्था की है शिक्षा मंत्री जी...। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी।)

बस दो मिनट, पूरी बात तो कहूं। उस पीईओ को न संसाधन दिये। पंचायत सहायक आपने लगाये वो ग्राम पंचायतों वाले उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। आरटीई में जिस प्रकार साठ हजार से भी ज्यादा बच्चों का 7482 स्कूलों में प्रवेश नहीं हो रहा है। राइट टू एजुकेशन में आपने राइडर लगाये। राइडर लगाने के बाद में लोग हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आप वापस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आये। राइट टू एजुकेशन को आपने समाप्त सा ही कर दिया और जो मान्यता के लिए स्कूलें हैं उनके 3-3, 4-4 लाख रुपये आपने जमा कर लिये। उनकी जो आठवीं से दसवीं की मान्यता है उस मान्यता को आप दे नहीं रहे हैं। 2500 में से 600 के लगभग ऐसे विद्यालय हैं जिनको आपने अपात्र घोषित करके दे दिया फिर पौने चार लाख रुपये आपने जमा क्यों किये? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समय में पांच सौ से ज्यादा विद्यालयों में तालाबंदी हुई है।

मैं एक और बात कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक बहुत-बड़ी प्रमुख समस्या है कि 1986 से पहले चयन आयोग लेता था थर्ड ग्रेड के टीचर, फिर प्रधान ने लिया। फिर आपने लिया। 9,18 वर्ष का जो वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आपने 2005 में आपकी सरकार थी तो एक आदेश निकाला फिर 2009 में दूसरा आदेश 26.9 या 8 को निकाला और उसके बाद में आपने कहा कि रिकवरी करो। कुछ अध्यापक उसमें ऐसे आते हैं कि वो तीन-तीन लाख रुपये या दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपये आप उनसे वसूली की बात कर रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम बहुत भला कर रहे हैं प्रदेश में लोगों को।

एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च माध्यमिक तृतीय श्रेणी में 2016 का जो संशोधित लेवल द्वितीय है, यह आरटैट 2011 में हुई थी। सात साल के लिए वेलिड थी और यह संशोधित जो परिणाम था 1.8.2013 को हुआ था। जब उनका रिजल्ट नहीं आया था तो ये एप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब बाद में संशोधित हो गया तो यह मान लिया कि 2011 वाली ही डेट कट आफ डेट मानेंगे जबकि 2013 का जब संशोधित हुआ है तो 2013 तक जो लोग आ गये उनको इस पात्रता सूची में शामिल करके इनको लेना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसी भी प्रकार, एक स्थानांतरण नीति बनाई कि बहुत रिश्तेदार हों, बहुत ऐसे हों वो लोग आ जाएं, पार्टी के पदाधिकारी आ जाएं, वो लोग आ जाएं। यह कौनसी स्थानान्तरण नीति है? क्या इसके लिए 163 का मेंडेट आपको दिया था? क्या सब कुछ भगवा करने के लिए आपको दिया था? आज स्कूलों में शौचालय नहीं है, भवन नहीं है। रमसा का जो प्रयोग करना चाहिए, जो फंड आना चाहिए, वो केन्द्र से मोदीजी से आप ला नहीं पाये। आज विद्यालयों में न शौचालय हैं, न भवन हैं। 23-23 हजार स्कूल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बंद पड़े हैं। वो जीर्ण-शीर्ण होने के कगार पर हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप यों बताते हो कि हमारी वो संख्या बढ़ गयी, ये बढ़ गयी। इससे काम नहीं चलेगा। एक किलोमीटर का आपने खुद ने बताया था कि एक्ट क्या कहता है आपका। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? उस एक्ट की पालना हो नहीं रही है। केवल एक लाइन लगा दी कि हम तो वाउचर दे देंगे। क्या वाउचर है कोई नहीं समझता। न कोई आप देते हो। इसलिए मेहरबानी करके, एक और आदेश निकाला है साहब, आप जाओगे वहां शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों से चार साल की उपलब्धियां बंटवाओगे और जब आपका शिक्षक नेता यहां आ गया टीवी डिबेट के ऊपर श्री नारायण सिंह, तो उसको सस्पेंड कर दिया। यह कौनसा तमाशा है? यह कौनसा प्रजातंत्र है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? मंत्री महोदय, फिर दूसरे एक अधिकारी को भी आपने सस्पेंड कर दिया। इतना गुरूर मत कीजिये इस मेंडेट के ऊपर। इतना गुरूर मत कीजिये, आपको अच्छा काम करने के लिए दिया था। अच्छा काम कीजिये। क्या यही आपकी शिक्षा नीति थी कि केवल रिश्तेदारों के और भाजपा के लोग बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जो असाध्य रोग मानकर कर रहे हो उसमें भी बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है, आपको दिखवाना पड़ेगा इसको। पिता नेत्रहीन है, माता के वो है, श्वसुर के हार्ट में प्रोब्लम है ऐसे के कर रहे हो और खुद के जो असाध्य रोग से पीड़ित है उसके लिए नहीं कर रहे हो। आपके +++ स्क्रूटनी होती है, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन दूसरा है और पता नहीं वहां सुनते हैं कि +++ अब कौन करता है यह आप जांच करवा लीजिये। जवाब दे दीजिये। इन्कार कर दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोप लगा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आप पर नहीं लगा रहा हूं न, आप चिन्ता क्यों कर रहे हो? वहां पर ये लेन-देन का मामला होकर के स्थानान्तरण होते हैं। असाध्य रोग वाले लोगों के भी, पीड़ित शिक्षकों के भी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी आदतें हम में नहीं आयी हैं। आप कैसे करते थे यह सारा राजस्थान जानता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ। तभी तो सूपड़ा साफ हुआ हैं न। सत्रह में जीरो हो गये न आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपका हुआ है न सूपड़ा साफ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं न आप तो विराज जाओ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): डोटासरा जी, तीन सीटों की जीरो दिख रही है आपको और तीन स्टेट की जीरो नहीं दिख रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्रह। सत्रह।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): तीन राज्य गये हैं तीन सीटों के बदले। अभी-भी आपका अहंकार नहीं उतर रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपना पूत कुंवारा डोले और पड़ौसी के बेटे की शादी में डीजे पर नाचना बंद करो आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप लोग इसी अहंकार में रसातल को जाओगे। पूरे देश में चार स्टेट में बचे हो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): खाता खोलकर बता दो, खाता ही।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पूरे देश में नाम लेने को चार स्टेट बचे हैं। अब आप बहुत जल्दी साफ होओगे। शून्य होगी कांग्रेस इस देश में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड कर रहा हूं। हमारे शेखावाटी में जिस प्रकार से 600 कालेजों को दो जिलों में संबद्धता नहीं दी जा रही है एफिलिएशन रिन्युअल नहीं किया जा रहा है उसको आप तुरन्त कराएं। परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मंत्री महोदय, आपको इसमें आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। आपने एंडोमेंट फीस बढ़ाई, यह किया, वो किया। 30-30, 40-40 लाख रुपये की आप एफडीआर लेओगे उसके बाद करोगे। क्या यही आपकी उच्च शिक्षा नीति थी क्या? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देखना पड़ेगा छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि शिक्षा का जिस प्रकार से चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृत शिक्षा हो, जो बंटाधार आपने सवा चार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साल में किया है, राजस्थान की जनता इसको याद रखेगी और आपको आने वाले समय में सबक सिखायेगी और कांग्रेस की सरकार आयेगी उसके बाद में इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल जी चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर से आरोप लगाये और यह कहा कि शिक्षा का भट्ठा इन साढ़े चार साल में बैठा दिया। आप अपने पांच साल भी याद कीजिये। उन पांच सालों में आपके उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आपने जिस तरह से बिना किसी सबूत पर शिक्षा मंत्रीजी पर जो आरोप लगाये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, मैंने शिक्षा मंत्रीजी पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। आप जबरदस्ती लगाना चाह रहे हो तो आप लगा दो अपने श्रीमुख से। मैंने यह कहा है कि जिस प्रकार से ये जो असाध्य रोग वाला खेल चल रहा है +++ उसमें बू आ रही है उसको चैक करवाने की जरूरत है। मैंने कब लगाया शिक्षा मंत्रीजी पर? आप जबरदस्ती लगाओ न अपने श्रीमुख से।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं अपने श्रीमुख से वो ही बोल रहा हूं जो आप बोले थे। आपने कहा कि पैसे का खेल चल रहा है पता नहीं कहा से चल रहा है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप निकालो मतलब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप पक्का कर रहे हो क्या, मुहर लगा रहे हो क्या? क्यों कह रहे हो? इन्होंने क्या बोला वो छोड़ो, आप बोलो कुछ बोलना हो तो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है कि आप बोले थे तब तक हम तो बोले नहीं। आप बोले तब भी कभी नहीं बोले और जब हम बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम कह रहे हैं बोलो आप। लक्ष्मणगढ़ वालों ने क्या बोला, वो छोड़ो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इसलिए आरोप लगाना किसी पर कि आपने यह भट्ठा बैठा दिया शिक्षा का, आजादी के बाद 52 साल तक राज आपने किया और आज जिस तरह से हमारी सरकार बनने के बाद इन चार सालों में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जितने शिक्षकों के प्रमोशन किये हैं, जितने शिक्षकों की भर्ती की है और आगे 77 हजार शिक्षकों की भर्ती और करने जा रहे हैं, यह आपके राज में नहीं हुआ है। हमारे राज में जितने स्टे थे, पहले भी हमारी सरकार थी उसमें भी हमने खोल कर भर्ती की थी और इस राज में भी मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा पर ध्यान देने के लिये सरकार बनने के साथ ही एक साथ हर पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जिससे गांव में रहने वाले गरीब के बेटा या बेटी को भी शिक्षा मिल सके, आपने खोले थे क्या कभी इतने स्कूल? आपने किया था चलते हुए काम...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको झूंठी बड़ाई करते हुए ग्लानि नहीं हो रही है क्या? 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। आप लोग गांवों में जाओगे तो लोग आपको पीटेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पीटेंगे या नहीं पीटेंगे, वह तो समय बतायेगा कि किसको पीटेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): जीतेंगे, जीतेंगे, यह मुरारीलाल के सपने देखने छोड़ दो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पीटेंगे या नहीं पीटेंगे, कौन पिटेगा, वह तो समय बतायेगा। क्यों पिटेंगे, हमने कर्म खराब किये हैं क्या? आप भी गये थे मेरे क्षेत्र में, किसी एक ने भी कहा क्या कि हम आकर पीटेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पिछली बार दो लाख से हारे थे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आज तीन स्टेट में आप हार गये। जहां बीजेपी का नामोनिशान नहीं था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार के +++ जीत कर आ गये न, दो महीने में ही। हमने कर्म अच्छे किये हुए थे, बुरा कर्म नहीं किया था। गलती हो जाती है, कभी शेर का शिकार गीदड़ से हो जाता है, कोई जरूरी है क्या।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है श्रवण जी....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे को नहीं, आसन से कहो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं आसन के माध्यम से ही कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी की आज्ञा से ही कह रहा हूं, आप बीच में खड़े होकर जो बार-बार बोल रहे हैं, हमने एक भी शब्द नहीं बोला। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जब उन्होंने अपनी बात कही, हमने बीच में हस्तक्षेप

(श्री धर्मपाल चौधरी)

नहीं किया। इसलिए यह बातें कि आज राजस्थान में शिक्षा का भट्टा ही बैठा दिया, हमारे शासन में जो ट्रांसफर किये, वह एक पालिसी के माध्यम से किये और मैं तीन बार इस राजस्थान की विधान सभा में आया हुआ हूं, जब आपका राज था तब आपने बदलियां किस हिसाब से कीं? क्या राजनीतिक हिसाब से नहीं की, क्या डिजायर सिस्टम से आपने ट्रांसफर नहीं किये? खुद कर लो वह सब ठीक। हमारे राज में वाट्सएप पर किसी ने चला दिया और कह दिया कि पार्टी के कार्यकर्ता के कहने से बदलियां होंगी, तब आपको तकलीफ हो गई। इसलिए इस बात को छोड़िये, जिसका राज होता है, राजकाज में जो सब करते हैं....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी अनुमति हो तो एक लाइन बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष: उनकी अनुमति से क्या होगा? अब आप भी विराज जाओ और आप भी विराज जाओ, मैं दूसरे को पुकार लूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनका भी पिंड छूट जायेगा और मैं भी कुछ नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा, कला व संस्कृति की डिमांड्स पर चर्चा हो रही है, मैं आज इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस तरह से इन चार सालों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की प्रगति हुई है, वह पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के लिये एक मील का पत्थर साबित होकर गिनी जायेगी। शिक्षा में आज से चार साल पहले जिस तरह के हालात थे, उन हालात में राजस्थान प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे पिछड़ गया था कि यहां के बच्चों को 9वीं में जाते ही 10वीं पास करना बड़ा कठिन हो जाता था। 8वीं तक फेल नहीं करना, 5वीं में फेल नहीं करना, इस तरह की जो व्यवस्था थी इससे कांग्रेस के लोगों की मानसिकता प्रदर्शित होती है कि हम राजस्थान प्रदेश में शिक्षा के स्तर को गिरा कर, राजस्थान के नौजवान युवकों को एक नरेगा का मजदूर बनाकर किस तरह से खड़ा करें। शहर में भीड़ नहीं बढ़े, उसकी व्यवस्था कोई करने वाली थी तो यह कांग्रेस सरकार थी ताकि 10वीं और 12वीं पास भी नहीं कर पाये। अशोक जी ने तो यह भी कहा था कि

(श्री केसाराम चौधरी)

अगर कोई चपरासी में भी नौकरी देनी है तो 12वीं पास किये हुए को नौकरी देनी है। इस तरह से जो व्यवस्था की कि न तो गांव का विद्यार्थी 12वीं पास कर पायेगा और न ही वह आगे चपरासी के लिये भी अपना फार्म भर सकेगा।

माननीय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। आपने जिस तरह से प्रदेश में 5863 विद्यालयों को क्रमोन्नत करके ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। गांवों में आज इसकी बहुत ही सराहना करते हैं कि आज हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिये दूरदराज नहीं जाना पड़ता और एक ही पंचायत के दायरे में कहीं न कहीं पंचायत हैड क्वार्टर पर पहुंचकर वह अपनी 12वीं क्लास पास कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12वीं पास करने के बाद बच्चियों को दूरदराज से आने के लिये, 5 किलोमीटर दूर से आने वाली जो छात्राएं थीं, उनको साइकिलें देते थे, उनके पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं कि आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने 9वीं क्लास में जो भी बच्ची पढ़ती है, उसको साइकिल देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण में एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चियां दूरदराज से साइकिल से पहुंचकर भी 12वीं पास कर सकती हैं, नहीं तो ड्राप आउट होती थीं। इन चार वर्षों में जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, नामांकन में जो 12 लाख की वृद्धि हुई है, यह शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ इशारा करती है कि निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलने के कारण से बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ लालायित हो रहे हैं। यही कारण है कि 12 लाख तक नामांकन इन विद्यालयों

(14.48 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

में बढ़ा है, 74 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश ले रहे हैं, नहीं तो बीच में ही ड्राप आउट होकर पढ़ाई को छोड़ देते थे क्योंकि 8वीं तक फेल नहीं करना तो 9वीं, 10वीं में फैल होकर बट नैचुरल था कि वह अपनी शिक्षा को छोड़ देते थे और ड्राप आउट हो जाते थे, उसको भी आपने ठीक किया है, इसके लिये राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। जहां स्कूलों में

(श्री केसाराम चौधरी)

कमरों की कमी थी वहां पर रमसा के तहत कमरे बनाकर, जहां लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, हर स्कूल में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की है, इसके लिये 2018-19 में 360 करोड़ की राशि उपलब्ध कराकर कमरों और शौचालयों का निर्माण करने की व्यवस्था की है, इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। आगामी वर्षों में विभिन्न श्रेणी 1832 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा। जो विद्यालय पीछे रहे गये हैं और पंचायत हैड क्वार्टर है, उन विद्यालयों के लिये भी हमारी सरकार की मंशा है कि चाहे प्राइवेट स्कूल भी है, फिर भी वहां विद्यालय खोलकर बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा पंचायत हैड क्वार्टर पर मिल जाये, ऐसी व्यवस्था करने की मंशा हमारी सरकार की है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन दिन के लिये पौष्टिक आहार के रूप में दूध की जो व्यवस्था की है, उसके लिये भी मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि हमारे बच्चे पढ़-लिखकर बलवान और सशक्त हों। ऐसा नहीं हो कि दुर्बल रह जाएं, उसके लिये सरकार ने जो मंशा जाहिर की है, उसके लिये भी तीन दिन के दूध की जो व्यवस्था की है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मदरसों के जो हालात हैं। कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं कि हम मुसलमानों के पक्षधर हैं, मगर जिस तरह से मदरसों की दुर्दशा चल रही थी, उस दुर्दशा को ठीक करने के लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान गया और अब पांच सौ मदरसों का चयन करके उनका आधुनीकरण किया जाएगा। मदरसों में भी शिक्षा का स्तर बढ़े, मदरसों से एक अच्छा पादरी निकल सकता है, एक धर्म गुरु निकल सकता है, मगर उन मदरसों से डाक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता, उनका अच्छा आधुनीकरण उन बच्चों को भी मुख्य धारा में लाने के लिये सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके लिये मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में पहल करते हुए 24 राजकीय महिला आई.टी.आई. विंग खोलकर 4 हजार महिलाओं को 12 व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 23 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने जो व्यवस्था दी है, इस कारण से निश्चित रूप से महिलाएं आई.टी.आई. करके, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके, महिलाएं भी तकनीक में माहिर हो सकें, इसके लिये मैं आपकी सोच की सराहना करता हूं। इससे महिलाओं का निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा में

(श्री केसाराम चौधरी)

रुझान बढ़ेगा। प्रदेश में जो 8 नई आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव दिया है, वे निश्चित रूप से गांवों में खोलें, ताकि जैसे जोधपुर शहर में आई.टी.आई. भी वहीं पर है, पोलीटेक्निक भी वहीं है, इंजीनियरिंग कालेज भी वहीं है, इनको गांवों की तरफ बढ़ाइये। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड स्तर पर सरकारी आई.टी.आई. और सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र 125 किलोमीटर लंबा है और इस क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मारवाड़ जंक्शन में आई.टी.आई. भी नहीं है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में महाविद्यालय खोलकर मेरे क्षेत्र की जनता को सरकारी कालेज खोलकर यह व्यवस्था देंगे।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने शिक्षा में इतना आमूलचूल परिवर्तन किया है। स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं, वे बी.ए. एवं ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पायी हुई शिक्षा से कहीं भी नौकरी नहीं... कालेजों से बेरोजगार निकलते हैं, उस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये जब तक हम इस शिक्षा में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। हम शिक्षा लेकर, पढ़-लिखकर, पूर्व के जमाने में लोगों ने कहा था कि 'अनपढ़िया घोड़े चढ़े, पढ़िया मांगे भीख' इस तरह की शिक्षा में आपने जो परिवर्तन किया है, वह परिवर्तन यह कि आज पढ़ा-लिखा व्यक्ति भीख मांगने की कगार पर है। आज 50 की वैकेंसी निकलती है तो पचास हजार, एक-एक लाख लोग, एक-एक करोड़ लोग इंटरव्यू के लिये आ जाते हैं। इसलिए इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। पहली क्लास से लेकर बाहरवीं क्लास तक और बारहवीं क्लास से लेकर कालेज तक, जिस ट्रेड में व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है, उस ट्रेड की शिक्षा उसको दी जाए। एग्रीकल्चर की शिक्षा पहली से ही स्टार्ट करके कालेज शिक्षा तक उसको केवल एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात को समाप्त करुंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में निजी आई.टी.आई. भी नहीं है और महाविद्यालय भी नहीं है। मैं निवेदन करुंगा कि इस बजट में मेरे मारवाड़ जंक्शन में एक महाविद्यालय की घोषणा

(श्री केसाराम चौधरी)

करने की कृपा करें, ताकि मेरे क्षेत्र के जो 12वीं पास बच्चे हैं, उनको दूरदराज के स्कूलों में नहीं जाना पड़े, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले और मेरे क्षेत्र में महिलाएं भी पढ़ सकें। कालेज शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसा निवेदन करते हुए सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीया सदस्या श्रीमती संजना जी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): शिक्षा, कला व संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर कई माननीय विधायकों ने अपने-अपने सुझाव यहां सदन में रखे हैं, मुझे भी बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज सुराज के लक्ष्य व वादों को पूरा करते हुए प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म को ध्यान में रखकर ठोस नीतियों के साथ हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट 2018-19 पेश किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस सरकार के समय गर्त में डूबे राजस्थान को सशक्त व सम्पन्न बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार के सराहनीय प्रयास रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों के अन्दर क्षेत्र में कई इम्प्रूवमेंट एंड्स इनोवेशन किये हैं। छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हितों को देखते हुए ग्राम पंचायतों के 5883 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें आज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक विद्यालय संचालित है। जिसमें सभी संकाय संचालित हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये और राजस्थान सरकार की ओर से प्रत्येक तहसील स्तर पर डीपीएस की तर्ज पर स्वामी विवेकानंद माडल स्कूलों का निर्माण करवाया गया और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल का शुभारम्भ माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने किया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। वर्ष 2015-16 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय, आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया। इसी क्रम में 2018-19 के अन्दर

(श्रीमती संजना आगरी)

एडिशनल के रूप में उसमें क्लासरूम और टायलैट जैसी व्यवस्थाएं कीं, जिससे ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं को सुविधा मिली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि बजट 2018-19 की घोषणा में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में आगामी वर्ष में 17 उप खण्ड महाविद्यालय, उप खण्ड नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। रायपुर उप खण्ड उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने तत्कालीन सरकार के अन्दर यहां पर कई बार विधायक के रूप में छात्र-छात्राओं की समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन वहां पर आज तक महाविद्यालय नहीं खोला गया। मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी और मेरी बड़ी बहन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के सभी युवा साथियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान रखते हुए, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए रायपुर में उप खण्ड महाविद्यालय खोलने की आपने घोषणा की। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसी सत्र से आप रायपुर के अन्दर महाविद्यालय का सत्र प्रारम्भ करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में गुढ़ा कलां और चण्डावल नगर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर 360 के लगभग छात्र-छात्राओं की संख्या है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से चण्डावल और गुढ़ा कलां के अन्दर दोनों विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जहां पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन जो गांव आते हैं, उनकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। ग्रामीण परिवेश में छात्राओं का 7 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवली कलां, खांखरा, कानावास, कर्मावास, माल्यान, भंवरभाटा, बूटेलाव, बागावास विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या भी ज्यादा है और वे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। मैं निवेदन करती हूं कि इन्हें माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आप घोषणा कराएं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मगरा क्षेत्र है, वहां पहाड़ी इलाकों में छोटी-छोटी ढाणियां बसी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन जी निवेदन करना चाहूंगी कि मगरा क्षेत्र

(श्रीमती संजना आगरी)

में पोखरिया नाड़ी, गोदेलाव, लाखा खेत, खेजड़ी का बाला, इन विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कराने का आप आदेश कराएंगे।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी साहब ने देशव्यापी स्तर पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का उद्घोष 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुभारम्भ किया। हमारी सरकार की यह सकारात्मक सोच है कि केवल बेटी को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है। उसे दुनिया में जीने के लिए काबिल बनाना भी हमारा कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस पाली जिले का प्रतिनिधित्व करती हूं, हमारा जिला 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के अन्दर प्रथम स्थान पर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमें इस बात की भी खुशी है कि 8 मार्च को झुंझुनूं के अन्दर हमारे देश के प्रधान मंत्री और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी इसी योजना का समापन करने के लिए, एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यहां पर आने का अवसर जो मोदी जी दे रहे हैं, उनका पूरे सदन की ओर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूं।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटी के जन्म से लेकर इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 'राजश्री योजना' का शुभारम्भ किया जिसमें बेटी जब 12वीं क्लास तक सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययन करेगी तो बेटी की मां को जन्म से लगाकर 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने आर्थिक पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 10वीं व 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर 'देवनारायण योजना' की तर्ज पर स्कूटी देने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए इसे भामाशाह कार्ड से जोड़ा गया ताकि पात्रता रखने वाली बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। बालिका शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए राजस्थान सरकार ने आयोजित सुविधाओं का विस्तार किया। गांवों के अन्दर आदर्श विद्यालय, देवनारायण स्कूटी योजना, कक्षा नवीं की बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, लैपटाप वितरण, छात्रवृत्ति, गार्गी पुरस्कार, महिला कर्मचारियों की

(श्रीमती संजना आगरी)

लंबे समय से चाइल्ड केयर लीव की मांग को पूरा करके अधिकतम दो वर्ष किया। इसके साथ ही महिलाओं को सक्षम और आगे बढ़ाने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी योजनाओं को सुचारु रूप से लागू किया। उनको धरातल पर क्रियान्वित करने का काम भी हमारे माननीय सदस्यों ने किया। मैं इस सदन की ओर से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत बधाई देते हुए हमारी राजस्थान की इस नारी शक्ति और हमारी मुख्य मंत्रीजी के लिए महिला सशक्तीकरण के नाम पर, महिलाओं-बहनों के नाम पर दो पंक्ति मैं अर्पित करना चाहूंगी-"नारी कभी प्रेम की सर्वोच्चता पर राधा कहलाती है, कभी मातृभूमि पर प्राणों को न्यौछावर कर झांसी की रानी बन जाती है, कभी अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला बन जाती है, कभी खेल के मैदान में साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा बन जाती है, कभी त्याग का आत्मदान कर पन्नाधाय बन जाती है, कभी राजनीति में दुर्गा समझे जाने वाली वसुंधरा और सुषमा कहलाती है, प्रबंधन और शीर्ष उद्योगों में सावित्री जिन्दल बन जाती है, कही नीरजा बनकर मातृभूमि का सम्मान बचाती है।"

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि नारी का कमजोर आकलन किया जाए तो यह देश निश्चित रूप से कमजोर होगा। इस देश को मजबूत बनाने के लिए देश के सर्वोच्च पद पर बैठे गणमान्य नागरिक यदि नारी सशक्तीकरण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम महिलाओं-बहनों को देश के सशक्तीकरण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। महिला सशक्तीकरण की हम लोगों की डिमांड नहीं, हम लोगों की कमांड होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी रावत। माननीय सदस्य श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो रही है। शिक्षा को राजनीति से अलग रखकर पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो सबको इस शिक्षा को हम कैसे अच्छी गुणवत्ता वाली, संस्कारवान शिक्षा बना सकें, इस पर हमें डिबेट करनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए। कैसे हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कीं, इस पर सुझाव भी दिए। मैं सभापति महोदय,

(श्री मेवाराम जैन)

निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चार साल के अन्दर शिक्षा पर खूब प्रयोग हुए। इन प्रयोगों से मेरी समझ में जो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसके बजाय शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है और दिनों-दिन इसमें गिरावट आ रही है। आपने एक साथ 23 हजार प्राइमरी स्कूले बंद कर दीं, यह कहकर की बच्चे नहीं है, स्ट्रेंथ कम है। उधर, आप कह रहे हो कि सीनियर सैकण्डरी स्कूलें जो क्रमोन्नत की है, उसके अन्दर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। जिस तरह से 23 हजार स्कूल, भवन आलीशान बने हुए, उस भवन की आज हालत क्या है? अगर थोड़ा प्रयास उन स्कूलों की तरफ करते कि उन स्कूलों के अंदर हम स्ट्रेंथ बढ़ाए तो वह स्कूलें बंद नहीं होतीं, उनके अन्दर बच्चे होते और वे अच्छी स्कूल चल सकती थी। शिक्षा के अधिकार में यह कहा है कि एक किलोमीटर से ज्यादा बच्चे को जाना नहीं पड़े, आपको वापस यह स्कूलें खोलनी पड़ेंगी। आपने स्कूलें बंद करके कुठाराघात किया है। जनता के साथ, बच्चों के साथ एक धोखा किया है। आपने इसके साथ ही 60 हजार पद खत्म कर दिए। आपने क्रमोन्नत करके हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की घोषणा की। अच्छी बात है। उसके साथ-साथ उस विद्यालय में, जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल की है, उस पंचायत में कम से कम बच्चों के बैठने के लिए कमरे, हाल हों, स्टाफ पूरा हो। इस पर भी विचार करते। अभी तक कई ऐसी स्कूलें हैं, जहां सीनियर सैकण्डरी में पांच-पांच कमरे ही हैं। बताओ पांच कमरे हैं, उसमें 12 क्लासें कैसे बैठेगी? आप उसमें स्टाफ का पता करों। आप प्रत्येक मुख्यालय पर माडल स्कूल बना रहे हैं। उसका खाली नाम देने से नहीं होगा। उसके अन्दर पूरा स्टाफ हो, पूरे कमरे हों, तभी जाकर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयोग हो सकता था। जो स्कूलें बंद कीं, उसके साथ-साथ बच्चियों की स्कूलें भी बंद कर दीं। यह सबसे ज्यादा किया है कि जो बच्चियां हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी स्कूलें खुली थीं और एक झटके में उन सबको मर्ज कर दी। कम से कम इसको तो बख़्शते। बच्चियों की स्कूलों को तो बंद नहीं करते। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आप पुनर्विचार करें। पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी की बात की थी, परन्तु अभी तक पूरी पंचायतों पर स्कूलें नहीं खुलीं। मैं सिर्फ बाड़मेर विधान सभा की मेरी बात करता हूं, 8 पंचायतें ऐसी हैं जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली, 3 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मिडल स्कूल ही है, आठवीं तक ही है, दसवीं भी नहीं हुई वहां पंचायत मुख्यालय पर। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा

(श्री मेवाराम जैन)

में राजनीति नहीं हो। आपने हर पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की है, आप उसको जरूर खोलें। आज सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोलने से पांचवी से आठवीं तक के स्कूलों की हालत क्या हुई है? आप गांवों में पता करोगे तो एक प्राइमरी स्कूल में एक-एक अध्यापक, दो-दो अध्यापक और मिडल स्कूल में दो-दो अध्यापक। जब शुरू से ही बच्चों की हालत यह होगी तो आगे जाकर वह बच्चे कैसे शिक्षावान होंगे, संस्कारवान होंगे क्योंकि शुरू में ही कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। जो अध्यापकों के पद भरने की बात कह रहे हो, नीचे वाले जो पांचवी से आठवीं तक के शिक्षक थे, उनको क्रमोन्नत कर सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी के अन्दर लगा दिया। यह पद सारे खाली पड़े हैं। भर्ती आप कर नहीं पाए। जो भर्ती किए, उतने ही रिटायरमेंट हो गए। अब आप कह रहे हो कि हमने 77 हजार पदों की घोषणा की है। घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। जब वहां अध्यापक लगेगे तभी इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी।

आज पीपीपी मोड की बात भी चली। पीपीपी मोड पर वह स्कूल देनी है जो सबसे बढ़िया स्कूल चल रही है, कास्टली भवन बना हुआ है, उस विद्यालय को अगर पीपीपी मोड पर दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खराब स्थिति कोई हो नहीं सकती है। बाड़मेर शहर में एक गांधीचौक है, सबसे बढ़िया स्कूल है, 5-6 करोड़ की तो खाली जमीन है, उसको देने का उसमें नाम था। मैं तो कहूंगा कि पीपीपी मोड वाला आपने बंद भी कर दिया तो आगे यह नहीं करें, अच्छा यही रहेगा।

मिड डे मील की बात करें, उसमें पोषाहार पकाने वाली बहुत ही गरीब या विधवा महिला लगी हुई हैं, उसको आप एक हजार रुपये दे रहे हो, तो एक हजार रुपये से उस बेचारी का क्या होगा। कम से कम उसका नरेगा जितना मानदेय तो करो ताकि उसका भरण-पोषण हो सके। प्रबोधक भी आज वेतन विसंगतियों के लिए जूझ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों को भी पंचायत सहायकों में लगा दिया। पंचायत सहायक में कोई धणी-धोरी नहीं है, शिक्षा विभाग वाले भी नहीं है। पंचायत वाले कह रहे है कि हम उनको तनख्वाह नहीं देंगे। वह बीच में ही लटके हुए हैं। काफी बच गए हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगी, वह अभी भी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप नौकरी लगाने की बात करो।

आज प्रतिबंधित ज़िलों की अपन बात कर रहे हैं। कई सालों से अध्यापक पांच ज़िलों में बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री मेवाराम जैन)

चाहूंगा कि वह चाहते हैं कि अपने ज़िलों में जाएं परन्तु अगर उनको पांच ज़िलों में भेज दिया और हमारे यहां अध्यापक पांच ज़िलों में नहीं लगे तो यह पूरे पांच ज़िले खाली हो जाएंगे और सारे अध्यापक वहां चले जाएंगे। उनको भेजो हमको कोई एतराज नहीं है परन्तु यहां अध्यापकों की व्यवस्था करके भेजो अगर यूं ही इनको भेज दिया तो पूरे पांच ज़िले, कम से कम आधे से ज्यादा खाली हो जाएंगे।

सभापति महोदय, डेपुटेशन की बात करना चाहता हूं। आज कई जगह पर कार्यालयों में अध्यापक 5-5, 7-7 साल से डेपुटेशन पर बैठे हैं और स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं, वहां नहीं जा रहे। डेपुटेशन छह महीने के लिए करो, एक साल के लिए करो, दो साल के लिए करो, लेकिन पांच-पांच, सात-सात साल से अध्यापक डेपुटेशन के नाम से इन कार्यालयों में बैठे हैं, उनको आप वापस भेजिए।

जो भी हाल स्वीकृत हो रहे हैं, चाहे शौचालय की बात है, चाहे दूसरी बात है, ऐसी जगह होने चाहिए जहां वास्तव में कमरों की आवश्यकता है। जहां पहले ही कमरे खूब थे वहां इन्होंने और कर दिए। जहां आवश्यकता थी उस जगह तो किया नहीं, यह राजनीतिक भेंट चढ़ गए। इसमें भी स्कूल चिन्हित हो जाए कि इस स्कूल में हाल की कमी है, उस जगह ही यह कमरे होने चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। संस्कृत शिक्षा में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जितनी संस्कृत स्कूल हैं उनमें स्टाफ नहीं है। पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे तो बच्चे कहां से आएंगे। वह चाह रहे हैं कि हमें बदलकर या तो प्राइमरी में दे दिया जाए या उसमें दे दिया जाए ताकि पढ़ाई हो सके। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर में महिला कालेज है उसको पी जी कालेज किया जाए। बाड़मेर जिला वह जिला है जहां तेल, लिग्नाइट, गैस है, रायल्टी सबसे ज्यादा बाड़मेर दे रहा है और एक घोषणा बाड़मेर में नहीं कर पाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसको पी जी कालेज किया जाए। जहां पर स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपल लगाया जाए। कालेज की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि रिपेयर नहीं की तो करोड़ों की बिल्डिंग है वह गिर जाएगी। रिपेयरिंग कराई जाए। पालिटेक्निक कालेज है, वहां सारे पद खाली पड़े हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उन पदों को भरा जाए। पालिटेक्निक बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि कमरों में कोई बैठ नहीं सकता है। जर्जर हालत है।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी गर्ग।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर राजनीति नहीं हो। ट्रांसफर पोस्टिंग राजनीति के हिसाब से नहीं करें। कैसे हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को दे सकें, इस पर ध्यान दें। सभापति महोदय, समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मानव के विकास के लिए शिक्षा को उसके ज्ञान, विकास और कौशल की धुरी माना है। देश-प्रदेश और समाज को कौशलवर्द्धन एवं समृद्धि की शिक्षा ही एक देन है। शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन, क्रांति और उन्नति सम्भव है। हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा को उन्होंने भी पहला पायदान माना था। शिक्षा अपरिहार्य, विचारणीय और अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा की नींव को मजबूत करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार सदैव ही तत्पर है। हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार और आयाम स्थापित किए हैं। पूर्व में वह मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने 2308 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए थे। अब की बार करीब 5863 विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं। निश्चित रूप से यह प्रदेश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। इन घोषणाओं के लिए मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। जनप्रतिनिधि चाहे पंचायती राज में हो, सहकारिता के क्षेत्र में हो, उनके लिए भी उन्होंने शैक्षणिक

(श्री अर्जुन लाल)

योग्यता का आधार सुनिश्चित करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा कार्य किया है। जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते थे, साक्षर थे या निरक्षर थे वह पहले हमेशा एक मठाधीश की तरह किसी न किसी संस्था में विराजमान हो जाते थे, उनके लिए भी पढ़ाई की, शिक्षा की बाध्यता रखते हुए आठवीं और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता का आधार रखा है। आज भी कई लोग जो निरक्षर, साक्षर हैं वह बुढापे में आठवीं व दसवीं पास करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इन्होंने आदर्श विद्यालय खोलने की तथा 825 आदर्श विद्यालयों के लिए 2475 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए 250 करोड़ रुपये की इन्होंने घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं। इन्होंने आगामी वर्ष में 1832 विद्यालय क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव किया है। निश्चित रूप से जो सबसे वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय या जो ग्राम पंचायत मुख्यालय से पांच-छह किलोमीटर दूरी पर स्थापित विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत करेंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक राजस्व ग्राम पर शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

मिड डे मील के अन्दर अभी बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने कहा था कि मिड डे मील सही तरीके से नहीं मिल रहा। पौष्टिकता के लिए, बच्चों को सम्बल-सशक्त बनाने के लिए मिड डे मील में महिला उत्पादक सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से बच्चों के लिए दूध लेकर, सप्ताह में तीन बार दूध देने का ...(व्यवधान) आपने भी दूध लिया था, आप पढ़ते थे तो। आपकी सरकार ने उसको बंद किया था। यूनिसेफ से जो मिल रहा था उसको बंद किया था, वापस हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने इसको चालू किया है इसके लिए भी हम उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

करीब एक लाख 10 हजार, आप देखिये, आपके 60 साल के राज के अन्दर, जो पूरी पदोन्नतियां दी गई हैं शिक्षकों और कार्मिकों को, तो आप देख लीजिये, पूरी, जो हमारी इस सरकार ने एक लाख 10 हजार पदोन्नतियां शिक्षकों और कार्मिकों को दी हैं, आप पूरा योग लगा लीजिये, इसके बराबर नहीं होंगी।

श्री सभापति: गलती मान रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): वे इसके लिये गलती कहां मान रहे हैं, वे

(श्री अर्जुन लाल)

तो कह रहे हैं कि अभी हुई नहीं। इनको पता भी नहीं है कि हुई कि नहीं हुई।

अब की बार 77 हजार के करीब मुख्य मंत्री महोदय ने रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की है। मैं मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जिस तरह से अब की बार काउंसलिंग करके, कहीं पर भी इस तरह की मारामारी नहीं हुई, सिफारिशों की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें यहां लगा दो। काउंसलिंग के जरिये शिक्षकों का पदस्थापन किया। उससे जो आरोप लगा रहे थे, हमारे डोटासरा जी, उनकी बात की असत्यता पर भी छाप लगती है कि काउंसलिंग के जरिये सबको लगाया गया।

इसके अलावा, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे जोधपुर में बावली और लूणी, दोनों जगह राजकीय महाविद्यालय तथा ओसियां को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, उसका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि निजी महाविद्यालय या जो सरकारी महाविद्यालय थे, उसके अन्दर सैल्फ फाइनेंसिंग से जो पाठ्यक्रम चलते थे, पांच वर्ष हो गये उनकी अवधि को देखते हुए अभी स्टेट फाइनेंसिंग के द्वारा वे चलाएंगे, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों पर जो भार पड़ता था, वह कम हो जाएगा।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र की मैंने जो मेरी मांग दे रखी है, उस पर मंत्री महोदय से गौर करने के लिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, करीब 6 या 7, जो वंचित रह गये हैं, हालांकि वहां पास के अन्यत्र गांव के अन्दर जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, लेकिन वे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नहीं हैं, उनमें, जैसे रावर की ढाणी, खातियासनी, पीथावास, जालेली दईकड़ा, खारिया आनावास और एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर दसवीं क्लास में बालिकाओं की संख्या करीब 45 से बाहर है, तो उन विद्यालयों को, आपकी नीति और नियम में भी आपने यह दे रखा है कि जिस बालिका विद्यालय में 40 छात्राएं होती हैं तो हम उसको निश्चित रूप से क्रमोन्नत करेंगे। तो मेरे ये छह विद्यालय हैं, जिनको सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं।

इसके साथ जो विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनको भी, मेरे करीब ये 10 ऐसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें आठवीं में करीब 30 और 40 के बीच विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जैसे बीनावास,

(श्री अर्जुन लाल)

बीरावास, सोवणिया, जसपाली, जालखा, हर्ष, बिलाड़ा की आदर्श नगरी, पीपाड़ शहर का वार्ड संख्या 10, मुरकासनी, बड़ी कलां, आकथली, रावर गांव, इनमें भी 35 से 40 बच्चे आठवीं क्लास में हैं। किसी में तो 40 से भी ज्यादा हैं, तो उनको भी माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे, ऐसी मैं मांग करता हूं।

साथ के साथ कई विद्यालय, पूर्व में यह था कि विद्यार्थी तय करेंगे कि उस विद्यालय के अन्दर कौनसा सब्जैक्ट वे रखना चाहते हैं। लेकिन वे विद्यार्थी जो नवीं या आठवीं में थे और सब्जैक्ट मांग रहे थे, वे अब पास आउट हो गये। अब पीछे के जो विद्यार्थी आये हैं, वे अब यह मांग कर रहे हैं कि हमारे तो विज्ञान वर्ग, छात्र अब इतने होशियार नहीं हैं, तो हमें कला वर्ग चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक मिनट, सर। उनके लिये आपने 120 की जो स्ट्रेंथ का, 12वीं के उस सब्जैक्ट के लिये 120 छात्र होने चाहिये, इसकी संख्या को कम करते हुए, या तो दूसरा कोई इसका फार्मूला रखकर या 120 छात्रों की संख्या का जो आपने मापदण्ड रखा है, उसको कम करते हुए, वहां पर विज्ञान वर्ग, कला वर्ग या जो भी वहां के बच्चे चाहते हैं उसके अनुसार संकाय खुलवाएं।

इसके अलावा, मेरे यहां जो बिलाड़ा और पीपाड़ शहर महाविद्यालय हैं, उसमें विज्ञान संकाय खोलने की मैं मांग करता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 पर बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन भी करता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता तो कृपा करके मेरे बीच में नहीं बोलें। नहीं तो फिर मेरा टेम्पर लूज हो जाता है।

श्री सभापति: कृपया टेम्प्रेचर को उसी स्थान पर रखें। उसको लूज नहीं करें।

श्री हीरालाल (निवाई): मैंने टेम्पर बोला, टेम्प्रेचर नहीं बोला।

श्री सभापति: टेम्पर?

श्री हीरालाल (निवाई): टैम्प्रेचर तो बीमार का होता है। टैम्पर, स्वभाव।

माननीय सभापति महोदय, हमारा भारत शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु के नाम से जाना जाता है और आज भी है। सूरज सबसे पहले हमारे भारत में उगता है। उसकी किरणें भारत में आती हैं। इसलिये जगत गुरु माना जाता है, और हमारे यहां के नालन्दा, तक्षशिला और वाराणसी विश्वविद्यालय, जिनमें चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, जर्मनी, वहां के छात्र आकर अध्ययन करते थे। यह वह देश है। इसलिये विश्व गुरु के नाम का दर्जा है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति माननीय ओबामाजी ने कहा था कि अमरीकी छात्रों जाग जाओ, नहीं तो भारतवासी छात्र आ जाएंगे। तो हमारे तेज से, हमारी विद्वता से, विदेशी, बाहर के लोग, पाश्चात्य देश भी प्रभावित हैं। हमारे यहां के शिक्षकविद् आज विश्व में नाम कमाते हैं। हमारे यहां के मूल निकी हेली नीति अमरीका के यू.एन.ओ. में प्रतिनिधि हैं, तो यह भारत के लोगों के लिये बहुत गौरव की बात है। लार्ड मैकाले ने, जब भारत गुलाम था ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताएं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप क्यों बोल रहे हो, फिर नहीं बोलने दूंगा मैं, किसी को भी। (व्यवधान) मैंने पहले कह दिया कि कृपया बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

श्री सभापति: हीरालालजी, आप इधर ही ध्यान रखें, आसन की ओर।

श्री हीरालाल (निवाई): पहली बार आये हो विधान सभा में, विश्नोईजी, थोड़ा स्तर बनाओ आप, सीखो अभी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बोलो, बोलो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): 'बोलो', 'बोलो' क्या? क्या बोलो, कौन हो आप कहने वाले? मुझे सभापतिजी निर्देश दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय हीरालालजी, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बोलो, बोलो।

श्री हीरालाल (निवाई): मुझे सभापतिजी कह सकते हैं। Don't disturb me.

मैकाले ने केवल क्लर्क पैदा करने की शिक्षा के जगत में उन्होंने

(श्री हीरालाल)

प्रयास किया। लेकिन भारत तो विश्व गुरु है, उसको कोई आज मिटा नहीं सके। हमारी भारतीय संस्कृति में, यहां मुगल आये, अंग्रेज आये, हुण आये, शक आये, पर इस भारतीय संस्कृति को बदलने की क्षमता किसी में नहीं थी। हमारी संस्कृति में वह ताकत है, जो आता है उसको आत्मसात कर लेते हैं। अमल्गमेशन, हमारी संस्कृति में अमल्गमेशन की ताकत है। शिक्षित राष्ट्र, उन्नत राष्ट्र, और जो उन्नत होगा तभी विकसित राष्ट्र होगा। हमारे यहां हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर पंचायत क्षेत्र पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल का सृजन किया।

पांच हजार से ज्यादा स्कूलें उन्होंने क्रमोन्नत कीं, उसमें यह नहीं देखा कि यह पंचायत कौनसी है, कौनसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी वसुन्धराजी और हमारी सरकार और हमारे देवनानीजी यहां पर नहीं हैं, देवनानीजी को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने भी अपना प्रयास किया और उनके समय में सबसे ज्यादा प्रमोशन हुए। लेवल-टू, लेवल-फर्स्ट, प्रधानाचार्य सैकण्डरी के लैक्चरर्स, सैकिण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यहां तक कि बाबू इनके भी प्रमोशन हुए। यह ऐतिहासिक प्रमोशन है, किसी भी सरकार ने पिछले पांच साल में, दूसरी सरकार थी इससे आने के पहले, आपको करना चाहिए थे, आपको किसने रोका था?

लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कितनी मेहनत करके यह जो प्रमोशन किये, आज कितने लोगों के घर में चिराग जला, वह लोग प्रमोट हुए, दूसरी जगह पर पहुंचे, कोई आज थर्ड ग्रेड में था तो वह आज सैकिण्ड ग्रेड में गया तो यह सबसे बड़ी बात है।

पोषाहार के मामले में हमारी सरकार ने तीन दिन दूध का किया। छह दिन के अलग-अलग मेन्यू हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आपके समय की ही बात है, आपके ही लोग कहते थे कि पोषाहार में यह है, वह है, आपने क्या दिया पोषाहार में? उस टाइम सारा गड़बड़ घोटाला होता था। आज पूरा उसी हिसाब से है, जहां पर मेन्यू है उस दिन वही खाना बनता है बच्चों का।

आज शिक्षा में यही नहीं है, मदरसों के क्षेत्र में हमारे अल्पसंख्यक

(श्री हीरालाल)
भाइयों के लिए भी हमारी सरकार ने 25 करोड़ रुपये इन मदरसों के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको डवलप करने के लिए रखा है।

देश में हमारी जो संस्कृति है, मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे महान पुरुष हैं, उनको भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं। वह नहीं तो भूल जाएंगे, भूल जाएंगे कि राम कौन था, कृष्ण कौन था? इसलिए आज का आधुनिक जो स्टूडेंट है वह पाश्चात्य की ओर झुक रहा है तो हमें उनसे दूर करने के लिए, हमारी संस्कृति की शिक्षा, हमारे महान पुरुषों की शिक्षा, हमारे कौन विद्वान हुए हैं, कौन इस भारत के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

मैं इस बात को भी फख्र के साथ कहूंगा कि मेरे जिले से टोंक का एक गुर्जर समाज का लड़का, जिसने पूरे राजस्थान में कला संवर्ग में वर्ष 2014-15 में पहला स्थान प्राप्त किया। साइंस और मैथेमेटिक्स में तो एक और एक दो ही होते हैं पर आर्ट्स में यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वह बच्चा खेती भी करता था और पढ़ता भी था और अपने मां-बाप का सहारा था और पूरे राजस्थान में कला संवर्ग में प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया।

बालिका शिक्षा में हमारी सरकार ने नए आयाम पैदा किये हैं। भामाशाह योजना के तहत महिला को जिस तरह से मजबूत बनाया है, माननीय वसुन्धराजी ने बालिका शिक्षा के प्रति भी अपनी समर्पित भावना से काम किया है। पहले साइकिल्स देना, साइकिल्स के बाद स्कूटी, स्कूटी के बाद लैपटाप, लैपटाप के बाद में गार्गी पुरस्कार इस तरह की व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने की है। कम से कम आप एक उपलब्धि तो बताओ कि किसी को कोई साइकिल बांटी हो और फिर बढ़-बढ़कर बात करते हो कि ऐसा किया, वैसा किया, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार कर रही है, अगर वह अच्छा काम कर रही है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और जो ठीक काम नहीं करें तो आप आलोचना, समालोचना करें, कोई बात नहीं, यह आपका धर्म है आलोचना, समालोचना करना।

आज शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम पैदा किये और शिक्षा में जिस तरह की विकृति, मुझे यह कहना नहीं चाहिए अब शिक्षक, मातृ देवो भव, पितृ

(श्री हीरालाल)

देवो भव, गुरु देवो भव, तीन ही भगवान हैं- माता, पिता और गुरु, गुरु को भगवान के रूप में माना है। आज हमने जब जिनको भगवान के रूप में माना है, उन भगवानों का, सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जो शिक्षकों को और शिक्षा जगत को शर्मसार कर देते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह मांग करूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी कि जो ऐसे शिक्षक हों, जो हमारी बालिकाओं के साथ छेड़-छाड़ करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। ऐसे शिक्षकों का रेस्टिकेशन कर दिया जाए। ऐसे भी कुछ शिक्षक देखे हैं और वह ऐसे आते हैं कि नशे में वह आ जाते हैं शराब पीकर, यह बड़े शर्म की बात है कि वह शिक्षक होकर इस तरह से शराब पीकर स्कूलों में आना, मैं जो शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं दो मिनट और लूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, इस ओर भी ध्यान दें। और अब अपने जहां पद रिक्त हैं, शिक्षा मंत्रीजी, जो खाली पद हैं उनको भी भरें। मैं दो मिनट में कंक्लूड करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं वैसे वाहियात नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा बिलकुल कान्करेंट चीज बोलूंगा।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, मांग करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर राजकीय महाविद्यालय है, जहां पर साढ़े चार सौ, पांच सौ बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं जिनमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कला वर्ग का एक सेक्शन और खोलें तथा छात्रों को 80, एक कला वर्ग में 80 छात्र आते हैं बाकी के 500 में से बाकी के छात्र वंचित रह जाते हैं तो मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि मेरे राजकीय महाविद्यालय में मात्र कला संकाय है, मेरी आपसे प्रार्थना है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप बहुत दयावान हैं, बहुत हंसमुख हैं और आप सबके प्रति ध्यान रखने वाली हैं और बालिकाओं के प्रति मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादा ध्यान रखें, एक विज्ञान और वाणिज्य का सैक्शन भी खोल दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजकीय महाविद्यालय पांच साल से स्नातक है, एक सैकिण्ड और लूंगा, उसे स्नातकोत्तर किया जाए और मेरे कालेज में बाउंड्री नहीं है, कालेज

(श्री हीरालाल)

तो बना दिया, उसकी बाउंड्री नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने बहुत पैसा देकर ऐसा शानदार और जानदार भवन बनाया है, बाईपास से जो भी जाएंगे, उसको दिखता है लेकिन बाउंड्री के बिना वह थोड़ा अधूरा लगता है, पशु चरते रहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि अगर उसकी बाउंड्री बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद, हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सैकिण्ड, साहब, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: सैकिण्ड आपका बड़ा लम्बा है।

श्री हीरालाल (निवाई): दो सैकण्ड और दीजिए। जो और लोग बोलते हैं उनको ज्यादा देते हैं, मेरे प्रति आप थोड़ा पोलाइट रुख रखें, आदरणीय सभापतिजी।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह कहूंगा, माननीय देवनानीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय नवरंगपुरा, पीपलू जिसको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें।

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, झिलाय, जिसको राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें।

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, पीपलू, उसको राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय नटवाड़ा, मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र के यह गांव हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद, हीरालालजी, हो गया, हो गया, बहुत हो गया।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सैकिण्ड, साहब, इतने कठोर मत बनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री नवनीत लालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): बस दो सैकिण्ड और लूंगा मैं। दो सैकिण्ड, प्लीज।

श्री सभापति: हां, आप बोलो दो सैकिण्ड। बोलो दो सैकिण्ड।

(श्री हीरालाल)

श्री हीरालाल (निवाई): शहीद जय नारायण व्यास माध्यमिक विद्यालय लुहारा को सीनियर हायर सैकण्डरी करें।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढाणी जुगलपुरा को सीनियर हायर सैकिण्डरी करें।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नला को सीनियर हायर सैकिण्डरी करें।

श्री सभापति: दस सैकण्ड हो गये।

श्री हीरालाल (निवाई): राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, राहोली को क्रमोन्नत करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री नवनीत लालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): और उत्कृष्ट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्योसिंहपुरा, उसको आप सैकिण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करें। राजकीय उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठो-बैठो हीरालालजी। अब नोट नहीं करें, भैया, अंकन नहीं हो।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री सभापति: श्री नवनीत लालजी बोलें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 पर बोलेने का समय दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद।

आज शिक्षा पर बहस चल रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है कि मनुष्य को अपनी समाज और संस्कृति में बैठकर वातावरण को बनाने का एक आधार बनाती है।

शिक्षा नहीं होती तो मानव कानून के बंधन में नहीं आता। अत: मेरा एक आग्रह यह है कि मान्यवर, जब शिक्षा की उत्पत्ति हुई उस समय पर कागज की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो माननीय वाल्मीकि जैसे संतों ने शिक्षा पत्थरों पर लिखी, पत्तों पर लिखी और वह अक्षर धुल गये, जानवर खा गये, जिस भाषा का नाम संस्कृत दिया गया है तो मेरा ऐसा आग्रह है कि आज शिक्षा को लेकर हमारा देश जब आजाद नहीं था, उस वक्त राष्ट्रीय नेता जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि पहले शिक्षा दो, फिर संगठन करो और फिर आंदोलन करो।

लेकिन देश के नेताओं ने अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में झंडी पकड़ा दी,

(श्री नवनीत लाल)

देश आजाद कर दिया। देश आजाद होने के बाद यह समस्या आज ज्यों की त्यों चल रही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर आंदोलन हुआ होता तो वह आन्दोलन करने वाला व्यक्ति कानून की बात को समझ सकता था। तो मेरा आग्रह है, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने गत चार वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कीं। ग्राम पंचायतों में 5,863 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। मान्यवर, राजकीय विद्यालयों में नामांकन 12 प्रतिशत तक बढ़ा है। पहले जहां केवल 48.9 प्रतिशत विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करते थे। आज 74 प्रतिशत बालक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं।

मान्यवर, 2015-16 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक आदर्श विद्यालय की घोषणा की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक महोदय, अन्दर कमरे में जाकर विराजो, रेस्ट फर्मा लो, आपको नींद आ रही है। आप नींद लो। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपने आज नाम ही ऐसे दिये हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनकी क्यों चिंता करते हो इतनी?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कितने सो रहे हो, आपको पता ही नहीं। यहां मामले उठा रहे हो और आपने कोई स्थगन लगाया नहीं, कुछ नहीं लगाया सुबह और दूसरे को देख रहे हो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आप भी सचेतक हो, वह भी सचेतक हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको तो रात भर नींद के अलावा कुछ मिला ही नहीं होगा। उठकर भागना पड़ा...(व्यवधान)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 2017-18 में प्रथम चरण में 825 आदर्श विद्यालय हेतु 2,475 करोड़ 76 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण में 1,163 आदर्श विद्यालयों में 3,369 क्लासरूम, कमरें, टायलेट आदि के लिये 307 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा हुई है।

मान्यवर, अभी हाल आगामी वर्ष में विविध श्रेणी के 1,832 विद्यालय क्रमोन्नत किये गये। साथ ही विगत चार वर्षों में विभिन्न वर्गों के कुल 67,961 शिक्षकों एवं कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है तथा 1 लाख 9 हजार 662 शिक्षकों को पदोन्नति दी गयी। मान्यवर, प्रदेश में आगामी वर्ष में 17 उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोलने की जो घोषणा की है, अटरू

(श्री नवनीत लाल)

जिला बारां में, जोहड़ जिला बाड़मेर, बीछीवाड़ा जिला डूंगरपुर, रानीवाड़ा जिला जालौर, बावड़ी लूणी जोधपुर, पासाकृपाल नगर अलवर, रेवदर सिरोही, हनुमानगढ़, नदबई नगर भरतपुर। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जो महाविद्यालय की घोषणा हुई है, इसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में, जहां ट्राइबल इलाका है, आदिवासियों का क्षेत्र है, वहां पर महाविद्यालय नहीं है। मेरा आग्रह है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय 745 हैं, जिनमें 34 हजार 467 बालक-बालिकाएं हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय 375 हैं जिनमें बालक संख्या 29,947 है। सीनियर विद्यालय 31 हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो लाइन कला और संस्कृति पर बोल दो आप तो। (व्यवधान)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): आ जाएगा आगे, आप सुन लेना। पढ़ लेना वह कागज, जो मैं पढ़ रहा हूं। सीनियर विद्यालय 88 हैं जिनमें ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): पांचवीं बार आये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ध्यान नहीं है, हम लोग थोड़ा कला, संस्कृति के बारे में कम जानते हैं। (व्यवधान)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): 77 हजार 575 बालक-बालिकाएं हैं, जहां पर आदिवासी एरिया है, गरीबों का क्षेत्र है, वहां पर 12वीं क्लास पास करने के बाद बालक-बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। इसलिये मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जिला बांसवाड़ा और विधान सभा क्षेत्र घाटोल में महाविद्यालय खोला जाये ताकि गरीब व जनजाति के छात्र-छात्राएं पढ़ सकें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि समानीकरण हुआ है तो जहां पर समानीकरण हुआ है, वहां सर्वे होना चाहिये। समानीकरण ऐसी स्थिति में वहां कहीं दूर क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, वहां छात्र बड़ी स्कूल यानी माध्यमिक में जा नहीं सकते। इसके कारण कई बालक पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं, ऐसी स्थिति है। इसलिये जहां समानीकरण हुआ है, वहां सर्वे करवाया जाये। उस स्कूल से बड़े स्कूल की दूरी कितनी है, इसका सर्वे कराया जाये ताकि उन लड़कों की पढ़ाई चालू रहे, ऐसा मेरा आग्रह है। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री गोरधन जी (अनुपस्थित) माननीय सदस्य, छोटू सिंहजी (अनुपस्थित) माननीय सदस्य श्री गोपाल कृष्ण जी। (व्यवधान) प्लीज आप विराजें। अंकन नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: गोपाल कृष्ण जी बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति की चर्चा में अपने आपको ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य देने दें। गोपाल जोशी जी, आप बोलिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): डोटासरा जी, मेरा आब्जेक्शन है। मैं तो कभी आपके बीच में बोलता ही नहीं हूं।

श्री सभापति: हां, बोलें-बोलें, नहीं बोलेंगे यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मेरा निवेदन यह है कि मैं बोलूं तब तक तो यह बात नहीं उठाएं, बाद में उठा लेना, जो भी उठाना है। मेरे को तो बोलने दो, मैं तो थोड़ा-सा बोलूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और न ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बीच में बोलोगे। सभापतिजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा के लिये बोलने का अवसर दिया। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिस पर कुछ भी बोला जा सकता है। शिक्षा विकास का पर्याय है और इस शिक्षा के पर्याय में ऐसी बातें कही जा सकती हैं कि बिना शिक्षा के दुनिया के अन्दर कुछ हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी शिक्षित नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। कुछ भी नहीं है।

राजस्थान का जब गठन हुआ था तब कुछ समझौते हुए थे आपस में, कि जयपुर राजधानी रहेगी राजस्थान की और राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर

(श्री गोपाल कृष्ण)

में रहेगा। शिक्षा का पूर्ण रूप से बीकानेर के अन्दर, प्राइमरी, सैकण्डरी, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और सभी तरह की शिक्षा बीकानेर में रहेंगे और उसका निदेशालय था, जो इन सभी को कन्ट्रोल करता था। एक निदेशक वहां पर इसी काम के लिए था और वह सारे के सारे शिक्षा के विभाग वहां पर थे। लेकिन धीरे-धीरे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बीकानेर को इस तरह से कमजोर किया गया कि सारे के सारे विभाग, प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक एजुकेशन के अलावा यहां से हटा दिये गये और नये अगर शिक्षा के सम्बन्ध में कोई विभाग बनते हैं तो वो भी जयपुर के अन्दर कर दिये गये। भीड़ के अन्दर और भीड़। जयपुर में तो यूं ही बहुत भीड़ हो रही है। पापुलेशन की भीड़ हो रही है। जगह नहीं है। गाड़ियों को चलने की जगह नहीं है। आफिस के लिए जगह नहीं है। आदमी समाते नहीं हैं और इतने आफिसेज हो गये कि यहां पर और ज्यादा भीड़ कर दी गई। हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, बीकानेर के साथ। पता नहीं कब तक करेंगे। रमसा वगैरह का भी आफिस यहीं पर कर दिया।

माननीय मंत्रीजी अभी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ बातें कही थीं। मैं उनको बताऊंगा। मैं यह समझता हूं कि प्राइमरी शिक्षा यदि सॉलिड नहीं है तो निश्चित रूप से सॉलिड अगर कोई लड़का नहीं होगा, उसको दो, चार, पांच, सात, आठ का गुणा भी नहीं आयेगा तो आठवीं तक पास करने की जो बात थी, वह ठीक नहीं थी और नैचुरली लड़कों की शिक्षा पूर्ण नहीं होने के कारण से लोग कमजोर रहते हैं। इसलिए प्राइमरी शिक्षा पर बहुत जोर देना चाहिए। मैं अपनी सीधी बात पर आता हूं। मंत्रीजी नहीं हैं। मंत्रीजी नहीं हैं। मंत्रीजी ने एक वादा किया था।

श्री सभापति: आप फर्माओ, मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): सुन रहे हैं?

श्री सभापति: हां। मान लें। अपने आप पहुंच जायेगी बात।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अच्छा। आप सुन रहे हैं, लेकिन आप कहोगे या नहीं कहोगे, मुझे इसका पता नहीं है।

श्री सभापति: कहेंगे।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप कैसे कहोगे। Any Way. आपने कह दिया। मुझे संतोष है इस बात का।

प्राइमरी शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर के लिए हमने आपसे कहा था कि बीकानेर के अन्दर ले आएं। मंत्री महोदय ने हमको वादा किया था कि आपका प्राइमरी का डिप्टी डायरेक्टर बीकानेर आ जायेगा। अब लोग मेरे को गाना सुनाते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। वादा हैं, वादों का क्या, वायदे तो वायदे हैं। इसलिए ये सारे गाने हमको सुनने पड़ते हैं और प्राइमरी का डिप्टी डायरेक्टर बीकानेर नहीं आया। ठीक है, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं लेकिन छोटी सी क्लेरीकल मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको भी मंत्रीजी ठीक करें तो करें, वहां के निदेशालय के लोग नहीं करते हैं। टाइपिंग की मिस्टेक को भी यहां पर आकर ठीक करवाना पड़ता है इसलिए ये छोटी-छोटी बातों के लिए बीकानेर निदेशालय होने के कारण आईएएस, डायरेक्टर वहां पर रहता है। उसके बावजूद भी नहीं होता।

प्रतिबन्धित जिलों की बात कहते हैं ट्रांसफर के लिए, कि प्रतिबन्धित जिलों से ट्रांसफर नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि आप कितने साल तक प्रतिबन्धित जिले के अन्दर उसको रखोगे? कितने वर्षों के बाद में उसका वहां से ट्रांसफर कर दोगे? कम से कम यह खुलासा कर दें। उतने साल तक हम रिकमण्डेशन नहीं करेंगे वर्ना रिकमण्डेशन करें तो कितने साल बाद करें। कम से कम इस बात का स्पष्टीकरण आप कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए पाजिटिव बात रहेगी।

सभापति महोदय, निवेदन यह है कि लिटरेट और एजुकेशन, अब कोई आदमी सिर्फ पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं होता है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। Now there is a difference between literate and educated. लिटरेट और एजुकेटेड के अन्दर बहुत डिफरेंस होता है। हम सिर्फ उसको किताबी ज्ञान दे दें और उसके बाद में अगर वह शिक्षित नहीं हुआ और उसको समझा नहीं, सिर्फ पढ़ ही लिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है।

कन्फ्यूसियस एक चाइनीज फिलॉस्फर थे। कहते हैं कि 'The essence of knowledge is, having it, to apply it.' अगर आप एप्लाई ही नहीं कर सकते हो तो विद्या क्या? विद्वान वह है जो विद्या का उपयोग कर सके। हम अगर ऐसी शिक्षा नहीं दें, विद्या का उपयोग अगर नहीं कर सकें तो

(श्री गोपाल कृष्ण)

उस विद्या का क्या करें। तो सिर्फ लिटरेट होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को प्राइमरी से सॉलिड शिक्षा दें तो ही हम बाद में ऊपर का बोझ, जब ज्यादा काम्प्लीकेटेड इश्यु को पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी सोच है कि असेन्शियल होना चाहिए।

आपने कुछ विषय वस्तु के अन्दर चेन्ज किया है, हिस्ट्री में चेन्ज किया। मैं यह समझता हूं कि पहले जैसे अकबर महान लिखते थे, अकबर महान लिखने की जगह पर महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति, कहते हैं कि हारी हुई बाजी जीते, वह सिक्न्दर। मैंने कहा कि हारी हुई बाजी जो जीते वह महाराणा प्रताप।

श्री सभापति: हां।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): वह हारी हुई बाजी जीतता है और वह जीतता भी किसके बल पर। एक बात मैं बताता हूं। जब अकबर के सामने सरेण्डर का एक संदेश गया तो उनके यहां पर पृथ्वीराज सिंहजी एक बीकानेर के थे जो बहुत बड़े कवि भी थे तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अगर चाहो तो मैं पूछ लेता हूं, मुझे तो यह लगता नहीं है कि उनका कहा हुआ है। बाद में उन्होंने एक कविता लिखी। कविता लिखी तो लिखी क्या, वह लिखते हैं:-:-

'पटकूं मूछां पाण के पटकूं निज जन करद
दीजे लिख दीवाण,
इण दो महली बात इक।'

इन दोनों के बीच में से एक बात लिख दीजिए कि 'पटकूं मूछां पाण, या पटकूं निस्तन करां।'

फिर महाराणा ने भी क्या लिखा। महाराणा ने लिखा:-

'तुरक कहां सो मुख पतौ, इण तन सूं इकलिंग'

इस मुख से तो एकलिंग ही बोला जायेगा, तुरक नहीं बोला जायेगा। यह देख लिया।

'ऊगै जांही ऊगसी, प्राची बीच पतंग'

जठै सूरज ऊगै, वठै ही ऊगसी। पूरब में ही ऊगसी। दूसरी जगह कौनी ऊगै। इन चीजों को अगर अब हिस्ट्री में लिखो, यह देखो कि सिकन्दर कौन है? महाराणा प्रताप जो हारी हुई बाजी को जीत गया। यह कहावत उसके अन्दर शामिल होनी चाहिए। जो हारी हुई बाजी को जीतता है, वह महाराणा

(श्री गोपाल कृष्ण)

प्रताप। जो हारी हुई बाजी को जीत जाता है, वह शिवाजी। शिवाजी के बारे में भी जिस ढंग से उन्होंने लिखा है, पहाड़ी जानवर है, कोई उस ढंग का आदमी है। शिवाजी इतने हिम्मत वाले, होशियार और ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इसको शिक्षा में मानें, कला में मानें या संस्कृति में मानें? कहां मानें।

श्री सभापति: विराजें प्लीज। नो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, मेरे जो जचेगा, वही बात कहूंगा। आपके जो जचेगी, वह बात तो मैं कहूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कंक्लूड करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मेरे को तो कहने दो। जो बात मेरे जचती है, वही कहूंगा। दूसरी बात नहीं कहूंगा। कहूंगा वही जो मेरे जचेगी। मेरा मतलब है कि हिस्ट्री के अन्दर अपने ही वीरों की जिस ढंग से उन्होंने दुर्दशा की है, तो दुर्दशा को तो हटाना ही चाहिए और वीरता का सही बखान होना चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मेरी सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात इसमें नहीं कहता मैं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी के लिए धन्यवाद देता हूं कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपने कानूनी रूप से तो खोल दी लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं किया। न कोई आफिस, न कोई स्टाफ, न कोई सैंक्शन, न वीसी, यह कब तक होगा? लोग फिर वही पूछते हैं। यह वायदे हैं, वायदों का क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको जल्दी से जल्दी महीने भर के अन्दर कुछ कर देंगे तो हमारा सुनना बन्द हो जाएगा।

मैं तो यही कहता हूं। तो आप अगर यह कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जायेगी। आपने बहुत अच्छा किया कि उसका विधेयक तो पास करवा दिया, पक्का काम तो हो गया इसमें कोई संदेह नहीं है, वी.सी. वगैरह का और सबका इंतजाम आप कर दें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बार-बार एक बात 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' की बात जब अपन करते हैं तो बीकानेर पश्चिम के अन्दर एक महिला महाविद्यालय खोलने की मैं कहता हूं। बीकानेर पश्चिम में नहीं है, है तो एक प्राइवेट है जो वहां उस ढंग से होती है, वहां लोगबाग प्रिजुडिस हैं और इसलिए अगर वहां पर ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): साहब, थोड़ा-सा है, मैं कभी-कभी बोलता हूं, मेरे को दो-चार मिनट दें।

श्री सभापति: नहीं। पर आपको उसका फायदा मिल चुका है। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं प्राइमरी की बात भी कहता हूं।

श्री सभापति: सभी कायदे की बात कहते हैं अपनी-अपनी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): कोई बात नहीं, साहब, मैं इसको शोर्ट कर देता हूं। ऐसी तो कोई बात नहीं है।

दूसरा यह है कि वहां पर एक प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड का गठन माध्यमिक के अन्दर करना है तो उसको बीकानेर में कराएं। एक तो यह है। दूसरा यह है कि 'रमसा' के बजट में खेल के मैदानों का भी विकास किया जाना चाहिए। एक यह है कि वाल क्लाइंबिंग का बड़ा होता है, एक हमारे यहां मगन बिस्सा नाम से एक व्यक्ति है जो एवरेस्ट की चोटी पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): साहब, एक मिनट।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य, श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): धन्यवाद। आपने मेरे को समय दिया उसके लिए थैंक यू।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, शिक्षा, कला, संस्कृति मांग संख्या 24 पर आज बहस है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, काफी बहस हुई और यह बहस इस विधान सभा के परिसर तक सीमित नहीं है, यह बहुत लार्जर बहस है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य में अक्षय शक्ति है, अनन्त शक्ति है और मनुष्य में जो अक्षय और अनन्त शक्ति है उसको प्रस्फुटित करने का माध्यम शिक्षा है। शिक्षा से हम इन्सान को इन्सान बनाते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और अनपढ़, शिक्षित तो हमारे ग्रामीणों में बहुत हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके फर्क को तो आप समझ सकते हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

शिक्षा और इतिहास, कहा गया है कि 1193 से पहले तो हिन्दुस्तान था और 1193 के बाद में एक लुटेरा हिन्दुस्तान बन गया, निश्चित रूप से बन गया। हम हारे, मुगल आये, तुगलक आये, हम हारे। हमारी हार के कारणों में जाने का माध्यम भी शिक्षा ही होगा। हम क्यों हारे? क्या हम वर्ण व्यवस्था के कारण हारे या वर्ण व्यवस्था हमारी हार का कारण नहीं थी? हमारे पास शास्त्र तो बहुत थे पर क्या हम शस्त्रों की कमजोरी से हारे? क्या तलवार तोप का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए हारे? यह बहुत लार्जर विषय है जिस पर देश में चर्चा हो रही है, देश में चर्चा होगी, पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। मैं बहुत लम्बी बात में इस सदन का समय नहीं लेना चाहता।

सभापति जी, राजस्थान में शिक्षा निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी जब सन् 2008 में थीं, आज तो 2018 है, 2008 में उन्होंने पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षा के कोई चार-साढ़े चार हजार केन्द्र खोले। एक साथ 2008 में क्रमोन्नत हुई, साढ़े चार हजार स्कूलें माध्यमिक हुई। सवाल यह उठता है कि उससे पहले क्यों नहीं हुई? पहले न होना और 2008 में माध्यमिक बनना, यह ऐतिहासिक महत्व की बात है। 2008 में जो माध्यमिक बनीं वो अब इस शासन में उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हो गयीं, उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हो गयीं। निश्चित रूप से शिक्षा का कदम युवकों को शिक्षा देने का, बालकों को बालिकाओं को शिक्षा देने का कदम आगे बढ़ा और मील के पत्थर की तरह वो कदम है।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी की जो प्रगति रिपोर्ट आयी उसमें लिखा है कि 800 स्कूलों में हमने इतना बजट दिया और इसलिए उसको आदर्श उच्च माध्यमिक कह दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पिछली साल 850 कर दिये, इस साल 1100 कुछ कर रहे हैं पर किसी स्कूल में जहां कमरों की कमी है, उसके भवन से ही क्या स्कूल आदर्श हो जाएगा? माननीय सभापति जी, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आदर्श स्कूल को सिर्फ भवन से न जोड़ें, आदर्श स्कूल में वो जो कमी है, कक्षाओं की कमी है, कक्षा कक्षों की कमी है, उसको पूरा करना राज्य सरकार का दायित्व है, 'रमसा' का दायित्व है और 'रमसा' का कार्यक्रम चल रहा है। आप सिर्फ इस आधार पर स्कूलों को आदर्श स्कूल न कहें। आदर्श स्कूल उसको कहें जहां आप कला के साथ विज्ञान भी खोल दें, व्यापार की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्लासें भी खोल दें, जहां तीनों फैकल्टीज पढ़ने का, तीनों विषय पढ़ने का अवसर हो। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको देखें कि आदर्श विद्‌यालय उसी को कहा जा सकेगा हकीकत में जहां विज्ञान भी है, व्यापार भी है और कला भी है। खाली भवन बनाने से आप जो उसको आदर्श कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह न तो उचित है, यह आदर्श शब्द का कुल मिलाकर सही उपयोग नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

सभापति जी, मेरा जिला बीकानेर है। अभी बीकानेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने तकनीकी विश्वविद्‌यालय की बात उठाई है। हम लोग दो-तीन साल से, तकनीकी विश्वविद्‌यालय का मुद्दा सन् 2015 से उठा रहे हैं। वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद है कि उन्होंने टैक्निकल यूनिवर्सिटी का विधेयक, उसको अधिनियम बना दिया। उसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर तो 2018 में चुनाव है, माननीया मुख्य मंत्रीजी की तकनीकी विश्वविद्‌यालय की घोषणा यह बजट में है और उसको मूर्त रूप देने का दायित्व आपका है कि आने वाले सैशन में तकनीकी विश्वविद्‌यालय खुले। सभापति जी, हमारे दो इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, बीकानेर इंजीरियरिंग कालेज एण्ड कालेज फार टैक्निकल एजुकेशन। इन दोनों महाविद्‌यालयों को, मैंने पहले भी निवेदन और आज भी कह रहा हूं, इनको आप संघटक कालेजेज, कांस्टिट्‌युएंट कालेजेज की श्रेणी दें क्योंकि ये कालेजेज वर्षों से चल रहे हैं, इनके पास सब भवन हैं, कम्प्यूटर्स हैं, लैब है और जो भी एक अभियांत्रिकी महाविद्‌यालय के लिए चाहिए वो सारे साधन हैं, विद्‌यार्थियों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए इनको शीघ्र से शीघ्र संघटक कालेज घोषित करें और तकनीकी विश्वविद्‌यालय के लिए आप हमारे वाइस चांसलर और जो भी पैराफर्नेलिया है, उसकी शीघ्र नियुक्ति करने की घोषणा करें। चाहे नियुक्ति इंटरिम हो लेकिन एक बार नियुक्ति होनी चाहिए ताकि तकनीकी विश्वविद्‌यालय का जो स्वरूप है वो स्वरूप बिलकुल बने।

इसके द्‌वारा मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, सभापति जी, कि इंजीनियरिंग कालेज की शिक्षा को कम खर्चीला बनाइये। आज बीकानेर में 80, 90 हजार रुपये एक विद्‌यार्थी के इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने में लगते हैं, अंदाजा करिये कि एक मध्यम श्रेणी का आदमी 80, 90 हजार रुपये और यह बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज फार टैक्निकल एजुकेशन, ये राजकीय महाविद्‌यालय नहीं हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सोसाइटीज के ग्रुप में ये संस्थाएं चल रही हैं और ये self-financing के तौर पर 80, 90 हजार फीस ले रही हैं, जबकि अन्य Engineering Colleges में फीसों की तादाद हमारे से आधी है, 30, 40, 45 हजार के बीच में है, इसलिए ये जो फीस का बहुत बड़ा अंतर Bikaner College for Technical Education और राजस्थान के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में है, उसको भी दूर करने की सख्त आवश्यकता है, उस पर शीघ्र विचार करने की जरूरत है।

सभापति जी, हम एक तरफ विश्वविद्यालय खोल रहे हैं कौशल विकास का। कौशल विकास, Polytechnic, ITI, Engineering College, Technical College यह एक श्रेणी है। यदि हमें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है और राजस्थान में अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ पैदा करने हैं तो निश्चित रूप से आपको हमारी अभियांत्रिकी शिक्षा को सस्ता करना पड़ेगा और एक कड़ी के तौर पर जोड़ना पड़ेगा कि Polytechnic, ITI, फिर अभियांत्रिकी महाविद्यालय और फिर तकनीकी विश्वविद्यालय। यदि हमें राजस्थान में...आपके ध्यान में होगा कि राजस्थान में मात्र कौशल विकास के द्वारा, सरकार ने माना है, राज्यपाल महोदय ने माना है कि 2 लाख 15 हजार लोग ही प्रशिक्षित किए थे। यदि हमें ज्ञानवान लोगों को प्रशिक्षित करना है, उच्च शिक्षा देनी है तो निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, मैं सिर्फ एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 13 दिसम्बर को घोषणा की थी कि अब राजस्थान में नियुक्ति की उम्र 35 नहीं 40 होगी। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, सभापति जी। मुझे दु:ख इस बात का है कि 13 दिसम्बर की घोषणा के बाद जो 3 विज्ञप्तियां लोगों को रोजगार देने के लिए निकलीं, उन तीनों विज्ञप्तियों में उम्र 40 नहीं 35 है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): Shame! Shame!

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीया उच्च शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी दोनों नोट करें, क्योंकि यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी की है कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक LCUT 571 पद की विज्ञप्ति जारी की और विज्ञप्ति मेरे पास है, जिसमें 35 साल की उम्र है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संगणक की राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है 400 पदों के लिए और इसमें भी उम्र 35 है। अभी तक भर्ती की तारीख खतम नहीं हुई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने 2100 पद विज्ञापित किए हैं, उम्र आज भी 35 है।

मैं निवेदन करूंगा कि इन तीनों विज्ञप्तियों की तारीखें अभी बाकी हैं, राज्य सरकार तत्काल मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार नई घोषणाएं जारी करे और 40 वर्ष की उम्र तक के सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, 2 मिनट।

श्री सभापति: Please, Please. समय की मर्यादा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप चाहें तो...अन्यथा कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, उससे भी अधिक समय आपको मिल चुका है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या अनीता जी।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): मेरा ही है न।

श्री सभापति: हां, अनिता जी कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करती हूं। प्रदेश को मजबूत करना है तो युवाओं को संस्कारवान शिक्षा देकर प्रदेश को मजबूती दे सकते हैं। ये अगर किसी ने समझा तो हमारी सरकार ने समझा। उसके लिए मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देती हूं। मैं उस जिले से आती हूं, जिस जिले में गुरु-शिष्य का पाठ पढ़ाने वाली कालीबाई कलासुआ पैदा हुईं, गुरु की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाली, 1947 की बात है, मैं उस जिले से आती हूं और मैं अपने आपको इसके लिए गौरवान्वित महसूस करती हूं, पर जब-जब हमारे विपक्षी भाइयों का

(श्रीमती अनिता कटारा)

कार्यकाल देखें तो बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इतना लंबा उन्होंने राज किया और उस राज का उनका मूल मंत्र यही था कि हर व्यक्ति अनपढ़ रहना चाहिए और अनपढ़ व्यक्ति ही हमको मजबूती के साथ जिता सकता है। यह विपक्षी भाइयों का मूल मंत्र है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा बोलती हैं।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): यह मैं मानती हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जिस जिले से आती हूं, अभी माननीय सदस्य अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि डूंगरपुर जिले को इन विपक्षी भाइयों ने पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया। वह बहुत लंबा काल हो गया। आज भी अगर हमारे डूंगरपुर जिले में जाकर देखो तो हर घर में 2 से 3 व्यक्ति अनपढ़ मिल जाएंगे। जो मैंने विपक्षी भाइयों के लिए बोला, वह पूरा-पूरा इन पर सार्थक है कि नहीं, वह तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, पूर्ण साक्षर जिला घोषित करने के बाद भी इनके मन में संतुष्टि नहीं हुई और 1 से लगाकर 8 तक के बालक-बालिकाओं को बिना फेल करे पास कर दो, ताकि जो अनपढ़ हैं, वे अनपढ़ ही बने रहें। पता नहीं पड़े कि कौन-से बालक-बालिका ने 'अ', 'आ' सीखा है कि नहीं सीखा है, 1 से 10 तक अंक उसको आते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब देखने वाला कोई रहे ही नहीं।

यह उनकी रणनीति हुआ करती है, पर जब-जब हमारी सरकार आई, हमारे दोनों ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय वासुदेव जी और हमारी उच्च शिक्षा मंत्री महोदया आदरणीय किरण जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो किया ही है, साथ ही साथ, जब-जब सरकारें बदलती हैं तो कर्मचारी तनाव में रहकर अपना कार्य करते हैं, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस पर अमल किया और इन्होंने सोचा कि जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, वे बिल्कुल तनाव-मुक्त होकर अपना कार्य करें, अपनी नौकरी करें और उसके लिए इन्होंने प्रमोशन की नीति बनाई, ट्रांसफर की नीति बनाई ताकि कहीं पर भी राजनीति न हो और जो नौकरी कर रहा है, वह बिल्कुल तनाव-मुक्त होकर करे।

अगर यह सब किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। यह मैं एक बार नहीं बार-बार कहना चाहूंगी और सभी को उसके लिए, हमने पूर्व में क्या गलती की, वह माननी चाहिए विपक्षी भाइयों को और अब जो-जो भी सकारात्मक हो रहा है, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सहयोग के लिए तैयार हैं।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): मैं मानती हूं कि हर ग्राम पंचायत में हमारे विद्यालय क्रमोन्नत करने का जो कार्य किया है हमारी मुख्य मंत्री महोदया, हमारे मंत्रीजी ने, वह किसी और के बस का रोग नहीं था। क्योंकि एक विद्यालय क्रमोन्नत करवाने का नाम आता था तो गाड़ियां भर-भर कर जयपुर में आते थे, यह हमारी आंखों से हमने देखा हुआ है। वापस उसका रिजल्ट कब मिलेगा यह किसी को पता नहीं था पर हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने, हमारी सरकार ने इस प्रकार से बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर ग्राम पंचायत पर विद्यालय क्रमोन्नत करने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो सरकार काम करती है उसके लिए हर कोई मांगना चाहेगा, बार-बार मांगना चाहेगा और उस पिछड़े हुए डूंगरपुर जिले से आने के बाद जो समस्याएं देखो तो जितनी भी पूरी करो उसके बाद में भी लम्बे-लम्बे, बड़े-बड़े पुराने वक्त के खड्डे पड़े हुए हैं उनको भरने में अभी काफी समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि मेरे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नोकना को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश फर्माएं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तलैया को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश फर्माएं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खोखरा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश करें, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पानतलाई को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश करें। ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं।

सागवाड़ा के महाविद्यालय में सभी पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से रिक्वैस्ट करती हूं कि जल्द से जल्द व्याख्याताओं के पद भरे जाएं।

पूरे सागवाड़ा में कई संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें उच्च माध्यमिक भी हैं, प्राथमिक भी हैं और सभी विद्यालय संस्कृत के चल रहे हैं। बारहवीं की पढ़ाई करने के बाद में जो बालक-बालिकाएं विचार करते हैं कि हम आगे संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं पर कालेज, महाविद्यालय की पढ़ाई कहां करें, ऐसे बालक-बालिकाओं के मन में बहुत सारी इस प्रकार की धारणा रहती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से रिक्वैस्ट करती हूं कि सागवाड़ा में संस्कृत

(श्रीमती अनिता कटारा)

महाविद्यालय खोलने का आदेश फर्माएं। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्याशंकर जी नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में कई माननीय सदस्यों द्वारा आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में रखे जो हमारी शिक्षा नीति के लिए या शिक्षा नीति में बदलाव के लिए अपना स्थान रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा नीति हमारी बनी हुई है, यह एक भेदभावपूर्ण शिक्षा नीति बनी हुई है। उच्च वर्ग के लोगों के लिए या उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए अलग से शिक्षा नीति जिसे हम कान्वेंट स्कूल कह सकते हैं, निम्न और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए वो शिक्षा नीति जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार या राज्यों के माध्यम से संचालित है और गरीब वर्ग के लोग जिस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा नीति के माध्यम से समाज में जो स्थान उन्हें बनाना चाहिए वो स्थान नहीं बना पाते। हम लगातार देख रहे हैं कि जहां उच्च शिक्षा के लिए अपना स्थान बनाने की आवश्यकता होती है तो जो कान्वेंट स्कूलों से बच्चे निकलते हैं वो अपना स्थान उस स्थान पर तुरन्त ही बना पाते हैं लेकिन जो सामान्य विद्यालयों से निकले हुए बच्चे, जिन्होंने यदि ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के बाद भी यदि वो सामान्य जीवन जीते हैं तो समाज में अपनी कोई अलग पहचान नहीं बना पाते। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूं और मैं गांवों में यह बात देखता हूं कि जो बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसके बाद वो जब सामान्य गांव का जीवन जीते हैं तो गांव का जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी सामान्य रूप से रहकर अपने जीवन को जीता है और उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता। यदि वो खेती करता है या व्यवसाय करता है तो उसके व्यवसाय करने की जो परम्परा रही है, उसके पूर्वज जिस प्रकार से जो व्यवसाय करते आ रहे हैं उसी स्वरूप

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

में वो अपने आपको जोड़ लेता है। यदि कृषि कार्य या अन्य कार्य करता है तो वो अपने जीवन को भी उसी रूप से जोड़ लेता है।

आज आवश्यकता है कि शिक्षा नीति में जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई बेरोजगारी के बाद हम यदि हमारी शिक्षा नीति की बात करें तो हमें महसूस होता है कि बच्चे के अन्दर जो टेलेंट होने की आवश्यकता है या अलग से प्रतिभा जुड़ने की आवश्यकता है तो उसके लिए हम उसको या तो आईटीआई की बात करेंगे या उसको कहीं पोलीटैक्निक कालेज या इंजीनियरिंग कालेज के माध्यम से जोड़ने की बात करेंगे। यदि हमारी शिक्षा नीति में शुरू से ही ये सारी व्यवस्थाएं होतीं, हमारी शिक्षा नीति में इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई होती कि बच्चे के अन्दर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुरूप ही वो अपना सब्जैक्ट चयन करे और जीवन-यापन के लिए आगे बढ़ता चला जाए तो यदि यह व्यवस्था की हुई होती तो आज यह जो बेरोजगारी की समस्या पूरे राष्ट्र में बनी हुई है यह हम कहीं न कहीं कम महसूस करते।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व आज इसी सदन में कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक महोदय द्वारा गुरुकुल व्यवस्था पर काफी प्रकाश डाला गया या मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर काफी प्रकाश डाला गया। आज हम आजादी के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी यह महसूस कर रहे हैं कि इस देश में यदि गुरुकुल शिक्षा पद्धति जैसी व्यवस्था होती तो जिस प्रकार का निर्माण बालक का गुरुकुल के माध्यम से होता था और उसके बाद वो स्वावलम्बी बनने की बात करता था या स्वावलम्बी बन जाता था, आज उसके विपरीत इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चा अपने आपको असहाय महसूस करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आजाद हिन्दुस्तान या इससे पूर्व की व्यवस्था कान्वेंट स्कूल की ओर दिलाना चाहूंगा कि एक साधारण से व्यक्ति द्वारा....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो कचहरी हाउस हो गया है। एक भी माननीय सदस्य, मंत्री तक भी सीरियसली आराम से माननीय सदस्यों को नहीं सुन रहे हैं। आप डिस्कस कर रहे हो दोनों मंत्री तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह आप चैम्बर में कर आओ लेकिन कम से कम हाउस की गरिमा तो बनाये रखो।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आपकी आदत हो गई क्या यह? विराजो।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): आप तो सुन रहो हो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो सुन रहे हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आपका यह जो बोलना है न, ये अफसर यहां से सुनकर जाते हैं और वैसा ही फिर आपके साथ ट्रीटमेंट करते हैं।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इन कान्वेंट स्कूलों को जितना बड़ा भू-भाग या जितनी बड़ी सम्पदा इनको आबंटित की गई और वो बहुत ही नोर्मल चार्ज पर की गई। एक माननीय सदस्य द्वारा लोक सभा में एक प्रश्न लगाकर यह जानकारी चाही गई थी कि आजाद हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा भू-भाग किसके पास है तो उसकी जानकारी में यह आया कि इस देश में सबसे बड़ा भू-भाग या सबसे ज्यादा मूल्यवान जमीन इस देश के कान्वेंट स्कूलों के पास है। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी सब लोगों की छत्र-छाया में ये कान्वेंट स्कूल फलते-फूलते आए हैं और आज भी फलते-फूलते जा रहे हैं। एक सामान्य अनुमान के आधार पर मैं यह बताना चाहूंगा कि इस देश के जितने भी कान्वेंट स्कूल हैं, जो एक व्यवस्था के निमित्त इस देश में चल रहे हैं, एक धर्म आधारित व्यवस्था के रूप में स्कूल चल रहे हैं और वो एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपया डोनेशन और फीस के रूप में अर्जित करते हैं।

इस व्यवस्था से अर्जित धन का उपयोग वे इस देश में या अन्य गरीब राष्ट्रों में धर्म परिवर्तन या अन्य अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए उपयोग में लिया करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि इस व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगे और इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था प्रारम्भ की जाये कि समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होता जा रहा है, उस भेदभाव को कहीं न कहीं हम रोकने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 2014 में, इससे पूर्ववर्ती सरकार के समय जो हमारे राजस्थान प्रदेश की शिक्षण व्यवस्थाएं थीं, उस शिक्षण व्यवस्था का एक छोटा सा नमूना मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

बताना चाहूंगा। 2014 में जब नोडल विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक में भाग लेने का अवसर मुझे मिला और जब मैंने परिचय करना चाहा तो वहां लगभग 80 प्रतिशत प्रधानाचार्य कार्यवाहक थे। इसके विपरीत वर्तमान माननीया मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के प्रयासों में आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो गई है।

इसके अतिरिक्त जहां हम रिजल्ट की बात करें तो आज हम प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़कर वर्तमान में ऐसी स्थिति में हैं कि विगत दो वर्ष में मेरे ही क्षेत्र में 34 सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों ने शत-प्रतिशत परिणाम देकर प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल लुभावने वादे करके लोगों के बीच में काम कर रहे थे, उन पर एक विराम-सा लगा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक विषय आपकी जानकारी में और लाना चाहूंगा। विगत वर्षों में हमारे यहां अलग-अलग सब्जैक्ट्स खुले, उन सब्जैक्ट्स में कई जगह सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जिनकी आवश्यकता थी, उसके विपरीत दिशा में सब्जैक्ट्स खोले गये और जहां हमारी आवश्यकता थी, जिस आवश्यकता के अनुसार हमने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया, उस पर विचार होना चाहिए कि जहां जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता है, उसी के अनुरूप विषय खोले जाएं।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दोनों उपखण्ड क्षेत्र में कहीं भी महाविद्यालय नहीं है और जिले का एक दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण, जो शिक्षा में पूरे जिले में अग्रणी होने के बाद भी वहां महाविद्यालय नहीं है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरे इटावा में महाविद्यालय खोलने का आप आज ही इस बजट के माध्यम से, अपनी मांगों के माध्यम से हमारी मांग को पूरी करने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य रामहेत सिंहजी यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। इस वित्तीय वर्ष के बजट में मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने मेरे किशनगढ़बास के कृपाल नगर में एक राजकीय महाविद्यालय दिया। मैं आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी महोदया का और माननीया मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से आभारी हूं।

राजस्थान में जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज आता है, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो जाता है। माननीय भैरोंसिंहजी के समय में जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि प्राइमरी से मिडिल किये और 1990 से 1993 तक जब माननीय भैरोंसिंहजी वापस आये, तो हर पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल किये और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री का जब 2003 से 2008 तक राज था, तो हर पंचायत मुख्यालय पर कोशिश की कि वहां पर सैकण्डरी स्कूल हो और अब की बार राज आने के बाद हर पंचायत मुख्यालय को सीनियर स्कूल में जोड़ने का काम किया ताकि गरीब का बालक भी अपने गांव में ही, अपने घर की रोटी खाकर, वहीं अपने घर में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करे। इसमें राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक कांग्रेस का राज होता था, एक-एक स्कूल के लिए सैक्रेटेरिएट और मंत्रियों के कई-कई दिन और कई-कई महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता था। तब देखा जाता था कि यहां कौन विधायक कांग्रेस का है, कौन विधायक बीजेपी का है, उस आधार पर, राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जाते थे लेकिन आज शिक्षा को राजनीति से दूर रखा और उसी का परिणाम है माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक आदेश से सब पंचायत मुख्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय कर दिया और बजट में भी लगभग 1,600 के आसपास जो रह गये थे, उनको भी खोलने की घोषणा की है। इससे हमारे राजस्थान की विशेषकर बालिका शिक्षा पर, हमारे जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो पिछड़ापन था, वह दूर होगा। आने वाले समय में राजनीति को शिक्षा से अलग किया है।

राजस्थान में एक लाख से अधिक पदों पर काउंसलिंग के माध्यम से जब प्रमोशन हुआ तो उससे पूछा कि कहां आपकी जगह है, बता दीजिये और उस काउंसलिंग के माध्यम से कौन कहां का है, क्या है उसकी प्रायोरिटी? वह स्वयं प्रार्थी की प्रायोरिटी के आधार पर काउंसलिंग करके राजस्थान की सरकार ने राजनीति को शिक्षा क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया है। यह सराहनीय कदम है। इसमें कुछ लोगों को इस बात की परेशानी हो सकती है कि मेरा

(श्री रामहेत सिंह यादव)

व्यक्ति दूर गया, मेरे परिवार का व्यक्ति दूर गया लेकिन "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व" के आधार पर जो निर्णय राजस्थान सरकार का रहा, उसकी जितनी तारीफ की जाये, कम है।

वैसे तो बहुत सारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें कह दीं, मैं तो दो-तीन समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। माननीया उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी अनुशंसा पर मुझे मेरे उपखण्ड पर एक राजकीय महाविद्यालय मिला लेकिन मेरे कोटकासिम उपखण्ड मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय है, जो डिग्री तक तो राजकीय बजट से है और आचार्य प्रथम और आचार्य द्वितीय वर्ष जो पीजी की क्लास होती है संस्कृत में, वह स्ववित्त पोषित है और जिस दानदाता के सहयोग से वह सब्जैक्ट चलता था, उनका देहावसान होने के बाद वह एड मिल नहीं पा रही और उस महाविद्यालय को बहुत कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए वहां विशेषकर बालिका शिक्षा के मामले में उस कालेज की आवश्यकता है और संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी और उस महाविद्यालय ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। अलवर मुख्यालय के बाद कोटकासिम में ही संस्कृत पीजी महाविद्यालय है। आपने 56 सब्जैक्ट्स को जो स्ववित्त पोषित थे, पांच वर्ष से अधिक जो स्ववित्त पोषित बजट से चल रहे थे, उनको राजकीय बजट से किया है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस संस्कृत महाविद्यालय के पीजी आचार्य प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष है, जो स्ववित्त पोषित है, उसको भी आप राजकीय बजट से बनाने की घोषणा करेंगे।

एक शिक्षा विभाग ने तो पंचायत मुख्यालय पर जो स्कूल थे, उनको क्रमोन्नत कर दिया लेकिन लाडपुर में, जो पंचायत मुख्यालय है, वहां पर संस्कृत का दसवीं तक का स्कूल है। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी सीनियर सैकण्डरी स्तर तक करें ताकि वहां के बालकों को संस्कृत पढ़ने का मौका मिले।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपके विभाग ने यह तो तय किया है कि हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर माध्यमिक स्कूल खुले, लेकिन जिस पंचायत में पहले से ही सीनियर माध्यमिक विद्यालय है और पंचायत मुख्यालय से चार किलोमीटर-पांच किलोमीटर दूरी पर है तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी जगह

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जो पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल है, जैसे मेरे यहां गुणसार में है, पाटन मेवान में है। ये दोनों पंचायत मुख्यालय हैं लेकिन दोनों जगह सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। गुणसार में तो भोजराजका में है, वह वहां से कम से कम पांच किलोमीटर दूर पड़ता है तो पंचायत मुख्यालय का आप इसमें ध्यान रखकर गुणसार को भी करेंगे।

इसी तरह से उजोली पंचायत में आकोली गांव है जो पांच किलोमीटर दूर है, हरियाणा बोर्डर पर है और अच्छा स्कूल है, इसलिए उसमें भी सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी करेंगे।

मेरे किशनगढ़बास सीनियर माध्यमिक विद्यालय में स्ववित्तपोषित ज्योग्राफी का सब्जैक्ट है, मैं चाहूंगा आप उसको भी राजकीय बजट से चलाने की घोषणा करेंगे। इसी तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में, पंचायतों में जो मिडिल स्कूल हैं, जैसे- जाखोपुर है, अहीर बासना है, भोजपुर है, गुजरीवास और शाहपुर है। मैं चाहूंगा कि इन मिडिल स्कूल्स को भी आप सैकण्डरी करने का काम करेंगे।

एक स्कूलों में पानी की बड़ी समस्या है। जहां विशेषकर डार्क जोन है, वहां पर आप हैण्डपम्प देते हैं, हैण्डपम्प कामयाब नहीं है और कहीं हैण्डपम्प लग जाता है तो उसमें आपके हिसाब से तीन सौ मीटर, साढ़े तीन सौ मीटर से ज्यादा बोरिंग नहीं करते तो 6 महीने में ही वह हैण्डपम्प खराब हो जाता है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो डार्क जोन में सीनियर स्कूल है या सैकण्डरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, आप उसको सौर ऊर्जा से जो सिंगल फेस है उसको ये सैंक्शन करे। उसके साथ कम से कम 600 मीटर गहराई तक वो सिंगल फेस होना चाहिए। जो तीन सौ, ढाई सौ जो है वे कामयाब नहीं है। इसलिए, मेरे क्षेत्र में लगभग दो दर्जन सीनियर सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं, जिसमें पानी की दिक्कत है। इसलिए, सौलर से वहां पर सिंगल फेस सैंक्शन करें ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए।

एक जो इन स्कूलों में जो पोषाहार बनाने वाली महिलाएं हैं, जो काम करती हैं उनका मानदेय बहुत कम है। अगर आप मानदेय नहीं देंगे, काम नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। इसलिए कम से कम दो हजार रुपये उनका मानदेय होना चाहिए प्रत्येक कार्यकर्ता का।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इसलिए आपसे कहना चाहता हूं एक आपने अच्छा काम किया था कि सब भामाशाहों को स्कूल से जोड़ा, कार्यक्रम हुए, दानदाताओं ने सहयोग किया। ये सतत प्रक्रिया है, उसमें पूरा योगदान रहना चाहिए और कहीं न कहीं ऐसे भामाशाह को जोड़कर या सीएसआर का फण्ड है, जो ठीक से लगे उसके लिए एक एजेन्सी आप जिला स्तर पर कोई ऐसे अधिकारी को नियुक्त करें ताकि वो लगातार सीएसआर का फण्ड है या दानदाताओं या भामाशाहों से मिलकर और अच्छा काम करे।

जैसे मैं बताना चाहता हूं मेरा विमरानी कालेज है, डिग्री कालेज है। होण्डा टू व्हीलर ने लगभग एक करोड़ दस लाख रुपये मेरे कालेज में लगाया है और अलवर जिले का ही नहीं राजस्थान में ऐसा बढ़िया खेल का मैदान बनेगा, शायद और दूसरी जगह नहीं होगा तो उसके मोटिवेशन के लिए, जब आप इतने अधिकारी डीईओ, बहुत सारे "रमसा" और अधिकारी बैठा रखे हैं तो एक डीईओ लेवल का अधिकारी आप सिर्फ इसी काम के लिए बैठाइए कि भामाशाहों से मिलना, कम्पनियों से मिलना, उनसे राजकीय के अलावा भी ऐड लेने के लिए। सीएसआर के फण्ड की किस स्कूल में आवश्यकता है, किन सरपंचों को आवश्यकता है, वो सम्पर्क कर लेता है, किसी प्रधान को या कोई और, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे सक्षम लोग अपनी दूरी के कारण या सम्पर्क के कारण वहां काम होना आवश्यक है लेकिन हो नहीं पाता।

इसलिए एक पद कम से कम जिले में आप ऐसा सोशल वैलफेयर का रखें ताकि उनसे दानदाताओं से भामाशाहों से सहयोग ले सके। मैंने पुन: मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखी हैं उनका ध्यान करेंगे और रिप्लाई के समय निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें रिलीफ देने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बुहत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्या शकुन्तला जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24 के पारित होने एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 की शेष मांगें पारित होने और आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्या।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया। जो कि एक विद्या की देवी सरस्वती मां सब पर आशीर्वाद रखे और सरकार को भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देवे।

सभापति महोदय, इतनी देर से ये कह रहे थे साठ वर्ष, सत्तर वर्ष तो ऐसा लगता है कि ये जितने भी पुराने लेखक हुए, कवि हुए या वैज्ञानिक हुए। चाहे हरिवंशराय जी हों, दिनकर जी हैं, मैथिलीशरण जी हैं, चाहे प्रेम चन्द जी हैं, अपने राष्ट्रपति जैसे रहे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी हैं, वो शायद अभी दो-चार साल में पढ़कर के बने होंगे, पहले तो विद्यालय थे ही नहीं, 50-60 साल से तो विद्यालय ही नहीं थे। ये जितने आईएएस, आरएएस रिटायर हो गये, हवा में पढ़कर के रिटायर हो गये, ऐसा महसूस होता है इन बातों को सुनकर के।

इतिहास की बात करते हैं तो जो हमारा पुराना इतिहास है तो क्या इतिहास सब्जैक्ट को ही खतम कर देंगे, जो शब्द है वो ही लुप्त कर देंगे? ऊंचे-ऊंचे शब्द फेंककर के शिक्षा का जो नारा है बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, तो बेटी को पढ़ाने का जो नारा है कैसे सार्थक होगा। जिन विद्यालयों में चाहे पांचवीं, आठवीं, दसवीं, बाहरवीं तो जहां पांचवीं का विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र में उसे आठवीं किया जाए, आठवीं का है उसे दसवीं, दसवीं का है उसे बारहवीं।

ऐसे विद्यालय जिनमें लड़कियों की संख्या 50-60-70-80 नहीं, डेढ़ सौ तक की हैं, ऐसे विद्यालयों का सर्वे करवाकर के अगर उन्हें क्रमोन्नत किया जाए, एक पंचायत हैड-क्वार्टर करके उसका गीत गा रहे हैं, तो ऐसे तो यह नारा सार्थक होने वाला नहीं है।

जिन गांवों की दूरी 6-6 किलोमीटर तक है। नाथूसर लोज, जो रामपुर

(श्री शकुन्तला रावत)

पंचायत से 6 किलोमीटर दूर है तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे ही विद्यालय ऊंचपुर, नांगलहेड़ी है, गुवाडा, आलनपुर है, माजरा ढाकोडा है, बुर्जा है, कोठिया है, जहां लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उन्हें क्रमोन्नत नहीं करेंगे तब तक यह नारा सार्थक नहीं हो सकता है।

एक तरफ सुविधाएं देने की बात करते हैं, चाहे एसएस में हो, चाहे नरेगा में हो। स्कूलों की चारदीवारी है, चाहे कमरे बनाने का है, शौचालय बनाने का है, सभी विद्यालयों का सर्वे करवाकर के यह काम किये जाएं। चार वर्ष से विषय अध्यापक, जिन विद्यालयों में नहीं लगे हैं चाहे मैथ्स, इंग्लिश है, ऐसे विद्यालय नारायणपुर, बानसूर, रामपुर, हरसौरा, बालिका इनमें डेपुटेशन पर हम लोग वैसे प्राइवेट अध्यापक पैसे से लगाकर के पढ़ा रहे हैं। चार वर्ष से आज तक बार-बार सदन में उठाने के बाद भी नहीं लगा रहे हैं और नये विद्यालय खोले हैं...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीगण।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...इनमें देवसन, उसमें विज्ञान संकाय खोले। बबेरा एग्रीकल्चर, गृह विज्ञान बहराम का बांस और एग्रीकल्चर सबलपुरा इस तरह से संभाग वाइज, अगर ये करें तो ज्यादा उचित रहेगा। कालेज की मांग जो शिक्षा का ही एक मैं मानती हूं कि सबसे बड़ा पहलू है।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य धन्धा कृषि और पशुपालन है, महाविद्यालय की मांग बार-बार उठाई जा रही है। लेकिन, सरकार बार-बार यह कह देती है संसाधानों के अभाव में, तो ये संसाधन कब उपलब्ध होंगे? क्या देव नारायण योजना से पॉलीटेक्निक कालेज हो, चाहे नारायणपुर में महिला महाविद्यालय हो, ऐसा करोड़ों का बजट पड़ा है तो क्यों नहीं महाविद्यालय खोलकर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को एजुकेशन दी जाए। वे निजी विद्यालयों की फीस वहन करने में असमर्थ हैं, हजारों बच्चों को बारहवीं पास करके घर बैठना पड़ता है।

आवासीय विद्यालय खोलने की बात करते हैं वहां पर फोरेस्ट का एक्ट लगा देते हैं, यहां वन विभाग की जमीन है नहीं खुलेगा। क्यों नहीं, जो ऐसी बड़ी पंचायतें हैं जहां एससी., एसटी. तबका ज्यादा निवास करता है चाहे ओबीसी है, एसबीसी है। रामपुर है, कराणा है, बबेड़ी है, हमीरपुर, हाजीपुर, हरसौरा, चतरपुरा, नीमूचाणा ऐसी जगह आवासीय विद्यालय खोलने के नाम का तो यहां जिक्र किया जाता है लेकिन नहीं खोले जा रहे हैं।

(श्री शकुन्तला रावत)

जो छात्र-छात्राएं परिवहन के अभाव में भी काफी छूट जाते हैं, शिक्षा से विहीन रह जाते हैं। जो बड़े-बड़े रूट हैं, वहां पर भी रोडवेज बस की सुविधाएं नहीं है। इनसे आने-जाने में अध्यापक-अध्यापिकाओं को भी, छात्र-छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एक सभापति महोदय, लैपटाप जिन बच्चों को दिया जाता है, सेम प्रतिशत के अंक वाले बच्चे उसमें रह जाते हैं तो उनको किस नियम के तहत रखा जाता है? इस तरह से बच्चों में निराशा पैदा होती है, क्योंकि, कोई नियम इस तरीके का नहीं है कि इस कारण से बच्चों को रख दिया गया है। वो बच्चे दिखाते हुए डोलते हैं, कागज जमा कराते रहते हैं। आप कराइये, आपको मिल जाएगा फिर कहेंगे आपने समय पर जमा नहीं करवाया है और जैसा अभी रामहेत जी ने कहा पोषाहार बनाने वाली महिलाएं, क्योंकि जो सम्पन्न महिला है वो तो काम करने वाली है नहीं। जिस महिला के कोई साधन नहीं कमाई का, बच्चों का पालन पोषण करने का, वो ही महिला वहां काम करती है तो कम से कम उनका 5 हजार रुपये किया जाना चाहिए। जिससे वो अपना खर्चा चला सके।

सभी विद्यालयों में जहां उनकी खुद की जमीन खेल मैदान की नहीं है, लेकिन जिस ग्राम पंचायत ने खेल मैदान की जमीन का पट्टा सरपंचों ने बनाकर के दे दिया तो क्यों नहीं एस.एस. में, नरेगा में उन विद्यालयों के पास में इस तरह के खेल मैदान बनाए जाएं?

जैसे विजयपुरा है, बहराम का वास है, बिलाली है, रामपुर, जयसिंहपुरा है, बबेड़ी खेड़ा श्यामपुरा, गूंता, शाहपुरा, हरसौरा, बबेरा, देवसन, मुण्डावरा, घड़ी, बबूकावास, कराणा, ज्ञानपुरा, चतरपुरा, खोरी, नीमूचाणा, बासदयाल, खोलावास, हाजीपुरा, हमीरपुर इन जगहों पर जमीन उपलब्ध है, लेकिन वहां पर कोई किसी तरीके से इस तरीके का मैदान बनाने का काम नहीं हो रहा है, पट्टा देने के बाद भी और चाहे विद्यार्थी मित्र हों, प्रेरक हों, कम्प्यूटर शिक्षक हों, लैब असिस्टेंट हों, प्रबोधक हों, ये सारे ही आये दिन धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो वादे कर लिये गये थे चाहे सुराज संकल्प यात्रा में हो, चाहे विज्ञापन में हो, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? जो रह गये चाहे विद्यार्थी मित्र हों, चाहे कम्प्यूटर आपरेटर हों, इनको क्यों नहीं आप किसी न किसी पद पर नये पद सृजन करके इनको लगाया

(श्री शकुन्तला रावत)

जाए। रोजगार लाखों को देने की आप बात करते हैं, लेकिन इनको स्कूल में रोजगार देने के लिए सरकार ने मुंह मोड़ रखा है और स्कूलों के नामकरण के नाम पर, सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जो चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना में जो शहीद हो गये, उन शहीदों के नाम से स्कूलों का नामकरण करके शिक्षा विभाग उनके मां-बाप को उनके बच्चे को अमर करने का एक काम कर सकता है। मैं मांग करती हूं कि चतरपुरा का रामसिंह, आलपुर का रामकुमार, नारायणपुर में भंवर सिंह, चान्दाली में लालाराम यादव ऐसे अनेकों जो शहीद हुए हैं उनके नाम से उन स्कूलों का नामकरण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम अमर हो जाए और उनके मां-बाप को भी और उनकी आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह से एक गौरव मिलेगा और वो गौरव आप देने का काम करें, क्योंकि जो तारा आसमान से टूट गया वो वापस आसमान में लग नहीं सकता। जिस इन्सान ने, जिस मां के लाल ने इस धरती का खून से तिलक कर दिया वो वापस इस धरती पर आ नहीं सकता, लेकिन आप उसको अमर करने का एक काम कर सकते हैं। मेरी ऐसी मांग है।

ग्रामीण क्षेत्र में जो संगीत शिक्षा प्रारम्भिक, माध्यमिक और हायर सैकण्डरी में संगीत तथा चित्रकला के, मैंने मांग भी उठाई थी, अनिवार्य होने के बावजूद भी वहां पर इनके शिक्षक नहीं लगाये जा रहे हैं। क्यों नहीं नये शिक्षक भर्ती किये जाएं? किताबें आदि इनकी कितनी सामग्री छाप दी जाती हैं, लेकिन सरकार का पैसा वेस्ट जा रहा है। इस तरीके से नयी भर्ती करके और रोजगार क्यों नहीं दिया जाए? राजस्थानी भाषा को भी क्यों नहीं राजस्थान में अनिवार्य विषय घोषित करना चाहिए, जिससे राजस्थानी परम्परा कायम रह सके। संस्कृति जो हमारी लुप्त होती जा रही है, जिससे कि आगे आने वाले समय में राजस्थान में राजस्थानी भाषा को महत्व मिले और पुरानी जो हमारी संस्कृति जहां पर लेख लिखे हुए हैं ताड़ वृक्ष जैसे, जहां पेंटिंग्स हैं, चित्रकारी है, बावड़ियों पर जो कारीगरी की गयी है, चित्रकारी है वो धरोहर हमारी रह सके और इतिहास कायम रह सके ऐसा भी काम करना चाहिए।

मैं एक शिक्षा का उदाहरण देती हूं, बड़े-बड़े कह रहे थे कि हमने पंचायत में शिक्षा कर दी। रामपुर ग्राम पंचायत की सरपंच के पास दसवीं पास की भी मार्कशीट है, बारहवीं पास की भी है, बीए पास की भी है, लेकिन उसे कौनसे कानून के तहत हटा दिया गया। अब हाई कोर्ट से उसको बहाल कर

(श्री शकुन्तला रावत)

दिया गया। अब कौनसी सरपंच रहेगी, या तो नया चुनाव करवाया जाए, वो सरपंच रहेगी या फिर वो कोर्ट से जो बहाल होकर के आयी है वो सरपंच रहेगी। समझ में नहीं आता शिक्षा के नाम पर ये धंधा खोला गया था, जो कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ में ये इस तरह का एक अन्याय हुआ है, आधे से ज्यादा कोर्ट केसों में लगे हुए हैं। अध्यापकों का काम क्या करना है, आपको सर्वे करना है तो आप जाइये। सरकार उसको बता देगी चाहे परीक्षा हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इससे बढ़िया क्यों नहीं जो बेरोजगार विद्यार्थी मित्र, शिक्षक और ये हैं इनको, एक्स्ट्रा पैसा तो आप उन्हें भी देते हैं, इनको ऐसी ड्यूटी पर लगाकर के क्यों नहीं उनको रोजगार देने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी ने तो बोल भी दिया है शायद, लेकिन जो ऐसी कई महिलाएं हैं और अध्यापक हैं जिनकी तनख्वाह साल-साल भर, छह-छह महीनों से उनके लिए भी यहां से आर्डर निकालें। एजुकेशन लोन समय पर नहीं मिलता है, सभापति महोदय, पढ़ाई के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको वंचित ही रहना पड़ता है, लेकिन नियमों की बात कर देते हैं हर बार की ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है।

श्री सभापति: विराजें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट के लिए, सभापति महोदय। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सभापति: बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मैं दो लाइन मेरी तो कह दूं सरकार के लिए?

श्री सभापति: हां, दो लाइन जो हमेशा कहते हैं वो कह दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, वो तो मैं हमेशा कहती हूं तो आज भी कह देती हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आज नया है या वो पुराना ही है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप पण्डित हैं, मैं बुद्धिमान हूं। नया लिखकर लाती हूं। मैं मेरी मर्जी से बनाती हूं। अब ये पण्डित जी महाराज हैं मैं बुद्धिमान हूं। ये कवियों के लेखों में से निकालते हैं।

श्री सभापति: उन पण्डित जी को भूल जाएं, आप तो अपनी बात कहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 'बिना पत्थर के पहाड़ नहीं होता, बिना फूल के पेड़-पौधा नहीं होता' और सम्माननीय सभापति महोदय, बिना विषय अध्यापकों के बालकों के ज्ञान का विकास नहीं होता, विकास नहीं होता। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री समाराम जी गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या-24 कला, शिक्षा और संस्कृति पर बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद। शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो शिक्षा में पूरे प्रदेश में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है वो आज तारीफेकाबिल है। सभी कहते हैं कि क्या हुआ, जैसे पूर्व में भी 2003 से 2008 तक हमारी सरकार रही थी उस समय भी जो राजीव गांधी पाठशाला थी उसको प्राथमिक विद्यालय में किया और पांचवीं को आठवीं किया और पंचायत मुख्यालय पर दसवीं किया और फिर 2009 से पूर्व सरकार कांग्रेस की रही। इन्होंने आठवीं तक को बिना पढ़ाये पास कर दिया। शिक्षा में जैसे नींव के बिना अगर भवन नहीं होता है इसी तरह इन्होंने इसको मजाक समझ रखा था। शिक्षा एक ऐसा विभाग है जो आज राष्ट्र को परम लेवल तक ले जाता है। इसको इन्होंने मजाक समझा था और हमारी सरकार आने के बाद में शिक्षा का जो ढर्रा था उसको सुधारा था। जिस प्रकार से आठवीं को बोर्ड किया उसके बाद में पांचवीं को भी बोर्ड किया और बिना मांगें शिक्षा विभाग ने हर पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला। नहीं तो पूरे ढिंढोरा पीटना पड़ता था, लोग पीछे भागते थे कि हमारे यहां स्कूल क्रमोन्नत कराओ। बिना मांगे इस प्रकार से बालिका शिक्षा को महत्व दिया है जिससे बच्चियां बाहर नहीं जाती हैं। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जिस प्रकार से उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श विद्यालय के नाम ही इनके साथ में अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई, अच्छे संस्कार जिस प्रकार से स्कूलों का जो परसेंटेज जो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में शिक्षा का परसेंटेज इस बार बहुत ही बढ़िया रहा था। चार साल में स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। सरकारी स्कूलों में जैसे हमारे खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट की

(श्री समाराम गरासिया)

मान्यता अब हम नहीं समझते क्योंकि अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अन्तर है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ी है और पोषाहार भी गुणवत्ता की तरह ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान नहीं रखा। उसकी मोनिटरिंग होती है और मदरसों के अन्दर भी सब समान रूप से देख करके जो इस प्रकार का जो हमारी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किया है यह बहुत तारीफेकाबिल है। जिस प्रकार से हमारे जैसे वनवासी क्षेत्रों में वास्तव में कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें उसके लिए बच्चियों हेतु साइकिल दी। दुनिया भर के लोग कहते हैं कि आज बच्चों की इतनी साइकिल कहां से आई। इस प्रकार प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्ची के जन्म से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए सरकार व्यवस्था करती है, लोगों में इनका प्रचार-प्रसार जो होता है वो तारीफेकाबिल है। ये जो विपक्षी बैठे हैं इनके मन भी यह तो विश्वास है कि वास्तव में इन्होंने अच्छा काम किया है। ये तो अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं बाकी इनको भी यह लग रहा है कि वास्तव में इस सरकार ने ये जो आमूल-चूल परिवर्तन किया ये तारीफेकाबिल है। इसमें कोई दोराय नहीं है। ये सब कहते हैं। हम हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी घूमते हैं तो इनके पास में ऐसा कोई शब्द नहीं है शिक्षा के प्रति हो, चिकित्सा के प्रति हो, ऐसा कोई नहीं है जैसे शिक्षा विभाग में पूर्व सरकार में भी जब अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने एक लीलोरीवली में एक घोषणा भी की थी और एक पत्थर भी लगाया था, लेकिन हमारी सरकार जब आयी, यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और जनजाति मंत्री द्वारा एक घोषणा हुई थी, वहां 3 करोड़ 29 लाख का आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास बन करके उसका उद्घाटन भी हुआ। उसमें सौ बच्चियां पढ़ती हैं और मेरे खुद के गांव में भी दो करोड़ चालीस लाख का आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास बनाया। माउंट आबू के अन्दर बीस-पच्चीस सालों से अटके हुए दो बालिका जनजाति छात्रावास थे,

(17.00 बजे)

वह भी प्रगति पर हैं। पहली बार चार साल में ऐसा हुआ, अभी एक साल बाकी है और मुख्य मंत्री महोदया की घोषणा है कि मार्च के बाद जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाएगा यह कहते हैं कि घोषणा कागजों में ही नहीं रहे, जैसे पूर्व सरकार में खाली टेबल थपथपाई थी और घोषणा कागजों में ही रह गई और जहां पत्थर लगे थे, वहां पत्थर ही रह गये थे, लेकिन हमारी सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारी उच्च

(श्री समाराम गरासिया)

शिक्षा मंत्री महोदय यहां विराजी हैं, मेरी एक ही मांग है मेरे आदिवासी बैल्ट में एक कालेज की घोषणा कारणवश रह गई है, वहां आज एक कालेज की घोषणा हो जाये, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: वाह साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मामन सिंह जी।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24 शिक्षा, कला व संस्कृति पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चार सालों में हमारी सरकार ने विशेष रूप से शिक्षा व किसान पर समर्पित बजट रखा है। चाहे घर हो, चाहे तहसील हो, प्रदेश और देश में जो शिक्षित हो गये तो देश का, प्रदेश का और उस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होता है। इसी सोच को रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनाया। क्योंकि एक शिक्षक को ही उस क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का ज्यादा ज्ञान होता है इसलिए हमारे माननीय देवनानी जी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा मंत्री बनाया। उसका परिणाम यह हुआ कि ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, चार सालों में ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन हुए जो इतिहास के पन्ने पर लिखे जाएंगे। 70 साल के काल में पहली बार एक साथ इतने स्कूलों को क्रमोन्नत करना, 5-6 हजार सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल, हजार-पांच सौ तो हर सरकार ने किये, लेकिन एक साथ इतने करना। एक लाख के करीब कर्मचारियों की डीपीसी करना और कुछ ऐसे अहम फैसले लिये गये जैसे समानीकरण, पहले एक जगह एक ही स्कूल में दस अध्यापक और एक में दो, उनका सबका समानीकरण किया गया, सैटअप चेंज किया गया। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय खोले गये, जिसमें सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराये गये। उसका परिणाम यह हुआ कि 12 लाख से अधिक का नामांकन इन चार सालों में बढ़ा। बच्चे आकर्षित हुए। बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह सारी बातें बता दीं, इसमें जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है। पाठ्यक्रम में बदलाव, तुष्टिकरण की नीति के तहत अकबर महान पाठ्यक्रम था। 600 साल तक जिन्होंने देश को परतंत्र रखा, उन मुगलों को महान बता रहे हैं। उसको परिवर्तित करने का बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया। दो साल पहले मैंने ही मंत्रीजी से यह बात कही थी, आपको इसके लिये बहुत धन्यवाद कि महाराणा प्रताप जैसे देश भक्त का नाम पाठ्यक्रम में किया है। ऐसे बहुत से

(मास्टर मामन सिंह यादव)

फैसले हैं, नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में समानीकरण किया गया, निष्पक्षता से, अपने आप स्कूल छांट लो, ना कोई पार्टीवाइज झंझट, शिक्षा को राजनीति से बिलकुल अलग रखा गया। ऐसे ही विद्यालय क्रमोन्नत करने में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत मुख्यालय को आधार बना दिया। चाहे वह दूसरी पार्टी का हो चाहे अपना हो, यह सारा समानीकरण इस तरह से किया।

विवेकानंद माडल स्कूल जिनको बहुत ही अच्छे स्कूल कहे जा सकते हैं। उनमें भी सारी सुविधाएं दी गईं, कम्प्यूटर वगैरह सभी सुविधाएं हैं। विवेकानंद माडल स्कूल तिजारा में भी है। गुणवत्ता शिक्षा और संस्कृति, नैतिक शिक्षा, वंदे मातरम्, सूर्य प्रणाम, यह कई ऐसे अहम फ़ैसले हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच पर माननीय मंत्री महोदय ने किये, इसके लिये धन्यवाद।

शिक्षा के क्षेत्र में चार सालों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, वह सबके सामने हैं। कोई असत्य आलोचना करना चाहे या कोई रात को रात न माने, दिन को दिन नहीं माने, तो उसका तो कोई इलाज नहीं, सावन में जो अंधा हो जाये उसको हरा ही हरा, बाकी अच्छा काम हुआ है।

कुछ मेरे क्षेत्र की समस्या हैं, चूंकि समय 10 मिनट का ही है, वह मैं आपको बता देना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय सुन रहे हैं, आप बताएं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मंत्री महोदय, को ऐसा कई बार सुना चुका हूं कि मेरे यहां एक समस्या है कि भिवाड़ी नगर परिषद मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में आता है, 8 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर परिषद बन गई। अब वह रिकार्ड में पंचायत मुख्यालय नहीं रहे। मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी पंचायत मुख्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल बना दिया लेकिन भिवाड़ी में वह 7 पंचायतें वंचित रह गईं क्योंकि वह रिकार्ड में मुख्यालय नहीं है, जबकि उनको मर्ज किया गया है। पूरे तीन लाख की आबादी में एक स्कूल, कैसे काम चल सकता है। यह बात मैं मंत्री महोदय से 20-30 बार निवेदन कर चुका हूं, लिखकर भी दे चुका हूं, यह बहुत अहम बात है। इसको समझने की जरूरत है गौर करने की और बिलकुल घोषणा करने की जरूरत है। आप रिकार्ड निकलवाइए, वह पहले पंचायत

(मास्टर मामन सिंह यादव)

मुख्यालय थे, पांच-छह साल पहले ही थे। अब एक स्कूल से ढाई तीन लाख की आबादी कैसे हो सकती है। मंत्री महोदय पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो यह बहुत दुखद बात है, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के जन संवाद में भी हमने यह लैटर दिया था। वहां ग्रामीणों ने भी मांग की थी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी यह महसूस किया था, हेमसिंह भड़ाना जी हमारे प्रभारी मंत्री महोदय भी वहां बैठे हुए थे, मुख्य मंत्रीजी ने भी इसको संज्ञान में लिया कि हां आपकी यह बात सही है कि आपके मुख्यालय पर भी होना चाहिये। यह सात स्कूल हैं जो वंचित रह गये। मंत्री महोदय, साडोद, आलमपुर, सातडका, खजुरीवास, मिलकपुर गुर्जर, शहदपुर, इस तरह से हमारे यह सात स्कूल रह गये, इनको करने का काम करेंगे। दो तीन पंचायत मुख्यालय हैं जो रह गये, मसीद, थड़ा और दरामपुर, तीन पंचायत मुख्यालय हैं जो रह गये हैं, मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको भी क्रमोन्नत करने का काम करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): दो मिनट साहब, बहुत अहम बात है। शिक्षा में काम बहुत हुआ है जिसकी वाहवाही हो रही है।

श्री सभापति: आप तो पूरे जानकार हैं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): जो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, 60 परसेंट कर्मचारी थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं, प्रतिबंधित जिलों में वह 10-20 साल से बैठे हुए हैं। पहली सरकार ने भी नहीं खोला और अबकी सरकार ने भी नहीं खोला। कृपा करके उसमें सीमा तय कीजिए, चाहे दस साल, पांच साल जो भी करनी हो। विशेष रूप से महिलाओं की नई नियुक्ति हो चाहे प्रमोशन हो, उसको उसका गृह जिला देने का काम करना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। तबादले भी खोलने चाहिए क्योंकि थर्ड ग्रेड का अध्यापक 20-20 साल से दूसरे जिलों में बैठा है, वह अपने जिले में आ जाये, यह काम करें, 54 हजार की नई भर्तियां हो रही हैं, यह भी बहुत अच्छा है। मिड डे मील की जो महिलाएं खाना बनाती हैं, मैं भी स्कूल का हैड मास्टर रहा हूं ...

श्री सभापति: यह विषय तो कई बार आ गया है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक मिनट साहब, जो दस सालों से केवल एक हजार रुपये पर काम कर रही हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब

(मास्टर मामन सिंह यादव)

सबका मानदेय बढ़ाया है तो इनका भी दो हजार कर दो, गरीब महिला है वह एक हजार में क्या कर सकती है। बिसरोदा, असलीमपुर, टपूकड़ा में जहां सौ से अधिक संख्या है वहां भूगोल, गणित का सब्जैक्ट खोलने का काम करेंगे।

यह तो स्कूल शिक्षा में था। अब कालेज शिक्षा में, मेरे यहां तिजारा में कांग्रेस सरकार के समय में कालेज खुला था। जाते-जाते लिस्ट लगा गये, न स्टाफ था, न बजट था। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने आठ करोड़ रुपये दिये हैं। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन गयी है और उद्घाटन भी हो गया है। वह तो तिजारा हैडक्वार्टर पर है, लेकिन जो भिवाड़ी नगर परिषद है, वहां पूरी तीन लाख की आबादी है और वहां हरियाणा बोर्डर पड़ता है। जिस दिन से विधान सभा में आया हूं, जो भी सत्र है, सब में इसी की मेरी मांग पहले नंबर पर चल रही है कि भिवाड़ी में कालेज हो। लेकिन खेद के साथ कहना है कि आज तक मेरी कालेज की अभिलाषा पूरी नहीं हो पायी है और मुझे बहुत ही भरे मन से कहना पड़ रहा है कि इसकी घोषणा करेंगे तो धन्यवाद देंगे। बहुत ही आवश्यक चीज है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री तरुण राय जी कागा।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): प्लीज, एक चीज है, मंत्री महोदया इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां किसान ट्रस्ट बाबा मोहनराम के नाम से कालेज चल रहा है। स्टाफ है, 38 बीघा जमीन है, चार-दीवारी है, सब कुछ है, लैब, कम्प्यूटर, केवल नाम करना है, बाबा मोहनराम राजकीय महाविद्यालय, इसमें बताओ क्या दिक्कत है? एक तो यह और जो आठ पंचायतों की मांग है नगर परिषद वाली, वह कराने का काम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री तरुण राय जी कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): सभापति जी महोदय, आज मुझे मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला और संस्कृति के मौजूं पे जो बोलने का मौका फराद किया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे सूबे की वजीरे आला इज्जत-ए-मुआब वसुंधरा राजे जी, हमारी हाई एजुकेशन मिनिस्टर किरण माहेश्वरी जी का मेरे दिल की अमीक गहराइयों से शुक्राना अदा करने का नजराना पेश करता हूं, जिन्होंने मेरे गुजिश्ता चार सालों के मुतालबात को सर अंजाम देते हुए मेरे इलाके को जो सौगात और तोहफा अता

(श्री तरुण राय कागा)

किया है, जिसके लिए मैं इनका वालहाना इस्तकबाल करता हूं। हालांकि, मेरे से काबिल, काफी दानिश्वर, काफी मुकरबिन आला कानून बने हैं। अपने मुखातबों में, काफी कुछ किताबों में इस तालीम के बारे में वजाहत से अपने बयानात अर्ज किये हैं। लेकिन मैं, मेरी जानिब से कुछ बातें कहने के लिये आपके सामने खड़ा हूं। मैं हमेशा कहा करता हूं, जिस तरह से अभी काफी कुछ जेरे बहस-बातें हुईं, शिक्षा और संस्कार, अगर हमारी तालीम के साथ-साथ अखलाक की तालीम नहीं है, तो हमारी यह जो तालीम है, वह बिल्कुल बेमायना रह जाएगी। इसमें हमारे सबरा किन ने काफी कुछ जोर भी दिया है, लेकिन हमारी मोहतरमा इस ऐवान की सदस्या ने कुछ नजीर पेश की है, कुछ मिसाल दी है। इससे पहले तो फलां फलां शिक्षित तालीमयाफ्ता नहीं होते, तो उनके नाम भी हमको गिना दिये। मैं आपसे मुतमईन हूं, इत्तफाक रखता हूं, हां वह हमारा बर सगई, हिन्द मुल्क था, जहां तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे मरकज हुआ करते थे, जिसमें हमारे लोग तालीमयाफ्ता हुए थे, लेकिन मैं आपको बड़े रंजोगम से जिक्र करना चाहूंगा कि वो मंजर भी हमने देखे तारीख की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पायी।

श्री सभापति: तरुण राय जी, यह तो रिपीट हुआ है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे जो मुखालिफुल दल के आदमी हैं, अगर यह किया होता तो, हमारे जो चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में हम शमे जलाकर निकले, तो हमें आठवीं पास ख़वातीन मिल पायी, यह आपकी शिक्षा का मयार था।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसका ट्रांसलेट करा लेते, समझ में नहीं आ रहा।

श्री सभापति: आप थोड़ी-थोड़ी उर्दू सीख लें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): इसलिये मुझे गम है। हम आपको कहा करते हैं कि:-

'कभी उल्फत बदल गयी,

कभी नीयत बदल गयी।

खुदगर्ज हुए तो सीरत बदल गयी।

अपना कुसूर दूसरों पर डालकर आप सोचते हैं कि हकीकत बदल गयी।

मैं आपका खयाल इसी जानिब करना चाहूंगा, जिस तरह से मुझे बहुत

(श्री तरुण राय कागा)

बड़ा अफसोस। आज रेमंड का मालिक, आज बच्चों को संस्कार दिये होते तो वह सड़क पर नहीं होता। बहुत अफसोसनाक है, हैरतनाक है। (व्यवधान) मैं उर्दू नहीं बोल रहा। अगर रेमंड के मालिक ने अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार दिये होते, मुंबई में महिला ख़वातीन सड़कर अपनी आलीशान बिल्डिंग में मर गई, उसके बच्चे को अभी तक पता नहीं कि मेरी मां कहां है। कई आई.ए.एस., आई.पी.एस. खुदकुशी कर गये, अखलाक की कमी में, यह संस्कार के अभाव में। इसलिए मैं हमारे तालीमी मोकबत को गुजारिश करुंगा कि इस पर पुरज़ोर से अमल किया जाए। यह हमारे लिये बहुत ही जरूरियत। मैं ज्यादा यह कहना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के शोहबे में जिस तरह से अच्छा-अच्छा काम किया व ऐलान किया है, वह बहुत ही लाजवाब है। यह हमारे सूबे के लिए बिल्कुल नुमायां साबित होगा। (व्यवधान) हां, हां, जी आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। इस तरह से भी आपको कहूंगा कि:

आप इतना खफा मत होइये, आप इतना परेशान मत होइये,
आपने ही तो खेतों में इंसान के सर बोये हैं
अब जमीन खून उगलती है तो यह हैरत क्यों है।

मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरा इलाका एक सरहदी इलाका है। मेरा जो इंतख़ाबी इलाका चौहटन विधान सभा है, मैं उस इलाके से आता हूं। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने तालीम के वजीर ने काफी कुछ इनायत करके सीनियर हाई सैकण्डरी स्कूलें की हैं, लेकिन आप लोगों ने जो हमारी सरकार और हमारी हुकूमत पर बेवजह में इल्जाम आयद किये हैं। आपको यह मालूम है कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार आते हुए, इस तरह से समानीकरण, इस तरह से करके हमारी स्कूलें मर्ज कर दीं।

कुछ जरा गिरहबान में झांको, पीछे मुड़कर के देखो, यह आपकी ही करामात है। आपकी सरकार में सिलसिला जारी हुआ था। आपने सोचा हमने जो स्कीम्स चालू की थीं, वह बीजेपी बंद कर देगी। हमने तो आपके कारवां को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है, पूरी तरह से याद है पिछला इंतखाब भी, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, हार जीत तो होती है किस्मत की बाजी। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन, एक

(श्री तरुण राय कागा)

कागावास, एक कागापाड़ा, एक कागा की बस्ती, तीन कागाओं की स्कूले बंद कर दीं आपने, नमो-नमो आपको।

श्री सभापति: गांव के नाम हैं।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): उसके बारे में चार साल से हमारे शिक्षा मंत्रीजी को लिख रहा हूं। दस दिन पहले भी लिखकर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कागा का शाब्दिक अर्थ होता है कौआ, तो कौवे की स्कूल बंद कर दी क्या?

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अब मैं कहता हूं। अब कागापाड़ा छोड़ो, कागावास छोड़ो, कबूतरपाड़ा करके उस स्कूल को बहाल करो। मेरे को कोई मतलब नहीं है कागा-कूगा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे इलाके में हमारे कोली समाज, मेघवाल समाज और भील समाज के लोग जो रहते हैं, अशिक्षित हैं। वहां हमारे हमसाया जो सूबा है, गुजरात, अपने रोजगार के लिए हमेशा पलायन करके वहां चले जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इलाके में कस्तूरबा गांधी स्कूल है, जो उन बच्चों के लिए है लेकिन वह आठवीं तक है। मैं निवेदन करूंगा, अपना मुतालबा करूंगा, मांग करूंगा उसको सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाए ताकि जो लोग जिंदगी बसर करने के लिए रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ सकें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं, मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। हमारे उस इलाके में ज्यादातर आप देखो। नहीं, अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पाया। हमेशा मुख्तसर बोलता हूं, हमेशा कम बोलता हूं इसलिए, सर, मैं कहता हूं आपने जो शिक्षा मंत्रीजी, मैंने दो-तीन बातें नोट कराई हैं। आप उनके बारे में गौर फरमाएं। ज्यादा मैं नहीं कहकर यह कहता हूं:

"मेरा मजहब तो ये दो हथेलियां हैं, मेरा मजहब दो हथेलियां हैं,
जुड़ते हैं तो पूजा होती है, खुलते हैं तो दुआ कहते हैं।"

श्री सभापति: वाह भाई वाह। माननीय नंद किशोर जी महरिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन। आप विराजो। हो गया आपका पूरा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद।

सूचना

राज्यपाल महोदय के स्वाइन फ्लू

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाइंट आफ इंफोर्मेशन है, माननीय सभापति महोदय। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय अस्वस्थ हुए। यहां पर एसएमएस में उनकी जांच हुई। उनके स्वाइन फ्लू बताया गया। फिर दिल्ली में उनको स्वाइन फ्लू नहीं बताया गया। यहां टैस्टिंग हुआ, दोबारा स्वाइन फ्लू बताया गया। राज्यपाल महोदय ने सरकार को नोटिस दिया है कि मेरे स्वाइन फ्लू कैसे बताया। जब स्वाइन फ्लू यहां बता दिया तो उनको रिलीज कैसे कर दिया? आपने छोड़ कैसे दिया? उनको आईसीयू में क्यों नहीं लिया? ये सवाल हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री भी गायब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी गायब, हमारे गृह मंत्री भी गायब, जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जाइए। बैठ जाइए। हो गया। इंफोर्मेशन हो गयी। अंकन नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पाइंट आफ इंफोर्मेशन का कोई जवाब नहीं दिया जाता। सरकार के ध्यान में कोई चीज लाना चाहते हैं, आप ले आये। अब सरकार की जिम्मेदारी है उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है, सरकार एक्शन ले लेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका काम सरकार के ध्यान में लाना है। अब सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। आपके चिल्लाने से क्या होगा?

श्री सभापति: राजेन्द्र सिंह जी भादू। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा नियमों से चलती है। यह सारे के सारे नियम सभापति महोदय आपने हमें इस नीली किताब के द्वारा दिये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नियमों में यह नियम स्पष्ट लिखा है कि उच्च अधिकार प्राप्त किसी संवैधानिक व्यक्ति के बारे में कोई टीका-टिप्पणी सदन में नहीं की जा सकती। मैं समझ सकता हूं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: अंकन नहीं होगा। आप विराजें प्लीज। वह अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप बीच में क्यों खड़े हुए हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: बिलकुल अपराध है। गलत बोलना अपराध है।

श्री हीरालाल (निवाई): आपकी जांच कराओ। आपके फ्लू है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने जो इनकी आदत पड़ गई गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सदन में व्यवधान पैदा करना और महामहिम राज्यपाल का नाम लेकर उनके स्वास्थ्य के बारे में टीका-टिप्पणी करना, यह इनको अधिकार नहीं है। अगर इनके जिज्ञासा कोई होती तो ये माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से जाकर वेश्म में मिल सकते थे। आप इसको डिलीट कराएं, सभापति महोदय। वर्ना यह कार्यवाही ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजे प्लीज। तीसरी बार हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप पालन योग्य नियम जो है, नियम 272, 273 पढ़ लें। यह नहीं कर सकते टिप्पणी उन पर। डिलीट करवाइए सभापति महोदय इसको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: अंकन नहीं होगा। आप विराजें। आपको इंफोर्मेशन देनी थी। इंफोर्मेशन दे दी दैट्स आल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। गलत, सही का विषय अपने आप देखेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा है कि आपने बिना नियम के उठाया है इसलिए मैं बाध्य तो नहीं हूं परन्तु चूंकि यह महामहिम का मामला है इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको पूरी सही जानकारी दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जवाब दें, उससे पहले मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। नियम 272 में सभापति महोदय खण्ड 5 में व्याख्या की गई है। शब्द उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अंतर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव में की जा सकती है, ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमत किए जाने के रूप में मूल प्रस्ताव में की जानी चाहिए। मतलब कौन सा प्रस्ताव है? किस प्रकार महामहिम राज्यपाल का नाम लेकर इन्होंने सनसनी फैलाने का काम किया है। आप इनको प्रताड़ित कीजिए, सभापति महोदय। चिकित्सा मंत्रीजी जवाब दे देंगे। परन्तु आप प्रताड़ित करिए। आप 272 की व्याख्या पढ़ लीजिए। मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अगर आप व्यवस्था फरमाएंगे तो इस प्रकार बचकानी हरकत करने वालों पर पाबंदी लगेगी।

श्री सभापति: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्यपाल महोदय के स्वाइन फ्लू बीमारी की स्थिति

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल यह जानकारी आई कि महामहिम राज्यपाल महोदय अस्वस्थ हैं तो उनकी स्वाइन फ्लू की जांच की गई। जांच में उनके पाजिटिव आया। उसके बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेरा इलाज चलता है वहां डाक्टर चौधरी का तो मैं अपोलो में जाकर दिखाऊंगा। यहां से रात्रि को 10.30 बजे वह प्लेन से अपोलो में गए और अपोलो में उनकी जांच की गई। वर्बली अभी तक लिखित में नहीं आया है, अपोलो वालों ने यह कहा कि साहब, इनके स्वाइन फ्लू निगेटिव है। उसके बाद उनका जो सैम्पल था, यहां पर जो प्रिजर्व किया गया था, उसकी दोबारा जांच की गई। उसमें दोबारा उनके पाजिटिव आया है। फिर भी क्योंकि यह गवर्नर साहब का मामला है, मैंने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई है, मेडिकल एजुकेशन सैक्रेटरी आनंद कुमार जी की अध्यक्षता में। उसमें प्रिंसिपल डाक्टर यू.एस. अग्रवाल, हैड आफ दी डिपार्टमेंट डा. आर.के. माहेश्वरी और आनंद कुमार जी की कमेटी बैठाई है और उनको कहा है कि तीन दिन में आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए कि वास्तव में मामला क्या है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र सिंह जी भादू। सारी-सारी। राजेन्द्र सिंह जी भादू, सारी। नंद किशोर जी महरिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24 शिक्षा, कला, संस्कृति पर बोलने का समय दिया। हमारी शिक्षा पद्धति में स्कूल-कालेज जो हैं, उनकी शुरूआत प्रारम्भिक शिक्षा से होती है। प्रारम्भिक शिक्षा में 2013-14 में 74274 स्कूलें थीं और 2017-18 में 49742 रह गईं।

25532 स्कूलें बंद हो गईं या समायोजित हो गईं लेकिन उनकी करोड़ों-अरबों रुपये की सम्पत्ति, गांव वालों ने चंदा करके, दानदाताओं के द्वारा व सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसमें आज भेड़-बकरियां चर रही हैं, वह बिलकुल बेकार हो गई हैं, उनको संभालने की जरूरत है। जो स्कूलें चल रही हैं उनमें भी कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं हैं। खेल के नाम पर प्राथमिक शिक्षा में जीरो बजट है। पूरे साल में एक रुपया भी खेल के नाम प्राथमिक शिक्षा वालों को नहीं दिया जा रहा है। पिओन, एलडीसी की भर्ती हुए तो बरसों बीत गए है। इतनी स्कूलें बंद और समायोजित होने के बाद, आज भी पद खाली पड़े हैं। बड़ी स्कूलों में, सब्जैक्ट टीचर तो आधी में भी नहीं हैं, इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा वर्ना हम क्वालिटी आफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं वह दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है।

अभी 14 से 18 साल के बच्चों का सर्वे हुआ, असर की रिपोर्ट सामने आई हैं उसका असर अगर सरकार माने तो बहुत जबरदस्त है, 83 परसेंट बच्चों को घड़ी में समय देखना नहीं आता है, 71 परसेंट 14 से 18 साल के बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकते। उस रिपोर्ट में है कि 21.4 परसेंट बच्चों को यह भी पता नहीं है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमारे स्कूलों की यह हालत है। फिर इनको पीपीपी मोड पर देने की बातें और हो रही हैं, तो इससे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमारे शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी सुधारने की आवश्यकता है। उनकी सीटें भरने की भी आवश्यकता है।

तबादला नीति की बातें हर सरकार करती आई है। घोषणा पत्र में भी घोषणा की गई थी लेकिन अब तक ऐसी कोई नीति नहीं बन पाई। 20-20

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

साल से लोग प्रतिबंधित ज़िलों में बैठे हैं। हम जब हर चीज में राइडर लगा रहे हैं तो इसमें भी कोई राइडर तो होना चाहिए कि प्रतिबंधित ज़िले से कोई कब वापस आएगा, ऐसी घोषणा अगर सरकार करे तो अच्छा रहेगा।

स्कूलों के साथ ही हम कालेज एजुकेशन की बात करें। सुराज संकल्प घोषण पत्र में स्पष्ट घोषणा थी कि हर उपखण्ड में एक सरकारी कालेज और एक कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत से ऐसे उपखण्ड हैं जहां आज भी सरकारी कालेज नहीं है, कन्या महाविद्यालय तो बहुत दूर की बात है। जहां है वहां क्या हालात है, हमारे रामगढ़ में 50 साल पुराना कालेज है उसमें 1500 बच्चे हैं। पिछले कई सालों से पी जी सब्जैक्ट की मांग चलती आ रही है, गणित विषय की मांग चल रही है, वह पूरी नहीं हो पाई।

सभापति महोदय, हमारे सीकर ज़िले में पांच कॉलेज है, पांचों में ही प्रिंसिंपल नहीं है, वाइस प्रिंसिंपल नहीं है। यह स्थिति है कि आर्टस का एक कॉलेज है वह तो 10-12 किलोमीटर दूर कटराथल गांव के एक स्कूल में चल रहा है। कामर्स का कालेज एक स्कूल में चल रहा है जो 600 गज की जगह है। सरकार के नियम हैं आठ हजार वर्ग मीटर होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अधीन सीकर जिले में 600 कालेज हैं, कालेजेज के हिसाब से प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके जो भी वाइस चासंलर है, उनकी जो स्थिति है वह यह कि 61 दिन में हमारे यहां 7 आर्डर कालेज एफिलिएशन, एंडोमेंट फण्ड राशि के निकाले। पहले साढ़े तीन लाख निकाले, फिर पांच लाख, दस लाख निकाले, फिर बीस परसेंट छूट दे दी, फिर समय की छूट दे दी, लास्ट में उनको 15 लाख, 35 लाख रुपये की। दो महीने में इतने आर्डर हुए तो हालत यह हुई कि कोर्ट को स्टे देना पडा। लास्ट के आर्डर में कोर्ट ने स्टे दे दिया, 600 कालेज वाले विश्वविद्यालय की यह स्थिति है, यह ठीक नहीं है। वह अपनी प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिए निजी कालेज को परेशान कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि निजी कालेजेज पर पाबंदी नहीं हो, पूरी पाबंदी रखे लेकिन हम हमारे गिरहबान में भी तो झांके कि सरकारी कालेजेज में हमने क्या सुविधाएं दे रखी हैं। लैक्चरर नहीं हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं, जगह नहीं है, गेम्स की जगह नहीं है। इस स्थिति को तुरन्त सुधारने की आवश्यकता है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो एग्जाम होते हैं, उनमें हम पांच-सात साल

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

में एक बार भाग लेते हैं, वह भी हमारे हिमाचल, महाराष्ट्र जैसे स्टेट भाग लेते हैं। पिछली बार जब भाग लिया तो क्वालिटी में 1974 में 73वां नम्बर हमारा रहा, यह हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है। इसी वजह से बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है हमें अलग से आईटीआई खोलनी पड़ रही है, स्किल डवलपमेंट खोलना पड़ रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि बच्चा 12^{th} करें तब तक उसका 20-25 परसेंट टाइम है वह स्किल डवलपमेंट में खर्च हो। 12^{th} करके जब वह बाहर निकले तो कुछ तो बनकर निकले। बेरोजगारी की अभी स्थिति यह है 60 करोड़ के लगभग बेरोजगारों की फौज देश में घूम रही है। वह भी अनआर्गेनाइज सैक्टर में, जहां ओने-पोने तनख्वाह में उनको काम करना पड़ रहा है। लर्न फार अर्न की हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन हालात यह है कि जो भी भर्तियां हैं या तो हम निकालते नहीं हैं और निकालते हैं तो उन पर स्टे आ जाता है। बजट जैसे दस्तावेज में ही आप देखिए कि नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स को, नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर लिख दिया गया, पूरा प्रदेश कंफ्यूज है। अब तक उसका स्पष्टीकरण भी नहीं आ रहा। जो पद निकाले, 54 हजार पदों की थर्ड ग्रेड में घोषणा हुई। पहले 35 हजार थे वह उसमें सम्मिलित हैं या नहीं हैं, यह आज माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें तो ठीक रहेगा, 9 हजार की सैकिण्ड ग्रेड की बात थी, वह भी पहले से चल रही थी। मजे की बात है कि 1200 प्रधानाध्यापक की भी भर्ती निकाल दी। प्रधानाध्यापक कोई बेरोजगार तो बनता नहीं है। बेरोजगारी के कोटे में वह चीज़ें निकाली हैं वह गड़बड़ है।

शिक्षा के साथ टैक्नोलोजी को जोड़ना पड़ेगा। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हम उसको इस तरह से जोड़ें कि उसमें उसका इंटरेस्ट बने और बच्चा काम करे। सीकर का दीनदयाल विश्वविद्यालय है उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दस साल हो गए, उसकी चारदीवारी भी अब तक नहीं बनी है। उसमें प्रशासन लगा रखा है उसको भी देखने की बात है। पहले भी जहां-जहां यह वी सी साहब रहे हैं वहां-वहां घोटालों की शिकायतें और जांच अब तक चल रही है।

फतेहपुर में सरकारी कालेज, कई बार मैंने कह दिया, मुझे पता है आप नहीं खोलेंगे लेकिन फिर भी मैं जनता की बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वहां सरकारी कालेज की आवश्यकता है। रामगढ़ में पी जी खोली जाए। जिन गांवों में पांचवीं, आठवीं की मांग है उनमें पांचवीं व आठवीं स्कूल खोली जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राजेन्द्र सिंह जी भादू। माननीय सदस्य, बायतू से आने वाले।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले चार वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई वह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय या प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर बच्चों को शिक्षा देना, चार या पांच किलोमीटर दूरी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा उपलब्ध कराना, अनेकानेक क्षेत्र में शिक्षा में बहुत उच्च स्तर के कार्य हुए, मैं इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी और हमारे प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री सम्माननीय देवनानी जी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम, स्कूलों को आगे बढ़ाने का काम, यह काम तो हमने किया लेकिन मैं विशेष तौर से आपसे मेरे क्षेत्र की दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। हमारे दूर-दराज के क्षेत्र में विद्यालयों के अन्दर अध्यापकों की कमी है वह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूर-दराज के क्षेत्र में 250-300 बच्चों पर, कुछ विद्यालयों में तो दो या तीन अध्यापक से ज्यादा नहीं है। कुछ विद्यालय मेरे ऐसे क्षेत्र में हैं जिनमें प्रधानाध्यापक भी नहीं है। ऐसे माध्यमिक विद्यालयों में जहां बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे पढ़ते हैं उनमें जब अध्यापन के लिए अध्यापक ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें इस बात का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा।

मैंने मंत्री महोदय से पहले भी कई दफे निवेदन किया है कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं, चाहे वे उच्च माध्यमिक के हैं, चाहे माध्यमिक के हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सबके अन्दर हमारे शिक्षकों की जो कमी है उसे निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। विशेष रूप से, जहां हमारे प्रधानाध्यापक इस वक्त नहीं हैं, वहां प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति हर हाल के अन्दर होनी चाहिए, जिससे हमें इन सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। विशेष रूप से कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन उनको माध्यमिक विद्यालय में लम्बे समय से क्रमोन्नत नहीं किया गया है। जबकि हमारे वहां 200-300-400 तक छात्र अध्ययनरत हैं। फिर भी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)
अभी तक उन्हें क्रमोन्नत नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जो ऐसे विद्यालय हैं, उन्हें भी क्रमोन्नत किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जहां हमारे छात्रों की बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने से हमारे छात्रों की वृद्धि हुई है, वहां छात्र कक्षों की बहुत कमी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी मद में हमारे छात्र कक्ष जरूर वहां बनें। छात्र कक्ष बनने से हमारे छात्रों को बैठने के लिये सुविधा होगी और इससे हमें अच्छी शिक्षा हमारे छात्रों को देने में सुविधा रहेगी।

साथ ही साथ हमारे जो बहुत अच्छे से विद्यालय चल रहे थे, चाहे वे उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय थे, मेरे सूरतगढ़ के अन्दर पी.पी.पी. मोड पर उन विद्यालयों को कर दिया गया है, जबकि वहां संख्या 500 से 600 छात्रों की है। वहां पूरा स्टाफ है, लेकिन फिर भी उनको पी.पी.पी. मोड पर देने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विद्यालय, जिनमें बहुत अच्छे से छात्रों की संख्या है, जहां पूरे अध्यापकगण वहां शिक्षा दिला रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को कम से कम पी.पी.पी. मोड पर नहीं दिया जाये। दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां हमारे शिक्षकों की कमी है, अगर वहां पी.पी.पी. मोड पर दिया जाता है तो यह एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहां अच्छी तरह से विद्यालय चल रहे हैं उन्हें पी.पी.पी. मोड पर नहीं दिया जाये। इस तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ ही एक बात मैं हमारी उच्च शिक्षा मंत्री महोदया से उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सूरतगढ़ के अन्दर जो महाविद्यालय है, बहुत पुराना महाविद्यालय है, लेकिन उसमें पी.जी. के पूरे जो कोर्सेज होने चाहिए, जो पूरे सब्जैक्ट होने चाहिए, वे अभी तक नहीं हुए हैं। इसके लिये मैं पहले भी माननीय मंत्री महोदय को लिखकर दे चुका हूं। निश्चित रूप से हमारे वहां भी उन विषयों को जारी किया जाये, खोला जाये। यही निवेदन करते हुए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अजीत सिंहजी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा के लिये मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्राचीनकाल से भारतीय शिक्षा का इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीनकाल में भारत में शिक्षा के कई प्रमुख केन्द्र थे। काशी, तक्षशिला, नालन्दा विश्वविद्यालय, मिथिला, प्रयागराज, शिला, बलबी, अयोध्या, ऐसे प्रमुख केन्द्र शिक्षा के रहे थे और चाणक्य जैसे शिक्षक इस देश के अन्दर रहे थे। विश्व के लोग भारत में शिक्षा लेने आया करते थे। ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारे इस देश का रहा है और इसीलिये भारत विश्व गुरु कहलाया करता था। लेकिन समय का परिवर्तन देखिये, आज क्या हालत शिक्षा की हो गई है। आजादी के बाद सबसे बड़ी कहीं कमजोरी है तो हमारी शिक्षा नीति की रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा उत्सव और कारोबार के आगे भी है। शिक्षा तंत्र पूर्णरूपेण पोस्टमार्टम करके रख दिया गया है। श्री राधाकृष्ण आयोग से लेकर शिक्षा का अधिकार, 2009 तक शिक्षा तंत्र को ठीक करने हेतु 38 समितियों व आयोगों का गठन हुआ था, लेकिन वे ढाक के तीन पात रही हैं।

एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा वह सशक्त हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम मैकाले और वुड की शिक्षा नीतियों को ढो रहे हैं। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक तरह की सरकारें अपनी जद में शिक्षाविदों का रखती हैं। मैं आज इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस देश की जो शिक्षा नीति है, मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हम कहीं से भी संतुष्ट नहीं हैं।

मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि दुनिया के लोग देश के अन्दर शिक्षा लेने आया करते थे, आज एम.बी.बी.एस. करने लोग चाइना के अन्दर जाते हैं। क्या हालत है, जब अस्पताल के अन्दर पेशेण्ट दिखाने जाता है तो वहां डाक्टर से पूछता है कि ये डाक्टर चाइना का है या इण्डिया का है। ऐसी हालत अस्पतालों के अन्दर हो चुकी है। शिक्षा के क्या हालात इस देश के अन्दर हो चुके हैं, मैं आपसे एक

(श्री अजीत सिंह)

निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर, जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो हालत है, वह हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते कि वे डिग्रियां बांटने के अलावा कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा विडम्बना नहीं होगी कि चाहे एल.एल.बी. करने वाला हो, चाहे एम.एससी. करने वाला हो, चाहे बी.टेक का छात्र हो, आज उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी के लिये भी आवेदन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों की विकराल फौज खड़ी हो गई है। आजादी के बाद सबसे कमजोर हमारी शिक्षा नीति रही है।

आज मैं आपसे यह निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन चार वर्षों के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किये हैं, वे अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। चाहे राजस्थान के अन्दर सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल देने की बात की। यह बात सही है कि जब सीनियर सैकण्डरी स्कूल देने की बात की है तो निश्चित ही कमरों की भी कमी आयेगी, स्टाफ की भी कमी आयेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमरों की व्यवस्था करने का काम किया है। भामाशाहों को जोड़ने का काम किया है और उसके माध्यम से आज शिक्षा के उस विद्यालय के स्तर को सुधारने का काम किया है। आज विद्यालयों के अन्दर बिजली की व्यवस्था की जा रही है, शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। भामाशाहों के माध्यम से फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों के स्तर पर सरकारी विद्यालयों का स्तर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर 12 लाख विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालयों के अन्दर नामांकन बढ़ा है। हमारे रिजल्ट्स का स्तर सुधर रहा है। इससे हम अब यह बात समझ सकते हैं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करके शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इस बात की चिंता की है।

काउंसलिंग के माध्यम से जिस तरह से टीचर्स का ट्रांसफर करने की बात की है, यह अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। हम यह जरूर समझ सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, जन प्रतिनिधियों को आपने साइड में रख करके एक अच्छी व्यवस्था इस प्रदेश में लागू करने का काम किया है।

(श्री अजीत सिंह)

लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, एक थर्ड ग्रेड का टीचर, नौ साल से वह ट्रांसफर के लिये वंचित रह रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकारी की भी आप एक सीमा तक मानें। क्या आवश्यकता है कि जब जिला मुख्यालय पर, डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर, ब्लाक स्तर पर अगर डी.ई.ओ. को अधिकार दे दिया जाये कि वह उसके वहां पर थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर जिले के जिले में कर दिये जाएं, कौनसी दिक्कत आ सकती है, कहां जाएगा? लेकिन उसको एक अवसर मिलना चाहिए। क्यों चिंता नहीं हो, जबकि मैं कहना चाहता हूं। यह अधिकारी ऊपर से चाहते हैं, जिस व्यक्ति का जिले के अन्दर ट्रांसफर कर देते हैं, जिले के बाहर भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमको उससे क्यों वंचित किया जाता है? आज इस बात के लिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इस बात को सोचें। ये अधिकारी हमारे को चलाएं नहीं, अधिकारी को हमारी भी राय मानने का अधिकार है, इस बात की भी आपको चिंता करनी चाहिए। अधिकारी के भरोसे इस शिक्षा नीति को सम्पूर्ण तरीके से चलाने का काम नहीं करें। नवाचार करें, अच्छे काम करें, लेकिन उससे पहले आपको हमारी भी चिंता करनी पड़ेगी। इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्यों नहीं थर्ड ग्रेड टीचर के एक सीमित एरिये में चाहे कहीं भी, ट्रांसफर्स को एक बार खोलने की आज आवश्यकता है। हम बार-बार आपसे कहते हैं। या तो हमें बताएं कि नहीं खोलेंगे। क्योंकि आज आपने जो बात कही है, हमारे पास हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं। ट्रांसफर नीति के अन्दर हमारे को विचार करना चाहिए।

मैं इतना कह सकता हूं कि आज हमारे इस राजस्थान के अन्दर चाहे माडल स्कूल की बात करें, चाहे आदर्श स्कूल की बात करें, मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने का हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, और जो परिवर्तन प्रदेश के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, वह अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज प्राइवेट विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों से कम्पीटीशन करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं हमारे उन टीचर्स ने मेहनत की है। मैं जानता हूं कि यह पूर्व समय का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं थे। अध्यापक थे तो वे विद्यालयों के बाहर राजनीति किया करते थे। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उनको राजनीति से हटाकर वापस शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया है। उनको

(श्री अजीत सिंह)

एक जिम्मेदारी दी है, रिजल्ट्स की उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। आज छुट्टियों के अन्दर भी बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिये, वे गांव में, शहर में, कस्बे में विद्यालय के लिये नामांकन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिल सके, इस बात की चिंता कर रहे हैं। मैं राजस्थान के शिक्षकों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मेरे टोंक के अन्दर एक हायर सैकण्डरी स्कूल में 600 बच्चों का नामांकन वहां पर था। लेकिन चार साल के अन्दर 1800 से ऊपर वहां नामांकन रहा है, 90 परसेंट से ऊपर उस विद्यालय का रिजल्ट रहा है। कहीं न कहीं अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अध्यापकों की चिंता भी आपको और हमको करनी पड़ेगी।

आज मैं इस अवसर पर आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को लैपटाप बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं, स्कूटी बांटते हैं, कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन गरीब बच्चों के लिए आपने चिंता की है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चा टैलेंटेड है, चाहे सरकारी विद्यालय का हो या चाहे प्राइवेट विद्यालय का हो तो लैपटाप बांटने में हम उन प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों को क्यों नहीं जोड़ने का काम करते? वह हमारे प्रदेश का बच्चा है, वह हमारे प्रदेश का टैलेंट है, हमें कहीं न कहीं इस बात की चिंता करनी चाहिए कि सरकारी विद्यालयों की तरह प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी क्यों नहीं लैपटाप बांटा जाए, उनको क्यों वंचित किया जाता है? वह हमारे ही बच्चे हैं। मैं यह जानता हूं कि इस बात का आपको और हमको कहीं न कहीं चिंतन करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

आज विद्यालयों के अन्दर निश्चित रूप से जब बच्चों का नामांकन बढ़ा है तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। आज पानी की बहुत सारे विद्यालयों के अन्दर कमी है। बजट का प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से विद्यालयों के अन्दर पानी की व्यवस्था की गयी। चाहे हैंडपम्प खुदवाया गया, चाहे टंकी लगायी गयी है, चाहे टैंकर के माध्यम से पानी डलवाने का हमने काम किया है।

हम यह कह सकते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार सरकारी विद्यालयों को कैसे, गरीब के बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दिलाई जाए इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण इस प्रदेश में देखने को कहीं नहीं मिल सकता, नामांकन के बढ़ने से, रिजल्ट के माध्यम से।

(श्री अजीत सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे टोंक के अन्दर एक अरबी फारसी विश्व विख्यात शोध संस्थान है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने डिजिटाइजेशन के लिए कि उसका जो जितना भी ग्रंथ है, संग्रह है, उनको पूरा विश्व देख सके उसके लिए 23 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अभी भी मेरे यहां पर विदेशों से स्कालर्स आते हैं, उस विश्वविख्यात अरबी फारसी शोध संस्थान में वहां पर कोई गेस्ट हाउस ढंग का नहीं है, कोई ऑडिटोरियम बना हुआ नहीं है जबकि आप मानेंगे कि नहीं वहां पर आप जाकर एक बार टोंक में पधारें। रामायण का बाल खण्ड जो विश्व में मेरे ख्याल से ऐतिहासिक होगा, वहां पर अरबी फारसी शोध संस्थान में रखा हुआ है। फारसी और अरबी के अन्दर वहां पर रामायण का, गीता का, उपनिषदों का, फारसी और अरबी में उनका अनुवाद करके विश्व में पढ़ाने का काम कर रहा है, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे गौरवशाली इन्स्टीट्यूट को हमें कहीं न कहीं चिन्हित करके उस पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-चार मैं डिमांड कर लूं? सर, यह डिमांड है, हम अब कहां करेंगे? यहां पर नहीं कहेंगे तो हम अपनी बात को कहां पर कहेंगे बताइये? यह समय में आप क्यों बांध रहे हैं?

श्री सभापति: आसन की व्यवस्था की मर्यादा में रहते हुए ...(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह (टोंक): नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, साहब, लेकिन एक दो मिनट दीजिए, मैं कोई ज्यादा अपनी बात को नहीं कह रहा लेकिन मेरी महत्वपूर्ण एक दो डिमांड हैं।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों ने अभी तक आसन की व्यवस्था को माना है और आप भी मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अजीत सिंह (टोंक): मैं मेरे क्षेत्र के लिए, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, आप उनसे कहें कि वह यहां पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सब यहां पर ही हैं।

श्री अजीत सिंह (टोंक): सीट पर नहीं हैं, सॉरी, साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा 1997 में प्रयोगशाला सहायकों के पदों को समाप्त करते हुए अधिशेष घोषित कर अध्यापकों के पदों पर समायोजित किया गया था तब से प्रशिक्षित को अध्यापक के समान तथा अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से अध्यापक के समान वेतन तथा ए.सी.पी. के परिलाभ दिये गये। दिनांक 1.7.2013 से उनके वेतन तथा ए.सी.पी. परिलाभ को कम करते हुए प्रयोगशाला सहायक के सामान कर दिये गये, उससे उनका वेतन ए.सी.पी. का कम कर उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है। अत: निवेदन है कि उन्हें भी अध्यापकों के समकक्ष भत्ते व ए.सी.पी. के परिलाभ दिये जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी देवनानीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सिटी नम्बर-12 में छावनी टोंक एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, कला वर्ग में वहां पर भूगोल, चित्रकला व उर्दू विषय संचालित है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उक्त विद्यालय में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय हिंदी व संस्कृत खोले जाने हेतु कई बार मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इसकी घोषणा करें। वह विद्यालय पूर्ववर्ती सरकार के टाइम उर्दू जैसे विषय को वहां पर खोल दिया, वहां पर बच्चे नहीं हैं, वह पढ़ने से वंचित रहते हैं। आपसे बार-बार आग्रह करता हूं कि वहां पर बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने से रुकते हैं क्यों नहीं आप वहां पर हिंदी और संस्कृत विषय को खोलना चाहते? आज वहां पर महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसा वह विद्यालय शहर के हृदय पर है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इसकी घोषणा यहां पर ही करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से टोंक, जनसंख्या के आधार पर देखिए या क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो बड़ा जिला मुख्यालय है। वहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर स्थित है, उसको स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। इसका मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक): साहब, दो मिनट, एक मिनट में बोल जाएंगे। एक कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खुलवाया जाए ऐसा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन और आग्रह और करना चाहता हूं कि हमारे एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर रनिंग में जो विद्यालय, जो कालेज हैं, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि ऐसी वी.सी. में क्या ताकत है, ऐसी क्या पावर है कि आप रनिंग में चलने वाले तीन साल वाले को भी दे रहे हैं और हमने हमारे किसी के लिए आवेदन किया, आपसे भी आग्रह किया, उनसे भी व्यक्तिगत आग्रह किया तो नियमों के विरुद्ध वह दे सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे भी कहने से उनको दिये जाएं? इस बात की आप जांच करवाएं अगर वी.सी. कोई गलत काम करता है तो उसको रोकने का आपको काम करना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी के वी.सी. की, यह जो जिस तरह की व्यवस्था दी है, जो कानून के नियम के विरुद्ध अगर वह इस तरह का कोई एग्जाम सेंटर देते हैं तो उनकी कहीं न कहीं जांच करवाने की आज आवश्यकता है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, ठीक है हम अपने विषय को पूरा नहीं रख पाए लेकिन फिर भी मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रीजी से और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी एक दो मांग है, कन्या महाविद्यालय को पी.जी. में क्रमोन्नत करें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अजीत सिंह (टोंक): एक, हिंदी और संस्कृत सब्जैक्ट को विद्यालय में खोलने के लिए आज आप मेरी मांग पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय आपदा राहत मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की स्थिति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में दिनांक 4 मार्च, 2018 को हुई ओलावृष्टि के संबंध में जिला कलेक्टर से प्राप्त प्राथमिक सूचना विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला अलवर में 5 तहसीलों के 39 गांवों में लगभग 5 से लेकर 15 मिलीमीटर वर्षा के साथ ओले गिरे जिससे फसलों के नुकसान होने की आशंका है। जान-माल की क्षति के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं।

जिला भरतपुर में 3 तहसीलों में 28 गांवों में लगभग 7 से लेकर 9 मिलीमीटर वर्षा के साथ ओले गिरे जिससे फसलों में खराबा होने की सूचना प्राप्त हुई है। जान-माल की क्षति के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

नागौर जिले में 3 तहसीलों के 38 गांवों में लगभग 3 से लेकर 6 मिलीमीटर वर्षा के साथ ओले गिरे, फसलों का खराबा होने की सूचना प्राप्त हुई है, जान-माल की क्षति के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

सीकर जिले की 6 तहसीलों में 65 गांवों में लगभग 6 मिलीमीटर वर्षा के साथ ओले गिरने की सूचना प्राप्त हुई जिससे फसलों के खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। जान-माल की क्षति के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

इस प्रकार अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में चार जिलों, 17 तहसीलों में 180 गांवों में ओलावृष्टि हुई है।

जयपुर जिले में भी कुछ स्थानों पर लगभग 5 मिलीमीटर वर्षा के साथ मामूली ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है परन्तु फसलों और जान-माल की क्षति की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

जिला चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं आदि में भी वर्षा हुई है परन्तु ओलावृष्टि की सूचना नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 4.3.2018 को ही ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी किये जिसकी पालना में राजस्व विभाग द्वारा फसलों की विशेष गिरदावरी के लिए दिनांक 05.03.2018 को, आज आदेश प्रसारित किया है और अब फसलों के खराबे की वास्तविक स्थिति गिरदावरी के बाद प्राप्त होगी और उसके आधार पर आपदा विभाग को जो-जो भी सहायता किसान को करनी है, वह निश्चित रूप से करेंगे।

श्री सभापति: माननीय श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अभी दे रहा हूं, आपको परमिशन दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: मैंने उनका नाम पुकार लिया, आप बाद में बता देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब मंत्री महोदय ने जवाब दिया है तो मैं एक मिनट में मेरी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और आपने विशेष पैकेज मांगा था 11 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र से, उसमें से कितना प्राप्त हो गया? आज की तारीख में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह विषय अभी का नहीं है, अभी का नहीं है। यह तो पुराना विषय है, आज का विषय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपदा राहत मंत्रीजी, पुराना या नया, यह सदन का मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नो-नो, पहले कब मांगा, क्या मांगा, यह नहीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो आप करवा रहे हो यह कितने दिन में कमप्लीट करके किसानों को राहत प्रदान कर देंगे? यह तो बता दो कम से कम इसमें।

श्री सभापति: हां, यह बता देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत लम्बी जानकारी चाहते हैं पर अपने पुराने इतिहास को देखते नहीं हैं। पिछली बार जो खराबा हुआ उसकी 1950 करोड़ की मैंने यहां से खराबे की सूचना दिल्ली को भेजी और आज सदन में कहते हुए मैं प्रसन्नता महसूस करता हूं कि पहली बार 420 करोड़ रुपया हमें राजस्थान को आपदा में केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किया है। आपके सब सालों को जोड़ लो, सब सालों को, एक दो नहीं और आपको केन्द्र से सहायता, क्योंकि आपने भेजा क्या और मिला क्या, उसकी तुलना करोगे न तो हमने इन तीन सालों में जो भेजा है, उसका लगभग चालीस परसेंट, सेंट-परसेंट तो न पहले कभी मिला, न आज

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मिला है। जो 1950 करोड़ का भेजा उसके अगेंस्ट में भी मुझे 420 करोड़ रुपया मिला है, यह पहली बार हुआ है, केन्द्र सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार कि इतना जल्दी, टीम भी भेजी और टीम के साथ ही हमको आपदा में सहायता भी भेजी।

श्री सभापति: माननीय श्री कैलाशजी भंसाली।

(18.00 बजे)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आदरणीय सभापति जी, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार करने के लिये मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। यहां 15 लाख लोगों की बस्ती है। शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर का नाम एजुकेशन हब के लिये लिया जाता है। जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय है, आई आई टी है, एम.बी.एम. कालेज है और फैशन डिजाइनिंग कालेज है, स्पाइस पार्क है और एस.एन. मेडिकल कालेज के साथ-साथ तीन हास्पिटल्स का काम भी एस.एन. मेडिकल कालेज देखता है। इन सबमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है। इसके बारे में मैंने मंत्रीजी को लिखित में अपना निवेदन किया है।

मेरी कुछ प्रमुख मांगें हैं। जालामन क्षेत्र ऐसा है, जिसमें दो लाख की बस्ती है। वहां पर एक भी कालेज नहीं है और न कोई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सभी सब्जैक्ट्स के साथ अभी तक खोला गया है। मेरा एक विशेष निवेदन है डाक्टर पदमचंद विमला देवी गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दो सब्जेक्ट्स की कमी है। एक कामर्स नहीं है। आजकल लड़कियां कामर्स लेना पसंद करती हैं, क्योंकि सी.ए. और एम.बी.ए. का कोर्स बहुत रोचक हो गया है। इसी के साथ-साथ में होम साइंस और बॉटनी सब्जैक्ट्स के लिये माननीय मंत्री महोदय घोषणा करेंगे।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा की बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है, उसके लिये सरकार व्यवस्था करे। संस्कृत विद्यालय, जोधपुर में धान मंडी में है, सबसे पुराना संस्कृत विद्यालय है सारे राजस्थान में, उसको कालेज बनाने की घोषणा की जाए। आचार्य बहुत हैं और वहां पर स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी तादाद में हैं। मिशन गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल की

(श्री कैलाश भंसाली)

बिल्डिंग ऐसी है, एक बार छत गिर गयी, उससे तीन बच्चियों के चोटें आयीं और इतनी जर्जर हालत में है। मेरा निवेदन है कि एक बार इसकी पूरी बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाकर स्कूल को सौंपी जाए।

फतेहपाल बालिका विद्यालय 104 साल पुराना है, उसकी बिल्डिंग भी बहुत जर्जर हालत में है। अभी भामाशाह योजना के अन्तर्गत कुछ दानदाताओं से पैसा लेकर दस कमरे तैयार कराये गये और मैंने भी दस लाख रुपये उसके लिये दिये हैं।

गुरुकुल विद्यापीठ पद्धति को भी शहरों में प्रारम्भ किया जाये। समाज में इनका बहुत अच्छा परिणाम मिला और कुछ जगह आठ-दस बच्चों की स्कूलें थीं, उनको मर्ज किया गया। यह स्वागत योग्य कदम है, इसके लिये मैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

एस.एन. मेडिकल कालेज में अभी कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। वहां पर शीघ्र ही प्रिंसिपल लगाया जाये, क्योंकि तीन अस्पताल इसके नीचे आते हैं। इनकी अच्छी व्यवस्था हो और वहां स्टाफ में डाक्टर्स और नर्सेज की कमी है, इसके साथ-साथ विशेषज्ञों की बहुत कमी है। विशेषकर डा. पवन शारदा एस एम एस में डेपुटेशन पर हैं, उनको शीघ्र वहां भेजा जाये, क्योंकि कार्डियोलोजी में सिर्फ डा. सिंघवी साहब और विनीत जी हैं। वहां पर कार्यभार बहुत ज्यादा है और मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। (व्यवधान) प्रदेश का मुख्यालय है, वहां पर स्टाफ की अभी कमी है।

संगीत नाट्य अकादमी में अभी तक कोई अध्यक्ष का मनोनयन नहीं हुआ। राज्य सरकार किसी को इसका अध्यक्ष बनाये ताकि कला और संस्कृति का विस्तार हो। जोधपुर की एक बड़ी परम्परा है, जहां सलिल गायन होली पर होता है, उसमें अगर इस तरह की कोई क्लासें होंगी तो अच्छा रहेगा। प्राच्य महाविद्यालय में संसाधनों की कमी है, जगह बहुत है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और पुराने सूत्र बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको ई-श्रेणी से परिभाषित किया जाए।

भामाशाह योजना में बहुत लोगों ने दान दिया है, विशेषकर बिड़ला व्हाइट सीमेंट ने और जे.के. व्हाइट सीमेंट ने जोधपुर जिले में एजुकेशन में बहुत मदद की है। जोधपुर से पढ़े हुए डा. एल.एन. सिंघवी, डा. दलबीर भंडारी, श्री जी.सी. सिंघवी साहब, डा. अशोक माथुर जी और बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी जोधपुर ने दिये हैं। परन्तु आजकल जसवंत कालेज का जो विज्ञान संकाय है,

(श्री कैलाश भंसाली)

उसमें बहुत सारी कमियां हैं। स्टूडेंट्स तो काफी हैं, परन्तु टीचर्स कम हैं और व्यवस्थित ढंग से कालेज चलाया जाये। ऐसा सुना जा रहा है कि उसको पूर्व नरेश खाली करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो और उनसे कृपापूर्वक निवेदन किया जाये सरकार की ओर से, कि यह विद्यालय यही रहें, क्योंकि वह विद्यालय शहर के सेंटर में है। नया परिसर शहर से पांच किलोमीटर दूर है।

हमारे ओरियंटल कालेज में मुख्य अध्यापक नहीं हैं। शौर्य शिक्षण के लिये अभी तक जोधपुर में कालेज या स्कूल नहीं खोला गया है। इसके लिये भी मेरी मांग है।

शारीरिक शिक्षक का प्रदेश में सबसे बड़ा विद्यालय जोधपुर में है। परन्तु उसमें बिल्डिंग बहुत खराब हो गयी है और वह जर्जर हालत में है और कक्षा-कक्षों की बहुत कमी है। सरकार, विशेषकर मंत्रीजी उसमें दिलचस्पी लेंवे।

पूर्व सरकार ने जितना विस्तार हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन वर्षों में पंचायतों में आदर्श विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय और 1600 से ज्यादा विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है और इस बार 1200 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, इसके लिये मैं राजस्थान की जनता की ओर से मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, एक बात और है। जोधपुर में जिस तरह से एजुकेशन हब बना है, उसमें यातायात की व्यवस्था कम है। अच्छे-अच्छे प्रोफेसर अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हैं, इसलिये हवाई सेवाएं यहां अधिक ली जाएं और उसी कम्पनियों द्वारा एयरपोर्ट का विस्तार करवाकर व्यवस्था की जाए जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: एयर कनेक्टिविटी बढ़ायी जाए, विराजें। धन्यवाद। माननीय सदस्य, सुखराम जी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, संस्कृति और कला-मांग संख्या-24 पर आपने बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। शिक्षा से आदमी संस्कारित बनता है। शिक्षा से हीरे की तरह तराशते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥ विद्या से आदमी विनम्र बनता है

(श्री सुखराम विश्नोई)

और विनम्रता पात्रता से आती है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में संस्कार जरूरी है, जिस शिक्षा में संस्कार नहीं, वह शिक्षा कोई काम की नहीं है। शिक्षा में न तो कोई पक्षपात हो, न उसमें किसी तरह का दूसरा दबाव हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपका यह सुराज संकल्प यात्रा का जो घोषणा पत्र था। (व्यवधान)

श्री सभापति: जोधपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजना पड़ता है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप बोल कर रवाना नहीं हो सकते। बोलते ही जा रहे हो।

माननीय मंत्रीजी, आपके सुराज संकल्प में शिक्षा में प्रत्येक उप खण्ड पर एक कालेज की घोषणा की थी आपने और माननीय नेता ने, कि प्रत्येक उप खण्ड पर कालेज खोलेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने सांचौर में कालेज की घोषणा की। कालेज खुला मैडम, और प्रिंसीपल लगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप खण्ड हैं, सांचौर और चितलवाना। वह कालेज बन्द कर दिये। चारों तरफ कालेज खुल गये। मेरे दोनों उप खण्ड वंचित हैं। अगर आप कर सकते हो तो घोषणा जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा में साइकिल की बात कर रहे थे, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, साइकिल इतनी हल्की है कि विद्यार्थियों की कई साइकिलें टूट चुकी हैं। आप अगर नमूना देखना चाहते हो तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आओ, मैं नमूना बता दूंगा कि इतनी साइकिल टूट चुकी हैं। उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है।

इसके साथ-साथ, रंग किसी की बपौती नहीं है। भगवा रंग केवल मात्र हिन्दुओं की जागीरदारी नहीं है। हमारे सूफी सन्त अपनी पगड़ी पीले और भगवे रंग की बांधते हैं। इसलिए रंग साइकिल का हो जाए और फिर हम जीत जाएंगे। जीते तो नहीं आप तीनों उप चुनाव। साइकिलें आपने भगवे रंग की बांटी। केवल मात्र नाटक करने से कुछ नहीं होता है। धरातल पर काम करना पड़ता है।

सभापति महोदय, एकीकरण और समानीकरण के नाम पर, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक चीज की जांच करवा लो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वरणवा गांव है। उसकी सैकण्डरी स्कूल तीन

(श्री सुखराम विश्नोई)

किलोमीटर दूर है। उस वरणवा गांव की प्राइमरी स्कूल आपने बन्द कर दी। पूरे के पूरे बच्चे घर बैठे हैं। आप इसकी जांच करवा लो। इसमें अगर गलत बात निकले तो मुझे आप जो भी दण्ड दोगे, मैं भुगतने को तैयार हूं। कम से कम धरातल पर तो देखना चाहिए। आपने जो एकीकरण किया है, पांचवीं कक्षा के बच्चों को दसवीं में डाल दिया, न तो दसवीं वाले पढ़ पाते हैं और न पांचवीं वाले पढ़ पाते हैं। कम से कम प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो बेकार पड़ी है, फालतू बिखर रही हैं तो कम से कम भवन जिनके पूरे बने हुए हैं, उन जगहों को स्कूल के लिए अलग रखा जाए, इससे पढ़ाई में गुणवत्ता आयेगी। पढ़ाई आगे बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, डार्क जोन जिलों के लिए प्रतिबन्ध जो लगा रखा है, ऐसे जिले हैं, 15-15 साल से, 20-20 साल से शिक्षक दूर बैठे हैं, जहां म्युचल ट्रांसफर हो सकता है, कम से कम ऐसे ट्रांसफर पर तो प्रतिबन्ध हटना चाहिए। बाड़मेर, जालौर या सिरोही जिला है, उनमें यदि म्युचल करना चाहते हैं तो कम से कम वहां से तो प्रतिबन्ध हटना चाहिए।

सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं कहना चाहूंगा कि राइट टू एजुकेशन है, 33 जिलों में 7482 स्कूलों में भौतिक सत्यापन किया गया, बिलकुल आधे लड़के पाये गये। जिस वार्ड में स्कूल है, उस वार्ड का बच्चा वहां पढ़ना चाहिए परन्तु स्कूल में नामांकन नहीं मिला। जब 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने का प्रावधान है तो कम से कम उन प्राइवेट स्कूलों में यह कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। यह सुनिश्चित आप अगले सैशन में करें ताकि गरीब बच्चे वंचित न रह जाएं।

सभापति महोदय, स्कूलों में राजनीति, आपने पहले आदेश जारी कर दिए कि स्कूलों में स्कूल के आगे, कक्षा कक्ष के आगे, जो हमने शिक्षा में सुधार किये, सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य किये, उनके बारे में बोर्ड लगाया जाए या पट्टिकाएं लगायी जाएं, मतलब प्रचार किया जाए। जब लोगों ने विरोध किया तो वह बात आपने बन्द कर दी परन्तु एक से लगाकर पांच तक वास्तविक रिजल्ट देंगे, उसमें आपने ऐसे सर्कूलर जारी किये हैं कि वहां एक पुस्तिका बांटी जाए, जिसमें सरकार की उपलब्धियां होंगी। आज दिन तक 70 सालों में स्कूलों में राजनीति नहीं हुई। आप इस तरह से पुस्तिका बांटना चाहते हो, वह बन्द कर दो। स्कूलों को बिलकुल स्वतंत्र रहने दो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, मंत्रीजी की जानकारी में है या नहीं है...

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो पहले कांग्रेसी थे। कहां से कहां आ गये।

श्री सभापति: सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पहले तो कांग्रेस में थे। फिर भटक कर चले गये बीजेपी में। फिर अब कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हो। चुप बैठे रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पता नहीं कहां थे और कहां आ गये। बोलने की कहां जरूरत है आपको।

श्री हीरालाल (निवाई): कुछ सीखो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब सीखने को तो आठ महीने बचे हैं। आठ महीने में जो कुछ करना हो वह कर लो। फिर तो वापिस आने वाले नहीं हो आप।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी को जानकारी नहीं होगी या होगी आपने पाठ्य पुस्तकों के लिए जो पेपर्स खरीदे हैं पंजाब की तीन फर्मों से, तीन तरह के पेपर आते हैं, वर्जिन पल्प, वुड पल्प और री-साइकिल पेपर जो गजट साया होते हैं, हिन्दुस्तान सरकार के या राजस्थान सरकार के, वह री-साइकिल पेपर पर होते हैं क्योंकि वह ज्यादा समय तक रखने के लिए पेपर सुरक्षित हों। री-साइकिल सबसे हल्का पेपर है। आपने जो आदेश दिया वह दिया है वर्जिन पल्प का दिया है जो लकड़ी से या दूसरे पेड़ पौधों से बनता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन दो सालों के अन्दर कम से कम 21 करोड़ रुपये आपने ज्यादा दिये हैं, 21 करोड़ रुपये कम नहीं होते। आप अगर री-साइकिल पेपर खरीदते, जैसे कि चार पांच स्टेट को छोड़कर तमाम स्टेट्स पाठ्य पुस्तकों में री-साइकिल पेपर ही खरीदते हैं। इसकी जांच करवायी जाए। क्यों और किस कारण से आर्डर दिया गया वर्जिन पेपर का? क्यों 21 करोड़ रुपये ज्यादा दिये? पूरी इसकी जांच करवायी जाए ताकि यह खुलासा हो। जानबूझकर यह आर्डर दिया गया है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप संस्कृत की बात कर रहे हो। जब से भाजपा की सरकार बनी है, संस्कृत में तमाम बातें करो। भोजन मंत्र बोलो, तमाम तरह की बातें करो परन्तु संस्कृत के अन्दर बच्चों की संख्या कम हुई है, 45 परसेंट सीटें खाली पड़ी हुई है। संस्कृत में मानीटरिंग का जो मामला है, संभाग स्तर पर मानीटरिंग करते हैं। न तो ब्लाक स्तर पर है, न जिला स्तर पर है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि संस्कृत विभाग की स्कूल्स की मानीटरिंग आप जिस तरह से पीईओ को अधिकार दे रहे हो, पीईओ को दे दो, बीईओ को अधिकार दे दो, डीडीओ को अधिकार दे दो ताकि समय पर मानीटरिंग हो और उसकी संख्या बढ़े। कई स्कूल ऐसी हैं, आपकी प्राइमरी स्कूल्स उस संभाग में हैं, उस जिले में हैं परन्तु सैकण्डरी स्कूल है नहीं। जब आप प्राइमरी स्कूल चला रहे हो, सैकण्डरी स्कूल के बच्चे कहां जाएंगे? वह स्कूल छोड़ते गये। नामांकन कम होगा। संभाग में तमाम नामांकन कम हुए हैं।

सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक लगाने का आदेश किया था नवम्बर, 2017 में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 10 दिव्यांग पर एक विशेष शिक्षक लगेगा। अभी 22 मार्च को पेशी है हाई कोर्ट में, 87 हजार दिव्यांग मूक बधिर छात्र राजस्थान में पढ़ रहे हैं, 10 का हिसाब लगाया जाए तो कम से दस हजार शिक्षक चाहिए और उसके अंगेस्ट में सिर्फ 200 विशेष शिक्षक ही कार्यरत हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विशेष शिक्षक हैं, दस हजार की भर्ती भले ही मत करो, कम से कम पांच हजार की भर्ती तो विशेष शिक्षकों की की जाए ताकि दिव्यांग और मूक बधिर बच्चे आराम से पढ़ सकें और संस्कृत स्कूल के अन्दर जो डेपुटेशन किया जा रहा है, उसको निरस्त किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया परन्तु पोषाहार में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। वाकई में पोषाहार का कार्यक्रम चलता है। सवेरे स्कूल चालू होते ही वह आता है और बन्द होने के बाद जाता है। जिस तरह से शिक्षक ड्यूटी देता है उसी तरह वह भी हार्ड ड्यूटी देता है इसलिए उसका भी मानदेय बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: Only to the information.

सूचना

सादुलपुर के हमीरवास से एक नौजवान का अपहरण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस थाना हमीरवास में एक 22-23 साल के नौजवान लड़के का पिछले सात-आठ दिन से अपहरण हो रखा है और पुलिस ठण्डे बस्ते में बैठी हुई है। एक मात्र मां-बाप का बच्चा और जिसमें सात-आठ दिन से पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि टीम गठित करके उस मां-बाप को न्याय दें। जिस तरीके से बड़े लोगों का बच्चा अपहरण हो जाता है और पूरी सरकार चिन्तित हो जाती है उसी तरीके से इस बच्चे के लिए सरकार चिन्तित हो जाए। संदीप जाट, उम्र 22-23 वर्ष, गांव सुखावास। अपहरण की तुरन्त प्रभाव से सरकार चिन्तित होकर, एसओजी या बड़ी टीम गठित करके उसको न्याय दिलवाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य नारायण सिंहजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

'अंधकार दूर कर जो प्रकाश फैला दे,
बुझी हुई आशा में विश्वास जगा दे,
जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज,
उसे मुमकिन बनाने में राह दिखा दे,
वो है शिक्षा'

माननीय सभापति महोदय, आदि काल से ही शिक्षा का विकास और प्रसार निरन्तर होता आ रहा है। प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता बनाये रखने के लिए और समय की चुनौती का सामना करने के

(श्री नारायण सिंह देवल)

लिए प्रत्येक देश ने अपनी एक शिक्षा प्रणाली विकसित कर रखी है। सबके लिए शिक्षा आज हमारी बुनियादी आवश्यकता है और संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल में राजस्थान में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हुए हैं। विगत पांच साल की सरकार में हम लोग देखते थे कि कई विद्यालय दो या तीन अध्यापकों के भरोसे चलते थे परन्तु आज मैं कह सकता हूं कि हमारी इस सरकार ने पिछले चार साल में 68 हजार अध्यापकों की भर्ती की है और अभी इसी बजट में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है 77 हजार और नये अध्यापकों की भर्ती की जायेगी। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे स्कूल खाली रहते थे, वो सारे विद्यालय में पद भर जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों का पूर्ववर्ती सरकार में मोह भंग होता जाता था और अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजते थे परन्तु इस सरकार की दूरदृष्टि के कारण और सकारात्मक पहलू के कारण हमारे इन सरकारी विद्यालयों में 12 लाख से अधिक नामांकन की वृद्धि हुई है और पिछले चार वर्ष में 5863 विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया गया है और इसी बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1832 विद्यालयों को और क्रमोन्नत करने की घोषणा की है।

हमारे शिक्षक बंधुओं का कई समय से जो प्रमोशन नहीं हो रहा था, आज 1 लाख 10 हजार के प्रमोशन हुए और यह राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। पूर्ववर्ती सरकार में आये दिन अध्यापकों की ट्रांसफर को लेकर हड़ताल होती रहती थी परन्तु मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक अपनी च्वाईस के अनुसार जहां पोस्टिंग मांगता था वहां पोस्टिंग दी गयी।

इसके अलावा आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एकीकरण और समायोजन में हमारी जो बिल्डिंगें खाली हो गयी हैं तो रख-रखाव और साफ-सफाई नहीं होने के कारण वो बिल्डिंग धीरे-धीरे खण्डहर हो जाएगी, तो उन भवनों का कोई न कोई सरकारी उपयोग हो।

इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े ब्लाक हैं उसमें 134

(श्री नारायण सिंह देवल)

स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल खोले गये। जालौर जिले में जसवंतपुरा उपखण्ड क्षेत्र हैं, मेरी मांग है कि वहां पर स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल खोला जाए।

मेरे से पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने विद्यालय में जो पानी की चिंता की है तो मैं भी इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जहां-जहां, जिन-जिन विद्यालयों में पानी नहीं है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2018-19 के बजट में 17 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है और इसी में रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नये विद्यालय की घोषणा की है। इस निर्णय से हमारे युवा वर्ग में बहुत अधिक खुशी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा कि जुलाई के अन्दर इसकी विधिवत शुरूआत भी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, देश की साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है और राजस्थान की 2011 की जनगणना में पुरुषों की साक्षरता दर 79.2 परसेंट है जबकि हमारा जो जालौर जिला है उसकी पुरुष साक्षरता दर मात्र 54.90 परसेंट है। वहीं जो राजस्थान की महिला साक्षरता की दर है वो 52.10 परसेंट है और जालौर जिले की महिला साक्षरता दर 38.74 परसेंट है जो मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में अंतिम पायदान पर है। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस साक्षरता दर को ध्यान में रखते हुए जालौर जिले में इसके लिए आपको प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ा और आजोदर पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर विद्यालय हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटड़ा में 40 से अधिक छात्र एवं छात्राएं हैं तो वो भी आप घोषणा करें।

जो नई ग्राम पंचायत बनी हैं, जैसे आलड़ी, मैत्रीवाड़ा, सेड़िया, दुगावा वहां पर भी आप हायर सैकण्डरी खोलने की घोषणा करें और जिन पंचायत मुख्यालय में हायर सैकण्डरी स्कूल है परन्तु छात्रों के अनुपात में भवन होना चाहिए, वहां पर कई जगह भवन नहीं है जैसे धामसीन में मात्र छह ही कमरे

(श्री नारायण सिंह देवल)

हैं और बारहवीं स्कूल है, तो मेरी मांग है कि जो ऐसे विद्यालय हैं वहां पर भवन दिये जाएं।

इसके अलावा जो हमारे यूपीएस स्कूल हैं जैसे मीरपुरा, टीटोप, बासनदेवड़ा, सेवाड़िया, बीलड़, मोखातरा, लूणियासर, कालड़ु और वाड़ा, मैं उनको माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा ब्लाक में 39 विद्यालयों में नोर्म्स के अनुसार 66 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है और रानीवाड़ा ब्लाक में 30 विद्यालयों के भवन अतिवृष्टि से या इसके अलावा जर्जर हैं, इनकी भी मरम्मत करने की आवश्यकता है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के तीनों ब्लाक रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और सांचौर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लेवल फर्स्ट के करीब 450 पद खाली हैं, इन पदों को भी भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो भावना है कि विद्यालयों के अन्दर जो कुक कम हैल्पर काम कर रहे हैं, इनका मानदेय मात्र 1200 है तो यह भी बढ़ाया जाए।

इसके अलावा जो प्रबोधक है, इनके बारे में कहना चाहूंगा कि इनका अलग से कैडर है और दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल हो गये हैं, इनकी पदोन्नति नहीं हुई है तो इनकी पदोन्नति की जाए। क्योंकि इसके साथ के जो अध्यापक भर्ती हुए हैं वो आज लैक्चरर बन गये हैं और इनको अभी छह और सात हजार के भरोसे अपना गुजारा करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कला और संस्कृति के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला में सुंधा माता का एक पवित्र मंदिर बसा हुआ है। इस मंदिर में साल में 40 लाख से अधिक लोग आते हैं और इस मंदिर का निर्माण 900 साल पहले राजा चाचिकदेव चौहान ने किया था। इसी श्रृंखला में और मंदिर के पास में महाराणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में अपना काफी समय यहां बिताया था। कुछ खण्डहर के रूप में वहां अवशेष भी विद्यमान हैं। मैं आपके माध्यम से सुंधा माता मंदिर में एक महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की मांग करता हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन की बैठक अभी होली के अवकाश के बाद पहली बार हुई है। मैं सभी सभासदों को होली की बहुत-बहुत बधाई देता हूं और पूर्वोत्तर से तीन रंग की जो गुलाल आई है, वह गुलाल भी अपने विपक्षी साथियों पर छिड़कता हूं, जो आप स्वीकार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बल पर ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा, परन्तु कालांतर में वह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई और धीरे-धीरे शिक्षा के क्षेत्र में भारत पिछड़ता गया। भारत में कभी भी शिक्षा राज्याश्रित नहीं रही, आश्रमों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और वे हमेशा स्वावलंबी हुआ करते थे अथवा अभिभावकों के भरोसे चला करते थे, परन्तु अब पूर्ण रूप से शिक्षा राज्याश्रित हो गई है तो राज्यों का भी यह दायित्व है कि शिक्षा को अच्छी तरह से किस प्रकार से संचालित किया जाए, उसके लिए मेहनत की जाए।

मैं शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि आपने जिस प्रकार से इन पिछले 4 वर्षों में स्कूली शिक्षा में जो परिवर्तन किए हैं, उनसे नए आयाम स्थापित किए हैं। विपक्ष बार-बार यह सवाल उठाता है कि 23 हजार विद्यालय बंद कर दिए गए, मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा कि जब 23 हजार विद्यालय बंद हो गए तो नामांकन कैसे बढ़ा? व्यवस्था को सुनिश्चित और सही तरीके से किया, तब जाकर नामांकन बढ़ा है।

मैंने वे दिन भी देखे हैं जिस समय पिछली सरकार थी, उस समय में मेरे क्षेत्र का टेपू गांव, उसमें सीनियर सैकण्डरी विद्यालय और उसमें विज्ञान विषय और 5 वर्ष तक एक शारीरिक शिक्षक के भरोसे चलता रहा, लगातार विद्यालयों में तालाबंदियां होती रहीं, उन तालाबंदियों की सरकार के नुमाइन्दे आज हमें 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली स्थिति कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

हर पंचायत पर पहले सैकण्डरी पिछली सरकार के दौरान बनाना और अब सीनियर सैकण्डरी, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के अभियान में यह बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि गांव की बेटियां दूर 30-30 किलोमीटर

(श्री पब्बाराम)

तक जाकर कभी भी 12वीं तक की शिक्षा हासिल नहीं कर सकती थीं, आज वे वहां पर शिक्षा हासिल कर रही हैं...और वही विद्यालय जहां पर एक शिक्षक था, आज वहां पर 3 शिक्षक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ऐसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, न शिक्षा मंत्री, न उच्च शिक्षा मंत्री, न मुख्य सचेतक, न उप मुख्य सचेतक, न संसदीय कार्य मंत्री और न 20 का कोरम पूरा, क्या सदन चल रहा है।

श्री सभापति: बैठें, विराजें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): वे सब सुन रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने सुनी, तभी जाकर के ये सभा की व्यवस्था बनी।

श्री सभापति: कोरम पूरा है, विधिवत चल रहा है। कोरम पूरा है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी पिछली सरकार के समय शिक्षा विभाग में स्थानांतरण एक प्रकार का उद्योग बन गया था। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी ने काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को पोस्टिंग देने का जो कार्य किया है, शिक्षक अपनी मर्जी से जहां पर 3-4-5 स्थान दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक जगह चयनित करके वहां पर जा सकता है। हमारा बर्डन भी कम हुआ और विपक्ष का भी। ये कहा करते थे कि हमारे शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, हम कहते कि हम नहीं लगाते हैं, उनके पास में भी अभी शिक्षा का कोई टीचर नहीं जाता कि हमें कहीं पर लगा दो।

इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा रहा हूं, शिक्षा विभाग में मैंने 30 वर्ष गुजारे हैं। मैंने वह समय भी देखा है जब 1 शहर के विद्यालय में 5 स्टूडेंट्स और 15 शिक्षक। पिछली सरकार के दौरान समानीकरण के बहुत प्रयास किए गए, परन्तु इच्छा शक्ति की कमी के कारण वे निष्फल हुए और सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए। मैं शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा जितने स्टूडेंट्स हों, उतना ही स्टाफ हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद वहां से पद समाप्त हुए और 15-15 जो शिक्षक थे, जो 5 स्टूडेंट्स के ऊपर बैठे थे, वह 5 स्टूडेंट्स वाला अनार्थिक विद्यालय क्या चलने योग्य था, पर उसको मर्ज कर दिया। कौन-सा बुरा हो गया? कौन-सा सरकार का बुरा हो गया? कौन-सा राज्य का बुरा हो गया?

इस प्रकार के विद्यालयों को बंद करने की स्थिति तो होनी ही चाहिए

(श्री पब्बाराम)

और वे 15 शिक्षक हमारे गांवों में लगे हैं। मैंने वह समय भी देखा है, जब हमारे इंटीरियर के पूरे मेरे क्षेत्र में, पूरे फलौदी कांस्टीट्यूएंसी में एक भी गजेटेड अफसर, कोई प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक नहीं होता था, सिर्फ एक हैड-क्वार्टर पर होता था, आज इंटीरियर के अन्दर प्रधानाचार्य लगे हुए हैं। 1 लाख 10 हजार का जो प्रमोशन दिया है, वह ऐतिहासिक प्रमोशन है, आपके सम्पूर्ण कार्यकाल में देख लो, आपने इतने प्रमोशन नहीं दिए।

मैं शिक्षा मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं, आपने शिक्षकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। मैंने यहां पर मेरे अपने साथी लैक्चरर्स को देखा है, लैक्चरर्स लगने के बाद में पूरा कार्यकाल समाप्त करके सेवानिवृत्त भी उसी पद पर हो जाते थे, ये दिन उन शिक्षकों ने देखे हैं और आज खुशी से वे अपना प्रमोशन पा रहे हैं, तनख्वाह उनकी बढ़ रही है और लोगों को राहत मिली है, बच्चे उनके गांवों के अन्दर पढ़ने लगे हैं। बहुत बड़ा एक आमूलचूल परिवर्तन करने का आपने साहस किया है, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको बधाई देता हूं।

इसी प्रकार से एक नई व्यवस्था और शुरू की है आपने। एक BEO, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, तहसील हैड-क्वार्टर के ऊपर वह हुआ करता था, 200 विद्यालय, मॉनिटरिंग करना मुश्किल, उसी पद का जब उसी पंचायत के अन्दर अधिकारी बैठा है तो क्यों न उसको यह सारी व्यवस्था संभलवा दी जाए ताकि मानिटरिंग भी कर ले और वहां पर अच्छी तरह से शिक्षा संचालित हो, ये सारी बातें देख सके और इसीलिए, BEO के माध्यम से ये सारी जो नई व्यवस्था कायम की है, इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। पहले सरकारी विद्यालयों के छात्र कभी भी, मैरिट में बहुत कम आते थे। आज मैरिट में आने लगे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब दी जा रही है, तभी तो यह सम्भव हुआ है।

5863 विद्यालयों का क्रमोन्नयन, 'न भूतो, न भविष्यति', ऐतिहासिक कदम। इस साहसिक कदम के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षक हूं, इसलिए 5 मिनट का समय आपको अवश्य देना चाहिए।

श्री सभापति: यह आसन से व्यवस्था दी हुई है, उससे हम सभी बाध्य हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आप थोड़ा रहम करें। अभी पंचायती राज के अन्दर शैक्षणिक योग्यता आवश्यक कर दी तो सारा आपका सिस्टम ढह गया। अब पढ़े-लिखे लोग ही आते हैं, तब जाकर के तकलीफ हो रही है, जब सीनियर सैकण्डरी में 74 परसेंट बढ़ गया नामांकन।

इसी प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी 5854 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये हैं। कैसे नहीं बने?

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अपने क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं मुझे बिठाने के लिए और समय की भी पाबंदी है। मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से 40-40 किलोमीटर की परिधि के अन्दर एक पंचायत है और हैडक्वार्टर से 13 किलोमीटर दूर के विद्यालय को क्रमोन्नत कर दिया। (व्यवधान) अब वो हैडक्वार्टर से विद्यालय 13 किलोमीटर दूर है और उसके चारों तरफ 13 किलोमीटर की परिधि में कोई सीनियर सैकण्डरी विद्यालय नहीं है और वह हैडक्वार्टर की स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुई है। वहां की बच्चियां आज भी सीनियर सैकण्डरी की पढ़ाई से महरूम हैं इसलिए कृपया उसको अवश्य क्रमोन्नत करने की कृपा करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से संस्कृत विद्यालयों में स्टाफ की जबरदस्त कमी है। इसके लिए भी मेरा आपसे आग्रह है कि संस्कृत विद्यालय के अन्दर भी स्टाफ सही ढंग से दिया जाए। अभी आपने, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 1832 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कि हैडक्वार्टर के विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि आप विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से पहले कम से कम हम से चर्चा तो कर लें। जो विभाग के लेवल पर आपके पास में प्रस्ताव आए हैं वो कई त्रुटिपूर्ण हैं। जो 15 स्टूडेंट्स की स्कूल है और जिसके अन्दर छठी, सातवीं, आठवीं के अन्दर छात्र नहीं हैं उस विद्यालय का क्रमोन्नयन करने के लिए आपके पास में प्रस्ताव आ गया जबकि हैडक्वार्टर वाले का नहीं आया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए, कम से कम हमसे चर्चा करने के बाद में उसका क्रमोन्नयन किया जाए। मेहरबानी करके जो आपने राइडर रखा है 40 छात्रों का कि 10वीं में 40 छात्र हों तो 12वीं हो सकती है तो कृपया उस राइडर को

(श्री पब्बाराम)

हटा दीजिये। आपने जब शुरू में 5 हजार से अधिक विद्यालय क्रमोन्नत किये उस समय कोई राइडर नहीं रखा तो आज भी कोई राइडर मत कीजिये और एक साथ उसी स्थिति में वापस इनको क्रमोन्नत करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) धन्यवाद, माननीय शिक्षा मंत्रीजी। कुछ दूरस्थ विद्यालय हैं, जब 13-13, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर..

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने हां कर दी है और माननीय सभापति महोदय, हाथों-हाथ मिल रहा है तो एक-दो और बोलूंगा तो और रिजल्ट मिलेगा और एक-दो मिनट का समय और दिया जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। अब विराजें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अब मैं उच्च शिक्षा के बारे में 2-3 बातें कह देता हूं। हमारे एक नीतिगत फैसला लिया गया था कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की मर्यादा के काफी ऊपर हो चुका है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): यह नीतिगत बात है, मेरे को कहने दो।

श्री सभापति: नीतिगत बात है पर समय की मर्यादा अपनी जगह पर है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आप प्लीज, शिक्षा से जुड़े आदमी के साथ में इस तरह से क्रूरता मत दिखाइये। आप बड़े दयावान हैं, कृपया आप दो ही मिनट दे दें। दो मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूंगा। दो मिनट के बाद आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: समय समाप्त हो चुका है। दो मिनट सम्भव नहीं है। एक मिनट आपको।

श्री पब्बाराम (फलौदी): प्रारम्भिक और माध्यमिक दोनों के जो द्वितीय के पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का नीतिगत फैसला हुआ है उसमें फलौदी के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय प्रारम्भिक और माध्यमिक दोनों स्थानांतरित किए जाएं। राजकीय महाविद्यालय, फलौदी और बाप में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरे जाएं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे दोनों उपखण्डों पर कालेज हैं और पिछली

(श्री पब्बाराम)

साल आपने बाप में बनाया परन्तु बाप में सिर्फ एक प्रधानाचार्य के भरोसे वो कालेज चल रहा है इसलिए कृपया उसको ठीक करें।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्या सोना देवी जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसी प्रकार से राजकीय महाविद्यालय, फलौदी में वाणिज्य वर्ग में व्यावसायिक प्रबन्धन एवं विज्ञान वर्ग में प्राणी शास्त्र में पी.जी. का कोर्स शुरू किया जाए। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने बोलने का समय प्रदान किया। तीन-चार बार डिस्टर्ब करने के बाद में आपने फिर भी मुझ पर कृपा की इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज की डिमांड 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद साहब।

सर्वप्रथम डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा नमन जिन्होंने कहा था कि 'शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीकर इंसान दहाड़ लगाता है।'

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। पिछले चार साल से मैं विधान सभा में बार-बार मांग कर रही हूं कि रायसिंहनगर में शहीद भगत सिंह कालेज को सरकारी किया जाए लेकिन आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से आंसर आया कि गुणावगुण के आधार पर खोला जाएगा। एक नया वर्ड सरकार ने और सीख लिया। पहले तो कहा करते थे कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा और आजकल कहने लगे हैं कि गुणावगुण के आधार पर। मैं मांग करती हूं कि श्री विजयनगर तहसील में भी एक गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज खोला जाए। मैं मांग करती हूं कि जो आपने पूरे प्रदेश में पंचायत हैडक्वार्टर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले हैं पर मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायत हैडक्वार्टर को आप भूल गये हैं जिनमें डाबला, लिखमेवाला और 43PS है। मैं इस ओर भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इनको भी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया जाए और इसकी मैं मांग करती हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जहां-जहां भी ये स्कूल हैं, चाहे आदर्श स्कूल है, चाहे वो सीनियर है, चाहे टैंथ का, आठवीं का, प्राइमरी का, जो भी है वहां शिक्षकों का अभाव है तो वहां पर सब्जैक्ट अकोर्डिंग टीचर होने चाहिए,

(श्रीमती सोनादेवी)

यह मैं मांग करती हूं। साथ ही विद्यालय में जितने स्टाफ की जरूरत है उतनी शिक्षक भर्ती आप करें, मैं यह भी मांग करती हूं।

रायसिंहनगर शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजा गंगासिंह के द्वारा खुलवाया गया था जिसका भवन आज पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है। विशेष बजट देकर इस भवन का निर्माण करवाया जाए यह इसमें खेलकूद के लिए स्टेडियम है तो उसे भी बजट की राशि आबंटित की जाए यह भी मैं मांग करती हूं।

पिछले बजट में पूरे राजस्थान में सरकार को चार ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के संस्थान खोलने थे जिनमें से एक रायसिंहनगर के रामजीवाला में भी खुला था जो अभी तक नहीं खुला है जिसकी घोषणा पिछले बजट में की थी। दूसरे बनकर तैयार हो गये हैं पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ आपने भेदभाव *** क्यों किया यह मैं जानना चाहती हूं और मांग करती हूं कि यहां रामजीवाला में भी खोला जाए।

श्री सभापति: एक मिनट रुक माननीय सदस्या। +++ शब्द को वापस लें। इसको डिलीट करो।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सर, मैं मेरा शब्द वापस लेती हूं और इसकी जगह भेदभाव लिखा जाए, यह मैं मांग करती हूं।

इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जरूरी है और इससे शारीरिक विकास होता है इसलिए इसके लिए सीबीएसई की तर्ज पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक विषय को कक्षा एक से दस तक अनिवार्य तथा कक्षा 11 से 12 तक ऐच्छिक किया जाए। छात्र अनुपात संख्या 120 की नामांकन की बाध्यता को समाप्त करते हुए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद अनिवार्य रूप से दिया जाए यह मैं मांग करती हूं।

तीसरी मैं मांग करती हूं कि शूटिंग बालीबाल खेल को भी दूसरे खेलों के बराबर मान्यता दी जाए। इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि भातीवाला ग्राम पंचायत का 1APD ग्राम मेरे विधान सभा क्षेत्र का ऐसा ग्राम है जिसके सुखचैनपुरा ग्राम पंचायत भी लगती है और भातीवाला ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर भी लगता है तथा वो जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पंचायत हैडक्वार्टर भातीवाला कहता है कि यह सुखचैनपुरा का है और सुखचैनपुरा वाले कहते हैं कि यह भातीवाला का है तो उसके चारदीवारी भी

(श्रीमती सोनादेवी)

नहीं है, खेल का मैदान भी नहीं है, भवन भी नहीं है, टीचर भी नहीं है इसलिए मैं स्पेशल मांग करती हूं कि 1APD की जो प्राइमरी स्कूल है इसमें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए।

(18.49 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ ही आज के युग में कम्प्यूटर शिक्षा बहुत जरूरी है और इसके लिए राज्य में 4500 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा, आईसीटी योजनान्तर्गत कम्पनियों के अधीन ठेके पर चल रही थी जिसका द्वितीय चरण 31 अगस्त, 2015 को पूर्ण हो गया जिससे विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित हो गए एवं 4500 कम्प्यूटर अनुदेशक बेरोजगार हो गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा के कार्य का लाभ देते हुए नियमित करने की कृपा करें और कम्प्यूटर शिक्षा से विद्यार्थी वंचित न रहे, इसकी भी मैं मांग करती हूं। बहुत से विद्यालयों में अध्यापक नहीं है तो मैं यह भी मांग करती हूं कि इनकी पूर्ति की जाए।

राजकीय विद्यालयों में सभी श्रेणियों जैसे HI, VI, MR, CP, LD, MD, AUT के 87798 दिव्यांग छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।

तृतीय श्रेणी शिक्षक रीट भर्ती 2017 में विशेष शिक्षकों के पद भी भरे जाएं जिससे कि इन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा मिल सके। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 243 विशेष शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, जो कि आंकड़ा बहुत ही कम है। मैं मांग करती हूं कि इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

इसके साथ ही जो कुक कम हैल्पर हैं। सभी आपके भी बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि इनका मानदेय बहुत कम है, 1,200 रुपये ही है। मैं भी मांग करती हूं कि इनका 2,000 से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, जितना आप कर सकें, 5,000, 6,000 रुपये उनका मानदेय किया जाये।

इसके साथ ही आज मैं मांग करती हूं कि बावरी जाति अनुसूचित जाति को विशेष पैकेज देकर जयपुर में, राजधानी में छात्रावास खोला जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 एनपी में आठवीं का स्कूल है, बावरी जाति, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी वहां हैं, एससी जाति के विद्यार्थी हैं। मैं

(श्रीमती सोनादेवी)

मांग करती हूं कि 26 एनपी का जो आठवीं तक का स्कूल है, उसको 10वीं किया जाये, 40 एनपी, बावरी समाज का ही पूरा का पूरा गांव है, उसमें भी 10वीं का स्कूल है। मैं मांग करती हूं कि वह स्कूल 12वीं तक किया जाये।

अराइयांवाली बरानी बोर्डर पर है, सीमा पर है, जीरो लाइन पर है। वह भी बावरी समाज का सबसे बड़ा, बावरी बहुल क्षेत्र का गांव है। इसमें मैं मांग करती हूं कि जो आठवीं का स्कूल है, उसको 12वीं का किया जाये।

इसके साथ ही बिलोचिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्षतिग्रस्त भवन है। उसमें बच्चे बैठते हैं। कभी भी छत गिर सकती हैं। जो आदर्श नाम का है। आपने खानापूर्ति के नाम से बोर्ड के ऊपर आदर्श लगाया है। मैं मांग करती हूं कि धरातल पर उसको आदर्श बनाएं, उसमें भवन बनाएं ताकि वहां के बच्चे इसका लाभ ले सकें तथा वे बच्चे यह नहीं सोचें कि कभी भी हम पर यह छत गिर सकती है। बिलोचिया ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर है। इसमें भवन की मैं मांग करती हूं।

मैं मांग करती हूं कि गवर्नमेंट कालेज दिया जाये। उच्च शिक्षा मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करती हूं कि रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर में गवर्नमेंट कालेज दिया जाये। 000

जय हिन्द, जय भारत। जय भीम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये लास्ट कपल आफ लाइन्स हैं न, सारी की सारी इसको Don't record it. Don't record it. श्रीमती राजकुमारी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और सभी सदस्यों ने शिक्षा विभाग की जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बताया। चार साल पहले माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जर्जर हालात में स्कूलों को देखा तो उनके मन में, उन्होंने उसी टाइम यह ठान लिया कि मैं सरकार में आऊंगी तो शिक्षा पर विशेष योजना बनाऊंगी और इस पर काम किया माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने। सबसे पहले 2014 में सरकार ने गांव-गांव में, हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर 12वीं तक के स्कूल खोले।

(श्रीमती राजकुमारी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जिस हालात में स्कूलों को छोड़ा था, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं थी और शिक्षक भी नहीं थे। जहां शिक्षक थे तो वहां बच्चे नहीं थे। इस तरीके की राजनीति जैसा कि डेपुटेशन पर अपने चहेते टीचर हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनको नजदीकी विद्यालयों में डेपुटेशन पर लगाया जाता था। ऐसी कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा पर काम किया। अभी विपक्षी सदस्य कह रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने 60 साल देश में शासन करने के बाद में भी शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा और हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था। इसको देश में अग्रणी राज्यों में लाने का काम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया और शिक्षा मंत्रीजी ने किया। बहुत सारी योजनाएं लायी गईं। आप गांवों में देखोगे तो सरकारी बिल्डिंग चमकती हुई दिखाई देंगी। जहां बिल्डिंग नहीं थी, वहां बिल्डिंग्स के लिए भी पैसा दिया। हर जगह भवन बनाये, उनकी साफ-सफाई की। स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दिया। बालक-बालिकाएं स्कूल में पढ़ते थे, उन लोगों के लिए शौचालय नहीं हुआ करते थे। विद्यालय में ही गंदगी फैली रहती थी। यह काम पूर्ववर्ती सरकार ने क्यों नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार का सोच कभी विकास के प्रति रहा ही नहीं। अगर जनता के प्रति सोचा है और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। चाहे पूर्व में माननीया वसुन्धराजी का राज रहा हो, चाहे भैरोंसिंहजी का शासन रहा हो, जब-जब बीजेपी का शासन आया तो शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम किया। पिछली बार जब भैरोंसिंहजी की सरकार थी, उस टाइम में साक्षरता अभियान चलाया और साक्षरता अभियान के द्वारा लोगों में जागृति पैदा की। बालिका शिक्षा के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी योजनाएं लागू कीं। जैसाकि विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि साइकिल का वितरण किया। आप लोगों को क्या दिक्कत थी? बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण की। जो बालिकाएं दो-तीन किलोमीटर पैदल चलती थीं, उनके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने योजना बनाई और उन बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण की। आपको उससे भी परेशानी होने लगी। जैसे स्कूटी वितरण बालिकाओं के लिए, लैपटाप। आप लोगों ने क्या बांटा? आप लोगों ने चुनाव के टाइम पर साड़ियां बांटी या सीएफएल बांटे तो क्या उनमें घोटाला नहीं दिखाई दिया आपको? मुझे लगता है कि साड़ियों का वितरण जो किया, स्वाभिमानी जनता ने उसको नकारा और आपको 21 सीट राजस्थान में दी।

(श्रीमती राजकुमारी)

मैं शिक्षा मंत्रीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो बेटियों के लिए शारदा बालिका छात्रावास, विवेकानन्द माडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, लैपटाप वितरण, साइकिल वितरण, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना और जो बच्चियां दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी सरकार ने लागू की है। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

कुछ मांगें मेरे क्षेत्र की हैं। मेरा हिण्डौन शहर है, वह जिला मुख्यालय से भी बड़ा कस्बा है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार से बहुत मांगें करते रहे लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी माननीया किरणजी माहेश्वरी को और माननीया मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने पिछली बार हमारा कालेज है, उसको पीजी कालेज किया और उसमें विज्ञान विषय भी खोला। उसमें कुछ शिक्षकों की कमी है, उन विषय के लैक्चरर की भी आप व्यवस्था करेंगे। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मांग करती हूं।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि कुछ विद्यालय ऐसे छूट गये थे, आपने हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक का विद्यालय किया लेकिन कुछ जगह पर प्राइवेट स्कूल चल रहे थे। उस कारण से वहां पर 12वीं तक के स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो पाये तो मैं आपसे मांग करती हूं, आपसे निवेदन करती हूं कि इस साल इन विद्यालयों को, ग्राम पंचायत के विद्यालय लहचोड़ा, जोल, दांदालपुर, झारेड़ा और ढेरा, ये मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ विद्यालय वंचित रह गये हैं। इनको भी 12वीं में क्रमोन्नत करने के लिए आपसे निवेदन करती हूं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो आठवीं तक स्कूल हैं और जिनमें छात्र संख्या बहुत अधिक है।

(19.00 बजे)

और दूरदराज में दसवीं तक स्कूल है, बारहवीं तक स्कूल है तो शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करती हूं कि रिझवास और सौमली, आरणिया का पुरा और कर्मपुरा, एकोरासी ये पांच विद्यालय ऐसे हैं, इनको दसवीं तक के लिए आप माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा विभाग के मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने चार साल में ऐतिहासिक कदम उठाये और बहुत अच्छे कार्य किये। शिक्षा विभाग में जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है।

(श्रीमती राजकुमारी)

विपक्षी सदस्यों को मैं कहना चाहती हूं कि आपके क्षेत्र में कितने विद्यालय खुले, उनके लिए आप एक बार मंत्रीजी को धन्यवाद और मुख्य मंत्रीजी को जरूर देते, क्योंकि शिक्षा के लिए हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए।

शिक्षा के लिए आज हमारे जो बालक हैं वे किस तरीके से सरकारी विद्यालयों में जो प्रोत्साहन सरकार ने किया है, पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते थे और आज सरकारी विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं, छात्र संख्या बढ़ी है। इसलिए, मैं मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद देते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सुबह से इंतजार कर रही हूं लेकिन शाम को टाइम मिला है और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी विधान सभा के क्षेत्रवासियों की तरफ से जो होली का त्यौहार निकला है इसकी आप सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और शिक्षा विभाग के मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सुलभ, सांस्कृतिक और अच्छी शिक्षा देने का कार्य पूरे राजस्थान में किया है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों मंत्रियों को, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो देश में सर्वांगीण विकास कर पाएंगे।

इसका उदाहरण हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी का मैं देना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे विश्व में भारत माता की जय-जयकार करवा रखी है, मां भारती की जय-जयकार करवा रखी है और एक हमारा विपक्षी दल है, कांग्रेसी भाईयों का जिनको पता भी नहीं कि जय किसकी बोलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलनी चाहिए या व्यक्ति विशेष की जय बोलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो बच्चों को आठवीं तक फेल ही नहीं करेंगे यह निर्णय लिया था और एक हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हैं, इन्होंने आठवीं और दसवीं की योग्यता जो राजनैतिक दल है चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, इसके अन्दर योग्यता दिलवाने का जो काम किया है, पढ़े-लिखे लोग आएंगे तो ये अच्छे काम करेंगे।

(श्रीमती द्रोपती)

उपाध्यक्ष महोदय, ये मन्दिर है पूरी सात करोड़ जनता का, आज जिस सदन में हम बैठे हैं, सात करोड़ जनता का यहां निर्णय होता है। लेकिन, शिक्षा का आज का दिन है और मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से कुछ माननीय सदस्य ऐसी भाषा का उपयोग यहां पर करते हैं, वो वास्तव में निंदनीय है। ऐसी गलत भाषा यहां यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि, इसे मन्दिर मान सकते हैं हम सात करोड़ जनता का, जहां फैसला होता है इनके हक में, जनता के हक में तो ये शिक्षा का महत्व हम बता सकते हैं कि इन साठ सालों में इन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा दी है जिसका माननीय सदस्य कई बार भाषा का सदुपयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय किरण जी माहेश्वरी से मांग करती हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में दो उपखण्ड लगते हैं। एक तहसील पीलीबंगा और एक तहसील रावतसर। दोनों उपखण्डों पर सरकारी महाविद्यालय नहीं है। बच्चों को महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नोहर जाना पड़ता है, जो बहुत दूर है। पीलीबंगा और रावतसर उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी कालेज स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूं।

मैं उच्च शिक्षा विभाग मंत्री से बच्चों के भविष्य के लिए आईटीआई महाविद्यालय स्वीकृत करने की भी मांग रखती हूं कि रावतसर और पीलीबंगा में आईटीआई कालेज खोले जाएं।

हनुमानगढ़ जिला एक कृषि प्रधान जिला है, यहां पर बहुत ज्यादा किसान खेती करते हैं तो मैं एक मांग यह भी करती हूं कि हनुमानगढ़ जिले में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किया जाए ताकि वहां पर कृषि क्षेत्र है, वहां कृषि की भी शिक्षा प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावतसर के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय को भी स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने वाले विद्यालयों का मैं नाम बोलती हूं। मैं मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि मेरे ये स्कूल हैं जिन्हें क्रमोन्नत किया जाए- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 16 डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 7 डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 4 एसपीडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंहपुरा,

(श्रीमती द्रोपती)

राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय चक हरिराम वाला, ग्राम पंचायत डबलीबास चुगता, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 26 पीबीएन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठाकुरूवाला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकोका ये ऐसे विद्यालय हैं इनकी आपसी पंचायत की 7-8-10 किलोमीटर तक की दूरी है तो इनको उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। मैं मंत्रीजी से आग्रह करती हूं।

एक और मैं मांग करना चाहूंगी मंत्रीजी से कि प्रत्येक संभाग स्तर पर सैनिक स्कूल खोला जाए, ताकि बच्चों में सेना के प्रति और देश के प्रति वातावरण बने। जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और बच्चों में सैनिकों के प्रति भी अच्छी भावना जागेगी, सम्मान पनपेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं से बारहवीं में स्कूल क्रमोन्नत होने वाले भी नाम बोलूंगी। जो दसवीं से बारहवीं के स्कूल करने की कृपा करेंगे मंत्रीजी ग्राम पंचायत बुधवालिया, ग्राम पंचायत लालपुरा, ग्राम पंचायत किंकरालिया, ग्राम पंचायत सरदारपुरा खालसा, ग्राम पंचायत कनवाणी, ग्राम पंचायत खेदासरी, ग्राम पंचायत भैरूसरी, ग्राम पंचायत पीलीबंगा, ग्राम पंचायत डींगवाला।

इसी तरह से गांवों में हम लोग जाते हैं तो वहां पर लोग मांग करते हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, वहां शिक्षा का जो विषय है वो अपनी इच्छानुसार हो जैसे- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलुवाला, यहां छात्रों की संख्या 900 है और यहां जो संकाय है वो कला वर्ग है, तो इनको जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में किया जाए तो वहां बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

इसी तरह से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीलीबंगा शहर का भी है यहां 750 बच्चों की संख्या है, कृषि विज्ञान या वाणिज्य वर्ग का विषय खोला जाए तो उनको लाभ मिलेगा।

इसी तरह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबली राठान, यहां विज्ञान वर्ग की मांग हो रही है। बहुत सारे गांव इसमें आते हैं डबली, चुगता, डबली मौलबी, डबली मिडारोही, डबली पेमा आदि गांव हैं। जिनको विज्ञान वर्ग से वंचित रखा गया है, यहां विज्ञान वर्ग खोला जाएगा तो इनको लाभ मिलेगा।

(श्रीमती द्रोपती)

इसी तरह से बड़ोपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखड़ावाली, सूरावाली, लिखमीसर इनमें भी विज्ञान वर्ग, कृषि विज्ञान की मांग करती हूं कि यहां पर भी यह विषय खोला जाए ताकि बच्चों को लाभ हो।

इसी तरह से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावतसर, इस विद्यालय में 485 बालिकाएं पढ़ती हैं, सभी गरीब तबके की हैं। उपाध्यक्ष महोदय यह सेम ग्रस्त क्षेत्र है मेरा रावतसर तो यहां पर कमरों की बहुत ज्यादा कमी है बारिश के समय में पानी भर जाता है तो बच्चों का बाहर पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है कमरों के अन्दर भी नहीं जा पाते। यहां पर कम से कम 7 कमरों की जरूरत है, तो मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि ये 7 कमरे भी बनवाने के आप कृपा करें।

इसी तरह से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोलूवाला, निवादान में भी 373 बालिकाएं पढ़ रही हैं। वहां कला वर्ग संचालित है, विद्यालय में 8 कमरों की जरूरत है और कला वर्ग में राजनीतिक विज्ञान और इतिहास विषय भी स्वीकृत करने की आवश्यकता है तो वहां पर भी ये विषय स्वीकृत किये जाएं, ताकि उनका लाभ मिले।

कक्षा-कक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है मैं कुछ विद्यालयों के नाम बोल रही हूं तो उनमें कक्षा कक्षों की भी पूर्ति की जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोलूवाला निवादन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका लौंगवाला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 7 एलजीडब्ल्यूए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, मानक थेड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 एसटीबी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 एसपीडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 75000 आरडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संख्या-3 एमओडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 एलजीडब्ल्यू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठाकरूवाला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 24 पीबीएन ए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, 29 डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, 21-22 डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नं. 1-23 डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नं. 2-डीडब्ल्यूडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 आरडब्ल्यूएम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 16 डीडब्ल्यूडी, राजकीय

(श्रीमती द्रोपती)

उच्च प्राथमिक विद्यालय, 3 आरडब्ल्यूएम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 4 केडब्ल्यूएम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भैरूसरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 एसपीडी-बी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2 जेडब्ल्यूएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 10 रावतसर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रावतसर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, उतरादावास रावतसर ये विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालयों में कक्षा कक्ष की जरूरत है तो ये भी पूरी की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग और करूंगी कि जो अध्यापक प्रतिबंधित जिलों में हैं, 8 से 10 साल तक वो वहां सर्विस करते हैं। उनके घर में बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। कई बार मिसेज बीमार रहती है, कई बार बच्चे बीमार होते हैं। घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है और वह घर से दूर चला जाता है और अपना जो भारत देश है जो राजस्थान है, संयुक्त परिवार में निवास करते हैं तो ऐसे में कोई कर्मचारी बाहर डार्क जोन में जो आते हैं उनकी एक समय-सीमा बांध दो कि इतने साल ये सर्विस वहां करेगा उसके बाद उनको अपने जिले में स्थानांतरण करने का भी आप नियम बनाएं कि वह अपने गृह जिले में भी आ जाए।

इसी तरह से मैं अंत में एक और मांग करना चाहूंगी कि जो सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे हमारी ग्राम पंचायत कालीबंगा में तो यहां पर देशी-विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं तो कला और संस्कृति के अन्दर भी यहां मैं मांग करती हूं कि कालीबंगा को विश्व धरोहर के तहत विकसित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया। आने के बाद में हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ग्राम पंचायतों में गये। स्वागत का कार्यक्रम हुआ। वहां पर एक ही आवाज आ रही थी कि किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जहां पर भी गये यही

(श्री नाना लाल अहारी)

आवाज आयी। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक कदम लेकर 1 लाख 9 हजार 622 अध्यापकों को पदोन्नति देकर प्रत्येक विद्यालय में चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो दसवीं का स्कूल हो, प्रधानाध्यापक लगाने का काम किया और वह अध्यापक वर्षों से बैठा-बैठा विचार करता था कि ऐसी कोई सरकार आयेगी या कोई मंत्री आयेगा, हमारी सुध लेगा, हमारी डीपीसी करेगा, हमारा प्रमोशन करेगा। इस प्रकार का अगर ऐतिहासिक काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कई विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाये कि शिक्षा में यह कर दिया वो कर दिया। इनके कार्यकाल में राजीव गांधी पाठशाला खोली। आठवीं और दसवीं का अध्यापक लगा दिया सीधा-सीधा, जिसको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई शिक्षा नहीं दी। शिक्षा का भट्ठा बैठाने का काम इन्होंने किया। अगर उसके बाद में देखा जाए तो 2008 में वापस सत्ता इनके हाथ में गयी। बच्चों का नामान्तरण कर लिया चाहे बच्चा बकरी चराने गया या कहीं काम करने गया, उसको फेल करने का काम नहीं किया। आठवीं और पांचवीं का लोकल बोर्ड हटा दिया। इन्होंने एक ही काम किया कि बच्चे को उत्तीर्ण किया जाए। जब विद्यालयों में जाकर देखा, अभी-अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बच्चे को घड़ी का समय देखना नहीं आता है, किस स्टेट का रहने वाला है यह पता नहीं है। अगर यह सारी देन है तो कांग्रेस सरकार की है। हमारे विपक्षी सदस्यों की है और हमारा राज आते ही वापस आमूल-चूल परिवर्तन किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक चुनकर आया 2003-04 में तो ग्राम पंचायतों में केवल प्राथमिक विद्यालय ही खोले थे या राजीव गांधी पाठशाला थे। उस समय एक-एक पंचायत में हमने उन राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में बदलने का काम किया और प्राथमिक विद्यालय बदलने के साथ-साथ उसको यूपीएस विद्यालय में भी बदलने का काम किया। उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र केवल 62 यूपीएस विद्यालय थे और पांच साल के कार्यकाल में 72 यूपीएस विद्यालय और खोले, 33 माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम किया। वापस सत्ता आने के बाद में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं देखा कि यहां कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है, उन्होंने एक ही आदेश से, एक ही कलम से पांच हजार से अधिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम किया। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा काम हुआ होगा और आज

(श्री नाना लाल अहारी)

हमारे उस क्षेत्र में जहां से हम आते हैं एसटी क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, पूर्व में जब भैरोंसिंह जी का राज था और उस समय हमारा जो क्षेत्र था शिक्षा से पिछड़ा हुआ था। यहां का मीणा और वहां का मीणा शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया और पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत को कि हमारे आदिवासी बच्चों को अलग से बोनस अंक देकर मास्टर के रूप में, तहसीलदार के रूप में आगे लाने का काम किया। यह किसी सरकार ने नहीं सोचा था। हमारे उस क्षेत्र से होता क्या था कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गरीब क्षेत्र था। ये हमेशा कोई लोभ-लालच देते रहे और वोटों के समय कहते कि अबकी बार आएंगे तो ये घोषणा कर देंगे, ये कर देंगें पर आज तक किया कुछ नहीं। आज जब बीजेपी की सरकारें आने लगी उसके बाद में हमारे उदयपुर संभाग में आज हमारे वहां देखो अध्यापक भी मिल जायेगा। हमारे वहां पर तहसीलदार भी मिल जायेगा। हमारे वहां पर डाक्टर भी मिल जायेगा। कहीं-कहीं आरएएस, आईएएस की तैयारी में भी बच्चे मिल जाएंगें। अगर यह सारी देन किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इस समय मेरे वहां विधान सभा क्षेत्र में 94 माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं। उनमें से करीब 38 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसा भवन है, उसमें माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, उसमें बच्चों की पढाई सुचारु रूप से नहीं चल सकती है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है जहां माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिये कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। जहां विद्यालय में कक्षा कक्ष नहीं हैं, उनके लिये आज आप जरूर घोषणा करें।

दूसरा कई विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालयों में पानी टपकता है। हमने कुछ एमएलए फंड से चाइना मोजिंग का काम करवाया है, उससे भी पानी नहीं टपकता है। मेरा आपसे निवेदन है जितने भी विद्यालयों में पानी टपकता है, उन विद्यालयों में आप चाइना मोजिंग कराकर उन विद्यालयों को सही कराएं। इसके साथ-साथ टीएडी से उस क्षेत्र में कई बालक-बालिकाओं को स्कूटी देने का काम किया। कल हमारे उदयपुर जिले में एक जिला स्तर का कार्यक्रम था, उसमें करीब-करीब हमने 350 बच्चियों को स्कूटी वितरण करने का काम किया। उनमें सामान्य वर्ग की 95 परसेंट से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बच्चियां थीं, उनको भी स्कूटी वितरण करने का काम किया।

(श्री नाना लाल अहारी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांग है, मैं एक मिनट में खतम करता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा उपली सदकड़ी जो मुख्यालय तूबड़ा तलाब है, उसके लिये मैंने पिछले सालों में भी अधिकारियों और मंत्रीजी को, सबको लिखकर दे चुका, इन्होंने उपला पड़ाव, देलाड़ा स्कूल को अलग से कर दिया, मगर जो हमने कहा उपली सदकड़ी में मुख्यालय का तूबड़ा तालाब का जो यूपीएस विद्यालय है, उसको क्रमोन्नत किया जाए। खेरागाडी में माध्यमिक विद्यालय खोला जाये। नला पिपला जो नई ग्राम पंचायत है, उसमें पांचा पाडला में माध्यमिक विद्यालय खोला जाये। झोथरी में माध्यमिक विद्यालय खोला जाये, इन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। कुण्डा में एक कृषि विद्यालय खोला जाये। शक्तावतो का गुड़ा, जहां 2006 -07 में माध्यमिक विद्यालय खोला था, उसको सीनियर माध्यमिक विद्यालय किया जाये। साथ ही मेरे 40 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर भवन नहीं है, उन सब में भवन बनाया जाये। खैरवाड़ा में एक बालिका महाविद्यालय पिछले कांग्रेस के राज में चुनाव के समय में आनन फानन में घोषणा कर दी थी, मगर जब हमने देखा तो न वहां कोई विद्यालय था, बिल्डिंग के लिये मात्र एक कमरे में महाविद्यालय खोला। मैंने शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध किया, उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध किया, उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रुपया बजट देकर वहां बालिका विद्यालय का भवन खोल दिया है। साथ ही मेरा निवेदन है कि खैरवाड़ा मुख्यालय पर एक संस्कृत महाविद्यालय की भी घोषणा करें। सहमारी में भी एक महाविद्यालय की घोषणा करें। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 पर आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी बजट में बस्सी क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। पिछले दस साल से मैं हर सरकार से सिर्फ एक महाविद्यालय की मांग करती रही हूं और कोई भी सरकार मेरी मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। अभी इस सरकार से भी पांच साल से लगातार सिर्फ महाविद्यालय की मांग कर रही हूं। बस्सी जयपुर के नजदीक है, 35 किलोमीटर है और आज की मांग को देखते हुए, बालिका सुरक्षा को देखते हुए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा पूर्ण करते हुए बस्सी में एक

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

महाविद्यालय की घोषणा की जाये। हर बार कालेज की मांग करने पर सरकार पालिसीज का हवाला दे देती है कि सरकार कि यह पालिसीज है। अभी कुछ दिन पहले भी मंत्रीजी ने अपना एक वक्तव्य दिया था कि पालिसीज में बताया गया था कि 30 किलोमीटर के दायरे में कोई कालेज नहीं होना चाहिये और जहां पर निजी महाविद्यालय है, वहां पर यह महाविद्यालय नहीं दिया जा सकता, तो हमारा वह क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी लोगों को और विधायकों को यह बताना चाहती हूं कि अभी पाँच साल में जितने भी कालेजेज इस सरकार में दिये हैं, उनमें से आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जो पालिसीज को फुलफिल नहीं करते हैं, जो पालिसीज के अलावा हैं। वह सिर्फ रेविड़यां बांटने का काम हुआ है। उनमें से मैं सिर्फ कुछ के उदाहरण देना चाहती हूं, सादुलपुर, अटरू, नदबई, नगर, डूंगरगढ़, इन सबमें आपने महिला कालेजेज दिये हैं। कई तो ऐसे हैं जो 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। यह सारे ऐसे हैं जहां निजी महाविद्यालय हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जहां आलरेडी महाविद्यालय है। मैं नाम भी बता देती हूं, सादुलपुर में आलरेडी मोहतक महाविद्यालय था, अटरू में केशव महाविद्यालय है, नदबई में एसआरपी कालेज और श्रीमती निहाल महाविद्यालय, नगर में आदर्श महाविद्यालय तथा महाराजा अग्रसेन कालेज, डूंगरगढ़ में महिला महाविद्यालय। आपकी पालिसी तो यह है, सब जगह निजी महाविद्यालय होते हुए भी सिर्फ बस्सी के लिये पालिसीज क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी मैं बस्सी में महाविद्यालय मांगती हूं तो आप पालिसीज बता देते हैं। मैं यह समझती हूं कि सरकार की ऐसी सोच है, सरकार की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि बस्सी में विधायक पार्टी का नहीं है। विधायक निर्दलीय है तो क्या हुआ, वहां के नागरिक, वहां की बेटियां, वह इसी राजस्थान के नागरिक हैं और मैं समझती हूं कि सरकार की भी उनके प्रति पूरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं यह चाहती हूं कि कम से कम अब की बार जो यह लास्ट बजट है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी शायद अभी यहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करुंगी कि इस फाइनल बजट में, इसी सत्र में बस्सी में महाविद्यालय की घोषणा करेंगी तो उनको धन्यवाद दूंगी।

एक मैं बात करना चाहूंगी काउंसलिंग पर। माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो काउंसलिंग है वह काउंसलिंग नहीं है, एक

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कोड़ा है, अत्याचार है, जिसमें मुंह बंद करके काउंसलिंग का कोड़ा मारा जाता है, जिसमें आप बोल भी नहीं सकते हो। जितनी भी जगह होती है वह इस तरह से डिसाइडेड होती है कि जो अच्छी जगह है या जो सिटी के पास में है, वहां पर अपने लोगों के लिये उनको हाइड कर दिया जाता है, उनको छिपाया जाता है। उनको यह बताया जाता है कि यह बताओ ताजमहल कहां है, नहीं बोलोगे तो पिटोगे। ताजमहल में आप्शन है बैंगलोर, राजस्थान, उत्तराखण्ड़ या चेन्नई, जहां पर वह है उसका वह आप्शन ही नहीं देते हैं। उसके माइंड में तो है लेकिन वह डर के मारे में उन चार आप्शन में से एक बता देता है। यह है आपका अत्याचार जो शिक्षकों पर हो रहा है, बहुत खुले आम हो रहा है और हम उसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते कि यह गलत हो रहा है क्योंकि आप हवाला दे देते हो कि सारे काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि सभी पंचायत स्तर पर एक 12वीं तक का स्कूल कर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन जब वहां पर 12वीं तक के नये स्कूल हुए हैं तो वहां प्रिंसिपल भी लगेंगे, वहां पर जगह खाली है। उसके लिये जब हमारे लोकल लोग जाते हैं पोस्टिंग के लिये या ट्रांसफर के लिये तो उनसे काउंसलिंग की जाती है। जैसे बस्सी जयपुर के सबसे नजदीक है, तो बस्सी में जितने भी लोगों से मेरी बात होती है वह यह कहते हैं कि जब हम काउंसलिंग के लिये जाते हैं तो बस्सी की एक भी सीट दिखाई नहीं देती है। अच्छी जगहों को हाइड कर लिया जाता है, मुख्य पदों को छिपाते हैं ताकि अपने चहेतों को लगा सकें, आप यह काम न करें। मैं इसे सिर्फ यही कहूंगी कि यह शिक्षकों पर अत्याचार है। मर्जी आपकी होती है लेकिन हामी उनसे भरवाई जाती है।

दूसरा, जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं और जो स्कूल 12वीं वाले स्कूलों में मर्ज हुए हैं, उनको अब स्पेस कम लगता है क्योंकि दूसरे स्कूल मर्ज भी हुए हैं, वह क्रमोन्नत भी हो गये हैं। जब पंचायत में ही स्कूल मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि पंचायत में तो यहीं बच्चों को भेजा जाए। ऐसे में वहां पर बिल्डिंग की जरूरत भी ज्यादा हो जाती है। फैसेलिटीज भी चाहिए लेकिन सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। मैं मांग करना चाहूंगी कि सरकार जितने भी स्कूल क्रमोन्नत कर रही है, उसमें जिस तरह कम्पलसरी किया है कि हर पंचायत में एक 12वीं तक का स्कूल हो, इसी तरह से यह भी

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कम्पलसरी होना चाहिए कि वहां बिल्डिंग भी अच्छी हो, कमरे भी हों, पानी भी हो, हर चीज की वहां व्यवस्था अच्छी हो।

यह भी मैं मांग करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपने खुद के बजट से लगभग तीन-चार करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र में लगाये हैं, ताकि हम लोग बच्चों को कुछ राहत दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक मामला और मैं यहां पर उठाना चाहती हूं कि जो स्कूलों में थोड़े दिन पहले टिन के डिब्बे रखे गये थे कि यहां पर पैसा डालो, यह रमसा में जाएगा, पैसा इकट्ठा करो, फिर वह काम आएगा। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पैसा कहां पर है? वह टिन में जो पैसा इकट्ठा हो रहा था। एस.एम.सी. के मेम्बरों को बुलाया नहीं जाता, उसको क्राउड फंड भी कहते हैं। एज ए क्राउंड फंड बोलते हैं, उसको क्राउंड फंड वर्ड दिया है, लेकिन वह क्राउड फंड कहां जा रहा है? कहां गया है? मैंने भी कई जगह पर दान के हिसाब से दिया है और जब मैं एस.एम.सी. मेम्बरों से पूछती हूं कि आपके स्कूल में कितना फंड इकट्ठा हुआ? वे बोले, पता नहीं, हमें तो कभी बुलाते नहीं हैं, न ही हमारे सामने वह डिब्बा खुलता है। उस पैसे का क्या होता है? उसका क्या हिसाब-किताब है? बस कोई भी आता है, उसमें डालता है, न तो उसका कुछ रिटर्न में होता है। एक मैं यह मांग करना चाहती हूं कि उस पैसे का इस्तेमाल उसी स्कूल में हो।

एक जो सबसे जरूरी चीज है कि दिव्यांग नाम सरकार ने विकलांगों को दिया, अच्छा किया, लेकिन खाली दिव्यांग नाम देने से उनको खुश कर देने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान में 87 हजार दिव्यांगों को 10 हजार टीचर्स चाहिए, जो मूक बधिर, विमंदित, दृष्टिबाधित और जो विकलांग हैं, उनके लिये जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, वे चाहिए होते हैं, लेकिन वे हमारे यहां पर सिर्फ 200 ही हैं। जबकि हमें 10 हजार की जरूरत है। इसमें का सबसे बड़ा विद्यालय आनंदीलाल राजकीय मूक बधिर विद्यालय है, जिसमें 34 विषय शिक्षकों के अलावा 10 से अधिक सामान्य शिक्षक भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमों के अनुसार सामान्य शिक्षक दिव्यांग छात्रों को नहीं पढ़ा सकते। सामान्य शिक्षक गूंगी भाषा में उनको क्या समझा रहे हैं, पता नहीं, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उनको स्पेशल टीचर्स दें। दूसरा, इन्हें पढ़ाने के लिये शिक्षा विभाग ने दो सौ विशेषज्ञ लगा रखे हैं, जबकि राष्ट्रीय नीति में 87 हजार छात्रों के लिये 10 हजार से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। हालांकि, प्रदेश के कई बड़े विषय

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

स्कूलों में सामान्य शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विषय शिक्षक हैं, उनको डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा रखा है, जहां पर उनकी जरूरत नहीं है। अभी जो नई शिक्षक भर्तियां निकली हैं, उसमें भी विशेष टीचर्स के लिये कोई भर्ती नहीं है। उनमें भी कुछ परसेंटेज विशेष टीचर्स के लिये होनी चाहिए। आर.टी.आई. के एक खुलासे के हिसाब से प्रदेश में 29 आवासीय व गैर आवासीय स्कूल हैं, जिसमें दिव्यांगों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहां केवल 2400 सीट हैं, इसके अलावा जयपुर में पोद्दार सरकारी संस्थान नहीं हैं, जहां पर विकलांगों के पढ़ाई के इंतजाम हों, जबकि दिव्यांगों की संख्या 15 लाख से अधिक है। यह हमारे प्रदेश में दिव्यांगों को लेकर हाल है तो मैं यह समझती हूं कि दिव्यांगों को विकलांग बोलो या दिव्यांग बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है, जब हम उनके जीवन यापन का, उनकी पढ़ाई-लिखाई का, उनके फ्यूचर का भी ध्यान रख सकें। अभी बजट में सबको सब कुछ मिला और शायद हर कोई खुश भी है। इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आज शिक्षा पर जब बहस हो रही है, शिक्षा पर बात हो रही है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी ने भी इस मैटर को नहीं छुआ, किसी ने भी इसको देखा नहीं। जो अपनी नजर के सामने हैं या अपने क्षेत्र में हैं, सब उसकी ही बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में हम अपने प्रयास से अपने फंड से काफी कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है तो मैं यह समझती हूं कि कम-से-कम या आज या जब फाइनल बजट हो तो विकलांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की भर्तियां जरूर आप निकालें। इसी के साथ मैं मंत्रीजी काउंसलिंग की बात भी आपसे करना कहना चाहती हूं कि आप मेरे क्षेत्र का हाइड मत किया करो, क्योंकि जयपुर के नजदीक वही है, वे भी आपके चहेते ही हैं। आप अपने तो लगाते हो, मेरे अपने भी लगा दिया करो। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुदान की मांग संख्या-24 पर बोलने के लिए अनुमति दी, आपका आभार। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना करीब 15 साल पहले की गयी थी, लेकिन इस विश्वविद्यालय में मात्र 5 विभाग चल रहे हैं, 15 साल से लगातार कई बार विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव भी भिजवाये गये, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा जो नवीन विभाग हैं, वे

(श्री भंवरसिंह)

खोले जाने की अनुमति नहीं दी गयी। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय पूरे पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां नवीन विभाग नहीं खोले गये हैं।

इसके साथ-साथ जो डूंगर कालेज, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा कालेज है डूंगर महाविद्यालय, जहां करीब 8 हजार से भी ज्यादा छात्र-छात्राओं की संख्या है, वहीं महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय, ये दो बड़े महाविद्यालय हैं बीकानेर संभाग के और बीकानेर शहर में स्थित हैं। इन दोनों महाविद्यालयों को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाने की मांग पिछले लंबे समय से बीकानेर में चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का सुराज संकल्प पत्र है, उसमें भी यह घोषणा की गयी थी कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के डूंगर कालेज और एम.एस. कन्या महाविद्यालय को संघटक महाविद्यालय बनाया जाएगा, लेकिन यह आज तक घोषणा ही है। उपाध्यक्ष महोदय, सुराज संकल्प पत्र, 4 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन इस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके द्वारा वादा भी किया गया है और बीकानेर की जनता की यह मांग भी है तो मंत्री महोदय जब जवाब दें तो इस पर जरूर गौर फर्माएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा खोला गया, उसको समीक्षा समिति में ले लिया गया और लगातार 3 साल तक आपकी सरकार बनने के बाद में उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, बीटीयू को बंद कर दिया गया।

पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह कहा गया कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक साल का समय बीत जाने के बावजूद इस विश्वविद्यालय में न तो वाइस-चांसलर (उप-कुलपति) की नियुक्ति की गयी है, न रजिस्ट्रार को लगाया गया है और न ही अन्य पदों पर कोई नियुक्ति की गयी है और न ही किसी प्रकार के पिछले एक साल में कोई वित्तीय प्रावधान किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय और सरकार के द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि आपने जाते-जाते इस प्रकार से ये घोषणाएं कीं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी भी लग

(श्री भंवरसिंह)

रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये बजट घोषणा हुए एक साल हो गया, लेकिन बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के सही रूप में और सही तरीके से विधिवत स्थापित करने की दिशा में सरकार कोई काम नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में दस वर्षों से भी अधिक समय से संविदा पर लगे हुए जो कर्मचारी थे, जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी थे, जो 10-12 हजार रुपए की मासिक मानदेय पर यह काम कर रहे थे और ये करीब 150 कार्मिक हैं, जिनको डेढ़ साल पहले सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय और सरकार के एक आदेश द्वारा हटा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हटाए गए कार्मिक 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। इन कार्मिकों के सामने अपनी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक तरफ आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगे-लगाये 10-15 सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको आप हटा रहे हैं, कृपा करके ऐसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को पुन: लगाया जाए, जिससे कि उनकी रोजी-रोटी चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के द्वारा बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा का उप निदेशक कार्यालय खोला गया था, लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा का उप निदेशक कार्यालय चूरू में होने से बीकानेर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा का उप निदेशक कार्यालय खोला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में राजकीय महाविद्यालय सितम्बर, 2013 में खोला गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कटारिया जी की अध्यक्षता में जो समिति बनायी गयी, उस समीक्षा समिति में मेरे कोलायत के राजकीय महाविद्यालय को भी डाल दिया गया। अच्छे काम सरकार, मुख्य मंत्रीजी या मंत्रीजी अपने नाम लेना चाहते हैं और जो बुराइयां हैं, चाहे पेयजल योजनाओं को बंद करने की बात हो, वह समीक्षा में डालना में, चाहे कालेजों को करना हो, ये कोई 8-10 समीक्षा समितियां कटारिया जी के नाम बना दी गयीं।

वह एक-एक करके सारे जो निर्णय हैं, उनको बंद करते जा रहे हैं।

(श्री भंवरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सुराज संकल्प पत्र में भी इन्होंने यह घोषणा की थी राजस्थान की जनता से कि हमारी सरकार बनेगी तो राजस्थान के प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग गवर्नमेंट कालेज खोलेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, खोला हुआ कालेज बंद कर देना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा विधान सभा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र भी है और बीकानेर से जैसलमेर की 300 किलोमीटर की दूरी में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय एवं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत में, जो कि 200 किलोमीटर से भी लंबा-चौड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल पूरे राजस्थान के प्रत्येक उपखण्ड में एक-एक खोलने की पिछले सरकार द्वारा शुरूआत की गई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जजू में स्वामी विवेकानंद माडल विद्यालय खोलने के आदेश भी कर दिए गए थे। वर्तमान सरकार द्वारा उस विद्यालय के निर्माण कार्य को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो माडल स्कूल है, बजट पास होने और मंत्री महोदय जवाब दें, उसको भी उससे पहले बनाया जाए। कोलायत में लिग्नाइट, क्ले, बजरी, जिप्सम आदि खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। सोलर के प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में रोजाना लग रहे हैं। गवर्नमेंट आईटीआई की मांग लंबे समय से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि सरकारी आईटीआई कोलायत में भी खोला जाना नितांत आवश्यक है और क्षेत्र की जनता की मांग है। इस पर भी मंत्री महोदय गौर फर्माएं।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग लंबे समय से राजस्थान की 7 करोड़ आम जनता की है। इस सदन के द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भिजवा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्य मंत्रीजी और सरकार एक उच्च स्तरीय दल गठित करके, केन्द्र में जो आपकी सरकार है, उनसे वार्तालाप

(श्री भंवरसिंह)

करें। न सिर्फ राजस्थान में आपकी सरकार है अपितु केन्द्र में आपकी सरकार है और राजस्थान के 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपकी घोषणा भी है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाएंगे। राजस्थानी भाषा हमारी मदर लैंग्वेज है और इसको मान्यता दिलवाने के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा। दो मिनट में मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा साहित्य कला एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर में बनाई गयी है। सरकार और मंत्री महोदय हमेशा राजस्थानी भाषा की पैरवी करने की भी बात करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि राजस्थान में करीब 10-12 अकादमियां हैं। सभी अकादमियों में अलग-अलग सिन्धी अकादमी में अध्यक्ष बना दिए गए, उर्दू की अकादमी में अध्यक्ष बना दिए गए। राजस्थानी भाषा की अकादमी जो एकमात्र बीकानेर में स्थित है, पिछले चार साल से राजस्थान भाषा साहित्य कला अकादमी का न तो आज तक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न उनके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तव में राजस्थानी भाषा के चहेते हैं, राजस्थान के आमजन की भावनाओं की कद्र करना चाहते हैं तो चार साल में जिस प्रकार से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है और उस वजह से राजस्थानी भाषा के जो साहित्यकार हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और हर वर्ष जो एक करोड़ रुपए की राशि राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी को मिलती है, वह भी लैप्स हो गई। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते इस अकादमी को सही तरीके से अस्तित्व में लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर में लॉ कालेज है। उस लॉ कालेज में 700 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 3 शिक्षकों के भरोसे बीकानेर का लॉ कालेज चल रहा है और लॉ की पढ़ाई की स्थिति इतनी खराब है कि 3 शिक्षकों के भरोसे 750 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह विद्यार्थियों के साथ भारी अन्याय है। इसके साथ-साथ मैं विद्यालयों के क्रमोन्नयन के बारे में कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रदेश में सभी जगह क्रमोन्नत किए जा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जो ग्राम पंचायतें क्रमोन्नयन से वंचित हैं, उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों को दसवीं और बारहवीं तक क्रमोन्नत किया जाए। विद्यालयों के एकीकरण में मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब 100 से भी ज्यादा स्कूलें बंद हो गई हैं जिसकी वजह से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई एकदम से अवरूद्ध हो गई है। उन

(श्री भंवरसिंह)

विद्यालयों को पुन: चालू किया जाए। राजस्थान के 24 हजार विद्यार्थी मित्रों में से काफी विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक में समायोजित कर दिया गया लेकिन बीकानेर जिले में अभी भी 400-500 विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है तो एक-एक पद हर पंचायत में नया सृजित करके इन विद्यार्थी मित्रों को समायोजित किया जाए। इसके अलावा कम्प्यूटर शिक्षक और शिक्षाकर्मियों का मुद्दा लंबे समय से राजस्थान की सरकार के सामने और मंत्री महोदय के सामने हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उसका भी समाधान किया जाए। बीकानेर जिले के बीकानेर शहर या बीकानेर शहर के नजदीक के जो स्कूल हैं उसमें काउंसलिंग, चाहे कोई भी शहर हो काउंसलिंग में उपाध्यक्ष महोदय, वे ही पद भरे जाते हैं जो नजदीक के होते हैं। दूरस्थ पद हैं, वे आज भी खाली हैं जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों की मांग पूरे सदन के सभी विधायकों ने की है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे कि दस-दस साल से ज्यादा का समय हो गया है। कहीं न कहीं एक नीति बनाकर के प्रतिबंधित जिलों में जो हमारे शिक्षक हैं, उनको अपने गृह जिले अथवा नजदीकी जिले में आने की अनुमति दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-24 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा देश और प्रदेश का एक आधारभूत स्तम्भ है जिसके माध्यम से देश और प्रदेश का स्तर विश्व के धरातल पटल पर रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से इस प्रदेश के 24-25 हजार विद्यालयों को बंद किया है, जिससे विशेषकर वे ग्रामीण लोग, गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग, जिनको सरकारी विद्यालय के माध्यम से अपने नजदीक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता था, इस प्रदेश में वे लोग वास्तव में जिनको विद्यालय की आवश्यकता है और उन विद्यालयों को बंद करके सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसको सरकार अपने स्तर पर वापस लेने का प्रयास करें। किसी भी स्तर पर आपका निर्णय हो, जहां भी आप दूरी का माध्यम मानें, छात्र संख्या का माध्यम मानें लेकिन जिन ग्रामीण ढाणियों के

(श्री मनोज कुमार)

विद्यालय तीन-तीन किलोमीटर दूर हो गए, ऐसे विद्यालयों का आप तुरन्त प्रभाव से दोबारा सर्वे कराकर के इनका निर्णय करें। इनमें आधे से ज्यादा विद्यालय ऐसे होंगे जहां छात्र संख्या भी है, उनकी दूरी भी ज्यादा है और ये विद्यालय प्रदेश के उन आम जन को, जो वास्तव में सरकारी विद्यालय के अलावा पढ़ाने में असक्षम है, जो ढाणियों में रहते हैं, उनके पास सुविधा-संसाधन भी नहीं है, वे लोग पढ़ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का जो निर्णय लिया, वह एक सराहनीय कदम है। लेकिन सरकार ने इसमें एक बैरीकेड डाल दिया कि जिस विद्यालय में 40 की छात्र संख्या माध्यमिक विद्यालय में होगी, उसी ग्राम पंचायत में क्रमोन्नत किया जाएगा। सरकार से कहना चाहता हूं कि पहला काम तो यह कि जो बैरीकेड आपने डाला है, इस बैरीकेड को हटाकर आप जहां भी ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय है, उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आज ही सदन में घोषणा करें कि प्रत्येक पंचायत हैड-क्वार्टर पर क्रमोन्नत होगा। इसके साथ ही संसाधनों का अभाव लंबे समय से चल रहा है। विद्यालय क्रमोन्नत किया, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय उस पर नाम भी लिखा गया लेकिन नाम लिखने के साथ ही साथ जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया, उस विद्यालय में कमरों का बहुत अभाव है। इसके लिए भी सरकार बजट की घोषणा करे। ऐसा कोई विद्यालय नहीं हो, जो आपने क्रमोन्नत किया हो और क्रमोन्नत करने के बाद में उस विद्यालय में भवन नहीं बने। भवन नहीं बनता है तो छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जहां-जहां भी आपने विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं, वहां पहला काम भवन बनाने का किया जाए। विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया, क्रमोन्नत करने के बाद में विषय अध्यापकों की इतनी ज्यादा कमी है, आपका विद्यालय क्रमोन्नत हो गया और विषय अध्यापक वहां नहीं है तो क्रमोन्नत होने के बाद उस उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? और बिना पढ़ाए अगर आप क्रमोन्नत करके छात्रों का भविष्य खराब करना चाहें तो ऐसा कतई सम्भव नहीं है। आप इस बात पर विचार करें कि जिन विद्यालयों को आपने क्रमोन्नत किया है, वहां पर पूरा स्टाफ हो।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड के टीचर 2012-13 और 2008-09 में जो लगे, उनके वेतन में बहुत बड़ी विसंगति है। वे

(श्री मनोज कुमार)

अध्यापक बार-बार मांग कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड में लेवल एक ही है, उनका पदस्थापन भी एक ही है। उसके बाद भी उनके वेतन में विसंगति है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा अध्यापक बार-बार अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। सरकार हर बार कहीं न कहीं हर बात में एक ही बात कहती है कि वित्त विभाग को इसका निर्णय करने के लिए भेज दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या वित्त विभाग अपने अधीन नहीं है? हर बार आपका एक ही शब्द मिलता है कि वित्त विभाग ने रिजेक्ट कर दिया, वित्त विभाग ने स्वीकृत नहीं किया, निरीक्षण के लिए भेज दिया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस वित्त विभाग की जो बात बार-बार सदन में कही जाती है इस बात को हटाकर अपनी मंशा स्पष्ट करें कि इस काम को हम करना चाहते हैं, इस काम को हम नहीं करना चाहते। आप बार-बार वित्त विभाग का बेरीकेड लगाकर कि वित्त विभाग ने ऐसा निर्णय कर दिया इस कारण से हम नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर क्लियर करें कि आप वित्त विभाग के सहारे से नहीं।

हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय जहां-जहां बने हैं वहां खेल ग्राउण्ड का अभाव है। पूरे प्रदेश की यह स्थिति है, जहां-जहां भी खेल ग्राउण्ड नहीं है सरकार इसको प्राथमिकता से लेकर प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां है वहां पूर्णतया खेल ग्राउण्ड हो। खेलने की पूरी सामग्री भी छात्रों को मिले जिससे खेल के स्थान में बहुत आगे बढ़ सकें। हमारे राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हमारे प्रदेश के छात्र आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए खेल ग्राउण्ड व सामग्री की व्यवस्था सरकार करे।

जैसा कि सरकार ने घोषणा कर दी कि विद्यालयों को भी पीपीपी मोड पर दे रहे हैं। जिसका पूरे प्रदेश में आम नागरिक ने, गांव के लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का काला कानून, पीपीपी मोड, चिकित्सा को भी पीपीपी मोड़, आप एक बार घोषणा करते हो और फिर वापस लेते हो, तो पहले ही सोचकर करो। जनता के हित में पहले ही अच्छा फैसला करो। जनता के विरोध के बाद करो इससे अच्छा है पहले ही करो। आपको ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से भ्रमित करती है इस पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सोचकर पहले ही अच्छा निर्णय करो जिससे

(श्री मनोज कुमार)

जनता में आपका मैसेज अच्छा जाए। आपके विरोध में जनता की भावना बनी हुई है वह इसी कारण से बनी हुई है कि एक बार आप आर्डर कर देते हो, दूसरे दिन वापस ले लेते हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड में, सैकिण्ड ग्रेड में अभी भर्ती हुई उसमें हरियाणा और पंजाब से लगातार तीन वर्ष तक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी पढ़कर आए हैं, हमारे प्रदेश में उस अंग्रेजी को हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तीन साल में एक बार पढ़ते हैं, वह लोग तीन साल लगातार पढ़कर आए हैं, फिर भी आपने वर्तमान में काउंसलिंग के दौरान अपात्र मानते हुए उनको बाहर रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन छात्रों के, उन नौकरी लगने वाले लोगों के लिए आप तुरन्त फैसला करें, उन लोगों को न्यायालय की शरण नहीं लेनी पड़ी। आपके द्वारा एक आर्डर जारी किया गया जिसमें उनको सबको आपने माना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी तीन साल तक पढ़कर आए हैं उन सबको हम एक समान मानते हैं। राज्य सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की बीएमए अनिवार्य अंग्रेजी को राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए में वैकल्पिक अंग्रेजी के समकक्ष मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। उसके बाद भी आपने रोक रखा है। ऐसे निर्णय आपके ही द्वारा किए गए हैं। इसमें सकुर्लर जारी कर दिया, उसके बाद आप उनका रोक रहे हैं। इसलिए इस पर जल्दी निर्णय करें, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

दो मिनट और। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो-चार दिन पहले भी स्थगन के माध्यम से रखा और आज शिक्षा पर फिर चर्चा है। शेखावाटी विश्वविद्यालय की आज सभी माननीय विधायकों ने बड़ी बात रखी है। मंत्री महोदय उस विश्वविद्यालय पर, आप एक तरफ तो सम्बद्धता नहीं दे रहे हैं, उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। दूसरी तरफ आप परीक्षा के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप परीक्षा कराइये। जब आप यह मानते हो कि निरीक्षण के दौरान, या निरीक्षण नहीं किया गया, उनको सम्बद्धता नहीं दी गई, तो उन छात्रों के साथ आप किस तरीके से परीक्षा करा रहे हैं, किस आधार पर उनकी परीक्षा करा रहे हैं? आपको देनी है तो उनको मान्यता दीजिए, उनकी सम्बद्धता करिए, उसके बाद परीक्षा कराइये। पूरा निजी शिक्षण

(श्री मनोज कुमार)

संस्थान आपका विरोध कर रहा है कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, जब तक हमें मान्यता नहीं दी जाएगी, सम्बद्धता नहीं कर दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, आज स्पष्ट करें, उन छात्रों का 7-8 मार्च को ही एग्जाम है, आप किस तरीके से उनको एग्जाम दिलाएंगे, किस तरीके से उनका रिजल्ट जारी करेंगे। एक वी सी के माध्यम से सरकार घिर रही है, 600 कालेजेज के साथ अन्याय हो रहा है, आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बारे में बार-बार लिख चुका हूं, सदन में भी उठा चुका हूं। मंत्री महोदय आपने उसके लिए घोषणा की थी कि कमेटी गठित करूंगी, जांच कराएंगे और गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी तक हमें आपका किसी भी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, तीन सत्र निकल गए। आपने सदन में घोषणा की थी कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की हम जांच कराएंगे, लेकिन आप नहीं करा पाए, कौनसी मजबूरी है। पता नहीं आपको यह अधिकारी भ्रमित करते हैं, या हम कोई भ्रष्टाचार की बात करें तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आलम हो सकता है, नहीं तो सरकार पीछे क्यों हट रही है। इस सदन में घोषणा करने के बाद सरकार जांच क्यों नहीं करा रही। या तो नीचे से लेकर ऊपर तक आप सभी मिले हुए हो, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आलम है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू है। जांच करा कर इस सदन में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप पेश करें जिससे हमें भी संतुष्टि हो जाएगी कि आपने जांच करा ली। उसने कोई गलत किया है तो वह बताए, गलत नहीं किया है तो वह बताए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांग करता हूं कि आपके घोषणा पत्र के अनुसार हमारे कन्या महाविद्यालय, राजकीय आईटीआई भी नहीं है, इसके लिए भी मांग करता हूं कि आप हमारे यहां खोलने का प्रयास करें।

एक डार्क जोन वाली बात बार-बार सदन में भी उठ रही है। हमारे प्रदेश के टीचर हैं उनको आप डार्क जोन के नाम से चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि आपने भी 15 साल में नहीं खोले, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी नहीं खोल पा रही है। ऐसा क्या कारण है, क्या वह पाकिस्तान या विदेश से आए हुए लोग हैं जिन को आप इस तरह की प्रताड़ना डार्क जोन के नाम से दे रहे हैं। एक पालिसी

(श्री मनोज कुमार)

बनाकर डार्क जोन में रहने वाले टीचर्स के लिए, भविष्य में 5 साल, 10 साल, 15 साल निर्धारित करके उनको बाहर करने का प्रयास करें, नहीं तो यह बहुत घोर अन्याय है। आप एक शिक्षक को तो बांधकर रख रहे हो, दूसरे शिक्षकों को मनमर्जी स्थान पर नियुक्ति दे रहे हो। डार्क जोन को तोड़कर उन सब लोगों को खुला करना चाहिए। इस मांग पर कहना चाहूंगा शिक्षा पर चिंता की जाए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए मांग संख्या-24 शिक्षा, कला व संस्कृति पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज की डिबेट में राष्ट्र और संविधान के निर्माताओं को मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश आजादी से पहले रियासतों का देश था। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, रियासतों के समय भी चुनौती रहा, उससे पहले चाहे पेशवाओं का राज रहा, इस व्यवस्थाओं के देश में, वर्गो के बंटे देश में, जातियों के बंटे देश में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले क्या पता क्या-क्या रहा होगा। जो भी सत्तासीन लोग रहे वह अपने संघ, विधान के अनुसार चलते रहे। पहले इस वर्ग और जातियों के देश में चौथे वर्ग को तो शिक्षा पाने का हक व अधिकार इस देश में था ही नहीं। हर बार, हर सत्ता की शिक्षा एक चुनौती रही। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस रियासतों के देश में विलीनीकरण के बाद 1949 में, मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूं कि 26 नवम्बर, 1949 इस देश के लिए बहुत अहम तारीख रही है। जिस दिन हमारे देश को गणराज्य के रूप में गिना गया, उसके बाद इस देश को संविधान के रूप में बांधा गया। बांधने के बाद विभिन्न धाराओं का उल्लेख हर स्तर पर आवश्यकता के अनुसार इसमें फरमाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में शिक्षा के लिए, धारा 45 में प्रोविजन फरमाया गया, उस प्रोविजन के बाद प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया था। बाद में विभिन्न समूहों पर सरकारों द्वारा तत्संबंधी क्रियान्वयन करने हेतु नियम बनाए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित 1992 के अनुसार शिक्षा के तीन आयामों पर बल दिया गया।

(श्री पूरणमल सैनी)

उसमें नम्बर एक, सार्वजनिक पहुंच एवं नामांकन के लिये; नम्बर दो, 14 वर्ष की आयु तक सार्वजनिक ठहराव पर और तीसरा था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर।

(20.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की हम बात करें तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं। मेरा पक्ष और प्रतिपक्ष पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब शिक्षा को इतनी बड़ी चुनौती के रूप में लेकर और इस देश के गणराज्य बनने के 68 वर्ष बाद और आजादी के 71 वर्ष बाद भी, आज की तारीख में मेरे पूर्व वक्ता के रूप में माननीय मनोज जी न्यांगली की कही बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पाइन्ट्स में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरक्षित जिले हैं, इस प्रदेश के दस जिले हैं, उनमें आज तक यह कौनसी मजबूरी है कि दूसरे जिलों के अध्यापकों को वहां एक पाबन्दी के रूप के, और जेल के बन्दी के रूप में वहां रोका जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकारों की चिंता रही थी तो आज तक उन दस जिलों में। शिक्षा के लिये हमारे शिक्षक क्यों नहीं तैयार कर लिये गये?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारों ने चिंता जरूर जताई, लेकिन एक-दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिये और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने आपको ऊपर स्थापित करने के अलावा हमारी सरकारों ने कुछ करने के प्रयास नहीं किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं अगर लम्बा जाऊंगा तो समय आपने इतना फिक्स किया हुआ है। मैं इस राजस्थान प्रदेश के शेखावाटी से आता हूं और शेखावाटी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्त बातों पर नहीं जाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में, पहले से, हमारे आज जो माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, जो चिकित्सा का कार्य भार सम्भाल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को वर्गों में, मुझे इसलिये बोलना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन में एक ट्रांसफर की बात आई और हम माननीय मंत्री महोदय से मिलने गये। मैं आरोप नहीं लगा रहा, वास्तविकता निवेदन कर रहा हूं तो उनका जवाब यह रहा कि पिछले कांग्रेस के राज में भी और ये एस.सी., एस.टी. के लोग यहीं बैठे थे, जयपुर में, और अभी भी वे ही रहेंगे, तो हमारे वाले कब आएंगे। यह दूषित मानसिकता का संकेत था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री पूरणमल सैनी)

मैं इस बात के माध्यम से कहना यह चाह रहा हूं कि आज भी राजस्थान प्रदेश में और विभिन्न जगह हायर एजुकेशन के लिये 33 जिलों में से 31 जिलों को, और सम्बद्धता के लिये, एफिलिएशन जारी करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी विश्वविद्यालय में, आज भी उसके नीचे जितने भी निजी महाविद्यालय हैं, चाहे वे हायर एजुकेशन के रूप में प्रशिक्षण महाविद्यालय हों, और चाहे अकादमिक महाविद्यालय हों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा केवल धन संग्रहण की नीति से कालेजों के एफिलिएशन और अन्य शुल्कों में अन्यायपूर्ण वृद्धि के निस्तारण हेतु मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इनमें, चाहे वह एफिलिएशन फीस व अन्य शुल्कों में ताबड़तोड़ वृद्धि के लिये बात करें, उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय से जब वे निजी महाविद्यालय एफिलिएटेड थे, उस समय यहां की जो नीतियां थीं, वे भी उस शेखावाटी विश्वविद्यालय में लागू करवाई जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, सम्बद्धता में अभिवृद्धि के लिये, सम्बद्धता की अभिवृद्धि जब करवाई जाती है तो उसमें आज से पहले, 2015 से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता रही, तथा उन सभी महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाती है। उसी के आधार पर उस शेखावाटी विश्वविद्यालय को रखा जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनापत्ति शुल्क, आज से पहले, इस नियम के लाने से पहले उस शेखावाटी विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कालेजों में, और तीस हजार रुपये वार्षिक, चाहे वह स्थाई मान्यता प्राप्त है, चाहे अस्थाई है। हर बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस बात की फीस, तीस हजार रुपये हर बार लेते हैं। जो धारा 45 है, उसमें पहले 14 वर्ष तक का ही नहीं, उसकी नीति यह है कि शिक्षा सरकार के लिये कोई व्यवसाय नहीं है। यह लोक कल्याणकारी रूप में आता है, और जैसा मेरे पूर्व वक्ता के रूप में और माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा इसलिये जरूरी है, इस प्रदेश और देश के लिये ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि पूरे विश्व के लिये इसलिये जरूरी है कि उस शेरनी के दूध के समान इस ज्ञान को पीकर उस व्यक्ति के शेर की तरह दहाड़ने के काम में आती है।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे रिलेक्सेशन देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि एंडोमेंट फण्ड में भी वृद्धि की गई है, उसको भी शेखावाटी विश्वविद्यालय में वापस लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि इस सरकार के आते ही नियमों में, मैं दोहरा नहीं रहा हूं, एक नई बात, पहले भी जो इस सदन में दो वर्ष पहले मैंने 2015 में रखी थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुड एकेडमिक रूल, रिकार्ड के नाम पर एक नियम यह सरकार लेकर आई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह नियम यह था कि कोई भी छात्र तैयार होकर जब वह दसवीं-बारहवीं करेगा, स्नातक और स्नातकोत्तर करके आयेगा, एम.फिल करेगा, पीएच.डी. करेगा। उसके बाद वह कालेज लैक्चरर की परीक्षा में बैठने जायेगा। सरकार ने यह राइडर क्रिएट कर दिया कि वह विद्यार्थी, कक्षा दस और बारह में 55 परसेन्ट अंकुश है, अगर पास हुआ होगा तो इस कालेज लैक्चरर की परीक्षा में शामिल हो पायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यहां यह करना चाह रहा हूं कि वह दसवीं में जब पढ़ता था उसके बाद करीब 12 से 13 वर्ष, अपने जीवन के अहम वर्ष उस विद्यार्थी ने बर्बाद कर दिये, क्यों किये, वह कालेज लैक्चरर के लिये इसलिये तैयार हो रहा था, उसको नहीं पता कि आगे आने वाली सरकार, जो भूतलक्षी नियम है, वह पहले वाले लोगों पर भी लागू कर देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम जो गुड एकेडमिक रूल के रूप में लेकर आई थी, इसको वापस ले और भविष्य में आने वाले बच्चों पर इसको लागू करे। इतनी मैं मांग करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज तक सरकार किसी भी मामले में, चाहे वह ट्रांसफर के लिये नीति हो, नीति नहीं बना पाई हो। हम भी अक्सर, जब हमारे पास लोग आते हैं, ट्रांसफर के लिये अध्यापक लोग, तो हम भी माननीय मंत्री महोदय के यहां जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी इतने परेशान रहते हैं, चाहे कोई भी आये, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बात करना चाहे कि मेरी समस्याएं ये हैं, इनका भी स्थानान्तरण करो, तो उनको जोर देकर बोलना पड़ता है और डांट-डपट में बात करनी पड़ती है, चाहे वह कोई कितना भी बड़ा रहा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत रूप से आप भी चैन से रहें और दूसरे लोग भी चैन से रहें,

(श्री पूरणमल सैनी)

तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ट्रांसफर की नीति, स्थानान्तरण की नीति सरकार अपने चुनावी फायदों के लिये क्यों नहीं बनाना चाहती? मेरी मांग है कि इस राजस्थान प्रदेश के शिक्षाविद् लोगों को इधर-उधर करने के लिये अगर रखना चाहते हो और फेरबदल की शिक्षा दिलवाना चाहते हो तो मेरा निवेदन और आग्रह है कि इन लोगों के लिये ट्रांसफर की एक नीति बनाई जानी चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बातें बहुत थीं, लेकिन समय का अभाव है। माफी चाहते हुए, आपने समय दिया, इसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24, शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है। मुझे भी बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

इस भारत देश ने पूरे विश्व को अनेकों ऐसी देने दी हैं, जिनके आधार पर इसकी एक अलग ही पहचान है। भारत देश एक ऐसा देश है जो निश्चित तौर पर इसकी संस्कृति के आधार पर पहचाना जाता है। आज भी हम लोग अगर चर्चा करें तो ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके आधार पर हम कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तो हमने की है, मगर फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनकी वजह से आज भी कहीं न कहीं शिक्षा के अभाव में ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव, जो लगातार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे राजस्थान प्रदेश हो, चाहे विश्व के इस देश का कोई सा भी प्रदेश हो, मैं कहना चाहूंगी कि इस देश ने जो शून्य दिया पूरे विश्व को, उसके आधार पर इसकी एक अलग पहचान है। ग्लोब भी भारत देश ने ही विश्व को दिया और नक्षत्र ज्ञान के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा करें तो यह भी भारत की विश्व को एक बहुत बड़ी देन है। आयुर्वेद के आधार पर भी हम लोग देखें तो पूरे विश्व को भारत ने आयुर्वेद की जो देन दी है, मैं कहूंगी कि वह एक बहुत बड़ी देन है। आज पूरे विश्व में आयुर्वेद के आधार पर, लगातार आयुर्वेद की शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, उसके आधार पर पूरे विश्व में जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है।

मैं कहूंगी जो देश विश्व गुरु, जगत गुरु के रूप में पहचाना जाता था जिसमें अनेकों संतों ने जन्म लेकर, इस शिक्षा के लिए महापुरुषों ने जन्म

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लेकर इस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने का जो काम किया था वह इतिहास गवाह है, आज भी उन महापुरुषों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर शिक्षा को हासिल डाक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं करते तो देश को आज एक सुदृढ़ संविधान नहीं मिलता। यह कलम की जो ताकत थी, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की इतनी मुसीबतों के बाद उसी के आधार पर आज उन्होंने देश को संविधान दिया है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर पूर्व में हम लोग देखें तो अंग्रेज जो वायसराय थे, जो मैकाले थे, उन्होंने समाज को कमजोर करने के लिए गुरुकुल पद्धति से हमें जो शिक्षा मिलती थी, उस शिक्षा को तोड़ने की जो उन्होंने रणनीति तय की और जो इस शिक्षा को कमजोर करने का उन्होंने प्रयास किया, मैं यह कहना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति जो हमारी थी, उस नई शिक्षा नीति के नाम से युवा को पंगु बनाने का काम उन्होंने किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी शिक्षा के मूल मंत्र में जो बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके बारे में आज मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगी। वैसे मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने लगातार चाहे बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे बालकों की बात हो लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम इस राजस्थान की धरती पर सम्माननीया सी.एम. साहिबा ने स्थापित किये, माननीय मंत्री महोदय ने स्थापित किये, उनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो एक-एक योजना ऐसी योजना है जिन्हें धरातल पर लाकर यथार्थ में उसको हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि हमारे स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे? गांव, उस दूरदराज की ढाणी में बैठा हुआ, गांव में बैठने वाला छात्र भी कभी लैपटाप हाथ में लेकर ज्ञान अर्जन करेगा, ऐसा कभी हम सोच नहीं सकते थे लेकिन वह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है।

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि स्कूटी योजना जो गांव-ढाणी में बैठी हुई हमारी बालिका जो बारहवीं के बाद यह सपना देखती थी कि मैं भी शहर के कालेज में जाऊं और कालेज में जाकर एजुकेशन प्राप्त करूं। निश्चित तौर पर सम्माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने उनके सपने को भी साकार करने का काम किया है। मैं आज के दिन यह कहना चाहूंगी कि इस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

राजस्थान की धरती पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो हमने सपना देखा था, हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इसका शुभारंभ इस राजस्थान की धरती से किया, झुंझुनूं से किया, उसका रिजल्ट भी हम लोग देखें। अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहें आकड़ों में भी तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और मैं आज के दिन यह भी कहना चाहूंगी कि सम्माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने जो बेटी को एजुकेशन से ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, चाहे मजदूर एरिया हो, चाहे दूरदराज के गांव हो, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? प्रत्येक योजना में इस तरह का प्रावधान रखना, चाहे श्रम विभाग की हमारी योजना हो, जो लाभ मजदूरों को मिलता है उसकी योजना हो, उसमें भी हमने जो प्रावधान किया है कि जिसकी बेटी आठवीं तक पढ़ी हुई रहेगी उसी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहती हूं और आपको यह बताना चाहती हूं कि मेरी सांथलखेड़ी पंचायत, जहां पर पूरा मजदूर वर्ग रहता है और वहां के लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, हजारों की संख्या में श्रम विभाग से उनके जो कार्ड बनते हैं वह बने हुए हैं और आप देखिए कि उन लोगों को जब पता लगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि हमें हमारी बेटी के घर बैठाने से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाए तो उन लोगों ने लगातार जो बेटियां घर पर बैठी हुई थीं, उनको भी एडमिशन दिलवाया और उसी का नतीजा है कि हमारा जो 12 लाख का नामांकन बढ़ा, मैं मानती हूं कि यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

राजश्री योजना, हम राजश्री योजना के माध्यम से भी देखें तो हो सकता है कि जन्म के समय उन्हें पांच हजार की राशि मिलती है, फिर ग्यारह हजार की मिलती है, फिर 25 हजार की मिलती है लेकिन अगर वह बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे तो उसे यह राशि रोक ली जाती है तो मैं यह कहूंगी कि इसका भी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा शिक्षा को मिला है, बेटियों में जो शिक्षा के प्रति कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो उदासीनता थी उससे कहीं न कहीं लोग मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने यह बिलकुल मन बनाया है कि हमें योजनाओं का लाभ लेना है और हमारी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। आदर्श विद्यालय, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज हम उन स्कूलों को जाकर देखें तो आप देखिए कि पूरी की पूरी मूलभूत सुविधाएं उन स्कूलों में मिल रही हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं ज्यादा कोई जिक्र नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी यह कहना चाहती हूं कि कोटा उत्तर से आने वाले सम्माननीय विधायक साहब बोल रहे थे कि 126 विद्यालय हमने, जब आप विधायक थे उस समय आपने नए खुलवाये। कुछ विद्यालय बंद भी हुए हैं लेकिन मैं उसकी भी कोई, ठीक है कुछ कहीं न कहीं नामांकन कम था, बच्चे कम थे तो हमने बंद किये लेकिन फिर भी मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायत हैडक्वार्टर पर, प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर हमारा सीनियर स्कूल होगा, ऐसी सम्माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत हैडक्वार्टर ऐसा है जहां पर न माध्यमिक विद्यालय है, न उच्च माध्यमिक विद्यालय है, हाथियाखेड़ी, मैंने मंत्री महोदयजी को पूरे बच्चों के नाम भी लिखकर दिये हैं। उसको बंद कर दिया गया है। तीन-साढ़े तीन किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। पूरा राजपूत समाज का गांव है। बालिकाओं को दूर भेजने में कहीं न कहीं उनको झिझक पैदा हो रही है तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, मैंने डेढ़ सौ बच्चों की लिस्ट बनाकर आपको दी है कि अगर आप यह स्कूल खोलते हो तो यह डेढ़ सौ बच्चे पूरे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। मेरा यह निवेदन है कि अगर इसको भी आप खोलकर देंगे तो बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिलने वाला है।

चार वर्ष में सरकार ने जो विभिन्न संवर्गों में 67961 शिक्षकों को और कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने का जो काम किया है, जो घोषणा की है, मैं यह मानती हूं कि यह बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

मैं उच्च शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगी कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी नगरी से आती हूं जो एजुकेशन के नाम से पूरे देश में फेमस है, पूरे देश में एक पहचान उसकी बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि पूरे मेरे जो तीनों ही विश्वविद्यालय हैं, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। वहां पर कुछ कोर्सेज बढ़ाने की बात है अगर हम कोटा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में भी बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि वहां की जनता को, वहां के छात्रों को, पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कालेज हमारे यहां पर खुला हुआ है। पूरा नौ किलोमीटर दूर है। इतने वर्षों के बाद भी आज कालेज में, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछली बार सी.एम. साहिबा ने कुछ राशि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमें दी, मैंने एम.एल.ए. फंड से भी लगाई लेकिन आज भी कालेज के हमारे ऐसे हालात हैं कि बच्चों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्डिंग का अभाव है। संस्कृत महाविद्यालय हमारा चेचट और कालेज, गवर्नमेंट कालेज रामगंजमण्डी और संस्कृत महाविद्यालय कोटा शहर में जो है, तीनों में ही बिल्डिंग के अभाव की वजह से विधि कॉलेज भी उसके पास की पास बना हुआ है, मेरा यह निवेदन है कि अगर बिल्डिंग के लिए वहां पर भी कुछ किया जाएगा तो बहुत बड़ा लाभ हमारे कोटा के स्टूडेंट्स को मिलेगा।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रतिनियुक्ति पर देखिए, मेरा निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गांव में बैठा व्यक्ति भी यह सोचता है कि मेरा बच्चा भी पढ़े, लिखे और आगे बढ़े लेकिन हम मात्र शहरों में सुविधाएं उपलब्ध करवा दें इससे कहीं भी हमारा, हमारी जनता का भला नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि खेलों के नाम से जयपुर शहर में छह-छह, सात-सात वर्षों से टीचर लगे हुए हैं। ज्वाइन करने स्कूलों में गये थे, उसके बाद किसी ने शक्ल तक नहीं देखी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनका डेपुटेशन निरस्त किया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, हमारे एग्जाम बच्चों के अभी चल रहे हैं, आने वाले हैं। उस समय जो देहात के, हमारे पूरे इस जिले के देहात के जितने भी शिक्षक हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर कोटा शहर में लगे हुए हैं उन्हें एग्जाम के समय अगर हम लोग वापस उनके स्कूल में भेजेंगे तो निश्चित है कि कहीं न कहीं बहुत अच्छा फायदा गांव की जनता को, हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, यह मैं कहना चाहूंगी।

सरकार ने समानीकरण किया। यह एक बहुत बड़ा मन रखकर आपने काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

दूसरा, कुछ बिल्डिंग्स हमारी बिलकुल भवन रहित हैं, स्कूल जैसे लखारिया का है तो उसको भी अगर आप करेंगे तो और जो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करने के लिए भी मैं मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर उसको भी करेंगे तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, वहां से ही उसका सारा काम आपका हो जाएगा तो इसका भी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा था- 'हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।' राजस्थान में उनके इस कथन को मूल मंत्र मानते हुए निरन्तर कार्य किया जा रहा है और पिछले चार सालों में राजस्थान में शैक्षिक विकास को उज्ज्वल बनने की राहों का जो निर्माण किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण होगी, उस शिक्षा का धरातल उतना ही मजबूत होगा। प्राथमिक शिक्षा पर यदि बेहतर ढंग से ध्यान दिया जाता है तो उस शिक्षा का विकास अपने आप ही सहज और सरल हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदय को और हमारी उच्च शिक्षा मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किये हैं, निश्चित रूप से वह बहुत ही सराहनीय है। चाहे वह सैल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जो 68 सब्जेक्ट्स थे, उनका सरकारीकरण किया, पे माइनस पेंशन स्कीम के तहत जो प्रोफेसर रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। कालेजों के अन्दर पदनाम परिवर्तन किया, डी.पी.सी. में प्रिंसिपल्स की जो भर्तियां की हैं और सबसे बड़ी बात रूसा के अन्दर 100 कालेजों को, पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 कालेजों को यूजीसी द्वारा पैसा वितरण किया है।

इसके अलावा, दिशारी योजना के अन्तर्गत काम्पीटीटिव एग्जाम्स और मॉक एग्जाम्स के लिये लगभग 91 हजार लोगों को दिशारी योजना का लाभ मिला है। मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया को और उच्च शिक्षा मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं माननीया मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट कालेज में जो लैक्चरर्स हैं, वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएच.डी. के लिये सुपरवाइजर बनते हैं, जो बिलकुल ही गलत है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इस पर

(डा. मंजू बाघमार)

तत्काल नियन्त्रण लगाया जाना चाहिये, प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये, क्योंकि गवर्नमेंट कालेज के जो लैक्चरर्स हैं, उनको सैलेरी तो हमारी गवर्नमेंट दे रही है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में ही वह सुपरवाइजर का काम करेंगे तो उनकी गरिमा के लिये भी ठीक होगा।

इसके अलावा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उनके रिक्रूटमेंट के लिये हां की है और अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि भर्ती जो की जाती है, उसमें यूजीसी की गाइड लाइन को फालो किया जाये। यूजीसी की गाइड लाइन को फालो किया जाये, वह भी ठीक है, लेकिन उसके अनुसार उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो डिसाइड की गयी है, उसमें कई जगह डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। कई बार गुड एकेडमिक रिकार्ड के अन्दर फर्स्ट डिवीजन को माना गया और कई जगह उसमें सैकण्ड डिवीजन को माना गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन रहेगा कि इसमें स्टूडेंट्स और बच्चे काफी कन्फ्यूज्ड हैं। यदि सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज को एक साथ बिठाकर उनकी रिक्रूटमेंट पालिसी एक ही बना दी जाएगी तो ज्यादा ठीक होगा ताकि उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। जब राजभवन द्वारा सभी विश्वविद्यालयों की फीस को एक जैसा किया जा सकता है तो निश्चित रूप से सभी विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है, उसको भी एक जैसा करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो नोन-टीचिंग स्टाफ है, उसके अन्दर असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन है, उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। काफी लम्बे समय से वह पदोन्नतियां अटकी हुई हैं, उसकी कोई स्कीम भी नहीं बनी हुई है। अब कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर अपाइंट हुआ है तो वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर ही रिटायर होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उनमें फ्रस्टेशन बढ़ रहा है। इसलिये तत्काल उनकी पदोन्नति की घोषणा की जानी चाहिये।

इसके अलावा, यदि यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके नोन-टीचिंग स्टाफ को एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया जाये तो

(डा. मंजू बाघमार)

ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि एक ही जगह पूरी सर्विस में रहते हुए व्यवस्था में निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया से और मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अन्दर जो प्रशासनिक भर्तियां आयोजित की जाती हैं, उसमें जो अलाइड सर्विसेज होती हैं, उसके अन्दर राजस्थान यूनिवर्सिटीज सर्विसेज भी बनाई जानी चाहिए। अभी तक राजस्थान के अन्दर पहले तो पांच-छह यूनिवर्सिटीज थीं, अब 24 यूनिवर्सिटीज हो गयी हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए करें। उसका परिणाम यह होगा यदि कोई रजिस्ट्रार के पद पर अपांइट होता है तो वह लोंग लाइफ रहेगा, उसका ट्रांसफर वगैरह भी होता है, लेकिन उस काम की उसे जानकारी होगी तो यूनिवर्सिटीज के काम-काज के अन्दर किसी तरह की कोई रूकावट नहीं आयेगी, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटीज का काम -काज प्रभावित हो रहा है और ऐसा जो सिस्टम है, या ऐसी पालिसी मध्य प्रदेश में भी लागू हो रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और यूनिवर्सिटीज में ज्यादा समस्या आ रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक गण, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत जिनकी पदोन्नति नहीं हो रही है और काफी समय से कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर पर रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका न एसोसिएट प्रोफेसर में सलेक्शन हो पाया, न उनका प्रोफेसर में सलेक्शन हो पाया है, इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गुडविल में भी फर्क पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग में फर्क पड़ रहा है। रिसर्च नहीं हो पा रही, न्यू प्रोजेक्ट के अन्दर पैसा भी नहीं आ पा रहा है। इससे काफी नुकसान हो रहा है और तो और हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की दौड़ से भी बाहर हो गये हैं। यदि हम इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हम काफी आगे बढ़ सकते हैं।

यदि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो कौशल विश्वविद्यालय जो पहली बार देश में हमारे राजस्थान के अन्दर स्थापित हुआ है। मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया का और उच्च शिक्षा मंत्री महोदया का तहेदिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। पालीटेक्निक कालेज के जो शिक्षक हैं, जो तकनीकी शिक्षा देकर रोजगारोन्मुखी शिक्षा देकर बच्चों को आत्म निर्भर बना रहे हैं लेकिन उनके अन्दर भी पदोन्नतियां नहीं हो पा रही

(डा. मंजू बाघमार)

हैं। करीब 10-15 सालों से उन वरिष्ठ प्रवक्ताओं को न तो विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति मिल रही है, न तो एच.ओ.डी. बनाया जा रहा है, न उनको प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। केवल उनको एच.ओ.डी. और प्रिंसिपल के एक्स्ट्रा चार्ज देकर उनसे काम चलाया जा रहा है। इसकी तत्काल स्वीकृति जारी की जाएगी तो निश्चित रूप से उनमें जो एक फ्रस्ट्रेशन-सा आ रहा है, वह उनका ठीक होगा, खतम होगा।

इसके अलावा, माननीया मंत्री महोदया से मेरा निवेदन रहेगा कि राजस्थान के सरकारी क्षेत्र के अन्दर बल्कि उत्तर भारत के अन्दर एकमात्र महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में, जो 2007 से स्थापित है, उसमें गरीब और होनहार बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन स्वयं एक वित्त-पोषित संस्थान होने के कारण अन्य निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के बराबर उन्हें फीस देनी पड़ रही है। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन रहेगा कि इस सैल्फ फाइनेंस स्कीम के अन्तर्गत यह है, लेकिन फिर भी यदि अनुदान के रूप में सरकार उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा परिवर्तन होगा और बालिका शिक्षा को बढ़ाया दिया जायेगा और बालिकाओं को भी इंजीनियरिंग क्षेत्र के अन्दर जो सरकारी विद्यालय हैं, बालिकाओं की फीस के अन्दर उनको राहत प्रदान की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर मैं बात करूं तो मैं अपनी कुछ समस्याएं जरूर माननीय मंत्री महोदया के सामने रखना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कसारी है, जो छाजोली ग्राम पंचायत के अन्दर स्थित है और कुंवारखेड़ा जो वहां से तीन किलोमीटर दूर है, उस स्कूल के अन्दर उसको मर्ज कर दिया गया है, जबकि दोनों विद्यालयों के बीच में हाइवे आ रहा है और उनके नोर्म्स के अनुसार यदि बीच में हाइवे आता है, और उनकी दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा होती है तो वहां उनको मर्ज नहीं किया जा सकता है। जबकि ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, दोनों के द्वारा ही सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा तो जल्दी से उसको डी-मर्ज किया जाये, उसे मर्ज से बाहर किया जाये।

इसके अलावा, कुछ विद्यालयों को आठवीं से दसवीं में और दसवीं से बारहवीं के अन्दर क्रमोन्नत करने का जो अभी कार्य चल रहा है, उसके अन्दर मेरे क्षेत्र के कुछ विद्यालय हैं, उनको भी क्रमोन्नत किया जाए। एक बार पुन:

(डा. मंजू बाघमार)

मैं माननीया मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि न केवल स्कूली शिक्षा के अन्दर, बल्कि तकनीकी और उच्च शिक्षा के अन्दर जो नवाचार किये, पिछले चार सालों के अन्दर जो गुणात्मक रूप से उनमें परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है और वह एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, जो मेरे जनजातीय क्षेत्र में राजकीय हाड़ा रानी महाविद्यालय को पिछले वर्ष पी.जी. किया और वहां कुछ सब्जैक्ट खोलने की मैं मांग करता हूं। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा उपखण्ड में भी एक महाविद्यालय है, नया महाविद्यालय है, वहां भी सब्जैक्ट्स खोलने की जरूरत है, पदों की जरूरत है। अब मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी शिक्षा मंत्रीजी और हमारे तमाम कैबिनेट मंत्रियों और सदन द्वारा पिछले चार वर्षों में हमारे शिक्षा जगत् में बहुत ऊंचाइयों तक जाने का काम पड़ा है, उसमें हमने 68 हजार के आस-पास शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती की।

77 हजार के आस पास हम और करने जा रहे हैं, 2018-19 में। मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आप पहले शिक्षा मंत्रीजी होंगे, आपके झब्बे-कुर्ते किसी ने नहीं खींचे क्योंकि आप तेज बोल जाते हो जिसकी वजह से कई लोग पीछे हट जाते हैं। आपने वह कला की जो चार वर्षों में 01 लाख 09 हजार 622 के आसपास अध्यापकों और कार्मिकों को पदोन्नत किया। उन्होंने जिन्दगी भर आस भी नहीं रखी थी।

दूसरा, मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 2018-19 में 1832 नये सीनियर स्कूल खोलने का कहा है। हमारी मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी ने सप्ताह में तीन प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बालकों को दूध पिलाने का और मदरसों का आधुनीकरण किया। यह पहली बार ऐसा काम हुआ है। हमारे जितने भी मदरसा हैं पांच सौ अधिक, उनका सही तरीके से आधुनीकरण किया। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय के छह विद्यालय सीनियर होने से बाकी रह गये। सेमाल स्कूल को माध्यमिक उच्च माध्यमिक किया जाए।

(श्री अमृतलाल)

पाल सराड़ा, निठारा, नेवातलाई, आमलोदा और हतकालिया इन पंचायत मुख्यालयों पर बारहवीं स्कूल नहीं है, उनको भी आप क्रमोन्नत करने की अनुमति प्रदान करें।

हमारे यहां ट्राइबल बैल्ट में जो नवीन पंचायतें बनीं हैं, कहीं आठवीं है, कहीं दसवीं हैं, उनको भी बारहवीं किया जाए और कुछ विशेष बात यह है कि दूर-दराज इलाके और ढाणी मजरे हैं और वहां सात-सात, आठ-आठ किलोमीटर की दूरी पर हमारे माध्यमिक विद्यालय और सीनियर विद्यालय नहीं हैं। अगर आप उस एरिये का विशेषकर ध्यान रखकर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गेंगलाज में 101 से ज्यादा बालक हैं। वहां विज्ञान संकाय की मांग है। उसको किया जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमारी, वह तहसील हैड क्वार्टर है, पंचायत समिति हैड क्वार्टर है, 24 पंचायतों का ब्लाक है, वहां भी विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमरपुरा, तहसील सराड़ा में कृषि की मांग करता हूं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केजड़, बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें करीब एक हजार छात्र संख्या है, वहां पर विज्ञान विषय की मांग कर रहा हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सराड़ा, जहां कला वर्ग नहीं है, वहां विज्ञान वर्ग होने की वजह से बालक नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहां कला वर्ग की मांग कर रहा हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटालीखेड़ा में वाणिज्य वर्ग की मैं मांग कर रहा हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जावत में कला वर्ग की मांग कर रहा हूं।

मैं कला एवं संस्कृति के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बहुत बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं। एक हाड़ा रानी, जिन्होंने अपना सिर कटवाया था। वह महल आज की तारीख में प्राचीन झरोखे, छतरियां सारी टूट-फूट हो रही है, उसका भी विशेष ध्यान रखकर सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है। दूसरा, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, जयसमंद। उसका निर्माण 1731 में हुआ था। वहां झरोखे, छतरियां, हवामहल और रूठी रानी का जो महल है, उस पाल के ऊपर पत्थर के जो हाथी हैं, उनके कहीं पाँव टूट गये हैं, कहीं उनके नाखून टूट गये हैं, कहीं कान खण्डित हो गया है, कहीं आंख खण्डित हो गई है, उनको सही करने

(श्री अमृतलाल)

की जरूरत है। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने जहां अन्तिम सांस ली, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ है, उसमें महल बना हुआ है। वहां बीस साल तक चावण्ड तृतीय राजधानी रही और उसके पास एक समाधि स्थल है, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति है, वह भी खण्डित हो रही है और समाधि स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से टूरिज्म विभाग या अन्य विभाग जो कर रह है, उसको करना जरूरी है। यही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा का ध्यान रखते हुए माननीया उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पुन: निवेदन कर रहा हूं। आप उस क्षेत्र से भली-भांति वाकिफ हैं, वहां पांच हजार से ज्यादा बालक-बालिकाएं जनजाति क्षेत्र की पढ़ती हैं तो उसमें विषय की बहुत जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रीजी हमारे बीच में ऐनक लगाकर बैठे हैं, पूरे गौर से सुन रहे हैं, इनके मन में क्या है, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता हूं लेकिन हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल बैल्ट है, दूर-दराज है, पूरी छतें टपकती हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साफा भी रख रखा है, अभी पहनेंगे, देखना आप।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): जहां प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, सैकण्डरी हो, सीनियर हो, वहां खेल ग्राउण्ड की बहुत जरूरत हो। अगर खेल ग्राउण्ड होगा तो बालक हर तरह की एक्टिविटी करेगा।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जो सेमारी है, उस ब्लाक में माडल स्कूल नहीं है। आपके नियम में आता है तो जारी करें तो ठीक रहेगा। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, सराड़ा जो उप खण्ड है, वहां नहीं है, उसकी मंजूरी दिलाने का आदेश फर्माएं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान् हरिसिंहजी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जीवन का वह दीप है जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है और इसी को चरितार्थ करते हुए हमारी सेंसिटिव, विजिलेंट मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा बजट पेश किया है जो पिछले चार साल में शिक्षा के

(श्री हरिसिंह रावत)

क्षेत्र में कई ऐसे स्ट्रक्चरल, इम्प्रूवमैंट एवं इनोवेशंस किये हैं जिसकी वजह से आज ग्राम पंचायत में, कहावत है बिन मांगे मोती मिले, हर पंचायत हैड क्वार्टर पर 5863 विद्यालयों का उन्होंने आगाज किया। हमें ही नहीं, बल्कि हमारे सामने प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उन सबको दिया और मैं सोचता हूं कि मांगने से अगर दिया होता तो शायद काफी प्रभावी होता लेकिन बिन मांगे दिया तो शायद लोगों में ऐसा गया कि वह तो सरकार थी और दे दिया। इसलिए इसका हमें जो श्रेय मिलना था, वह शायद मिला नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी दृष्टि से हमारी सरकार ने ऐसे कई आयाम कायम किये जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। समय कम है। मेरा पहले समय था। मैं हास्पिटल चला गया था, जिसकी वजह से मेरा समय कट गया था। आपने समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। इसलिए मैं विस्तृत न कहकर मेरे अपने सब्जैक्ट पर आना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार ने कई ऐसे आयाम कायम किये। जिस प्रकार पहले 5863 स्कूल खोले, उसी प्रकार अभी और क्रमोन्नत करने में, पीएस टू यूपीएस, यूपीएस टू सैकण्डरी और सैकण्डरी टू सीनियर सैकण्डरीज, इसके अन्तर्गत इस वर्ष 1832 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रोग्राम रखा है। मैं समझता हूं कि हमारे कई माननीय सदस्यों के कई ऐसे स्कूल्स हैं, जहां बच्चे ज्यादा हैं या दूर-दराज बसे हुए स्कूल हैं, जिनमें यह कमी थी, वह भी पूर्ण होगी।

इसके साथ-साथ हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मिड-डे-मील के माध्यम से हमारे बच्चे पौष्टिक आहार लें और सप्ताह में तीन दिन दूध की व्यवस्था भी की है। मैं समझता हूं कि यह हमारे गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा पारितोषिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ-साथ ही स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले चाहे अभिभावक हो, चाहे बच्चे-बच्ची हो, उनमें एक ऐसी हीन भावना पैदा हो गयी थी कि शायद इंग्लिश मीडियम में तो केवल शहर के बच्चे या धनाढ्य परिवार के बच्चे ही ग्रहण कर सकते हैं लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे नरेन्द्र भाई मोदी का मैं

(श्री हरिसिंह रावत)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारे समाज के बच्चे थे, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, उनका भी एक सपना संजोया और उस सपने को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल प्रारम्भ किया जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उससे हमारे बच्चे-बच्चियों को एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिलेगी और जब इंग्लिश मीडियम से पढ़कर वर्ल्ड तक ये कॉम्पिटिशन में जा सकेंगे। इसके साथ-साथ ही इस माडल स्कूल में सभी व्यवस्था की है लेकिन मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कई ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और जो उनको एक स्कूल से अलग स्कूल में भेजा गया है, जिसकी वजह से दूसरी स्कूलों में भी शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी माडल स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है उनको तत्काल भरा जाए।

साथ-साथ ही नारी शिक्षा की बात करूं। इसमें भी हमारी केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक बहुत अच्छी पहल की है कि बेटी पैदा होने से लेकर बेटी पढ़े-लिखे और पढ़-लिखकर ससुराल जाने तक का भी हमारी सरकार ने एक बहुत अभिनव प्रोग्राम रखा है जिसमें नारी शिक्षा को महत्व देते हुए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' भी एक नारा दिया, उसके माध्यम से हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे अभिनव प्रोग्राम बनाये हैं जो बच्चियों को साइकिल, दूर है तो साइकिल के अलावा उनको ट्रांसफर वाउचर दिये जा रहे हैं। साथ-साथ बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कालेज में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको स्कूटी दी जा रही है। इन्हीं के साथ-साथ जो बच्चियां होनहार हैं उनको कई तरह के वजीफा कहो या इस तरह के कोई वित्तीय साधन दिये जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियां भी आगे आ रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात करूं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसमें भी एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं बेसहारा बच्चियां पढ़ती हैं, जिसके बाप है तो मां नहीं है, जिसके मां है तो बाप नहीं है, मैं समझता हूं कि उस विद्यालय को भी आठवीं से अगर बारहवीं तक क्रमोन्नत किया जाए तो यह एक अच्छी अनुकरणीय पहल होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होता यह है कि जो बच्चियां आठवीं के बाद आगे जाती हैं तो अगर मान लो उसकी कहीं व्यवस्था नहीं होती है तो वो बच्चियां शिक्षा से

(श्री हरिसिंह रावत)

वंचित रह जाती हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस आठवीं से बारहवीं तक क्रमोन्नत करने का चाहे यहां से हो, चाहे सेन्टर से हो, इसके लिए भी एक प्रयास करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मेरे क्षेत्र में कई ऐसी स्कूलें हैं जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। एक स्कूल है, दिवेर में भैरूलाल छुलीबाई नाथ ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल बनी है और उस स्कूल में केवल बालिकाएं पढ़ती हैं तो आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कूल को अगर सीनियर सेकण्डरी क्रमोन्नत करेंगे तो जिन्होंने यह भवन बनाया है उनका भी यही एक अनुरोध था कि, साहब, अगर हमारी यह बच्ची बारहवीं तक पढ़ेगी तो हमने जो इतना बड़ा फंड दिया है तो शायद हमारा भी यह फलीभूत होगा। तो आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसको सीनियर सैकण्डरी करे।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में अब पूरा नाम पूरा डिटेल में नहीं दूंगा लेकिन कुछ विद्यालय जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के मेरे करीबन 22 स्कूल हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। इसके साथ-साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय करीबन 10 स्कूलें हैं, यह भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा क्योंकि समय कम है इसलिए शायद व्याख्यान करने से अच्छा है कि मैं इनको दे दूंगा तो वो ठीक रहेगा।

इसके साथ-साथ ही मैं कालेज की बात करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारी उच्च शिक्षा मंत्रीजी और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में मुझे देवगढ़ में भी राजकीय महाविद्यालय दिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

साथ-साथ ही आपके माध्यम से मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीम और देवगढ़ में आपने हमें राजकीय महाविद्यालय दिये लेकिन उनमें अभी जो व्याख्याताओं की और मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी है उनको पूर्ण किया जाए ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके।

साथ-साथ ही विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय भी मेरे क्षेत्र के लिए जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार जिलों का संगम है और

(श्री हरिसिंह रावत)

100 किलोमीटर की परिधि में और कोई कालेज नहीं है, अगर मेरे वहां पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खुलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के काफी बच्चे-बच्चियों को फायदा मिलेगा, लेकिन जब मैंने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे वित्तीय संसाधन कम हैं, आप सैल्फ फाइनेंसिंग पैटर्न पर प्रारम्भ कर सकते हैं। यह उनका कहना सत्य ही है लेकिन मेरा क्षेत्र एक सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम लोग मजदूरी करते हैं या नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो इतने वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में अगर आप विज्ञान संकाय खोल देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों को इसका काफी लाभ मिलेगा और आपको धन्यवाद देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों कॉलेजों में विज्ञान खुलवाएंगे क्या?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, एक ही खोल दें, कम से कम भीम में खोल दें।

श्री उपाध्यक्ष: एक तो आपके भीम में है और दूसरी कहां है?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): देवगढ़। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर लास्ट में निवेदन करना चाहता हूं। भीम क्षेत्र, उपाध्यक्ष महोदय, शायद आप भी भलीभांति परिचित होंगे कि ब्यावर और बी अवेयर, यह नाम क्यों पढ़ा। हम रावत राजपूत समाज के लोग रहते हैं 200 किलोमीटर की रेंज में और हम चौहान वंशज से बिलोंग करते हैं पृथ्वी राज चौहान से और अंग्रेजों ने जब वहां रहते थे, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी सल्तनत रही हो। Beawar means, be aware यानी when you enter from here by this community means which community. रावत हमें, उपाध्यक्ष महोदय, एक उपाधि मिली है। एक्चुअल हम चौहान वंशज हैं और उसी के अन्तर्गत हमारे चौहान वंशज का, हम चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारे पूर्वजों का नाम ऊंचा हो तो हमारे जो भीम राजकीय महाविद्यालय है उसका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम होगा। तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि ये आज ही घोषणा करें ताकि हमारे क्षेत्र में संदेश जाएगा तो यह भी होगा

(श्री हरिसिंह रावत)

कि हमारी शिक्षा मंत्री हमारे जिले की हैं और उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा है और उन्होंने घोषणा की है तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो इसके लिए आज ही घोषणा करें।

साथ-साथ ही संस्कृत का भी उच्च शिक्षा मंत्रीजी के पास ही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत के विद्यालयों में लम्बे समय से शिक्षकों की जो कमी है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें ताकि संस्कृत की जो शिक्षा है वो हमारे बच्चे-बच्चियां अच्छी ग्रहण कर सकें। इसी आशा के साथ में मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब इसमें मंत्री महोदय से वक्तव्य करा लें? आप में से और कोई बोलना चाहेंगे? We have got 4 Ministers. There are couples of Ministers who will be replying on behalf of the other Ministers. Devnani Ji, you will be replying on behalf of Smt. Krishnendra Kaur?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यस।

श्री उपाध्यक्ष: And What about Yuva and Khel?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): खेल का तो है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: It's not part of it. So basically between the two of you, उच्च शिक्षा एण्ड शिक्षा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं जिन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में अपने बहुमूल्य विचार रखे और इसके साथ ही मांग संख्या-24 उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में हमें लगभग 88 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से कुल 27 ऐसे हैं जो नवीन राजकीय महाविद्यालय के लिये प्राप्त हुए। रिक्त पदों को भरने के लिये ऐसे 10 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। यूजी महाविद्यालय से पीजी महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के 5 और निजी महाविद्यालय को राजकीय क्षेत्र में लेने के लिये 4, नये संकाय और नये विषय के संदर्भ में 15 ऐसे कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। एनसीसी खोलने और अन्य विषयों पर 7, संस्कृत महाविद्यालय खोलने पर 2 और संस्कृत शिक्षा में क्रमोन्नति के 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए। संस्कृत महाविद्यालय के रिक्त पदों पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शिक्षकों की नियुक्ति के लिये भी प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुल 88 जो प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके लिये मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि इन सभी प्रस्तावों की रिप्लाई मैं आज ही इन तक पहुंचा दूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज अनुदान की मांगों पर अपनी बात सदन में रखूं, उससे पूर्व आदरणीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधान मंत्री, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगी।

'जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी,

आज कहें चाहे जो दुनिया कल को झुके बिना न रहेगी।

अर्थात हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश अग्रणी राज्य बने और इसके लिये हम अनवरत प्रयास करते रहेंगे और ध्येय की प्राप्ति करके ही रहेंगे। 2018-19 का जो प्रस्तावित बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी ने रखा, मैं उन्हें बहुत आभार देना चाहूंगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी घोषणाएं इस बजट में कीं। खास तौर से क्वालिटी और क्वांटिटी डवलपमेंट के लिये यह घोषणा की गई। जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसमें एक सैल्फ फाइनेंस मोड पर हमारे बहुत सारे विषय जो विभिन्न कालेजों में कई वर्षों से चल रहे थे, उनमें उन्होंने तय किया कि पांच साल से ज्यादा सालों में जो सैल्फ फाइनेंस मोड पर जो कोर्सेज चल रहे हैं, उनको अब स्टेट फाइनेंस मोड पर ले लिया जाएगा। यह रैगुलर किया गया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी, बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य जब जब मुझ से मिलते थे, यही बात कहते थे कि 10-11-12 साल से यह सैल्फ फाइनेंस के तहत कोर्सेज चल रहे हैं, इन्हें अगर सरकार स्टेट फाइनेंस मोड पर ले लें तो यह बहुत ही अच्छा होगा। तो यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा करके ऐसे सारे ही कोर्सेज, पांच वर्ष से अधिक के जो सैल्फ फाइनेंस मोड में चल रहे थे, उनको स्टेट फाइनेंस मोड पर लिया। ऐसे ही बांसवाड़ा में जनजाति छात्र, छात्राओं के लिये पृथक-पृथक दो छात्रावासों की घोषणा करी। पे माइनस पेंशन पर जो रिटायर्ड लैक्चरर्स थे, जिनको पहले फिक्स अमाउंट दिया जाता था 25 हजार रुपये, उसके बाद अब पे माइनस पेंशन योजना रिटायर्ड लैक्चरर्स के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि लैक्चरर्स की जो कमी है इससे थोड़ा बहुत पे माइनस पेंशन के माध्यम से हम लोग उन रिटायर्ड लैक्चरर्स को अपाइंट कर सकेंगे। ऐसे ही सभी राजकीय महाविद्यालयों में फ्री

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वाई फाई की घोषणा उन्होंने की, 50 राजकीय महाविद्यालयों में एन्टरप्रेन्योरशिप और स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, 3 इंजीनियरिंग कालेज में फैब लैब की स्थापना करने की घोषणा की। साथ ही आज बहुत सारे माननीय सदस्यों ने माननीया मुख्य मंत्रीजी को जो धन्यवाद दिया वह था जो हमारे 18 नये महाविद्यालय खोलने की जो उन्होंने घोषणा की। 2 यूजी कालेजेज में न्यू फैकल्टी और एक यूजी कालेज में नया सब्जैक्ट प्रारम्भ करने की घोषणा की। ऐसे ही जो 7 यूजी कालेज थे, उन्हें पीजी कालेज में क्रमोन्नत करने की उनके द्वारा घोषणा की गई। इसलिए आज मैं इस अवसर पर माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के तहत काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

ऐसे ही महामहिम राज्यपाल जी, जो कुलाधिपति भी हैं, उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके यहां आने के बाद राजस्थान में जिस तरीके का एक नवाचार उन्होंने शुरू किया, आज से पूर्व यूनिवर्सिटीज में ऐसी लाखों डिग्रियां पड़ी रहती थीं जिनका वितरण नहीं होता था। लेकिन महामहिम राज्यपाल जी द्वारा प्रतिवर्ष उनके द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन कराना सुनिश्चित किया गया और इन दीक्षांत समारोह में जितनी भी पेंडिंग डिग्रीज थीं, उनको पहले क्लियर किया उसके बाद हर वर्ष की जो डिग्रीज हैं, उनको उन दीक्षांत समारोह में वितरित किया जाता है। ऐसे ही पहले जो एक परम्परा चली आती थी कि जो पहले दीक्षांत समारोह होता था, उसमें गाउन पहनकर डिग्रियां ली जाती थीं जो कि एक तरह से विदेशी परम्परा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उस तरीके की एक परम्परा चली आ रही थी और वो ही चल रही थी। लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने उसमें बदलाव किया और भारतीय वेषभूषा के तहत ही दीक्षांत समारोह में हमारे सारे ही विद्यार्थी अपनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, काले गाउन को हटाकर भारतीय वेशभूषा में ही उसको आयोजित करना सुनिश्चित किया।

ऐसे ही विश्वविद्यालयों को यह कहा गया कि हर विश्वविद्यालय को एक साल में एक विलेज को स्मार्ट विलेज बनाना है और उसमें कैश लैस ट्रांजेक्शन हो, इस बात को सुनिश्चित करना है, यह भी एक बहुत ही अच्छा कदम रहा। जहां हर यूनिवर्सिटी ने एक-एक गांव गोद लिया है और गोद लेकर उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

में एक समान एकेडमिक कलेण्डर उन्होंने लागू किया, जिसकी कई समय से सब लोग मांग कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज अलग-अलग होती हैं, उनके अलग-अलग एकेडमिक कलेण्डर होते हैं, एकरूपता नहीं है। लेकिन यह एकरूपता लाने का काम भी किया इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल जी, कुलाधिपति जी को भी इस सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कई अच्छे नवाचार के जो काम शुरू किये, यह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होंगे।

ऐसे ही मैं आज यूनिवर्सिटीज का वर्तमान परिदृश्य रखूं तो हमारे यहां 12 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 2 टैक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ऐसी 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा देखें तो एग्रीकल्चर, मेडिकल, स्किल, पुलिस एवं स्पोर्टस की 11 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं, 7 डीम यूनिवर्सिटीज हमारे यहां राजस्थान में संचालित हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी ऐसे 6 संस्थान हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एमएनआईटी है, एम्स है, आईआईएम है, यह सारी एक तरह से राजस्थान को गौरवान्वित करती हैं, जहां राजस्थान में ऐसे 6 सेंट्रल लेवल के संस्थान चल रहे हैं। कालेजेज को देखें तो 3300 ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कालेजेज संचालित हो रहे हैं।

जिस तरीके से अभी कुछ सदस्यों ने यहां पर रखा और कहा कि यूनिवर्सिटीज का काम खास तौर से रिसर्च का होना चाहिये। हम लोगों ने इस ओर बहुत ध्यान दिया है और इनका मूल उद्देश्य शोध कार्य होना चाहिये, उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से हम लोगों ने कल्चरल, इकोनोमिकल एण्ड लिटरेचर के क्षेत्र में और महापुरुषों के जीवन पर कुछ अच्छे शोध होने चाहिये, इसके लिये शोध पीठ की स्थापना की। मैं आज आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि 7 विश्वविद्यालयों में 13 शोध पीठ हमने प्रारम्भ किये हैं और 4 शोध पीठ हमारे प्रस्तावित हैं। जिसमें कोटा विश्वविद्यालय में वंशावली लेखन भारतीय परम्परा अध्ययन शोध पीठ हमने कायम किया है। कोटा में ही स्वामी विवेकानंद शोध पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, अंबेडकर शोध पीठ और सिंधु संस्कृति एवं परम्परा अध्ययन शोध पीठ की स्थापना की है। ऐसे ही अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, उसमें भी अंबेडकर शोध पीठ, सिंधु शोध पीठ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध पीठ और दयानंद सरस्वती शोध पीठ स्थापित

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की। ऐसे ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है, उसमें मीराबाई शोध पीठ और अवंती बाई लोधी शोध पीठ, यह दोनों ही शोध पीठ प्रस्तावित हैं, आगामी वर्ष में इसकी स्थापना हो जाएगी। उदयुपर में मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर महाराणा प्रताप शोध पीठ स्थापित हुई है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का जहां पर मदनमोहन मालवीय सेंटर फोर वैल्यू एजुकेशन शोध पीठ स्थापित है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में दो शोध पीठ प्रस्तावित हैं, एक वेद विद्यापीठ और एक गोविंद गुरु शोध पीठ। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण शोध पीठ और बाबा रामदेव शोध संस्था, इस तरह के यह 13 शोध पीठ हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार ने जो हमारे सभी महापुरुष थे, उनके जीवन पर आधारित यह शोध पीठ स्थापित कर स्टूडेंट को यह मौका दिया है कि इन शोध पीठ के माध्यम से काफी कुछ वह इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं।

(21.00 बजे)

अभी हमारे कुछ सदस्य, जो सामने बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए जिन्होंने काफी सारे आरोप लगाए और कहा कि आप लोगों ने क्या किया, कालेजेज बंद कर दिए वगैरह और काफी कुछ कहा, लेकिन मैं मोटे-मोटे रूप से एक खाका आपके सामने रखना चाहती हूं कि कांग्रेस के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कालेजेज खुले हैं, इसका एक दृश्य आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूं कि आप जो घोषणा करते आए, वह सिर्फ एक दिखावा है और एक तरह से लोगों के बीच में सिर्फ शो करना है कि हम लोगों ने कालेजेज दिए, लेकिन धरती पर वे कालेजेज कब और कैसे आए, इसके बारे में बताना चाहूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस शासन का प्रथम वर्ष था तो इन्होंने एक भी कालेज की घोषणा नहीं की थी और हमारे प्रथम वर्ष में हमने 8 कालेजों की घोषणा की।

इनका जो द्वितीय वर्ष था, उसमें इन्होंने एक कालेज की घोषणा की, हमने 8 कालेजों की द्वितीय वर्ष में भी घोषणा की। जब इनका तीसरा साल था तो इन्होंने एक भी कालेज की घोषणा नहीं की, लेकिन हमने 12 कालेज की घोषणा की। जो चौथा साल था, उसमें इन्होंने केवल 2 कालेज की घोषणा की और हमने चौथे साल में 17 कालेज की घोषणा की, 5 साल का अगर मैं पूरा इनके सामने रखूं तो 5 साल में इनके द्वारा तीस कालेज यानी पांचवें

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साल में एक साथ 27 कालेज की घोषणा की गई और हमारा 5 साल का कार्यकाल अगर देखें तो हमने 63 कालेजेज की घोषणा की। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि चार साल में ऊंट के मुंह में जीरा, एक कालेज 0, एक 0, इतना और एक साथ इन्होंने पांचवें साल में जो 27 कालेज की घोषणा की, उसकी स्थिति यह थी कि न तो इन्होंने जमीन दी थी उन कालेजेज के लिए, न ही इन्होंने कोई बजट उसके अन्दर रखा था, कुछ भी नहीं किया था, केवल घोषणा की और वाहवाही लूटी, लेकिन हमने किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखा।

हमने यह नहीं कहा, क्योंकि यह कांग्रेस कार्यकाल में घोषणा हुई है, इसलिए इन कालेजेज को हम नहीं शुरू करेंगे। हमने उन कालेजेज को भी हाथ में लिया और उनके लिए भी जमीन दी। हमने उनके लिए जमीन के साथ अमाउंट भी स्वीकृत किया और मैं यह बताना चाहूंगी कि उनमें से 18 कालेज ऐसे हैं, जिनके भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैडम, आप भेदभाव की बात कर रहे हो, मेरा कालेज बंद किया सांचौर का...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनने की शक्ति रखनी होगी आपको। (व्यवधान) जो फैक्ट है, मैं वह बता रही हूं आपको। जो भी तथ्य है, वही बता रही हूं। कोई मैं अपने आपसे नहीं जोड़ रही हूं। यह साफ बात है, बहुत क्लियर है यह कि कांग्रेस ने जो 27 कॉलेजेज की लास्ट ईयर में घोषणा की, न तो उसका कोई बजट रखा, न कोई जमीन उनके लिए रखी, किसी तरीके का कुछ उन्होंने नहीं रखा। हमने उनमें से 18 कालेजेज में भवन का काम पूरा कर दिया और 11 के अन्दर निर्माणाधीन है और एक कालेज जो जयपुर का है, उसके लिए भी करीब 38 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट के अन्दर स्वीकृत भी कर दिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब ये सारा देखते हैं, तब इसमें इनकी मंशा साफ दिखती है कि जो इन्होंने कहा कि हमने हर उपखण्ड के ऊपर कालेज खोलने की जो घोषणा की है, हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं और वह काम हमारा जारी है, 289 जो उपखण्ड हैं, उसमें से 178 ऐसे थे जहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं था। यह सिनेरियो है उस समय का जब हम सरकार में आए। आज अगर मैं सिनेरियो को देखूं तो केवल 124 ही ऐसे उपखण्ड शेष रह गए हैं, जहां राजकीय कालेज नहीं हैं, 54 ऐसे राजकीय महाविद्यालय हमने इन उपखण्डों के अन्दर खोले तो यह कहना चाहिए कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आ रही है, जहां आप जब छोड़कर गए थे तो 178 ऐसे उपखण्ड मुख्यालय थे, जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं थे। हम उसको 124 नंबर पर ले आए और 54 कालेज उन उपखण्ड मुख्यालय पर हमने खोले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जो सरकार के नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो इंजीनियरिंग कालेजेज खोले बारां, धौलपुर और करौली उसके बारे में कहूंगी कि उन तीनों कालेजेज के लिए जमीन आरक्षित हो गई है, उसके ऊपर काम शुरू करने के लिए हमने बजट आबंटित किया है। बारां में 26 करोड़ रुपए हम लोगों को उसके लिए मिल गए और उसके अन्दर तुरन्त काम शुरू हो रहा है। बाड़मेर इंजीनियरिंग कालेज की आपके समय की घोषणा थी, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, अब उसके ऊपर भी 26 करोड़ रुपए, 13 करोड़ स्टेट फाइनेंस से और 13 करोड़ सैंट्रल से हम लेकर आए और इसमें हम लोग यह काम शुरू करने जा रहे हैं। नवीन संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय के बारे में भी बहुत सारी डिमाण्ड आई थीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी सावर तहसील केकड़ी के अंदर एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की, मैं आज आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि आगामी सत्र के अन्दर यह संस्कृत महाविद्यालय, जो सावर तहसील केकड़ी में स्थित है, इसको भी हम लोग शुरू कर देंगे।

जो बात कही है, उसे हम कहते ही नहीं हैं, उसकी पालना भी करते हैं और सिर्फ घोषणा ही नहीं, उस पर काम भी शुरू करते हैं। जो लंबे समय से डिमाण्ड चल रही थी हमारे लैक्चरार्स की, कि उन लैक्चरारों के नाम पर ही वे लोग भर्ती होते हैं और रिटायर होते हैं तो भी लैक्चरार के नाम पर ही रिटायर होते हैं तो इसलिए उन लोगों का कहना था कि हमारे पदनाम में परिवर्तन होना चाहिए, हमें भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की उपाधि मिले और उससे कहलवाए जाएं, लेकिन कभी इन्होंने नहीं सुना, पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसकी घोषणा की और न केवल घोषणा की, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया।

02.02.2018 को नोटिफिकेशन जारी हो गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इस अधिसूचना के अनुसार अब 1174

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारे लैक्चरार्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और 2037 ऐसे लैक्चरार्स हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। इस तरीके से उन लैक्चरार्स को यह सम्मान देने का काम भी इस सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार सदैव कर्मचारियों की हितैषी रही है और इसलिए जब पदोन्नति की बात यहां पर कही गई थी कि पदोन्नति नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि संस्कृत शिक्षा में टीचिंग पोस्ट के अन्दर 704 लोगों की और नान-टीचिंग के अन्दर 270, कालेज शिक्षा में 2069 टीचिंग पोस्ट में और 510 नान-टीचिंग के अन्दर और तकनीकी शिक्षा में 8 टीचिंग पोस्ट में, 84 नान-टीचिंग पोस्ट में। कुल-मिलाकर 3618 ऐसे हमारे टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के ऊपर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति इस सरकार में अभी हम लोगों ने की।

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए छात्राओं को ऐसे स्थानों पर, जहां सह शिक्षा के कालेजेज थे, उनमें भी उन्हें लिबर्टी दी है कि वे वहां सह शिक्षा के कालेज में भी एडमिशन ले सकती हैं, otherwise यह था कि जहां पर गर्ल्स कालेज खुल गया है, वहां पर सह शिक्षा के कालेज में गर्ल्स को अलाउड नहीं था एडमिशन, लेकिन हमने उन सह शिक्षा के कालेजेज में भी गर्ल्स को एडमिशन के लिए अलाउ किया है तो यह भी एक तरह से छात्राओं को प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने एक कदम उठाया है। साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सैक्टर के अन्दर अगर देखा जाए तो ग्रास एनरोलमेंट रेश्यो जो है, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

इसके अन्दर मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाह रही हूं, जहां 2008 में नेशनल ग्रास एनरोलमेंट रेश्यो था, वह 13.70 था, वही 2016 में 25.20 परसेंट हुआ यानी पिछले 8 वर्षों में जो वृद्धि हुई, वह 80 परसेंट हुई नेशनल लेवल के ऊपर ग्रास एनरोलमेंट रेशो में। यही अगर स्टेट का हम लोग देखें तो राजस्थान में यह 2008 में 9.80 परसेंट था, 2016 में वही 20.50 हुआ यानी 110 प्रतिशत ग्रास एनरोलमेंट रेश्यो में राजस्थान ने वृद्धि की है। यह अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है कि आज माननीय उपाध्यक्ष जी, जो 10 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनमें से 51.40 प्रतिशत जो हैं, वे हमारी बेटियां हैं, जो आज कालेज की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि पहले

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह था कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, स्कूल में भी नहीं पढ़ाते थे, अब तो स्कूल में तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ कालेज में भी 51.40 परसेंट लड़कियां पढ़ रही हैं।

2017-18 में बेटियों के नामांकन में 17.40 परसेंट की वृद्धि हुई है और अब यह पूरा ही अगर देखें तो 1997-98 में 60000 गर्ल्स थीं, जो पढ़ती थीं कालेज में। 2003-04 में 1.03 लाख हो गईं, 2008-09 में 1.63 और 2017-18 में यह बढ़कर 5.46 लाख गर्ल्स हैं, जो पढ़ रही हैं, इसलिए एक दशक के अन्दर 235 परसेंट गर्ल्स जो हैं, उनका नामांकन छात्राओं का कालेजेज के अन्दर हुआ है। यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी बताना चाहूंगी कि हमने गर्ल्स एजुकेशन के लिए 10 राजकीय कन्या महाविद्यालय और 2 राजकीय पोलीटैक्निक कन्या महाविद्यालयों के अन्दर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कम्युनिकेशन प्रोग्राम शुरू किया ताकि ये जो लड़कियां हैं, जो इन कालेजेज में पढ़ रही हैं, इनका इंग्लिश का इंप्रूवमेंट हो सके और ये जो बच्चियां हैं, हम लोग एक अलग से इनके लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, एक Ist Phase में हमने 12 गर्ल्स कालेजेज को लिया है, जिसमें 10 राजकीय हैं और 2 पालीटैक्निक गर्ल्स कालेज हैं।

जेंडर एटलस भी हमने बनाना शुरू किया है, उस जेंडर एटलस के अन्दर पहला हम लोगों ने उदयपुर डिवीजन का एक जेंडर एटलस बनाया है। माइक्रो लेवल पर यह जो जेंडर एटलस बना है उसमें भी यह बात सामने आई है कि गर्ल एजुकेशन में ट्राइबल एरिया के अन्दर भी एनरोलमेंट बहुत अच्छा बढ़ा है।

अभी यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आपके यहां पर यू.जी.सी. का आप लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, यू.जी.सी. आपको कोई ग्रांट नहीं दे रही है, वगैरह-वगैरह बहुत कुछ यहां पर कहा गया था लेकिन मैं यह भी उनको तथ्य के साथ में कहना चाहूंगी कि दिसम्बर, 2013 में केवल 14 ही राजकीय महाविद्यालय थे जो NAAC के द्वारा एक्रेडिटेड थे। लेकिन अब जो हमारे वर्तमान प्रयास रहे उसके बाद में अब 71 कालेजेज ऐसे हैं जो NAAC एक्रेडिटेड हो चुके हैं। उसके अलावा अभी और भी 121 कालेजेज हैं जो उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ उनकी इंस्पेक्शन टीम आनी है और वो इंस्पेक्शन टीम आ जाती है तो उसके बाद ये भी आ जाएंगे। इसमें जो 71 हैं उसमें भी 7 कालेज हैं जो ए ग्रेड है, 54 बी ग्रेड हैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और 10 कालेजेज ऐसे हैं जिनको सी ग्रेड एक्रेडिटेशन मिला है इसलिए अभी हम एक्रेडिटेशन के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और जितने कालेज एक्रेडिटेड होंगे उतना ही यू.जी.सी. का ग्रांट हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा।

RUSA से ग्रांट प्राप्त करने के लिए भी राज्य देश में सातवें स्थान पर है। जो कहा गया कि कोई ग्रांट नहीं मिल रहा है राजस्थान को, तो इसके लिए भी बताना चाहूंगी कि देश में हम लोग RUSA की जो ग्रांट है उसके मिलने में सातवें स्थान पर हैं और यूटिलाइजेशन के अन्दर अगर देखें तो हम लोग थर्ड पोजिशन पर हैं जहां हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी बहुत ही स्पीड-अप हम लोगों का हो रहा है। RUSA के तहत ही लगभग 107 कालेजेज के अन्दर हम लोगों को ग्रांट मिला जहां पर 2-2 करोड़ रुपये कालेजेज को मिला। जैसे हमारी माननीय सदस्या ने यहां पर कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कालेज के अन्दर जो ग्रांट मिला उससे कालेज का पूरा स्वरूप ही बदल गया। कालेज के अन्दर इतनी अच्छी लैब्स हो गई हैं, लैबोरेट्रीज हो गई हैं, कालेज के अन्दर प्ले-ग्राउण्ड्स बन गये हैं, उनमें ई-क्लास रूम्स बन गये हैं, स्मार्ट क्लास रूम्स बन गये हैं। यह सारा जो हुआ है वो RUSA का जो पैसा 2-2 करोड़ रुपया प्रत्येक कालेज में मिला उसी का है। साथ-साथ यूनिवर्सिटीज को भी 20-20 करोड़ रुपये हम लोगों ने आबंटित करवाये और ऐसे 5 यूनिवर्सिटीज को 20-20 करोड़ रुपये RUSA के तहत मिले। इसलिए यह जो 352 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर का ग्रांट मिला है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि इस ग्रांट में हमने स्मार्ट क्लास रूम बनाये, स्मार्ट एण्ड आईसीटी लैब बनाये, सेमिनार रूम्स, गर्ल्स कामन रूम, रैम्प एण्ड फैसेलिटीज फोर दिव्यांग पर्सन्स, लाइब्रेरी आटोमेशन, रिनोवेशन आफ द बिल्डिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसेलिटीज, यह सारा सब कुछ इस RUSA के पैसे से हुआ है जो सामने दिख रहा है। जब आप पहले कालेजेज में जाते थे तो आपके पास में यह डिमाण्ड आती थी कि हमारे यहां पर कुछ घोषणा करके जाओ, 5 लाख रुपये दे जाओ, 10 लाख रुपये दे जाओ लेकिन अब तो 2-2 करोड़ रुपये सरकार ने एक-एक कालेज के अन्दर लगाये हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अनूठा कार्यक्रम हमने राजकीय महाविद्यालय में शुरू किया जिसको हमने नाम दिया गुरु-शिष्य संवाद। यह गुरु-शिष्य संवाद इस तरीके का है जहां पर हमने जिला मुख्यालय पर जितने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी जिले के हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से कुछ सलेक्टेड स्टूडेंट्स जो कि छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधि, वहां पर अच्छा पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो फर्स्ट आ रहे हैं उनमें से फाइव बच्चों को लिया है, पांच गर्ल्स को चुना है और जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी मैम्बर्स हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं इनको लेते हैं और इन सबके साथ में बैठकर संवाद का कार्यक्रम रहता है। कहां उनकी क्या कमियां हैं, किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या हैल्प की जरूरत है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों की उसमें चर्चा होती है। यह गुरु-शिष्य संवाद, पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर पूरा डिपार्टमेंट अलांग विद् द मिनिस्टर, हम खुद वहां पर बैठते हैं और 8-8, 9-9 घंटे की, पूरे दिन भर की यह चर्चा होती है। वहां इस गुरु-शिष्य संवाद में स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ में बैठकर अलग-अलग ग्रुप के साथ चर्चा करके उनकी वहीं घोषणा करते हैं और वहीं के वहीं उन लोगों के सारे काम को शुरू करते हैं। इसको पूरे देश में बहुत सराहा गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश में इस तरीके का गुरु-शिष्य संवाद का आयोजन किया गया है और इससे बहुत सारी सफलता भी हम लोगों को मिली है।

सामाजिक सरोकार के कार्य में भी राजस्थान कहीं पीछे नहीं है। यहां पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको देश और समाज के प्रति उनके दायित्व को समझना है और उनके कर्तव्य का पालन करना है तो इस दिशा में हमने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षरोपण और संरक्षण के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किये हैं। आपको यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती दिवस 25 सितम्बर को गत तीन वर्षों से हम लोग इसमें रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार से भी ज्यादा यूनिट का युवा रक्तदान करते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी, 2016 से हमने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जयन्ती पर भी एक और रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जिसमें भी 5 हजार यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। इस तरीके के कुछ जो काम स्टूडेंट्स को करने हैं और टीचर्स, लैक्चरर्स, इन सब की उन्नति के लिए, उनके प्रमोशन होने चाहिए और कुछ नवाचार हम लोगों ने और किये हैं वो भी माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। क्योंकि मैं इस बात को मानती हूं कि-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

'मंजिलें उसी को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, बुलन्द हौसलों से उड़ान होती है।'

उपाध्यक्ष जी, The objectives of reform in education system are expansion, excellence and inclusion. Efforts are being made to initiate entrepreneurship and skill development programme for students to optimize their placements and carrier oriented opportunities. Government of Rajasthan, endeavors in becoming the hub of higher and technical education in our Country and we are already successful upto a great extent. मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगी कि कुछ नवाचार जो हम लोगों ने किए हैं उन नवाचार में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जैसे हमारा बांसवाड़ा विश्वविद्यालय जो गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय है और जब इन्होंने इस विश्वविद्यालय को छोड़ा था तो उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के दो कमरे के एक हास्टल में वो विश्वविद्यालय चल रहा था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उसको बांसवाड़ा में शिफ्ट किया। वहां पर हम लोगों ने 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आबंटित की है, साढ़े 12 करोड़ से भी ज्यादा हम लोगों ने अमाउंट का आबंटन किया है, उसकी बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। साथ-साथ जो नवाचार उन्होंने उस विश्वविद्यालय में किया है कि जो एम.बी.ए. का कोर्स चलता था वो अभी तक तो इंग्लिश के अन्दर ही एम.बी.ए. का पाठ्यक्रम चलता था लेकिन अब एम.बी.ए. को हिन्दी माध्यम से वहां पर उस जनजाति विश्वविद्यालय ने शुरू किया जो कि एक बहुत बड़ा नवाचार है। हिन्दी माध्यम से एम.बी.ए. पढ़ाना, क्योंकि जनजाति क्षेत्र का है और उन जनजाति के बच्चों को हिन्दी में उससे लाभ मिल रहा है और यह पाठ्यक्रम वहां पर शुरू किया है।

इसी तरीके से हायर एजुकेशन पोर्टल हमने बनाया है। यह हायर एजुकेशन पोर्टल हम लिंक कर रहे हैं शाला दर्पण और शाला दर्शन से जो स्कूल एजुकेशन का है वन टू फाइव और सिक्स टू ट्वेल्व का। उस शाला दर्शन और शाला दर्पण से इसको लिंक करते हुए यह हायर एजुकेशन पोर्टल बन रहा है तो हर स्टूडेंट का पूरा ट्रैक रहेगा स्कूल से लेकर कालेज तक का। इस हायर एजुकेशन पोर्टल का नाम दिया है हमने शिक्षा दृष्टि। इस शिक्षा दृष्टि में आनलाइन एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट कालेजेज और पोलीटैक्निक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कालेजेज के अन्दर शुरू हो चुके हैं। इसमें आनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, हमने जो प्राइवेट कालेजेज के लिए एन.ओ.सी. देने की बात होती है उसका भी आनलाइन प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब इसमें कालेज मैनेजमेंट माड्यूल और आनलाइन स्कालरशिप माड्यूल, यह भी अब शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि आज जो प्राइवेट कालेजेज आते हैं और जिन लोगों की एन.ओ.सी. आनलाइन एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन उनकी स्वीकृति भी आनलाइन हो जाएगी और उस स्वीकृति के साथ ही जो एफिलिएशन जिस भी सम्बन्धित यूनिवर्सिटी से होना है उस सम्बन्धित यूनिवर्सिटी को वहां से पहुंचेगा। वो सारा ऑनलाइन होगा और वो यूनिवर्सिटी भी एफिलिएशन उनको वहीं से दे देगी। यानी यह जो चक्कर काटना या किसी तरीके का कोई गलत न हो इसलिए पूरी तरीके से पारदर्शी रूप में इसको पूरा आनलाइन प्रोसेस शुरू करना हम लोगों ने तय किया है। इसमें शुरू भी हो चुका है और एडमिशन तथा एन.ओ.सी. प्राइवेट कालेजेज को देना स्टार्ट किया है और दूसरे दो भी इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे।

इसमें एक और नवाचार जो हमने किया है वो इण्डस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस सैल की स्थापना की गई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के युग में जो ग्लोबल कम्पीटिशन है उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयारी कराने के लिए 34 पोलीटैक्निक कालेजेज में I.T.I. cell की स्थापना हम कर चुके हैं। ऐसे ही एंटरप्रिन्योरशिप सैल भी हमने स्थापित किए हैं। यह प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना और प्रधान मंत्री युवा योजना अन्तर्गत विद्यार्थियों में उद्यमिता का विकास हो, उनके अन्दर बिजनेस स्किल डवलपमेंट हो और वो बिजनेस स्किल की तरफ आगे बढ़े इसके लिए यह एंटरप्रिन्योरशिप सैल हम लोगों ने शुरू किया है और उद्यमिता की प्रवृत्ति के विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इन्क्यूबेशन सेंटर, जो माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि हमारे युवाओं को स्वावलम्बी बनाना है, उन्हें जाब सीकर्स नहीं बल्कि जाब प्रोवाइडर्स बनाना है और जाब प्रोवाइडर्स बनाने के लिए ही ये इन्क्यूबेशन सेंटर हर सम्भाग मुख्यालय के ऊपर स्थापित किये गये हैं। और ये संचालित हो रहे हैं जिसमें लगभग 3,000 युवाओं को, विभिन्न तरह से उन लोगों को कार्यशालाओं के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई है और आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि ऐसे 24 स्टार्ट-अप्स उन्हीं इन्क्यूबेशन सेंटर से निकले हैं और वह 24 स्टार्ट-अप हमारे ही स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के, जिन्होंने अच्छे स्टार्ट-अप्स बनाये हैं जिसकी सब तरफ प्रशंसा हो रही है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साथ ही हमने थ्री-डी प्रिंटिंग और रोबोटिक लैब, जिसकी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा पिछली बार की थी, उसमें हमने पांच करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक थ्री-डी प्रिंटिंग और रोबोटिक लैब की स्थापना सी.ई.जी. जयपुर के अन्दर उसका कार्य चल रहा है, एक या डेढ़ महीने के अन्दर यह भी हमारा कमप्लीट हो जायेगा। थ्री-डी प्रिंटिंग का भी यह पहला है जहां पर नवाचार के माध्यम से राजस्थान फर्स्ट स्टेट होगा, जहां पर यह रोबोटिक लैब थ्री-डी प्रिंटिंग की होगी।

ऐसे ही स्मार्ट लैब हमने शुरू किये हैं। एनीमेशन एण्ड वीडियो इन्ट्रेक्टिव वर्चुअल लैब टूल, थ्री-डी प्रिंट फाइल्स इत्यादि स्वयं सीखने और सहकर्मी को सीखने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी संभागीय मुख्यालय पर लगभग 3.27 करोड़ रुपये की लागत से इनकी स्थापना की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैक्चरर्स की कमी सामने आ रही थी, बहुत लम्बे समय से भर्ती नहीं हुई। पिछला जो कार्यकाल रहा, उसमें भर्ती हुई नहीं। अब हम लोगों के आने के बाद 1,248 ऐसे लैक्चरर्स हैं उन लोगों की परीक्षाएं हुईं, रिजल्ट आया, अब इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। उस इंटरव्यू के प्रोसेस के तहत, एक प्रोसेस में शुरू होने से जो अभी यहां पर बात आई थी, गुड एकेडेमिक रिकार्ड के बारे में जो बात आई थी, लेकिन क्योंकि वह सब कुछ पहले से डिसाइड होकर इंटरव्यूज हो रहे हैं, इसलिए उसको अब बीच में चेंज करना सम्भव नहीं था लेकिन अब हम लोगों ने 935 और ऐसे लैक्चरर्स की भर्ती के लिए अर्थना भेजनी है आरपीएससी को, उसमें हमने यह गुड एकेडेमिक रिकार्ड को आसान किया जाएगा। इसमें यह न होकर और इंटरव्यू की भी आवश्यकता नहीं होगी, डाइरेक्ट मैरिट के आधार पर ही उन लैक्चरर्स की भर्ती करेंगे। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको उठाया है।

साथ-साथ ई-क्लासरूम्स हमने बनाये हैं, उन ई-क्लासरूम्स के अन्दर भी उनको आनलाइन ई-लैक्चर डिलीवर करने का भी एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर जो स्टूडियो हमारा बना हुआ है, उस स्टूडियो के अन्दर ही हमारे लैक्चरर यहां से ही आनलाइन लैक्चर्स डिलीवर करेंगे। ई-क्लासरूम्स कालेजेज के अन्दर बन चुके हैं और अभी फर्स्ट फेज में ऐसे 34 राजकीय महाविद्यालय हैं जहां पर ये ई-क्लासरूम्स बन गये हैं और जिनको हम लोग अभी फर्स्ट फेज में शुरू कर देंगे।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसी के साथ में जो काम्पीटेटिव एग्जाम्स हैं, उन काम्पीटेटिव एग्जाम के लिए भी उनको जो सहायता देनी है या उनको जो गाइडेंस देनी है, वह गाइडेंस भी आनलाइन ई-लैक्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जायेगी। इसको शुरू किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब आप लोग कहते थे कि एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने यह अपने लेवल पर प्रयास किया है। यह प्राइवेट कालेजेज के अन्दर एक आकर्षण का केन्द्र रहता है जब उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हमारे यहां पर 100 परसेंट प्लेसमेंट होता है और बच्चा चाहते या न चाहते हुए भी उस कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में इसीलिए एडमिशन लेता है, पोलीटैक्नीक में इसीलिए एडमिशन लेता है कि उसे वहां पर प्लेसमेंट मिल जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गवर्नमेंट के अन्दर भी एक सेंट्रल प्लेसमेंट सैल की स्थापना कर दी और यह सीईजी के अन्दर सेंट्रल प्लेसमेंट सैल ने लगभग एक हजार युवाओं को अभी नौकरियां दे दी हैं। जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों के अन्दर गये हैं और कुछ कम्पनीज ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने कैम्पस के अन्दर बुलाया और उनको प्लेसमेंट दिलाया, उनमें कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, जेसीबी, अडानी सोलर, सैंडगोविन, सोनालिका ट्रैक्टर और सिगमा इलेक्ट्रिक। ये इनमें से वह कम्पनियां हैं जिन कम्पनियों के हमारे यहां पर आकर कैम्पस के अन्दर ये इंटरव्यूज हुए और उसके माध्यम से यह सेंट्रल प्लेसमेंट सैल ने बहुत ही अच्छा काम हमारे यहां पर किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन टाइम इंटीग्रेटेड आनलाइन एडमिशन प्रोसेस, आज तक राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए, पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हर साल उनको एडमिशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब उन सबको खतम करके एक ही बार में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर से सैकिण्ड ईयर आये या थर्ड ईयर आये और पोस्ट ग्रेजुएशन में गये तो वह उसको बार-बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके का प्रोसेस शुरू किया है तो स्टूडेंट्स को बार-बार एवरी ईयर जो एडमिशन लेना होता था, उसको खतम करके यह किया है।

साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्री वाई-फाई की सुविधा हमने दी है, वह भी फर्स्ट टाइम हुआ है कि सारे राजकीय महाविद्यालय में फ्री वाई-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

फाई सुविधा मिल रही है और यह अगले सत्र से इसको पूरा फुलफ्लेश शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ कालेजेज में किया था लेकिन अब अगले सत्र से सारे ही कालेजेज के अन्दर फ्री वाई-फाई सुविधा होगी। जिसका सारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर था, वह कमप्लीट हो चुका है तो अब शुरू हो जायेगा।

ऐसे ही लाइब्रेरी आटोमेशन का भी हम लोगों ने काम किया है जिसके अन्दर इन्फ्लीनेक जो आपको जानकारी होगी। जब वह महाविद्यालय में यूजीसी ने जो ई-लाइब्रेरी की योजना थी, उसके तहत 97,000 ई-बुक्स और 6,000 ई-जर्नल्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का कार्य भी राजस्थान में यहां पर लाइब्रेरी आटोमेशन के माध्यम से होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूथ एम्प्लायमेंट स्कीम है, इग्नू के साथ हमने एक एमओयू किया, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे हमने एक एमओयू किया। यहां पर बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि स्टूडेंट्स के अन्दर स्किल कैसे आये, उनके साथ में स्किल डवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू करने चाहिए। इग्नू के साथ हमारा एमओयू हुआ, वह इसी दृष्टि से है कि जहां पर लगभग ऐसे 24 कोर्सेज हैं जो सलेक्ट किये गये और उन 24 कोर्सेज में से हमने हर कालेज को पांच कोर्स लेना अनिवार्य किया है। इग्नू के साथ में इस तरह का टाई-अप हुआ है जहां पर एससी, एसटी और गर्ल्स, इन तीन को उसमें कोई पेमेंट नहीं करना है, बिलकुल फ्री है उनके लिए और ये सारे स्किल डवलपमेंट के कोर्सेज हैं जो उन कालेजेज के अन्दर चलाये जाएंगे। पहले यह था कि कालेज में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को स्किल नहीं देकर, जब वह स्टूडेंट्स पास-आउट हो जाते हैं या ड्राप-आउट हो जाते हैं, उसके बाद ही स्किल दी जाती है लेकिन एक बहुत अच्छा नवाचार हुआ है जहां कालेज एजुकेशन के साथ-साथ स्किल डवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू हो गये हैं और एक बहुत ही अच्छा उसका हम लोगों को रेस्पोंस मिला है। लगभग 17,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और एवरी सिक्स मंथ अलग-अलग कोर्सेज को वह लोग सलेक्ट कर सकते हैं।

ऐसे ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नवाचार यह भी हुआ है, जहां पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब यहां पर एजुकेशन फेस्टीवल था, उस एजुकेशन फेस्टीवल के अन्दर एक अपर-एप जो है, उसको लांच किया था। वह अपर-एप यह है "अपस्किल प्रोफिशियंसी इन इंगलिश फोर राजस्थान", यहां पर इंगलिश इम्प्रूवमेंट के लिए 'हेलो इंगलिश' जो कम्पनी है, उसके साथ में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह एमओयू किया गया था और इसका लोकार्पण करते समय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह इच्छा जाहिर की थी कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। कालेज के स्टूडेंट्स इस एप को डाउनलोड करें तो एन्ड्रोयड मोबाइल के अन्दर नि:शुल्क इसमें यह डाउनलोड हो सकता है और इसमें लगभग 27,230 महाविद्यालय के छात्र हैं, लगभग 50,000 से अधिक और सारे लोग हैं जिन्होंने इसे डाउनलोड किया है।

ऐसे ही एक दिशारी एप हम लोगों ने लांच की है। यह दिशारी एप भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई है। राजस्थान पहला स्टेट होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूं जहां पर स्टूडेंट्स को आनलाइन स्टडी मैटेरियल, आनलाइन टैस्ट काम्पीटेटिव एग्जाम्स की उनको तैयारी करना है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करना है। उसको किस तरीके से करेंगे, वह सारा सब कुछ दिशारी एप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यह भी एन्ड्रोयड फोन के ऊपर नि:शुल्क डाउनलोड करता है।

साथ ही इसमें लगभग 12,000 से भी अधिक ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें क्विज के रूप में रखा है तो खेलते-खेलते ही वह स्टूडेंट, विद्यार्थी या कोई भी, जो भी अपना काम्पीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वह उसमें बहुत कुछ सीख सकता है और इसमें लगभग 30,000, क्योंकि इसको पूरा हम लोगों ने यह किया है कि मोनेटरिंग भी इसमें अन्दर हो रही है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस एप को डाउनलोड किया है तो लगभग 30,000 स्टूडेंट्स सहित, स्टूडेंट्स तो 30,000 हैं, ओवरआल 60,000 लोग हैं जो इस दिशारी एप के साथ में जुड़े हैं और दिशारी एप को, अब इसके हम लोग डेस्क-टाप वर्जन की भी तैयारी में लगे हुए हैं तो दिशारी एप को न केवल एन्ड्रोयड मोबाइल पर, लेकिन डेस्कटाप के ऊपर भी उसका वर्जन तैयार हो रहा है। वह भी बहुत जल्दी लांच कर देंगे तो यह भी शुरू हो जायेगा।

साथ ही दिशारी एप को हम लोगों ने कोचिंग और कैपेसिटी एन्हांसमेंट स्कीम के साथ भी जोड़ लिया, यानी यह तो हो गया जहां हम लोगों ने एप से डाउनलोड किया एन्ड्रोयड मोबाइल पर लेकिन साथ-साथ कालेजेज के अन्दर भी यह कोचिंग का कार्यक्रम दिशारी एप के तहत शुरू किया है। पहले चरण में 10 राजकीय महाविद्यालयों में क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से कोचिंग कक्षाएं प्रारम्भ की हैं। इन कक्षाओं में मेंटल एबिलिटी और मैथेमेटिकल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एबिलिटी की तैयारी करवाई जा रही है। लगभग 4,000 से भी अधिक विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है और यह काम कालेजेज में चल रहा है, 10 कालेजेज को इसके अन्दर सलेक्ट किया है।

ऐसे ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि एक नवाचार यह भी किया है हमने कि जहां राजकीय महाविद्यालय को सैटेलाइट इमेजनरी पर जियो टेगिंग करके महाविद्यालयों के अन्दर नेक है, रूसा का कितना किस तरीके से हुआ, नेक एक्रेडेटेड है या नहीं? यूजीसी का क्या स्टेटस है? इन सबको हम लोग जियो मैपिंग करके और उसका डिसप्ले उस पर हो जाता है जिससे कि बहुत ही आसानी हो जाती है।

जब कुछ आलाइन करना है, कलेक्शन कोई करनी है सूचनाओं की, तो सारा सब कुछ वो जियो मैंपिंग है तो उसके माध्यम से इन तीनों चीजों की सूचना मिल जाती है और नीतिगत कोई निर्णय लेना है तो बहुत आसानी हो जाती है। यह पूरा हम लोगों ने जियो टैगिंग किया है।

लैंग्वेज क्लब हमने शुरू किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह लैंग्वेज क्लब हमने स्टार्ट किया है इसके अन्तर्गत भाषा विकास के लिए इंग्लिश, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और राजस्थानी भाषा के लिए ये लैंग्वेज लैब राजकीय महाविद्यालयों में संचालित की जा रही है।

ऐसे ही मैं आपके माध्यम से यह भी कहूंगी कि हम डिजीटल लर्निंग कैम्पेन शुरू कर रहे हैं। डिजीटल लर्निंग कैम्पेन, हम माइक्रोसाफ्ट की सहायता से इसको शुरू कर रहे हैं। यहां पर, इसमें लगभग 10 हजार विद्यार्थियों और 500 जो हमारे संकाय के सदस्य हैं को तकनीकी प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाएगा। इसकी तैयारी हमारी हो चुकी है, इसमें नाम रजिस्टर हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही शुरू कर रहे हैं, माइक्रोसाफ्ट कम्पनी कर रही है और ये प्रशिक्षणार्थी जो भी होंगे उनका मूल्यांकन करने के पश्चात माइक्रोसाफ्ट कम्पनी जो है उनकी तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र देगी।

ऐसे ही बिग डाटा चैलेन्ज जिसको कि हमेशा हम जानते थे कि यह होना चाहिए, उसमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री इन्टरफेस को प्रोत्साहित करने के लिए दिसम्बर, 2017 में हमने एक एच.आर. कानक्लेव का आयोजन यहां पर किया था। इसमें आल इंडिया लेवल पर यह बिग डाटा चैलेन्ज काम्पीटिशन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हम लोगों ने आयोजित किया। इस बिग डाटा चैलेन्ज में हमारे पास में इस काम्पीटिशन में लगभग 537 टीमें आई थीं, 1700 से अधिक स्टूडेण्ट्स ने इसमें भाग लिया था और प्रथम पुरस्कार हम लोगों ने 1 लाख रुपये का दिया था, द्वितीय हमने 75 हजार का और तृतीय पुरस्कार हमने 50 हजार का दिया था और बहुत अच्छा स्टूडेण्ट्स का रेस्पोंस था इसमें बिग डाटा चैलेन्ज के अन्दर और उससे काफी कुछ स्टूडेण्ट्स के अन्दर यानी एक बहुत उत्साह का वातावरण था, जब ये बिग डाटा चैलेन्ज हम लोगों का काम्पीटिशन प्रोग्राम हो रहा था।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से क्योंकि बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहती हूं पर बहुत सारी चीजें जो नवाचार हम लोगों ने किये या प्रजेन्ट सिनेरियो थे मैं बहुत ही शार्ट, बहुत ही कम शब्दों के अन्दर कहूं तो उचित होगा कि हमने सारी चीजों को आपके सामने रखा। लेकिन, कुछ घोषणाएं जो हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं कि वे की जाएं वैसे तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन, कुछ जो मुझे लगता है कि जब महिला सशक्तीकरण की बात हम करें, अब महिला दिवस 8 मार्च को है, तीन दिन ही शेष रहे हैं और सबसे पहली घोषणा अगर मैं शुरू करूं तो यह महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में होनी चाहिए, जहां मैं यह कहूंगी कि किसी भी महिला की आवाज अगर होगी तो वह किस रूप में होगी तो वह यह होगी कि इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगी:-

छू ना सकूं आसमान न सही
सब के दिल को छू जाऊं,
तमन्ना बस इतनी-सी है।

तो महिलाएं यही चाहती हैं कि वे कुछ न कुछ अच्छा काम करें और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा यहां पर निर्णय लिया है, जिसकी मैं घोषणा करती हूं कि जेडीबी कन्या महाविद्यालय, कोटा जो है, उस कोटा का....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने बीट कर दिया आज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): राजकीय जेडीबी कन्या महाविद्यालय, कोटा, जो है आप मतलब महिला विरोधी लगते हो, मुझे लगता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। वर्ना इतनी इच्छी घोषणा कर रहे हैं, उसको आप बीच में हर्डल कर रहे हैं। मैं यह घोषणा कर रही हूं कि ये जो जेडीबी कन्या महाविद्यालय है कोटा का इसमें हमने पूरा लेडीज को रखा है। पूरा कालेज महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। इसमें चपरासी से लेकर प्राचार्य तक महिला होगी, इसकी घोषणा कर रही हूं। यह पहले चरण में है, हो सकता है इसको अच्छी सफलता मिलेगी तो हम हर संभाग के ऊपर एक ऐसा महाविद्यालय बनाएंगे, जहां पर सारी यानी टीचिंग, नान-टीचिंग स्टाफ सब कुछ महिला रहेगी। इस तरीके का करेंगे, तो एक तो हमने तय किया, मैंने इसकी घोषणा की है।

दूसरा माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो एक नया मंत्र दिया 'युवा शक्ति देवो भव:' और ये युवा शक्ति देवो भव: का, जो मंत्र उन्होंने दिया। वास्तव में, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जो मैक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया बहुत सारी पालिसीज उन्होंने बनाई और उन्होंने युवाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए, युवाओं को बहुत सशक्त होना चाहिए, युवाओं के लिए हम लोग क्या-क्या सोच सकते हैं। इसके बारे में समाज के अन्दर सरकार में बहुत सारे ऐसे कदम उठाये और मैं युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। पहले, उनके बारे में कुछ घोषणा करूं। उससे पहले युवाओं के लिए यह कहना बहुत ही वाजिब होगा कि

हर कामयाबी में तुम्हारा नाम होगा
तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा
डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का
एक दिन वक्त तुम्हारा गुलाम होगा।

और इसलिए युवाओं के लिए जो उनकी डिमाण्ड थी कि कुछ सीट्स हमारी बढ़नी चाहिए, पीजी के अन्दर सीट्स बढाओ तो हमने जो अभी राजकीय विद्यालय में 487 पीजी डिपार्टमेंट्स, इनमें अभी वर्तमान में 18043 ऐसे स्टूडेण्ट्स हैं जो अध्ययनरत हैं और इन पीजी डिपार्टमेंट्स में 50 परसेंट सीट्स की वृद्धि करने की मैं आज घोषणा करती हूं। अब इनमें माननीय उपाध्यक्ष जी, 18043 के स्थान पर अब 27093 सीट्स हो जाएंगी, 9050 सीट्स ज्यादा हो जाएंगी। यानी, 9050 स्टूडेण्ट्स और इतने ज्यादा हैं, जो पीजी कर पाएंगे। इनमें एमए में 6140, एमएससी में 1030 और एम.काम में 1880 स्टूडेण्ट्स को इससे लाभ मिलेगा तो एक बहुत बड़ा स्टूडेण्ट्स के लिए हुआ। जहां स्टूडेण्ट्स कहते थे कि हम गवर्नमेंट कालेज में पढ़ना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, सीट्स को बढ़ाओ तो 50 परसेंट सीट्स बढ़ी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बड़ी घोषणा यह भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जहां हमारे इस प्रदेश के अन्दर एक नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी जोधपुर में संचालित है, बहुत लम्बे समय से डिमाण्ड आ रही थी कि इस नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी के अन्दर राजस्थान के बच्चों को आरक्षण नहीं, और दूसरे स्टेट्स से कम्पेरिजन की जाती थी कि गुजरात में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, आन्ध्रा में चले जाओ। सभी जगह पर वहां के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनके अन्दर कहीं न कहीं उनके स्टूडेण्ट्स, जो उनके स्टेट के हैं उनको लाभ मिलता है। उनके लिए सीट्स आरक्षित होती हैं, लेकिन राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है, जहां नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से सदन में यह घोषणा करना चाहूंगी कि नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए 25 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की जाएंगी, इसकी घोषणा करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक और हमारे सामने विषय था आईआईआईटी, कोटा का, आईआईआईटी, कोटा सत्र 2013-14 के अन्दर इसको अस्थाई कैम्पस एमएनआईटी में शुरू किया। जबकि घोषणा इन्होंने की थी, पिछली सरकार में और वो घोषणा करके सिर्फ घोषणा ही थी, जैसा कि इनका हमेशा का नेचर है कि घोषणा करके, घोषणा ही रखो उसको। लेकिन, फिर जब 2013-14 के अन्दर हम लोग आए तो इसको अस्थाई रूप से एमएनआईटी, जयपुर के अन्दर शुरू किया, लेकिन अब इसका प्रथम बैच तो एमएनआईटी से पास-आउट हो गया है पर काफी हमारे जो कोटा से आए हुए माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस आईआईआईटी, कोटा को एमएनआईटी में जयपुर में क्यों संचालित होना चाहिए, इसे कोटा में क्यों नहीं आना चाहिए, तो मैं आज आप सबको माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस आईआईआईटी, कोटा को हम आरटीयू, कोटा के अन्दर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि अस्थाई रूप से ही इसे करना होगा, इसलिए इसे हम लोग कोटा के अन्दर ही संचालित करना चाहते हैं, लेकिन जो आरटीयू है, जो हमारी राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कोटा में है, जिसमें पैट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग का एक नव निर्मित भवन बना है। उसके अन्दर इसको हम लोग एमएनआईटी से लेकर वहां पर इसको संचालित करेंगे, इसलिए यह जो आप लोगों की डिमाण्ड थी, चन्द्रकान्ता जी हों, चाहे प्रहलाद जी गुंजल हों, सभी लोगों ने जो मांग रखी थी कि इस आईआईआईटी, कोटा को कोटा में ही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लाएं तो इसको कोटा में लेकिन केवल यही नहीं इसके भवन के निर्माण के लिए भी हमने जमीन आरक्षित कर दी है, लगभग 100 एकड़ जमीन हमने इसके लिए आरक्षित की है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके लिए जो शेयर हम लोगों को देना है 44.80 करोड़ राजस्थान का शेयर है, सेन्ट्रल का भी 44.80 करोड़ है। इसको हम लोग राजस्थान का और सेन्ट्रल का शेयर जल्दी से जल्दी करके, इस बिल्डिंग का कार्य प्रारम्भ करेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी कन्या महाविद्यालय, चौमूं शायद चौमूं के विधायक महोदय नहीं हैं, यहां पर इसलिए इसकी घोषणा को अभी रोक लेते हैं, वो कहीं सुनेंगे तब आएंगे तब देखेंगे, कर दें। कन्या महाविद्यालय, चौमूं में बहुत ज्यादा विधायक महोदय पीछे पड़े थे तो इनको कैमिस्ट्री के अन्दर पीजी की मैं घोषणा करती हूं।

इसी तरीके से चूरू में पीजी हिन्दी विषय के अन्दर इसकी भी घोषणा करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने की भी मैं घोषणा करती हूं। हर जिले के अन्दर एक आदर्श विद्यालय हमारा संस्कृत के अन्दर हो।

फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसको, माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्यटन और होटल व्यवसाय में रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए। यह बहुत जरूरी था कि फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम चलाया जाए, इसलिए मैग्रोहील कम्पनी जो है उनके साथ हमने एक एमओयू किया है और 12 विदेशी भाषा जिसमें जर्मन, जापानीज, स्पेनिश, रशियन, पोर्च्यूगीज, इटेलियन, फ्रेंच, टर्किश, चाइनीज, पारिश, अरेबिक और इंग्लिश ये सिखाने के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम हम प्रारम्भ करेंगे जो आनलाइन प्रोग्राम होगा और इसके प्रथम चरण में राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर और महारानी कालेज, जयपुर इन चार कालेजेज के अन्दर इस फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम को शुरू करने की मैं घोषणा करती हूं।

सौर ऊर्जा लगाने का हम लोगों ने तय किया, माननीय उपाध्यक्ष जी,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो कोटा विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, नसीराबाद में श्रीगंगानगर, कोटपूतली इत्यादि में रूफ टोप के ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाये। इससे हमारी बिजली आपूर्ति में हम बहुत आत्मनिर्भर हो गये। आज यह स्थिति आ गयी कि ये सोलर पैनल्स लगने से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था हमारा वो बिल तो खतम हुआ ही लेकिन साथ ही साथ हम इस स्थिति में आये कि विद्युत विभाग को हम लोग बिजली देने के लिए सक्षम हो गये। इस तरीके से कालेज की छत को हम लोगों ने यूज किया है और एक उदाहरण अगर मैं दूं तो राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर के अन्दर चालीस किलोवाट का एक सोलर पैनल हम लोगों ने लगाया था, जिसकी लागत आयी छब्बीस लाख रुपये और इससे विद्युत बिल की बचत प्रति महीना जो विद्युत बिल 90 हजार का आता था, पूरे एक साल का दस लाख अस्सी हजार रुपये हुआ। इससे अतिरिक्त विद्युत जो आय हमें हुई वो एक लाख अस्सी हजार हुई यानी हमारी रिक्वायरमेंट के बाद जो और बचत हुई वो एक लाख अस्सी हजार की हुई। दो साल के अन्दर ये पूरा खर्चा जो हम लोगों ने किया वो फ्री हो गया और उसके बाद में जितना भी विद्युत है वो फ्री आफ कोस्ट कालेज के लिए हुआ तो इस तरीके से इसी माडल के ऊपर आज मैं यह घोषणा करती हूं कि हम सारे ही राजकीय महाविद्यालयों में सोलर पैनल्स कालेज तय करें और लगा सकते हैं इसकी मैं घोषणा करती हूं।

लैब असिस्टेंट और एलडीसी के पद पर पदस्थापन के संबंध में हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा था तो मैं आज आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह घोषणा करना चाहूंगी कि 104 लैब असिस्टेंट और 32 एलडीसी के पदों पर आगामी सात दिनों के अन्दर ही हम इनके आदेश जारी कर देंगे। इनका पदस्थापन कर देंगे, जो लैब असिस्टेंट की कमी है इसकी पूर्ति कर देंगे।

नवीन विश्वविद्यालयों को एक परीक्षा आयोजन संस्था बनाना नहीं है अपितु ये विश्वविद्यालय जो आप लोगों ने अभी कहा था, अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं इस उद्देश्य से जुलाई, 2018 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र से अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा विश्वविद्यालय में हम लोग 5-5 पीजी डिपार्टमेंट्स और उसके अन्दर टीचिंग का काम प्रारम्भ कर देंगे। जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यूनिवर्सिटीज, अभी यहां पर बात आयी थी कि उन यूनिवर्सिटीज में कोई काम नहीं हो रहा है, क्या उनमें कर रहे हैं तो इनमें सबमें 5-5 पीजी डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने दे दिये हैं और केवल ये डिपार्टमेंट्स ही नहीं दिये इनके साथ में पद भी दिये हैं जिसका उल्लेख मैं अभी आगे करूंगी।

हमने भर्तियों के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार के गठन के बाद में उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा विभाग में टीचिंग के लगभग 2583 और नोन टीचिंग के 287 पदों पर भर्ती हमने पूर्ण कर ली है। आगामी वर्ष में टीचिंग के अन्दर 6366 और नोन टीचिंग के अन्दर 2016 ऐसे टोटल 8382 पदों की भर्ती की जायेगी चाहे वो संस्कृत हो, चाहे कालेज हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, इन सब के अन्दर 8382 जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ, उसकी हम लोग भर्ती करके बताएंगे आपको। यह बहुत-बड़ी बात है।

ऐसे ही यूजीसी वेतनमान के सन्दर्भ में जो बात आयी थी उसके लिए भी यूजीसी वेतनमान के बारे में भी यह प्रक्रिया पूरी प्रारम्भ हो चुकी है और यह प्रक्रिया चल रही है। शारीरिक शिक्षकों के पदनाम में परिवर्तन के संदर्भ में भी जैसे हमने लैक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदनाम में परिवर्तन किया इसी तरीके से जो फिजीकल ट्रैनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, पीटीआईज हैं उनके पदनाम में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं और इसकी मैं आज घोषणा कर रही हूं कि जो फिजीकल ट्रैनिंग इंस्ट्रक्टर हैं वो अब डाइरेक्टर, फिजीकल एजुकेशन कहलाये जाएंगे जो यूजीसी के नोर्म्स के तहत होगा। अक्टूबर में और सारी जगह हुआ था अब इसको हम लोगों ने ले लिया है यहां पर।

इसी तरीके से बात आई थी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा था कि एक समान नियम बनने चाहिए सारे ही राजकीय विश्वविद्यालयों में तो उसके बारे में भी मैं आज यह घोषणा करती हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मापदंडानुसार भर्ती के लिए एक समान ही हमारे नियम बनाये जाएंगे और जो एक अलग-अलग विसंगतियां आ जाती हैं किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह से तो वो एक जैसा ही होगा। सारे विश्वविद्यालयों में जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो एक समान होगी, इसकी मैं घोषणा करती हूं।

साथ ही प्रोफेसर और प्राचार्य की डीपीसी का इश्यु भी हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया उसके बारे में भी मैं कहूंगी कि ये जो हमारा आगामी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, उससे पहले सारे ही हमारे प्रिंसीपल्स की और हमारे प्रोफेसर्स की इनकी सबकी डीपीसी हम लोग कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षकों का सम्मान हम सबका कर्तव्य है क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस समाज के अन्दर समाज को बनाने में समाज को गढ़ने में है और इसमें हमेशा शिक्षकों का सम्मान स्कूल एजुकेशन लेवल पर ही होता आया है, 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उसके अन्दर जब भी देखते हैं तो स्कूल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनका तो सम्मान होता है, लेकिन कालेज एजुकेशन के टीचर्स, लैक्चरर्स का हमेशा यह मत था कि हमारे काम को कहीं पर भी कोई वेटेज नहीं मिलता तो इस बार मैं आपके माध्यम से सदन में यह घोषणा करना चाहती हूं कि हम भी हमारे यहां पर 5 सितम्बर को कालेज एजुकेशन के जो भी लैक्चरर्स जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं ऐसे सभी लैक्चरर्स का सम्मान हम लोग करेंगे। इसकी मैं घोषणा करती हूं।

साथ ही संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ और कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा इसकी घोषणा करती हूं। हमारे भीम से आने वाले विधायक ने जो बात कही थी कि उनके कालेज के नाम परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भीम के कालेज का नाम, तो मैं उनको आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि भीम में जो आपने कालेज के लिए नाम के लिए कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के लिए, उसी नाम से अब यह कालेज जाना जायेगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करती हूं। ऐसे ही हमारे सिवाना, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी थी कि इनके यहां पर भी जो महाविद्यालय है उसका भी नाम परिवर्तन होना चाहिए, वो केवल राजकीय महाविद्यालय नहीं बल्कि अब ये महाविद्यालय वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय, सिवाना के नाम से जाना जायेगा। इसकी भी आज मैं घोषणा करती हूं।

ऐसे ही ये पूरा मैनेजमेंट मॉड्यूल जो मैंने पहले भी कहा इंटीग्रेटेड पोर्टल के ऊपर, एफिलिएशन मैनेजमेंट मॉड्यूल जो कि यूनिवर्सिटीज के साथ में एफिलिएशन होता है उसके लिए इस पोर्टल के तहत काम शुरू हो जायेगा। आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य जो सीकर से आते हैं उनमें से कहा कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारे जो सीकर यूनिवर्सिटी है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और ये जो एंडोमेंट फंड के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारा इनके मन में संशय था कि ये जो एंडोमंड है वो एंडोमेंट फंड डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं उसकी वजह से प्राइवेट कालेजेज को बहुत प्राब्लम आ रही है, लेकिन अब इसके लिए भी हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गयी है। इस रिपोर्ट को बहुत शीघ्र ही हम लोग स्वीकृत भी कर देंगे जिसके अन्दर ये सारे ही हमारे निजी महाविद्यालयों को जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में एंडोमेंट फंड देना है वो पूरी राजस्थान की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक तरह का एंडोमेंट फंड होगा, ताकि कोई भिन्नता नहीं होगी। इस तरह का नहीं आयेगा कि यहां पर प्राइवेट कालेजेज का कोई हरेसमेंट हो रहा है इस तरीके की कोई भी बात नहीं होगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करती हूं कि एक ही तरह का एंडोमेंट फंड उनके अन्दर होगा सभी में।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो हमारे माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया, बीकानेर से आने वाले दोनों-तीनों सदस्यों ने उठाया कि हमारे यहां पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय तो खुला है, उसका अधिनियम भी बन गया है, लेकिन अब उसके आगे का काम क्या हो रहा है, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि उसका क्षेत्राधिकार हम लोगों ने तय कर लिया है। इसमें आरटीयू, कोटा और बीटीयू यानी बीकानेर टैक्निकल यूनिवर्सिटी और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा दोनों अभी तक तो एक ही टैक्निकल यूनिवर्सिटी थीं तो सारे जितने भी इंजीनियरिंग कालेजेज थे वो सब उसी कोटा टैक्निकल यूनिवर्सिटी में थे अब चूंकि बीकानेर टैक्निकल यूनिवर्सिटी अलग से बन गयी है तो उन्हीं में से कुछ कालेजेज को हमने बीकानेर टैक्निकल यूनिवर्सिटी में डाला है जिसमें मैं आपके माध्यम से सदन में यह रखना चाहूंगी कि कोटा डिवीजन, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टौंक और भीलवाड़ा ये सब सारे आरटीयू, कोटा में रहेंगे और बीटीयू जो बीकानेर है, जिसमें डिवीजन बीकानेर, डिवीजन जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट नागौर, अजमेर, अलवर, सीकर और झुंझुनूं ये सारे ही इनमें संचालित जितने भी कालेजेज हैं वो बीटीयू के क्षेत्राधिकार के अन्दर होंगे और आपने जो कहा कि इसमें और भी क्या काम शुरू होगा तो मैं यह भी आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि आगामी शैक्षणिक सत्र से ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

स्थित महाविद्यालयों का एफिलिएशन दे सकेगा, उसमें परीक्षा इत्यादि सारे कार्य शुरू कर सकेंगे और बहुत शीघ्र ही हम लोग इसमें वीसी की भी नियुक्ति करके और इसमें भी पांच डिपार्टमेंट्स जो हम लोगों को देने हैं वो भी हम लोग दे देंगे, तो आगामी सत्र जो होगा उसमें ये बीटीयू को प्रारम्भ करने का हमारा पूरा रहेगा। यह आपको मैं सदन में आश्वस्त करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम सब मिलकर, शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज हित में जो काम कर रहे हैं, उसमें प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक एजुकेशन हब बनाना हम लोगों का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिये ही इतने सारे नवाचार हमने शुरू किये हैं, इतनी सारी घोषणाएं की हैं। पूरी तरह से हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि उच्च शिक्षा के अन्दर अच्छे से अच्छा काम करके स्टूडेंट्स और समाज को उसका पूरा फायदा मिले, इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगी:

सारा जहां उसी का है, जो मुस्कराना जानता है,
रोशनी भी उसी की है, जो शमा जलाना जानता है।
उच्च शिक्षा भी उसी की है, जो इसे जुनून से ग्रहण करना जानता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एफिलिएशन का मुद्दा था, 600 निजी कालेज जो सीकर व शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हैं, केवल सीकर और झुंझुनूं के निजी कालेजों का एफिलिएशन का नवीनीकरण नहीं हुआ, बाकी 31 जिलों का हो गया, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। इसके ऊपर भी अपनी बात रखने का कष्ट करेंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में आपने वाइस चांसलर के लिये जो घोषणा की है, उसका बहुत स्वागत है, लेकिन बीकानेर विश्वविद्यालय में अभी जो दो अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, उनको संघटित कालेज बनाये बिना तकनीकी विश्वविद्यालय का कोई स्वरूप नहीं बनेगा, इसलिए इस संबंध में भी कई बार आपसे निवेदन किया गया है और मैं आज भी उपाध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि यह घोषणा भी अब बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का मूर्त रूप तभी होगा जब आप दोनों संघटक कालेजों की घोषणा करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक जी जो कांस्टीट्यूएंट कालेज बनाने के संबंध में जो बात की, ये दोनों ही इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी मोड पर हैं और सोसाइटी मोड पर चल रहे कालेजेज को कांस्टीट्यूएंट कालेज बनाना थोड़ा टैक्निकली डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए उस टैक्निकल यूनिवर्सिटी को रन करना है। मैं भी समझती हूं कि आप जो चाहते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में यह यूनिवर्सिटी तुरन्त शुरू हो सकेगी, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी की वैकल्पिक व्यवस्था करके इसको शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। कांस्टीट्यूएंट कालेज को बना सकते हैं या नहीं है, उसमें कुछ प्रोब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे है, बिकाज वे सोसाइटी मोड पर हैं। लेकिन यह हमारी पूरी मंशा है और इस टैक्निकल यूनिवर्सिटी को संचालित करें और उसके अन्दर जो भी बजट वगैरह स्वीकृत करना है, वह करें और इसको बहुत शीघ्र, इसके अन्दर सारी गतिविधियां जो एक यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, वे सारी शुरू हों, यह हमारी पूरी मंशा है।

ऐसे ही लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनके जवाब में भी मैं यह बताना चाहूंगी कि 2017-18 में जो 98 निजी महाविद्यालयों को एफिलिएशन प्रदान किया गया था और जो प्राइवेट कालेजेज के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उनमें 40 ऐसे निजी महाविद्यालय थे, जिन्होंने औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं, जिसकी वजह वे डिले हुए, इसलिए उन लोगों का एफिलिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। वे पूरी होने से अब हम लोग उनको एफिलिएशन दे देंगे। उनका यह जो बार-बार कहना है कि हमारे यहां पर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्शन करने का जो हमारा एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अन्दर यह प्रोविजन है कि जो कालेजेज हैं, उन कालेजेज का इंस्पेक्शन एवरी ईयर किया जाए और एवरी ईयर इंस्पेक्शन करके इनको एफिलिएशन दिया जाए। इसलिए वहां के जो वी.सी. हैं, उन्होंने उसको चैक कर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहीं राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, केवल सीकर व झुंझुनूं में ऐसा क्यों हो रहा है? एफिलिएशन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिया है, उस तरीके से हर वर्ष नहीं होता है। ये कोई नया नहीं मांग रहे। यह रिनुअल है। परीक्षाएं आ गयीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है तो आप कम से कम इस पर तो...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करती हूं कि उन निजी महाविद्यालयों को औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जब वे औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उनको एफिलिएशन मिल जाएगा, इसलिए आपके माध्यम से इनको जानकारी देना चाह रही हूं कि ऐसे 48 निजी महाविद्यालय हैं, जिन्होंने औपचारिकताएं पूरी करने में देरी की। अब उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो उनको भी एफिलिएशन मिल जाएगा। हमारी तरफ से हम किसी को रोकना नहीं चाहते। मैं अपने वक्तव्य को अब यहीं पर विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Mr. Devnani, Minister of Secondary Education.

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रात: काल से ही सदन में मांग संख्या 24 - कला, शिक्षा और संस्कृति में भाग लेते हुए माननीय सदस्यों ने काफी गंभीरतापूर्वक चर्चा की है और बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उन सुझावों से निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने 216 कट मोशन दिये हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कई अतिरिक्त विषय संकाय खोलने के प्रस्ताव हैं, विद्यालय क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव हैं, एकीकरण से मुक्त करने के संबंध में चर्चा है, पाठ्यक्रम में योग और वैदिक गणित, खेल-मैदान, पीपीपी मोड, रिक्त पदों को भरने संबंधी कई कट मोशन हैं। इन सबको अगले 48 घंटे में इनके कट मोशन के जवाब उनके यहां पहुंच जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्कूल शिक्षा का एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें 65 हजार राजकीय विद्यालयों में 84 लाख विद्यार्थी और विद्यालयों में 4 लाख 65 हजार से अधिक शिक्षक व कार्मिक काम करते हैं। इसके अलावा 34 हजार निजी विद्यालयों में अध्ययनरत 65 लाख विद्यार्थीयों और अन्य कार्मिक भी काम कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवार है और इस परिवार की ओर से मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने इस बजट में 28 हजार 659 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष जो कि 23 हजार 272 करोड़ था, से लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो कि ऐतिहासिक है। यदि मैं इनके समय से इसकी तुलना करूं तो इनके समय जो स्कूल शिक्षा का 2013-14 का बजट था, वह 13 हजार 435 करोड़ था और अब 28 हजार 659 करोड़। यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

लगभग दुगुने से ज्यादा है, फिर भी कहते हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में नयी भर्तियों में टोटल 77100, उसमें संस्कृत शिक्षा के कम कर दिये जाएं तो 75600 नई भर्तियों की स्वीकृति दी है, जो कि ऐतिहासिक है। किसी एक बजट में कभी 75600 नहीं ली। अभी लक्ष्मणगढ़ को भी कुछ मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी सौ पन्ने लेकर आए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो अपनी बात कंटीन्यू रखूंगा, 286 अरब का है। यदि 1 अरब पर एक मिनट भी बोला जाए तो 286 मिनट होते हैं, उतना नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई ने सुझाव दिये हैं। एक हल्का सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम-से-कम शिक्षा के सरस्वती मंदिरों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यदि अच्छी बातें हों तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए। कमी-बेशी है, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हम उसे ठीक करना चाहते हैं। उसमें आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन विपक्ष का धर्म केवल आलोचना करना नहीं, समालोचना करिए। अच्छे सुझाव दीजिए तो निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता जो निरन्तर बढ़ रही है। आप जानते हैं, कई बार कइयों से व्यक्तिगत मिलना होता है तो वे भी कहते हैं कि राजस्थान की स्कूल शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम उस ओर एक साथ चलकर यदि आगे बढ़ेंगे और इसमें पक्ष-विपक्ष से ऊंचा उठकर हम सब लोग नए बालक, जो निश्चित रूप से इस देश की नींव है। वैसे चर्चा करें तो शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक होती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, तो उसके सोचने की शक्ति बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा तो समाज समरस भी बनेगा और अंततः समरस और सशक्त भारत का सपना जो हमारे राष्ट्र नायकों ने देखा था, आजादी के आंदोलन के लोगों ने देखा। जिस पर हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई की अगुवाई में आज पूरा देश एक नवीन भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, मेरा मानना है कि जब संकल्प शुभ हो और प्रयास ईमानदारीपूर्वक किये जाएं तो परिणामों में सिद्धि प्राप्त होती है।

(22.00 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी)

बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होने तक हम न रुके हैं, न रुकेंगे। कई बार हम कहते हैं पथ में पथिक विश्राम कैसा। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। हम लक्ष्य तक पहुंचने तक विश्राम नहीं करेंगे। मैं सदन को राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शिक्षा चलाने नहीं आया हूं, मैं शिक्षा को सुधारने आया हूं। माननीय प्रधान मंत्रीजी का मैं अनुयायी हूं। प्रधान मंत्रीजी भी कहते हैं देश तो पहले भी चलता था। माननीय मनमोहन सिंह जी के समय भी चलता था लेकिन आज मैं देश को सुधारने आया हूं। शिक्षा तो हमेशा चलेगी लेकिन शिक्षा को सुधारना यह आज की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा:

बढ़ चले कदम अब रुक न पाएंगे कभी,
मंजिल पर पहुंच कर ही विराम लें सभी।

हम बिना मंजिल पर पहुंचे विराम नहीं लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पहले की बातों में नहीं जाता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं। जब हमने शिक्षा विभाग संभाला, तब राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मैंने लेखा-जोखा लिया। पुरानी बातों में नहीं जाकर संक्षिप्त में तस्वीर को जरूर प्रस्तुत करूंगा। उस समय 86000 विद्यालय तो थे, लेकिन जहां बच्चे थे, वहां शिक्षक नहीं थे, जहां शिक्षक थे, वहां बच्चे नहीं थे और जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी थे, वहां भवन नहीं थे। एक तस्वीर आपको प्रस्तुत करूं कि उस समय 142 स्कूल ऐसे थे जहां शून्य नामांकन था, 4164 स्कूल ऐसे थे जहां 15 से कम नामांकन था। यह पांचवीं और आठवीं के स्कूलों की बता रहा हूं। यदि पांचवीं में 15 से कम होंगे, एक कक्षा में कितने हुए और उसमें से भी कितने स्कूल जाते थे, यह भयावह स्थिति थी, 15 से 30 तक के नामांकन में 28 हजार विद्यालय थे। यह एक दर्दनाक स्थिति थी। इस बदहाली का कारण क्या था? लगातार नामांकन घटता जा रहा था। विद्यालयों में 52 प्रतिशत, आज कहते हैं पद रिक्त हैं, रिक्त हैं कुछ, लेकिन उस समय 52 प्रतिशत पद रिक्त थे। जरा अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम थे तब क्या था और आज उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं, तुलना करनी चाहिए। हमेशा कमी तो ठीक है कि कम है, परिवार में भी कोई न कोई चीज की तो हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी। विकास एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये पद आपने सवा चार साल में भर दिए या समाप्त कर दिए। कैसे कम हुए ये?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर दिए बिना नहीं बैठूंगा। एक बार मैं बोल लूं, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हमने पद भरे हैं। कांग्रेस ने समाप्त किए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कांग्रेस ने समाप्त किए हैं। उस समय इसका जो मेन कारण था, वह थी आपकी सरकार की इच्छा शक्ति और मेरे शिक्षकों और कार्मिकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। इस नकारात्मक शक्ति को हमने बदला क्योंकि हमारा संकल्प है सुराज। नकारात्मकता के कारण जड़ हो चुकी व्यवस्था को बदलना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा:

अंधेरा था घनघोर, राह न दिखती थी किसी ओर,
पड़े थे सूने स्कूल हमारे, मारते थे तुम शिक्षक को ताने,
हमने एक दीप जला दिया, विश्वास का, सम्मान का,
आज देखो प्रकाश, सुनो स्कूलों में जय नाद,
राजस्थान बदल रहा है, शून्य से सिरमौर बन रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे नेतृत्व के सुराज के स्वप्न को संकल्प बनाया और सिद्ध करने के लिए हमने टीम भावना से काम किया। जब मेरे से पूछते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन आप क्या सोचकर लाए? मैंने कहा कि मैंने 3टी का फार्मूला तय किया, 3टी में पहला टी है-टीम वर्क, हम नीचे से लेकर, शिक्षक से अभिभावक से लेकर के ऊपर सचिव और मंत्री तक, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, दूसरा टी है-टैक्नोलोजी और तीसरा टी है-ट्रांसपैरेंसी। इन तीन के अंतर्गत हमने काम करना प्रारम्भ किया जिसका परिणाम है कि आज जितना परिवर्तन हुआ, राजस्थान के मानव संसाधन मंत्री ने सारे देश को कहा है कि राजस्थान का अनुकरण कीजिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। आप सब भी जानते हैं आखिर यह सब कैसे हुआ। इसलिए हुआ कि हमने सबसे पहले स्टाफिंग पैटर्न बनाया। कुछ कह भी रहे थे कि जहां पांच बच्चे थे, पन्द्रह टीचर थे। हमने हर स्कूल के लिए टर्म्स तय किए कि स्टाफ इतना ही होगा तो एक स्टाफ वहां ज्यादा रह ही नहीं सकता,

(श्री वासुदेव देवनानी)

आटोमेटिकली उस पद पर स्थापित नहीं हो सकता। पहले क्या था, अधिकतर शहरी विद्यालयों में, रोड पर अध्यापक मिलते थे। बाकी स्कूल में नदारद। उसको हमने ठीक किया। इसके साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से लेकर 12 तक का स्कूल हो, उसका विवरण आगे दूंगा। इसके कारण से बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उस समय लालू यादव और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। वे यहां आए, उन्होंने पूछा कि माननीय देवनानी जी यह कैसे हुआ? उनको मैंने सारे डिटेल बताए तो उन्होंने कहा कि यह सारा हम वहां पर भी जाकर लागू करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के लोग, मध्यप्रदेश की टीम, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के अधिकारी यहां आकर देख रहे हैं और यहां से सारी जानकारियां ले जा रहे हैं। इससे राजस्थान का एक नाम बढ़ा है। आज मैं सदन में खड़ा होकर के जिस स्वाभिमान और आत्म सम्मान के साथ राजस्थान के शिक्षा विभाग की बात करता हूं तो उसका श्रेय माननीय मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता और संसाधन और वित्तीय स्वीकृति दिए जाने को देता हूं। इस सदन के माध्यम से मैं विभाग के साढ़े चार लाख से अधिक विशाल परिवार को जिन्होंने सुराज के संकल्प को अपना मंत्र बनाया है, करोड़ों अभिभावकों को, जिन्होंने संकल्प के मंत्र से तंत्र में हुए बदलाव में विश्वास प्रकट किया है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन 1850 में देश के 7 लाख 50 हजार गांवों में 7 लाख 32 हजार से अधिक गुरुकुल थे जिसकी चर्चा कोई कर रहे थे। मैं गुरुकुल की पुरानी चर्चा नहीं करता। लेकिन समाज की सहभागिता से शिक्षा की व्यवस्था चलती थी और शिक्षा से व्यक्ति निर्माण होता है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। यह एक सीधी-सी बात है। हमारी इस वैचारिक धरोहर पर विदेशी शासकों ने प्रहार किया। हर व्यक्ति के हुनर से देश में आई आर्थिक समृद्धि को उन्होंने हटाया। पूरे देश पर उन्होंने मैकाले की शिक्षा को थोपा, जिसमें न हाथ के हुनर की बात थी, न देश के स्वाभिमान की थी, न संस्कारों की बात थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ। यदि मैं राजनीतिक बात करूं तो नेहरू माडल के नाम से शिक्षा के ढांचे को हम लोग आगे बढ़ाते रहे। आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता से देश के बच्चों को इतिहास पढ़ाया गया। हमने इतिहास में परिवर्तन किया। आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। किसी ने चर्चा भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

की इधर से कि हमने अकबर महान के पाठ को हटाकर महाराणा प्रताप महान के पाठ को जोड़ा जिसका देश भर में स्वागत हुआ। 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ, आपके यहां तो डा. अम्बेड़कर का पाठ हटा दिया था। वीर सावरकर का पाठ हटा दिया था। उस पर कालिख पोत दी गई थी, उसके बाद विद्यार्थियों को मिला था। यह रिकार्ड में है बोर्ड के। मेरा विषय नहीं है। हमने आकर सारी विचारधाराओं से ऊपर उठकर नेहरू को भी, हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे, सबको उसमें स्थान दिया है और इसके आधार पर एक ही भाव मन में रहा कि :

तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित,

चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।

इस संकल्प से हम लोग काम कर रहे हैं। यह जो भी है केवल चर्चा से नहीं, केवल भाषणों से नहीं होगा। यह व्यक्ति का माइंड सैट करते हुए उस चीज में परिवर्तन लाने का एक सतत प्रयास है जिसको हम लोग करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब सब समर्पित किया है तो धन भी समर्पित कर दो। अकेले क्या करोगे आप?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने सुना नहीं। तन समर्पित, मन समर्पित, करो तो सही। मैंने तो किया है।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): वह तो मास्टर भंवरलाल जी कर गए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो कई बार कहता हूं। मैं यहां पर लाल बत्ती में घूमने के लिए मंत्री नहीं बना हूं। शिक्षा में परिवर्तन के लिए दायित्व मैंने ग्रहण किया है। यह बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लाल बत्ती तो मोदीजी ने छीन ली आप लोगों की।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं सरकार में यहां पर परिवर्तन लाने के लिए और शिक्षा में सुधार लाने के लिए संकल्पित हूं। चार वर्षों में जिस प्रकार का यह चरमराया हुआ ढांचा मिला और आपको आश्चर्य होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं आजादी के 68 वर्ष तक राजस्थान की केवल 37 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में केवल 12वीं पढ़ने की व्यवस्था थी। यानी 63 परसेंट ग्राम पंचायतें इससे महरूम थीं। उसके बारे में कभी किसी ने शायद सोचा नहीं कि इस प्रकार क्यों है?

(श्री वासुदेव देवनानी)

अधिकांश कोई विद्यालय भी थे तो कोई 6 से 12 थे, कोई 9 से 12 थे। हमने कहा कि स्कूलों को समन्वित करेंगे। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि आपने स्कूल बंद किए या प्राइमरी एजुकेशन बंद रही। मैं आपको सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्कूल बंद तो नहीं किए, समन्वय किए, लेकिन उसको और गहराई से समझने की आवश्यकता है। जहां कहीं कक्षा 1 से 12 तक का स्कूल है, तो उसमें प्राइमरी भी चलता है, कक्षा 1 से 12 है तो छठी से आठवीं भी चलता है, छठी से आठवीं है तो उसमें एक से आठ हो गया तो टोटल प्राथमिक कक्षाओं के आपके समय यूनिट्स थे 70659 और 34 हजार 92 कक्षा 6 से 8 के, 13 हजार 285 कक्षा 9 से 10 वाले और कक्षा 11 से 12 वाले 4 हजार 404, कुल संख्या 1 लाख 22 हजार 441 बनती है जो प्राइमरी स्कूल के यूनिट्स आपके समय थे। अब कितने हैं, केवल भ्रमित करने से नहीं होता, आंकड़ों से बात करो, एक-एक स्कूल पर बात करने को तैयार हूं। इस समय प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल 62 हजार 996 हैं जो उच्च प्राथमिक हैं, जिनमें प्राइमरी यूनिट चलता है ऐसे 32 हजार 585 हैं, 9 से 10 वाले में जिसमें कक्षा 1 से 5 में 13 हजार 685, उच्च माध्यमिक शिक्षा में 9 हजार 999, इस तरह 1 लाख 19 हजार, 175, आज भी प्राइमरी एजुकेशन के यूनिट्स हैं। यानी यह केवल 3 हजार का आंकड़ा है। यह एक-एक बिल्डिंग में नीचे और ऊपर चल रहे थे। उनको समन्वय किया, दीवार पर चल रहे थे। एक भी प्राइमरी स्कूल को हमने इसमें बंद नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्टाफ पैटर्न की बात कही तो आईटी के नोर्म्स के अनुसार हमने शिक्षक भी उपलब्ध कराने की बात कही। एक किलोमीटर के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन, दो किलोमीटर के अन्दर मिडिल एजुकेशन, फिर पांच किलोमीटर तक सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी की व्यवस्था, इसको हमने किया। उस माध्यम से मैंने टोटल क्रमोन्नत की बात बताई, उस आधार पर हम बढ़ते गए और आज राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत, बाकी मैं घोषणा करने वाला हूं, आप शायद कहेंगे कि इतनी ग्राम पंचायतों में नहीं है, अब राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जिसमें 12वीं तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो।

यह ठीक है वह चरणबद्ध है, एक बात मैंने कही, अभी मिडिल है तो उसको पहले चरण में सैकण्डरी करेंगे, आटोमैटिक वह सीनियर सैकण्डरी बनेगा। पूरे 9 हजार 895 ग्राम पंचायतें हैं उन सब में कक्षा 12वीं तक पढ़ने

(श्री वासुदेव देवनानी)

की व्यवस्था के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, उसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने उसमें प्रावधान कर दिया है।

हमने पिछले दिनों 53 प्राइमरी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। 84 प्राथमिक विद्यालयों को भी उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान भी इस बार किया है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर 584 अन्य विद्यालयों में आरटीई के मानदण्ड के अनुसार उन्हें क्रमोन्नत किया जाएगा। इस प्रकार इस वर्ष भी हमारे नेतृत्व ने ऐतिहासिक निर्णय करते हुए 01 हजार 832 विभिन्न स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया। जिसकी पालना में इस वर्ष 745 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को हम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने जा रहे हैं।

केवल स्कूल खोलने से तो कुछ नहीं होगा, क्रमोन्नत करने से भी नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता की आवश्यकता है। उसकी गुणवत्ता में सबसे पहले हमने तय किया कि आदर्श विद्यालय बनाएंगे। पहले कभी चलता ही नहीं था। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में इसलिए जाते थे क्योंकि वह अच्छे स्कूल थे। मेरा सरकारी स्कूल अच्छा बने। आज मेरा सदन के माध्यम से कहना है कि हम इन स्कूलों की इतनी गुणवत्ता बढ़ाते जाएंगे ताकि मेरे प्रत्येक अभिभावक की फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल बने, यह हमारा लक्ष्य है। बनना शुरू भी हुआ, कई प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कम होना शुरू हुआ है। मैं उसके भी डेटा लाया हूं, आपको बताऊंगा।

इस माध्यम से हमने इन आदर्श विद्यालयों के अन्दर कक्षा कक्ष, खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर लैब, विद्युत कनेक्शन, कम्प्यूटर व्यवस्था, शिक्षकों का पदस्थापन, प्रायोरिटी के आधार पर कर रहे हैं। आज 4 हजार 876 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में हम क्रमोन्नत कर चुके हैं। बाकी क्रम में है, हम सभी को करेंगे। इन विद्यालयों को विकसित करने के लिए मुझे खुशी है कि जन प्रतिनिधियों ने, सांसदों, विधायकों ने, भामाशाहों ने भी अपना अभूतपूर्व सहयोग किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आदर्श विद्यालय तो ठीक है, 12वीं का करेंगे। लेकिन उसी ग्राम पंचायत में 8वीं के विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का हमने तय किया है। जिसके आधार पर हम अभी तक 4

(श्री वासुदेव देवनानी)

हजार 36 ऐसे विद्यालय विकसित कर चुके हैं। इस वर्ष 5 हजार 242 विद्यालयों को और उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने योजना बनाई है। इन सबमें ई-लर्निंग हेतु कम्प्यूटर लैब की भी स्थापना करेंगे। राज्य के 9 हजार 280 विद्यालयों में शौचालय सुविधा, 9 हजार 103 विद्यालयों में ग्रीन बोर्ड, 9 हजार 253 विद्यालयों में आदमकद दर्पण भी उपलब्ध कराए हैं, शेष में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। यह कभी कल्पना नहीं की कि सरकारी स्कूल में कभी कोई ग्रीन बोर्ड से पढ़ेगा, उस ब्लैक बोर्ड में कभी चौक नहीं मिलता था, इस आधार पर हम इसको धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं।

खेल के मैदान की बात उठी। निश्चित रूप से हर जगह खेल के मैदान होने चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 4 हजार 551 विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध करा दिए हैं, 2 हजार 939 और विद्यालयों में खेल मैदान विकसित कर लिए गए हैं। एक हजार 501 विद्यालयों में खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित हो गई है, जिसके आधार पर हम क्रमश: बढ़ रहे हैं।

आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय के बाद, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अंग्रेजी मीडियम के लिए भी लोग जाते थे, ग्रामीण तरसते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल की चर्चा आई। आपके समय एक भी माडल स्कूल नहीं बन पाया। प्रारम्भ में कुछ हुए, लेकिन हमने आकर, आज राजस्थान के 134 पिछड़े ब्लाक में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, सीबीएसई से जुडे हुए हैं। उसमें शिक्षकों का पदस्थापन, प्रधानाचार्य की लीडरशिप इत्यादि हम लोग कर रहे हैं। इनके अन्दर एक नहीं, दो नहीं पांच सौ नहीं, हजार नहीं, 44 हजार विद्यार्थी आज इसमें अध्ययन कर रहे हैं।

हाउस में महिला शिक्षा की बात आई, 8 मार्च को महिला दिवस है। इन सारे स्कूलों में 55 परसेंट सीटे बच्चियों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार का हमने प्रयास किया। पहले यह केन्द्र सरकार के सहयोग से था, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार इन सबको संचालित कर रही है। इनमें शिक्षकों का पदस्थापन, अच्छे टीचर्स का इंटरव्यू लेकर हम करते हैं। माडल स्कूल के निर्माण पर 2013 तक केवल 140 करोड़ रुपये व्यय हुए, लेकिन हमारी सरकार ने चार वर्षों में 531.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च करते हुए इसका संचालन प्रारम्भ किया। फिर लगा कि केवल प्रथम तल पर है, संख्या बढ़नी चाहिए, उसके लिए 702 करोड़ से इसकी दूसरी मंजिल बनाकर उस स्कूल के

(श्री वासुदेव देवनानी)

निर्माण का काम आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इस ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जब स्कूल अच्छे बनेंगे, आदर्श बनेंगे, उत्कृष्ट बनेंगे, स्वामी विवेकानंद स्कूल बनेगे, निश्चित रूप से नामांकन बढ़ना ही है।

अब आपके सामने प्रत्यक्ष है। आंकड़े तो सब कुछ नैट पर है। आपके राज में 3 से 4 लाख का नामांकन गिर रहा था। यह सत्य है, रिकार्ड में है। इस स्थिति को संभालना और अभिभावकों की विश्वसनीयता प्राप्त करना हमारे लिए चुनौती थी। वह तो रुका, लेकिन इसके अलावा 12 लाख नये विद्यार्थी आए। इस सत्र में हमारे यहां 5 लाख 57 हजार विद्यार्थी बढ़े।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फर्जी नामांकन दिखाया, उसकी कोई जांच चल रही है उसके बारे में भी बता दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बिलकुल बताऊंगा। मैं समझता हूं कि यह बात जो आप कह रहे हैं अपने कार्यकाल की कह रहे हैं। किसी समय कहीं कोई रिकार्ड तक नहीं था, आज शाला दर्शन, शाला दर्पण में एक-एक विद्यार्थी का उसमें विवरण है। तब तो पता ही नहीं था कि प्राइमरी में कौन पढ़ रहा है, मिडिल में कौन पढ़ रहा है, सैकण्डरी में कौन पढ़ रहा है। अध्यापकों का कोई रिकार्ड नहीं। वह एक बहीखाता था। उसमें केवल नाम लिखा रहता था, पदोन्नति हो गयी, कोई रिटायर हो गया, पता ही नहीं। अब सारा कम्प्यूटराइजेशन करके शाला दर्शन, शाला दर्पण किया है। आज 84 लाख की बात कर रहा हूं, आप जाइये, लोगिंग कीजिए, हर विद्यार्थी का नाम देखिए, उसके घर जाइये, देखिए विद्यार्थी है कि नहीं। एक भी मेरे पास ले आइये, निश्चित रूप से मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। इस प्रकार का ढांचा था उसको हमने बदला। इस आधार पर बढ़ते हुए, यह सब सम्भव हुआ है। मेरे शिक्षकों के द्वारा की गई कड़ी मेहनत, स्वप्रेरणा से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना और राजकीय विद्यालयों में भौतिक व शैक्षणिक व्यवस्थाओं, परिणामों में सुधार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।

जब यह स्कूल बन जाएंगे, नामांकन बढ़ेगा, निश्चित रूप से जैसा कि कमरों की बात चली, उसका सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, राजनीतिक आरोप नहीं है, बजट की कापियां आती हैं आप उठाकर देख लें, 2009 से 2013 तक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर न तो एक रुपया खर्च हुआ, न ही कोई विद्यालय के नये भवन बने। प्राइमरी एजुकेशन

(श्री वासुदेव देवनानी)

के अन्दर हमने 4 साल में 1 हजार 168 प्राइमरी विद्यालय के नये भवन बनाए, 401 भवन विहीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के भवन बनाए। प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण और भवन विहीन का निर्माण हम लोग करते गए, आगे बढ़ते गए। उस समय आपका खर्चा इन पर जीरो था। हमने इन चार सालों में 453.68 करोड़ रुपये का खर्चा किया है। यह रिकार्ड है बजट का। उसको जरा देखिए, आलोचना करना सरल है, काम करना कठिन है, इसमें काम को एक बार स्वीकार कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को आज प्रसन्नता है। आपको भी उसमें धन्यवाद दूंगा कि जब मैंने कहा तो जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विद्यालयों के विकास के लिये आप अपना सहयोग कीजिये। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राइमरी सेट-अप में 1672 कार्यों के लिये माननीय विधायकों और सांसदों से 24 करोड़ रुपये से अधिक सहयोग मिला। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1815 विकास कार्यों पर 71.12 अर्थात एम.एल.ए., एम.पी. फण्ड से हमें 95 करोड़, जो आज तक किसी विधायक, यह हमने विश्वसनीयता अर्जित की, आप लोगों से निवेदन किया। आप लोगों ने सहृदयता के साथ राशि दी। उसमें आप सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में दी है। लेकिन 95 करोड़ ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): राजसमंद सबसे आगे है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सबने, केवल राजसमंद ही नहीं। हर, अजमेर जिला, राजसमंद जिला, लक्ष्मणगढ़, सीकर सभी ने दिया है।

इस सबका, मैंने जैसे पहले कहा कि शिक्षा में राजनीति करना मेरा स्वभाव नहीं है। इसका ही परिणाम है कि आप सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए एक बात कहूंगा,

सारी धरा भी साथ दे तो और बात है,
तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
यूं तो चलते हैं एक पैर से भी लोग,
दूसरा भी साथ दे तो और बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब मांगें पास करा दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मांगें पास करा दें, अब तो हो गया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले सुन लें। 286 अरब का पास कर रहे हैं तो 286 मिनट नहीं तो 143 मिनट तो सुन लें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): संतुष्ट हो गये तो करा देते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर तक, मैं भी सवेरे एक बजे से सुन ही रहा हूं। जितने घण्टे सुना है, कम से कम उतने घण्टे के प्रप्रोशनेट आपको भी सुनना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेल के मैदानों की जब चर्चा हुई तो उसमें तार फेंसिंग जैसे काम भी हुए हैं। जिसमें शिक्षा विभाग ने लगभग 2790 विकास कार्यों के लिये 252 करोड़ रुपये, हमारे पंचायती राज में मनरेगा और बाकी माध्यमों से हमको मिले हैं। निश्चित रूप से उसके लिये मैं पंचायत राज मंत्री का भी आभार व्यक्त करूंगा, आज स्कूलों के अन्दर खेल के मैदानों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके लिये सारी परेशानी हो रही है। चारदीवारी नहीं है। उसके साथ खेल के मैदान, जैसे मैंने कहा, इन्होंने उसके लिये हमको काफी सहयोग किया है। इसके लिये मैं निश्चित रूप से प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में, केवल माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा में 252 करोड़ और प्राइमरी एजुकेशन के अन्दर 2341 कार्यों के अन्दर 110 करोड़ रुपये, यानी कुल मिला करके आप देखेंगे कि लगभग ये 362 करोड़ रुपये मनरेगा से हमने प्राप्त किये। उसमें 340 करोड़ के कार्य अभी प्रगति पर हैं। निश्चित रूप से सरकार के पास संसाधनों की अपनी एक सीमा होती है। जैसे आपने कहा, कई बार हम लिखते हैं वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह काम उपलब्धि के आधार पर किये जाएंगे। हमने इसे चुनौती माना। हमारे पास है लेकिन उसके लिये किस प्रकार से करेंगे। तो कई और सोर्सेज भी हमने ढूंढने की कोशिश की। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों के साथ हमने लगभग, टोटल आपके समय थे 386 काम, उसके लिये आपने 95.90 करोड़ खर्च किये। हमारे कार्यों की संख्या है 4369, उसमें खर्चा किया है 1593 लाख। आगे बढ़े, बारहवीं के छात्रावास निर्माण, उसमें भी आपने केवल 45.99 खर्च किये, हमने 112 खर्च किये। इस प्रकार आगे बढ़ते जाओ, स्वामी विवेकानन्द में 140.82, हमने 702.39 करोड़ किये। फिर कहा कि पैसा कहां

(श्री वासुदेव देवनानी)

से आयेगा, जैसा मैंने आपको पहले कहा। हमने ढूंढा, डी.एम.एफ.टी. के पास पैसा रहता है। सैस होता है, उसमें से जरा विद्यालयों के लिये मांगा जाये। हमने नाबार्ड से पैसा लिया, टी.एस.पी. का पैसा लिया। मुख्य मंत्री जन सहभागिता से विकास योजनाएं शुरू कीं। डांग विकास योजना को इसके साथ जोड़ा। बी.ए.डी.पी. को, जो बोर्डर एरिया थे, उसके बाद मगरा विकास योजना, मेवात विकास योजना, इस प्रकार यदि कुल करेंगे तो आपके समय केवल 282 करोड़ के काम हुए, और आज कितने हुए, 3481.35 करोड़ का हमने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। यह तो केवल माध्यमिक शिक्षा का बता रहा हूं। सर्व शिक्षा में भी इन्हीं सबके सहयोग से 1452 करोड़ रुपये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सब हो गया, मंत्री महोदय, तो ये उप चुनाव में क्या हुआ फिर?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमेशा हर चीज को चुनाव ही, मैंने जब कहा, राजनीति से मत जोड़ो।

श्री हीरालाल (निवाई): तीन राज्यों का भी बताओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लेकिन दिमाग में राजनीति है, वह चुनाव में जो कुछ हुआ, उसके परिणाम नवम्बर, 2018 में आप स्वयं देख सकेंगे, क्या हुआ।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): फिर तीन राज्यों में क्या हुआ आपको?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): तीन राज्यों में क्या हुआ? अब यह बात आपके सामने है। अब इस बात की चर्चा उठाओगे तो दूर तक बात जायेगी। मैं उसको शुरू नहीं करना चाहता। आप पांच राज्यों में थे, अब जाकर तीन तक सिमट गये। आप 19 राज्यों में थे, हम तो पांच में थे और आज 21 राज्यों में पहुंच गये हैं। आप चार में रह गये हो। तो वह भी तो सोचिये। केवल उप चुनाव में उफान आ जाना, मुंगेरीलाल के सपने देखने के लिये किसी को मना नहीं है। आप जरूर देखिये।

इसलिये, मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा था कि सारे सहयोग से हमने आगे किया। एक दौर था, जब केन्द्र से पैसे आये भी, लेकिन आप लोग खर्च नहीं कर पाये। मुझे ध्यान है कि 2010-11 के अन्दर केन्द्र सरकार से आपके पास 744 करोड़ आये। आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। जब हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

लोग आये, यह रिकार्ड पर है, आपका खर्चा शून्य है। हम आये, हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से, तब एस्केलेशन हो गया, कहा कि और पैसा चाहिये, 744 करोड़ में नहीं हो सकता तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सहृदयता के साथ हमें 515 करोड़ रुपये दिये। इसके आधार पर उस 744 करोड़ से 515 करोड़, 12 करोड़ रुपये और जोड़ करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पूरा किया। यह है सारा।

इस वर्ष भी, आगे घोषणाओं में भी कहूंगा, 825 विद्यालयों के कार्यों के लिये हमने 248 करोड़ के तो काम कर लिये। लेकिन इसका एक चरण और करने वाले हैं, 359 करोड़ से 1163 हम नये विकास कार्य इस वर्ष और कराने वाले हैं। जिनमें 728 कक्षा कक्ष बनेंगे, 628 कला संस्कृति कक्ष बनेंगे, 801 कम्प्यूटर लैब बनेंगी, 833 विज्ञान प्रयोगशालाएं बनेंगी, 255 पुस्तकालय कक्ष बनेंगे। इस प्रकार के कामों को हम बढ़ाते हुए, और आशा है, अभी तो ये जितने मैंने वह डांग विकास, टी.एस.पी. का कहा, इनके भी हम लगातार करेंगे। इस प्रकार इनके पैसों का भी उपयोग करते हुए निरन्तर हम प्रगति की ओर और आर्थिक संरचना की ओर आगे बढ़ते जाएंगे।

अब आर्थिक संरचना भी हो गयी, स्कूल भी क्रमोन्नत हो गये, बच्चे भी आ गये, लेकिन बिना अध्यापकों के कैसे गाड़ी चलेगी। उस गाड़ी को ठीक करने के लिये पहले शिक्षक का मानस जीतना होता है। उस मानस में, मैंने एक बार एक नारा पढ़ा था, 'राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम', इस आधार पर सोचना शुरू किया। उस आधार पर सोचा कि मेरे शिक्षक को जो कुछ मिलना चाहिए, वह महरूम न रहे। इसलिये देखा कि कई वर्षों से पदोन्नतियां नहीं। वह टीचर काम करता है। समय पर उसकी पदोन्नति न हो तो उसका मन निराश होता है। फिर उससे अपेक्षा करो कि वह अच्छा काम करे! निश्चित रूप से हरेक को कठिनाई होती है। इसलिये हमने तय किया कि हम शिक्षकों को पदोन्नति देंगे। आज तक के इतिहास में, इन चार वर्षों के अन्दर 109622 शिक्षकों और कार्मिकों को पदोन्नति दे करके हम नियुक्तियों पर लाये। आप कह देंगे कि ये तो पुराने थे, आपके नयों का क्या हुआ। नयों का भी हिसाब-किताब पदोन्नति के साथ अभी बताता हूं। पदोन्नति किसकी की है, संयुक्त निदेशक एक भी नहीं था। हमने संयुक्त निदेशक के 03, उप निदेशक के 54, जिला शिक्षा अधिकारी के 333, प्रधानाचार्य 13987, प्रधानाध्यापक 4455, एडिशनल, उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा

(श्री वासुदेव देवनानी)

82, व्याख्याता 37948, वरिष्ठ अध्यापक 45883, वरिष्ठ अध्यापक 149, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक 2506, मंत्रालयिक कर्मचारी 4382, हमने इन सबको पदोन्नति दी। इतनी बड़ी पदोन्नतियों के बाद शिक्षक का निश्चित रूप से मन बना। वे आगे बढ़े। पदोन्नति से वे तो आगे बढ़े, लेकिन शिक्षकों के पद तो नीचे से पदोन्नति होगी तो खाली होंगे ही। उसके लिये हमने सबसे पहले उनके लिये किस प्रकार से पद खाली हों, कई वर्षों से पंचायत राज के शिक्षकों को कभी शिक्षा विभाग में लिया नहीं गया। सैट-अप चेंज नहीं हुआ। हमने कहा सैट-अप चेंज करेंगे। एक लाख से अधिक शिक्षकों का सैट-अप चेंज किया। इसके आधार पर पंचायत राज में वेकेंसीज बनीं। पंचायत राज की वेकेंसीज बनीं तो हमने आगे नई नियुक्तियां शुरू कीं। नई नियुक्तियों का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो जैसा पूर्व में मैंने कहा, इनके समय 50-52 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे। हमने इस वर्ष 67961 पद सीधी भर्ती से भरे हैं। आप कहेंगे कि ये तो कहीं दिखाई नहीं देता। आप सुन लीजिये, प्रधानाध्यापक 707, व्याख्याता 16069, वरिष्ठ अध्यापक 10640, अध्यापक 31414, शारीरिक शिक्षक 4054, पुस्तकालयाध्यक्ष, 1994 के बाद, एक भी उनकी वेकेंसी नहीं निकली। लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 442 पद क्रियेट किये। लिपिक ग्रेड द्वितीय-कनिष्ठ लिपिक 3117, प्रयोगशाला सहायक 1454, इस तरह कुल 67967, जो बार-बार कहते हैं न कि बेरोजगारों के साथ क्या किया। ये नियुक्तियां हैं। केवल ये ही नियुक्तियां नहीं हैं, अभी 21468 पद पाइप लाइन में हैं, जो नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं, यानी उनका सलेक्शन हो गया।

वरिष्ठ अध्यापकों का अभी हाल ही में आर.पी.एस.सी. का 9493 का परीक्षा परिणाम जारी है, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, डाकूमेंट उसके चैक हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि इस महीने के अंत तक हम उनका पदस्थापन भी कर देंगे। सैकिण्ड लेवल के 5873 की नियुक्ति शीघ्र करने जा रहे हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष 120 करने जा रहे हैं और लिपिक ग्रेड-द्वितीय, इसकी भी हम लोग नियुक्तियां, आज तक कई विभागों में लिपिक तो मिले, हमको 1700 लिपिक मिले, हमने देर नहीं की तुरन्त उनका पदस्थापन भी कर दिया। यानी, इस प्रकार का 21468 पद की निश्चित रूप से प्रक्रिया में जो आगामी इस महीने, डेढ़ महीने में हम लोग इनका पदस्थापन करेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का दुबारा आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस बजट में नवीन भर्ती यानी, पद खाली थे और पद तो इतने खाली यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

छोड़ गये। यह कोई जादू का सिरा नहीं है कि एक दिन में भर दें, प्रक्रिया होती है और उस आधार पर 75600 पदों में प्रधानाध्यापक 1200, व्याख्याता 5000 वरिष्ठ अध्यापक 9000, अध्यापक 54 हजार, एक ने कहा कि स्पष्ट करो, यह टोटल जो रीट की परीक्षा हुई है, यह पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा से आप जितने चाहो अध्यापक, इनकी तीन साल तक इसकी बनी रहती है, उसी में से हम 54 हजार लेने जा रहे हैं। कहा घोषणा कर दी, कब बनेंगे? 54 हजार, रीट की परीक्षा हो गयी है, परीक्षा परिणाम आते ही हम शीघ्र इनकी नियुक्तियां भी जारी कर देंगे और अन्य नई नियुक्तियों के लिए कहना चाहूंगा कि जैसे ही कल बजट पारित होगा तो इन सबकी अर्थना हम आर.पी.एस.सी. को या अपनी दूसरी एजेंसी जिसके द्वारा नियुक्ति होनी है, उसको हम भेज देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह तो कोर्ट में अटक गयी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): क्या? कोर्ट में अभी उन्होंने परीक्षा परिणाम में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेवल सैकिण्ड होगी शायद, कोर्ट में यह अटक गयी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लेकिन जब तक इसके परीक्षा परिणाम की तैयारी होगी तो मैं यह आशा करता हूं कि कोर्ट से हम इसका निराकरण करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जोड़ तो लेना जो आप इतने आंकड़े बोल रहे हो कहीं यह 15 लाख से ऊपर नहीं चले जाएं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बिलकुल जोड़ रखे हैं। एक-एक, नहीं जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 15 लाख से ऊपर नहीं चले जाएं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सदन के, किसी टी.वी. चैनल पर या सदन के अन्दर मैं बहस करने, जवाब देने के लिए तैयार हूं और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय," इरादे नेक हैं, लक्ष्य एक है। राजस्थान सिरमौर हो, ज्ञान का प्रकाश चहुं ओर हो, मंजिल तो मिल ही जाएगी जब ठान लिया हमने, तुम भी दो साथ तो बात कुछ और है।"

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह नहीं देंगे, साहब, साथ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, दिल पसीजेगा, कभी तो पसीजेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने अपना विवेक स्वास्थ्य मंत्रीजी को क्यों नहीं दिया?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह काम आपका है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सूरज जिस समय उगता है तो कैसी लाली होती है और अस्त होता है तो कैसी होती है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब नई नियुक्तियां और प्रमोशन की बात हो गयी तो इसका आप लोग फिर कहेंगे कि कर रहे हो तो परीक्षा परिणाम कहां है? भगवान आपको भी विवेक दे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमको तो विवेक दे दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको भी सद्बुद्धि दे, सभी को ईश्वर दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं परिणाम की बात करता हूं तो परिणाम यह मेरे तो नहीं हैं, बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम हैं। बोर्ड की परीक्षा परिणाम, दसवीं का बोर्ड, 2012-13 में 58 प्रतिशत था और आज यह बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है यानी, इतना बोर्ड बोल रहा है, बोर्ड के परीक्षा परिणाम कह रहे हैं और कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम एवरेज वह 73 प्रतिशत था वर्ष 2012-13 में और आज वह 90 प्रतिशत बढ़कर हो गया है और मुझे कहते हुए यह खुशी है।

अभी यह बात कही कि गुणवत्ता नहीं बढ़ी, गुणवत्ता नहीं बढ़ी तो जो 75 परसेंट से अधिक बालिकाएं अंक लाती हैं, उनको गार्गी पुरस्कार पहले से चल रहा है, आपके समय उनकी संख्या थी 44 हजार और इस बार जरा डाटा देखिए, कितने हैं? एक लाख 26 हजार बच्चियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करके एक रिकार्ड बनाया है यानी, तिगुना। यह परिवर्तन कोई, बच्चों ने मेहनत की, शिक्षकों को हमने उपलब्ध करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और यह सब शिक्षकों की मेहनत का एक परिणाम है कि जिसके आधार पर किया। कुछ ने सुझाव दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं की केन्द्रीकृत मोनिटरिंग और वहां पर इस सिस्टम को लागू किया जाए। इस बार बोर्ड ने यह तय किया है कि हम 15 जिलों में सैंट्रलाइज्ड मूल्यांकन अपनाने जा रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अब गुणवत्ता की बात आई। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए, कई बार यह पेज देख रहे हैं, अब दो सर्वे हुए। अभी कोई चर्चा कर रहा था। (व्यवधान) नहीं ऐसे नहीं, बोलता हूं वह सुनना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी से डरो मत, हम आपके साथ हैं, आप तो पूरे 100 पन्ने लाये हो पूरे 100 पन्ने बोलो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अभी 100 लाये नहीं, आप कहोगे तो आ जाएंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह हायर एजुकेशन में तो चुपचाप बैठे रहे, इनके कोई समझ में आया नहीं, अब यह सैकण्डरी एजुकेशन में बीच-बीच में बोल रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह मेरे से प्रेम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हायर एजुकेशन में तो कुछ हुआ ही नहीं था, बोलना क्या था? यह थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो बीच में ... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हायर एजुकेशन के समय तो हमारे डिप्टी चीफ व्हिप साहब आपको कह भी रहे थे कि कुछ बोलो, कुछ बोलो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2014 के अन्दर सरकारी विद्यालयों में 52 परसेंट और निजी विद्यालयों में 42 परसेंट था और आज बढ़कर 2016 के जो आंकड़े, मेरे पास 2017 के तो और आएंगे, 2018 के, उसमें 56.2 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। निजी विद्यालय घटकर 39 प्रतिशत आ गये। यह लोगों की हमारे प्रति बढ़ती हुई विश्वसनीयता है और इसीलिए राज्य के राजकीय विद्यालयों में प्रवेश इस वर्ष 28 प्रतिशत बढ़ा है। इसको जरा तय करिये, जरा आकड़ों के द्वारा चर्चा तो करिये और यह कब हुआ? इस बात की जानकारी दे रहा हूं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, उसमें कोई सरकार नहीं होती, एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम में आपके समय तो आप तय कर गये कि कक्षा एक से आठ तक परीक्षा नहीं करवाएंगे, बच्चा सीधा आगे जाएगा। वह नीचे जाता जा रहा था, न अभिभावक की रुचि थी, न बच्चे की थी और न टीचर्स की थी तो उसको हमने परिवर्तन किया। पांचवी और आठवीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

में बोर्ड लागू किया और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विद्यार्थियों के गणित, पर्यावरण व भाषा का औसत जो प्राप्तांक है, वह 27 प्रतिशत बढ़ा। आज आठवीं का नेशनल अचीवमेंट सर्वे में देश भर में राजस्थान प्रथम है और पांचवी में द्वितीय है और तीसरे में तृतीय है, यह जाकर नेशनल एचीवमेंट सर्वे पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आठवीं के विद्यार्थियों ने जो किया अपना परीक्षा परिणाम, निश्चित रूप से देश के अन्दर जो हमने प्राप्त किया है, यह हमारे लिए एक ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी अफसरों को धमकाने गये हैं कि इतने पन्ने क्यों लिखकर दिये?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह मेरे भाई हैं, इस तरह का आज तक उन्होंने काम किया नहीं, मुझे विश्वास है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी तो ग्रीन पन्ने चल रहे हैं, अब पीले पन्ने सारे बाकी पड़े हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसकी चिंता आप मत करिये। और इस सारी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने एस.आई.क्यू.ई., State Initiative for Quality Education भी किया, जिसमें कक्षा एक और दो में उसके बच्चों की क्या काबिलियत है, उसको पता करके उसके अनुसार वहां पर हमने नीति का निर्धारण किया। पिछले सदन में मुझे ध्यान है, मैंने एक चर्चा की थी, हम धीरे-धीरे शिक्षा के अन्दर ...(व्यवधान) अभी समय काफी है, अभी कुछ नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करने के लिए इनके पन्ने चुराने के लिए कई मंत्री बेताब हो रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह चले भी जाएंगे तो भी मुझे ध्यान है पूरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज एक बजे तक बोलना है, हम आपके साथ में हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मुझे आशा है, मैंने भी तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभी कहा है कि एक कदम आप भी साथ दो तो फिर देखो राजस्थान की तस्वीर हम कैसे बदलते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो दोनों कदम साथ रखेंगे, तीन होते तो तीन भी कर देते आपके साथ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हम तो सबको साथ, आ जाओ, शिक्षा में जो साथ आए, बढ़े चलो, साथ ले चलो, क्योंकि वह विद्यार्थी न आपका है, न मेरा है, इस राजस्थान की धरती का बालक है, उसे शिक्षित और संस्कारित करके हम देश के नव-निर्माण के अन्दर आपस में सहभागी बनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले एल.के.जी., हायर के.जी., आज के प्राइवेट स्कूलों में बच्चा वहां पर जाता है तो हमने सोचा कि हम भी बच्चों को इसके साथ जोड़ें। हमने आंगनबाड़ी केन्द्रों का समन्वयन किया और आंगनबाड़ी केन्द्र ने, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 11500 आंगनबाड़ियां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 7349 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इस तरह 14103, 18103 आंगनबाड़ी जो 500 मीटर के अन्दर है उनको हमने स्कूल के साथ जोड़ दिया है। केन्द्रों को महिला बाल विकास के साथ समन्वय करते हुए शाला दर्शन के डाटा के साथ राज-पोषण पोर्टल के साथ हमने साझा किया है, जिसके आधार पर लगातार गुणवत्ता मिलेगी, नामांकन भी बढ़ेगा और बच्चे जैसे ही आंगनबाड़ी से आएंगे तो सीधे प्राइमरी स्कूल के अन्दर भर्ती हो जाएंगे, इस प्रकार की एक आदर्श व्यवस्था, जहां पर कहीं कमरे की कमी थी, उसका भी बजट आबंटन होगा। एक-एक कमरा उनके लिए जिस स्कूल में सम्भव है, वहां भी हम बनाएंगे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे।

अब आंगनबाड़ी को भी जोड़ दिया तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनको लीडरशिप कौन सिखाएगा? फिर आप कह रहे हो, साहब, प्रधानाचार्य तो कम मेहनत करता है, हमने इनकी लीडरशिप के प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किये। एस.आई.ई.आर.टी. और डाइट के माध्यम से इनमें प्रति वर्ष करवा रहे हैं और जिनमें अधिकांश इसके आधार पर करवाते हुए अब तक 3646 तो राज्य स्तर पर, 21633 प्रधानाचार्य और संस्था प्रधानों को हमने ट्रेनिंग दी। प्राइमरी एजुकेशन में भी जो कक्षा एक से आठ, उनमें भी डेढ़ लाख अध्यापकों की गुणवत्ता ऐसे ही नहीं बढ़ी है, उसके लिए मेहनत की है शिक्षकों ने और विभाग ने, जिसके आधार पर आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं और

(श्री वासुदेव देवनानी)

इस आधार पर जब लीडरशिप, इसलिए मुझे स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य याद आता है कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक उस नाविक के समान है, जो नाव को अपनी इच्छानुसार मंजिल पर ले जा सकता है। संस्था प्रधान भी उस आधार पर वह नाविक है जिन बच्चों को जिधर ले जाएगा, उधर वह बच्चे जाएंगे इसलिए उनको 10 दिवसीय, 16 दिवसीय हमने लीडरशिप प्रशिक्षण दिया कि एस.एस.ए., रमसा, सब प्रकार से लेते हुए हम आगे बढ़े।

यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय प्रधान मंत्रीजी का एक सोच है डिजिटाइजेशन करना, इसलिए डिजिटाइजेशन के सपने को साकार करने के लिए अभी हमने अब तक बूट के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, यह शिक्षा का स्तर तो कब सुधरेगा, लेकिन आज राजस्व मंत्रीजी बेचैन हैं, इनकी नींद खराब हो गयी आज।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता सदन के उपाध्यक्ष करेंगे। हर काम पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। जहां हो, जितनी जिम्मेदारी है, उतना ईमानदारी के साथ वहन करो, बाकी जिम्मेदारी जिसकी है, वह वहन करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिये विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की बेहतरी के लिये हमने सार्थक प्रयास किये हैं। इसलिये बूट के माडल पर एक सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से एक सैटेलाइट तरीके हमने 2 हजार स्कूलों को हम करते थे, लेकिन आज इस बार हम इसके लिये अपना खुद का स्टूडियो बनाने जा रहे हैं जिससे 90 हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा। फिर हमने कुछ नवाचार भी किये हैं। नवाचार में मेरा इतना ही कहना है कुशल नेतृत्व, स्पष्ट नीति और साफ नीयत से यदि काम करें और विभाग में सबको योगदान लें तो निश्चित रूप से अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। इसमें खेल के मैदान में खेलते हुए बच्चे दिखेंगे और इन बच्चों को देखकर हमारा मन प्रसन्न होगा कि हम समाज के लिये कर रहे हैं।

इसके लिये निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और नवाचार में अभी विधायक महोदय कर रहे थे कि अक्षय पेटिका क्या है, कब खुलती है, पैसा कहां जाता है? इस प्रकार बात कर रहे हैं, आप गहराई में तो जाओ। स्कूल के प्रधानाचार्य के बाहर अक्षर पेटिका रखी है। बच्चे अभिभावक उसमें

(श्री वासुदेव देवनानी)

कुछ दान दें। एस एन सी और एस डी एम सी की जिस दिन मीटिंग होती है, सबके सामने खुलता है। वह स्कूल के लिये पैसा काम में आता है, सरकार उसको नहीं लेती। जिसके आधार पर अब तक उसके अन्दर लगभग 1 करोड़ की राशि एकत्रित हो गयी। दूसरा, हमने मुख्य मंत्री विद्यादान कोष शुरू किया। जिसके अन्दर भी साढ़े चार करोड़ रुपये अब तक प्राप्त हुए हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल भी शुरू किया। इसमें औद्योगिक इकाइयां, भामाशाह संस्थाओं ने राज्य के 155 स्कूलों के लिये 12 करोड़ 5 लाख रुपये इस प्रोजेक्ट के हमने स्वीकृत किये। यानी भामाशाह आ रहे हैं, औद्योगिक घराने आ रहे हैं, एम एल ए, एम पीज आ रहे हैं। आइये, हम क्यों सोचें, कौनसी सरकार कर रही है, उस बच्चे के भविष्य की आंखों में झांको तो वह बच्चा श्रेष्ठ बनेगा तो आपके भी चरण छुएगा और समाज में अपने शिक्षक के भी चरण छुएगा। इसलिये हमने विशेष प्रयत्न किये। एलन कोचिंग सेंटर, मेरे गरीब बच्चे थे, कैसे मेडिकल में जाएंगे, कैसे इंजीनियरिंग में जाएंगे? इनकी कोई नि:शुल्क कोचिंग होनी चाहिये। इनके पास एक-एक, दो-दो लाख रुपये नहीं है। फिर हमने एलन कोचिंग संस्था से एम.ओ.यू. किया है। उसमें नि:शुल्क कोचिंग सुविधा उनके लिये उपलब्ध करायी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयी, उसमें ए प्लस, ए और बी ग्रेड के लगभग 92 परसेंट बच्चों के आये हैं। केवल 7.52 प्लस वन जिनका डी आया है, सी ग्रेड है 7.52 परसेंट और डी ग्रेड है वन परसेंट, इन 9 परसेंट को भी हम सोच रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर इनकी भी गुणवत्ता में सुधार करें।

इस बार हमने कई नये संकाय, अतिरिक्त विषय भी शुरू किये। जहां पर कक्षा 10 में 100 से अधिक बच्चों का नामांकन था, उन कला संकाय वाले विद्यालयों में हमने विज्ञान संकाय और दसवीं में 120 से अधिक नामांकन थे, वहां कला-वाणिज्य के साथ में विज्ञान संकाय हमने खोला है। इस बार नामांकन के आधार पर पिछले चार सालों में 274 नये विद्यालयों में विज्ञान संकाय और 24 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय, अतिरिक्त संकाय के रूप में हमने खोला और जहां पर साथ में 184 विद्यालयों में कृषि विषय भी अतिरिक्त विषय के रूप में हमने प्रारम्भ किये। यानी कहीं कमी नहीं छोड़ी। विज्ञान चाहिये, विज्ञान खोली, आर्ट्स चाहिये आर्ट्स खोली, कामर्स चाहिये तो कामर्स खोली और एग्रीकल्चर जिसके लिये अभी डिमांड होती जा रही है, वह भी हमने प्रारम्भ की है। अभी बता रहे थे इसका क्या हुआ? ड्राप आउट, ड्राप

(श्री वासुदेव देवनानी)

आउट का मैं आपको बताऊंगा कि ड्राप आउट अब कितना कम हुआ है? ड्राप आउट आपके समय 2013-14 में था 13.64 प्रतिशत और आज कितना है, अब है केवल 2.16 यानी 13.64 से घटकर 2.16 प्रतिशत ड्राप आउट हो गया माध्यमिक शिक्षा में। यह है एक से बारहवीं कक्षा प्रारम्भ करने का लाभ। विद्यार्थी दो-दो, तीन-तीन बार टी.सी. लेकर घूमता था, वे आगे नहीं बढ़ पाये और खेलों की बात चली तो 6 हजार राजकीय विद्यालयों में खेलों के मैदान का विकास हम कर रहे हैं।

इसके साथ हम अभी तक भामाशाह पुरस्कार जो देते थे, उससे पहले डिजिटल सहयोग को उसमें नहीं जोड़ा था। इस बार हम डिजिटल सहयोग को भी उसमें जोड़ रहे हैं और उन भामाशाहों का भी मैं हृदय से सम्मान करता हूं और आगे बढ़ता हूं।

जैसे हमने कहा कि पाठ्यक्रम में हमने परिवर्तन किया है, लेकिन इस वर्ष हमने भगवान परशुराम और एक रावणा राजपूत का जो शहीद दलपत सिंह, इनको भी पाठ्यक्रम में जोड़ा है और आगामी वर्ष में वाल्मीकि समाज के धर्मगुरू महर्षि नवल है, जिनका जन्म नागौर जिले के गांव में हुआ था और बैरवा समाज के धर्मगुरु महर्षि बालिनाथ, जिनका जन्म दौसा में हुआ था, इनको भी हम अगले साल पाठ्यक्रम में स्थान देने जा रहे हैं। हर समाज के गुरुओं को, हर समाज के लोगों को लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे।

हमने व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया। पढ़-लिखकर रोजगार उनको मिले, ऐसे 720 स्कूलों में 10 कार्य हम लोग सिखा रहे हैं जिसमें 80 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

आज विद्यार्थी बड़ा परेशान रहता था, मुझे हर काम के लिये अजमेर जाना पड़ रहा है। बोर्ड आफिस में लंबी लाइनें लगती हैं। बोर्ड से आग्रह किया और बोर्ड ने 23 जिलों के अन्दर विद्यार्थी सेवा केन्द्र प्रारम्भ कर दिये और आगामी वर्ष जो 10 जिले हैं, उनमें विद्यार्थी सेवा केन्द्र हम प्रारम्भ कर देंगे। अब किसी जिले के बच्चे को टी.सी. या मार्कशीट के लिये अजमेर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार का एक यह भी परिवर्तन किया है।

इन सब बातों के साथ मोनिटरिंग की भी आवश्यकता होती है। जैसे बताया कि पी.ई.ओ. क्या होता है, मगर किसी ने समझने की कोशिश भी नहीं की। एक डी.ई.ओ. रहता था, जिसके पास सैकड़ों स्कूलें थीं, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, वह साल भर में भी किसी स्कूल में उसका नंबर नहीं आता था।

(श्री वासुदेव देवनानी)

हमने तय किया कि इसको डी-सैंट्रलाइज किया जाये। इसलिये हर ग्राम पंचायत में जब हमने आदर्श स्कूल बनाना शुरू किया तो उस आदर्श स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसे पी.ओ.ई. बनाएं। लेकिन बिना पी.ई.ओ. पावर के नहीं आता, लोगों की सर्विस बुक नहीं मिलती थीं, पता नहीं कहां चली जाती थीं। उनको वेतन समय पर नहीं मिलता था और भी कई प्रकार की समस्याएं थीं। इसलिये उस डी.ई.ओ. को हमने बताया कि वह अपने ग्राम पंचायत के जो 8-10 स्कूल हैं, उसकी भी वह मोनिटरिंग करेगा तो वहां के टीचर की सर्विस बुक पंचायत एजुकेशन आफिसर के पास रहेगी। सी.एल., पी.एल. सारी छुट्टियां वह सैंक्शन करेगा। इस प्रकार का रिकार्ड और मोनिटरिंग से जो प्राइमरी एजुकेशन, जिसकी ज्यादा चर्चा चली, इसके आधार पर प्राइमरी एजुकेशन को भी हम निश्चित रूप से इस प्रकार बढ़ाने जा रहे हैं। उपस्थिति बढ़ी है। पहले तो बी.ई.ओ. के पास ही जाता था, बी.ई.ओ. को पता ही नहीं रहता था कि इतने सारे स्कूलों में कितने टीचर्स हैं, कौन जा रहा है, उसको सुनिश्चित किया। इसमें जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा हमने संबलन का भी काम किया।

शाला दर्शन और शाला दर्पण में, जैसा मैंने आपको कहा कि हर प्रकार की उसके अन्दर व्यवस्था है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार आरोप भी लगते थे, आपके समय भी लगे होंगे और पहले भी लगे होंगे। मैं पूर्व की राजनीति इसमें नहीं करता, लेकिन इस पदस्थापन में काफी गड़बड़ होती थी। स्थान पता ही नहीं रहता था, कहां खाली है और कहां भरा हुआ है। हमने आकर काउंसलिंग सिस्टम लागू किया। एक विधायक महोदय पूछ रहे थे कि काउंसलिंग में वह स्थान नहीं दिखाये जाते, जिसके अन्दर वह है। मैं इस सदन के अंदर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग में जहां 100 स्थान खाली हैं, उसके 150 प्रतिशत विद्यार्थी के घटते हुए क्रम में सब अच्छे स्थान दिखा दोगे तो वही सारे शहर में और आसपास भर जाएंगे, दूर-दराज के क्षेत्रों में कोई शिक्षित जा ही नहीं पाएगा जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएं। हमेशा कुछ पद तो खाली रहेंगे, ऐसे स्थान जहां काफी समय से कोई शिक्षक गया नहीं, पद काफी समय से रिक्त हैं, विद्यार्थी बहुत ज्यादा हैं, 50 या 100 के स्कूल में तो अध्यापक पूरे भर दिए जाएंगे, लेकिन जहां 400 विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापक यदि नहीं पहुंचेगा तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं शिक्षक का हितैषी हूं, लेकिन शिक्षक के हितैषी होने के साथ शिक्षा मंत्री भी हूं। पूरी सम्पूर्ण शिक्षा को भी उसके अन्दर देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इन प्रतिबंधित जिलों की भी बात चली, उन प्रतिबंधित जिलों का हालांकि मैं बाद में उत्तर देता, लेकिन वे भी जिले हमारे राजस्थान के हैं। उन जिलों के भी शिक्षकों के पद भरे जाने चाहिए। हां, इसलिए सब लोग एक तरफ हैं, उसमें जो कैंसर पीड़ित इत्यादि हैं, हमने कइयों को बाड़मेर से, जालौर से राहत दी है। उन्होंने कहा कि हमें जेल में बंद किया है क्या? उन्होंने स्वयं ने अपना पदस्थापन वहां लिया है।

आज सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उस समय हर जिले के लिए पद तय होते हैं और यदि अजमेर जिला है, जयपुर जिला है या अलवर जिला है या शेखावाटी है, वहां पर कट-आफ मार्क्स मान लो 100 हैं और मेरे किसी टीचर का कट-आफ 80 है, उसे लगता है इन 4-5 जिलों में मेरा नहीं हो सकता, वह अपने आप को बाड़मेर के लिए एप्लाई करता है और फिर बाड़मेर में नौकरी ले लेता है, उसके बाद फिर इधर आने का वह प्रयत्न करता है।

इस तरह वहां की व्यवस्था भी ठीक चले, यहां की व्यवस्था भी ठीक चले, टीचर को भी हम राहत दें, इन सारी बातों को लेकर एक समग्र दृष्टि से हम लोग विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रतिबंधित जिले वालों को वहां लगाएंगे न, मैं तो यह पूछ रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा सबका ध्यान रखते हुए उचित समय पर विधि सम्मत हम प्रयत्न करेंगे। इसलिये इस प्रकार का अभी भी कई बार आते हैं।

हमने नये शिक्षकों की इस बार भर्ती की। लैब असिस्टेंट की भी की। कई लोगो के आये। साहब, अमुक है, इसमें महिला है या अमुक मेरा परिचित है, वह बाड़मेर या जालौर कैसे जायेगा। हमने पारदर्शिता रखी। उससे हमने 33 जिलों के अन्दर आप्शन भरवाये। उसको कम्प्यूटर में फीड कर दिया। जिसको जो जिला आया, हमने कहा भइया, वहां जाओ। इस पारदर्शिता के आधार पर किया। एक भी चेन्ज नहीं किया और न शायद हम करेंगे। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। यानी इस प्रकार से पारदर्शिता, जैसा मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी हमारे कार्य में दिखाई देती है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैन पावर बहुत आवश्यक है। मुझे ध्यान है, बीएसटीसी बहुत ज्यादा खुले, बीएड कालेज खुले। उनके बच्चों को दोनों साल के अन्दर बीस सप्ताह की ट्रेनिंग लेनी होती है लेकिन वे ट्रेनिंग कैसे लेते थे, मुझे सदन में कहने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्कूलों के साथ जोड़ा ताकि बच्चों के साथ उनका जुड़ाव हो। स्कूल टीचर क्या होता है, इसकी जानकारी मिले। इस आधार पर मुझे कहते हुए यह गर्व है कि बीएड और बीएसटीसी के जो व्यक्ति हैं, उनको हमने जोड़ा। यानी एक लाख प्रशिक्षणार्थी इस बार राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं खाली स्थान हैं, हम लोग भर रहे हैं। इसका विवरण आगे बताऊंगा। इस प्रकार कुल 63000 विद्यालयों को एक लाख छियालीस हजार आठ सौ सत्तावन ट्रेनिंग के रूप में छात्र अध्यापक-अध्यापिकाओं को लाभ मिला है।

अब यदि मैं बालिका सशक्तिकरण की बात करूं तो उसके अन्दर मैं कहना चाहता हूं:-

'ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां,
स्पर्श यदि खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां,
रोशन करेगा बेटा तो एक कुल को,
दो-दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां।

इस प्रकार का हमने सशक्तीकरण किया। इसलिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 200 संचालित हैं। उनमें 20026 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस प्रकार बच्चियां वहां पर रहकर अच्छा अध्ययन कर रही हैं। अभी हमने उनमें 16 डोरमेटरी, इत्यादि, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, 3.84 करोड़ की लागत से हमने इसको किया है। शारदे छात्रावास हैं 179 विकास खण्डों में आज 9 से 12 तक बालिकाएं संचालित हैं। उसमें 13387 बालिकाएं पढ़ रही हैं और रह रही हैं। उनके लिए भी 53.25 करोड़ की लागत से हमने छात्रावासों का निर्माण भी करवाया। मेवात छात्रावास भी चल रहे हैं। नौ मेवात छात्रावास हैं जिससे 445 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, मुख्य सचेतक महोदय आपकी परफोर्मेंस को कम करना चाह रहे हैं। ये बार-बार जाकर देख रहे हैं। ये गये थे। आपको बता दूं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको

(श्री वासुदेव देवनानी)

क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कह ही नहीं रहे हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करिए। आप चिन्ता मत करिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बच्चियों की बात चली तो मैं कहूंगा कि:-

'नवरात्र में पूजा बेटी की,
बाकी दिन कोख में मारी जाती है,
बहू के लिए घर-घर ढोक,
घर आये बेटी तो अशुभ'।

यह जो स्थिति है, सोच को बदलने का एक शिक्षा माध्यम है जिसके अन्दर झुन्झुनूं और सीकर में बालिका लिंगानुपात आपने पढ़ लिया होगा, बहुत बदलाव आया है राजस्थान भर के अन्दर। इसके लिए मैं चार लाइनें कहना चाहूंगा:-

'बेटी है अनमोल रत्न, आओ पढ़ाने का करें जतन,
खेलेगी, कूदेगी, पढ़ेगी, आगे वह अब बढ़ेगी,
न कोख में कत्ल, न आने पर बोझ,
वह रोशनी है हर घर की, वह बेटी राजस्थान की' ।

इसलिए हमने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। गार्गी पुरस्कार का मैं जिक्र कर चुका हूं। उसके आगे हमने इस बार से पद्माक्षी पुरस्कार शुरू किया है। उसके अन्दर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, नि:शक्त वर्ग, इस तरह आठ बच्चियां जो राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं उसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो फर्स्ट आयेंगी, उनको क्रमश: 40 हजार, 75 हजार और 01 लाख रुपये तथा प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। इस बार ऐसी 792 बच्चियों को हमने पुरस्कृत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मुख्य मंत्री बेटी योजना, कभी कल्पना की थी क्या, हर जिले में जो प्रथम दो स्थान प्राप्त करती हैं लेकिन उनके अंक न्यूनतम 75 प्रतिशत हो, एक ओबीसी, बीपीएल परिवार का प्रथम स्थान, तीन बच्चियों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार से उनका सारा खर्च उठाने की बात कही है और इस वर्ष के बजट में तो उन्होंने एक दिव्यांग बालिका को

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी इसमें सम्मिलित किया है। इस प्रकार बच्चियां आगे बढ़ें, उसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी, विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर 10वीं कक्षा में मैरिट में पहले तीन विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाने की व्यवस्था की है। उसका अधिकतम खर्चा 25 लाख है और शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं को आर्थिक सम्बलन दे रहे हैं। मूक बधिर, नेत्रहीन बालिकाओं को भी आर्थिक सम्बलनता पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं जिसमें 4.54 लाख, दो हजार की आर्थिक सहायता प्रत्येक को उपलब्ध करवा रहे हैं। साइकिल की बात उठी। मैं कुछ मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं कि कई माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये। कहा था कि साइकिल गड़बड़ थी। आप तो 2500 रुपये नकद देते थे। साइकिल खरीदी नहीं जाती थी। वह बालिका वैसी की वैसी ही रहती थी। हमने आकर उसको साइकिल प्रदान करना शुरू किया। हर नवीं में पढ़ने वाली बच्ची किसी कास्ट की हो, अमीर हो, गरीब हो, हरेक के लिए साइकिल की व्यवस्था की। साइकिल के रंग के लिए भी किसी को आपत्ति थी। आपके टाइम में काली देते रहे। समाज को पता ही नहीं लगे कि सरकार ने मुख्य मंत्री नि:शुल्क साइकिल मिली है। ऐसा लगता था प्राइवेट है या किस तरह घूम रही है। आज बच्ची जब उस पर घूमती है तो बडे गर्व की उसको अनुभूति होती है कि यह मेरी साइकिल है। इस प्रकार से मैं समझता हूं अपन सब का सिर गर्व के साथ ऊंचा उठना चाहिए। केसरिया रंग से आपको क्यों घृणा है। केसरिया का अर्थ है त्याग और तपस्या। इसीलिए तो आप किसी साधु और संत के पांव छूते हो। भले ही वह आठवीं पास हो या अनपढ़ हो लेकिन उसने घर त्याग दिया है। यदि वह साइकिल गेरूआ रंग की है तो माननीय सदस्य, सूर्य की किरणें भी तो केसरिया रंग की हैं। आप सूर्य की ओर मत देखो न, वह भगवा रंग दिखाई देता है, तो आगे बढ़ो। इसलिए हमने इसको किया। अब तक 11 लाख 51 हजार बच्चियों को हम साइकिल दे चुके हैं। बच्चियां जिनको साइकिल नहीं मिलीं या नवीं में उन्होंने नहीं ली या उसके बाद 10वीं, 11वीं में भर्ती हुई लेकिन कक्षा 9 से 12 तक कोई बच्ची यदि पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से आती है, उसको 20 रुपये और 25 रुपये का ट्रांसपोर्ट वाउचर भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं और इसके तहत हमने 37 हजार बालिकाओं को इस बार सुविधाएं दी हैं जिस पर लगभग 11 करोड़ रुपये हम खर्च चुके हैं। अगले वर्ष हमने

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। यह तो 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों का है। तो 01 से 08 वालों ने क्या कसूर किया। इस वर्ष से कक्षा 01 से 08 तक 02 लाख 88 हजार बच्चों को हम ट्रांसपोर्ट वाउचर देने जा रहे हैं और उसमें यदि कक्षा 01 से 05 का है तो दस रुपये और कक्षा 06 से 08 का है तो पन्द्रह रुपये, लेकिन वह भी कोई बाद में नहीं देंगे उपस्थिति आने के बाद। हर बच्ची के खाते में एडवांस एक महीने का हम जमा कराएंगे बैंक के अन्दर, और जितने दिन वह नहीं आयेगी, उसका काटकर अगले महीने का और जमा कराएंगे। यह है पारदर्शिता। ताकि हर बच्ची को सुविधा मिलती जाए। बच्चियों के सम्बलन की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल बच्चियों के प्रति समाज में कई बातें सुनते हैं। उसको आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाए, सैल्फ डिफेंस का, इसलिए हमने गत वर्ष तक 05 लाख 03 हजार बच्चियों को दिया। इस बार 03 लाख 60 हजार, इस तरह मिलाकर 08 लाख 63 बच्चियों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण भी हम दे रहे हैं।

इस नवाचार के बाद लगा कि प्राइवेट स्कूल फिर भी वहां जब भी कभी बुलाते हैं तो पेरेंट्स चले जाते हैं। सरकारी स्कूल में पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए पूछने नहीं आता था। हमने कहा पेरेंट टीचर मीट शुरू करेंगे। पिछले साल हमने पेरेंट टीचर मीट शुरू की। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 60 परसेंट पेरेंट्स इन मीटिंग्स में उपस्थित हुए। फिर एक प्रयोग और करने की इच्छा हुई कि पेरेंट टीचर मीट तो हो गया, लेकिन पुरुष आ गये। लेकिन बच्चे की पहली गुरु माता होती है, इसलिए हमने माताओं को जोड़ना शुरू किया तो चार पीटीएम में से एक पीटीएम मदर्स टीचर्स मीट करने का तय किया। कहा कि माताएं आएं और वह आयीं और अपने बच्चों के साथ अपने जब स्कूल में देखा, उसके बाद हमारे उपस्थिति भी बढ़ने लगी। माताओं का आना शुरू हुआ और अपने बच्चों का फीड बैक लेने लगे। फिर हमने पीटीएम के लिए कहा कि गरीब वर्ग भी होता है, मजदूर वर्ग भी होता है। धंधा बन्द करके कौन आएगा इसलिए हमने कहा कि हर महीने की अमावस्या के दिन हम इसको करेंगे और इस प्रकार के अभिभावकों को इसके साथ जोड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्वच्छता भी चाहिए। स्वच्छता के लिए आज राजस्थान में ...(व्यवधान) बताओ, बताओ आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो उपाध्यक्ष महोदय से मांग कर रहा हूं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। हम मंत्रीजी को पूरा सुनना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए पानी पेशाब की छुट्टी दे दो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप स्वयं जाना चाहो तो जा सकते हो, आपको मना थोड़े ही है। आपको किसने रोका है, माननीय उपाध्यक्ष ने नहीं रोका है।

स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय हमने शुरू किया इसलिए बच्चों के अन्दर यह बात जगे कि पहला, तीसरा और अन्तिम शनिवार को स्वच्छता दिवस मना रहे हैं। आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी, केन्द्र सरकार ने इसका एक परीक्षण करवाया और उसके अन्दर राजस्थान पहले तीन राज्यों में आया और स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त किया। यह है मेहनत। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। इसलिए इसको सोचते हुए कई शौचालयों का निर्माण कराया। आज राजस्थान का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जहां पर बच्चों और बच्चियों का अलग से शौचालय नहीं हो लेकिन मैं भी स्वीकार करता हूं, उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। जहां कहीं पानी की कमी है, वहां भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए वहां पर स्वच्छता के लिए पांच हजार रुपये प्रति स्कूल दस महीनों के लिए एसएसए से हम लोग स्कूलों को भी उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चियों को सेनेटरी नेपकिन के बारे में मैंने पिछली बार बता दिया कि जहां सौ से अधिक बच्चियां हैं, उनके अन्दर कर रहे हैं। और शारदा बालिका छात्रावास में तो हमने सब में मशीनें भी, डिस्पेंसर उपलब्ध करायी हैं।

(23.00 बजे)

पोर्टल के बारे में, अब यह शाला दर्पण और शाला दर्शन पोर्टल तो बता दिये। इसके अलावा हमने राज ई-ज्ञान पोर्टल भी शुरू किया है जिसमें बच्चा कक्षा एक से 12 तक की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध करा सकता है। फिर कई बार समस्याओं का समाधान नहीं होता इसीलिए शिक्षा समाधान पोर्टल, यह हमने बनाया ताकि सीधा मेरे पोर्टल पर आये और उसके समाधान की ओर हम लोग निरन्तर तुरन्त कार्यवाही करते हैं।

छात्रवृत्तियों में भी कई बार गड़बड़ होती थी इसलिए छात्रवृत्ति कोई भी, समाज या अधिकारिता विभाग देता है, कौन देता है, यह छात्रों का भी बैंक अकाउंट में सीधा जाने लगा इसलिए 88 परसेंट छात्र-छात्राओं को हमने आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया है जिसके कारण उसको छात्रवृत्ति का लाभ

(श्री वासुदेव देवनानी)

मिले। निजी विद्यालयों के बारे में हम चर्चा करते थे, उनका भी एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल में आज 34 हजार से अधिक विद्यालयों की जानकारी है, जिस बच्चे को जहां जाना हो, पेरेंट्स उसको क्लिक करके देख ले, इसलिए उसको सारा हमने किया है।

यह डिजीटल इंडिया की जब बात चली, कहीं एक चला कम्प्यूटर शिक्षकों का, हमने हमारे यहां 1 लाख 61 हजार शिक्षकों को डिजीटल शिक्षा दी है और 2 हजार विद्यालयों में 9 और 10 का हम अंग्रेजी और विज्ञान और गणित का भी कर रहे हैं।

फिर एक बहुत बड़ी समस्या जो आप लोग चर्चा भी करते थे और मेरे पास भी समस्या आती थी कि अध्यापकों को समय पर प्राइमरी एजुकेशन में वेतन नहीं मिलता था। हमने नई एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली बनायी आई.एफ.एम.एस. और उसके तहत आज प्रत्येक व्यक्ति को, टीचर को एक तारीख को तनख्वाह मिल जाए, उस वेतन पर व्यय होने वाली राशि पर हमारा पूरा नियंत्रण हो और विभाग वित्त विभाग से बार-बार उसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

शिक्षा के अधिकार की बात चली तो शिक्षा के अधिकार में आपके समय केवल 81,859 बच्चों को ही आर.टी.ई. के 25 प्रतिशत का लाभ होता था और आज कितना हो रहा है, 6 लाख 54 हजार 947 बच्चों को आर.टी.ई. में इसका लाभ मिल रहा है।

फिर प्राइवेट एजुकेशन की समस्या चली। फीस का लगा, हमने फीस अधिनियम विधान सभा में पारित करवाया। फिर इससे आगे कैसे बढ़ें, कहते हैं, साहब, आपने तो बढ़ा दिया, कागजों में है लेकिन आज 24,399 विद्यालय में फीस कमेटी का गठन हो चुका है ताकि अभिभावकों को पूरा लाभ मिलेगा। टोटल 34 हजार में से, मेरे पास लिस्ट है, आप डाउनलोड करके देख लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लागू नहीं है, मंत्रीजी, कल-परसों ही आया था कि प्रिंसिपल कह रही थी पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बैठिये, मैं बता रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा तो कहो कम से कम जो थोड़ा गले के नीचे उतरे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं जो कुछ कह रहा हूं सदन के सामने सत्य कह रहा हूं और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा।

आज 34 हजार स्कूल हैं उसमें से मैंने कहा कि 24 हजार फीस कमेटी बनी है, यह कमेटी निर्णय करेगी, बाकी को भी हमने कहा है। इस बार आर.टी.ई. में उसी स्कूल को सम्मिलित करेंगे जो अपने स्कूल में फीस कमेटी बना देगा। यह सरकार का नियंत्रण है कि उसको लगा कि इस प्रकार का हो जाए।

हमने विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान भी किया है और शिक्षा विभाग के एक शिक्षक सुरेश कुमार ओला ने अपने मित्र के साथ मिलकर के मोबाइल एप बनाया और वो मोबाइल एप में ग्राम पंचायत से लेकर के खेतीबाड़ी के वो पूरे काम आयेगा।

मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिया है और टोटल ये लैपटाप, पता है कैसे लैपटाप बंटते हैं, अभी एक सदस्य ने सदन के सामने मुद्दा उठाया इसलिए उसका जवाब देना आवश्यक है। हमने आठवीं, दसवीं और बारहवीं के पहले छह-छह हजार मैरिट जो बोर्ड की आती है और प्लस हर जिले में जो प्रथम 100 आते हैं, ऐसे 27,900 बच्चों को लैपटाप दे रहे हैं और इन चार सालों में 97,244 लैपटाप हम वितरित कर चुके हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों को दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा अब तक केवल कला के लिए थी और इस बार बाकी के लिए भी, विज्ञान और वाणिज्य के लिए भी हमने लागू कर दिया।

शिक्षक गुरु का स्थान लेता है, उस गुरु को पांच सितम्बर को, इस बार केवल प्रांत स्तर पर नहीं हमने जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर भी शिक्षक सम्मान समारोह, इसके लिए केवल कागजों में कार्यवाही नहीं की, उसके लिए बजट भी अलाट किया, जिला स्तर पर एक लाख और ब्लाक स्तर पर 10 हजार रुपये भी हमने स्वीकृत किये। इस बार हमने 1775 शिक्षकों का काम किया।

कई बार शहीदों की बात चलती है। मैं कहना चाहूंगा,

'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पर मरने वालों के यही बाकी निशां होंगे'।

इस तरह से विभाग को 209 प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसमें से 119 प्रस्तावों को तो हमने शहीदों के नाम कर दिया, 20 प्रस्ताव अभी सैनिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

कल्याण बोर्ड के पास हैं, 70 प्रस्ताव मेरे विभाग के पास हैं जो बहुत शीघ्र हम कोशिश करेंगे कि इस महीने भर में हम उनके भी नामकरण कर दें।

अब आगामी वर्ष की जो कुछ घोषणाएं हैं वो आपके सामने कर दूं। उसको सुनकर के शायद प्रत्येक को उसमें कुछ न कुछ मिलेगा, 24-25 घोषणाएं हैं, एक नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कुल 1832 स्कूलों की घोषणा की और उसमें सब बनें तो इस बार हमने उन विद्यालयों में उसके लिए ध्यान रखते हुए तय किया कि हमारे जो स्कूल हैं, जैसा मैंने कहा एक भी ग्राम पंचायत न बचे जिसमें बारहवीं का स्कूल न हो। तो कुल मिलाकर के हमारी टोटल छह कैटे गिरीज हैं, आप कह रहे हैं भेदभाव करते हो, बिना भेदभाव उन स्कूलों को क्रमोन्नत करने जा रहा हूं। पहला, ग्राम पंचायत, जिनमें कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, उन सबमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, ऐसे 345 स्कूल हैं।

सुनो, मैं और बता रहा हूं। आप सुनो तो सही फिर पूछना आप जितने प्रश्न पूछने हैं। आपके बैठने का धैर्य चाहिए, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उनकी तरफ देखो ही मत।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, देखूंगा सब की ओर।

उसके बाद जिन ग्राम पंचायत में कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है परन्तु निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, ऐसे भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हम उन माध्यमिक विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करने जा रहे हैं, ऐसे लगभग 400 हैं। यह मिला कर के 745 तो इन स्कूलों को हम क्रमोन्नत कर रहे हैं।

तीसरा, वह ग्राम पंचायतें, जिनमें कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, निजी भी नहीं है लेकिन वहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय भी नहीं है, ऐसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उसको पहले चरण में हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने जा रहे हैं, ऐसे 167 स्कूलों को भी हम सैकण्डरी करेंगे।

चौथी, जिनमें कोई स्कूल नहीं है लेकिन राजकीय उच्च प्राथमिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ऐसे 11 और थे, उनको भी इसके साथ करेंगे।

फिर कहा कि यह तो हो गये आपके सब के लेकिन साथ में कई बार बात आती है कि बच्चों की संख्या बढ़ गयी, तो बच्चों की संख्या बढ़ गयी तो क्रमोन्नत के आपके पास भी लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि के पास आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो हमने तय किया ऐसी ग्राम पंचायत जिनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तो है परन्तु ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनकी कक्षा 8 का नामांकन 30 है और उस स्कूल में 150 का नामांकन टोटल है, ऐसे स्कूलों को भी हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे, ऐसे 225 स्कूल हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा किया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसके साथ आपने कहा, भाई, प्राइमरी से अपर प्राइमरी तो होनी चाहिए। उसके मापदण्ड तय किये, जिनके यहां पांचवीं के अन्दर 20 बच्चे हैं और टोटल स्कूल के अन्दर 100 बच्चे हैं ऐसे भी 84 स्कूलों को हम प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने जा रहे हैं। ऐसे ये 1232 स्कूलों को क्रमोन्नत करेंगे।

उसके साथ जो 600 हैं वो हर विधान सभा में तीन-तीन आवश्यकता और गुणावगुण के आधार पर हम उसको क्रमोन्नत करेंगे। (व्यवधान) 200 हैं 200, मैंने इसमें नहीं कहा कि 160, 200 कहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, गुणावगुण के आधार पर करोगे कि अपने बी.जे.पी. वालों को ही बांटोगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने 200 कहा है, 200 में आप भी आते हैं, यदि 200 से बाहर हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। (व्यवधान) उसके लिए इन्तजार तो करो।

इसके अलावा कई बार संकायों की भी डिमाण्ड होती है। संकाय में हमने तय किया जिस कला संकाय वाले विद्यालय में कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन हैं, ऐसे 67 स्कूल हैं, उनमें सबमें विज्ञान संकाय हम प्रारम्भ करेंगे। ऐसे 67 हैं जहां पर 100 से अधिक 10वीं में नामांकन हैं। ऐसा आपने खूब बनाया है तो आपको भी प्रोत्साहन मिले। ऐसे सभी में हम विज्ञान संकाय

(श्री वासुदेव देवनानी)

खोल देंगे और जहां पर 120 पहुंच गये, ऐसे 2 स्कूल हैं, वहां भी विज्ञान संकाय हम खोल देंगे और सूची वो प्राप्त कर लें, उस सूची को अभी यहां पढ़ूंगा तो शायद बहुत समय लग जायेगा, पहले ही आप लोग कह रहे हो इसलिए आप कहें तो जिलेवाइज जरूर बता सकता हूं। इसमें अलवर, इसमें आपके बांसवाड़ा जिनमें सबसे ज्यादा हैं बाड़मेर जिसमें 141 स्कूलों को इन छह कैटेगरीज को मिलाकर क्रमोन्नत किये। आप पूछ रहे हैं तो मैं सवाई माधोपुर के, आपके जिले के बताऊं, जैसलमेर है, उसके अन्दर है, 64 आपके धौलपुर में है। सभी 33 के 33 जिलों के अन्दर यह क्रमोन्नत किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर, सीकर बता दो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब नई भर्ती, नई भर्ती में जैसा मैंने कहा कि 54 हजार थर्ड ग्रेड, 9 हजार सैकिण्ड ग्रेड, 5 हजार फर्स्ट ग्रेड, 1200 प्रधानाध्यापक, 4500 शारीरिक शिक्षक, पी.टी.आई. का जो अभाव कहते थे और 1500 संस्कृत शिक्षा अध्यापक, 1200 प्रयोगशाला सहायक और 700 पुस्तकालय अध्यक्ष, इन सब के लिए हम बहुत शीघ्र सम्बन्धित विभागों को अर्थना कर देंगे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय मंत्री महोदय, कुछ शहरी विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करने का रखा जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने जो 3-3 कहे तो आप कहोगे 3 में आप शहरी विद्यालय दोगे तो उसको भी हम क्रमोन्नत करेंगे। अब इसमें पिछली बार मैंने कहा था, SIRT, कई राज्यों ने उसे SCERT में बदल दिया है, इस बार इसको सैद्धांतिक सहमति वित्त विभाग ने दे दी है तो केन्द्र व राज्य का अनुपात 60:40 में इसको SCERT में भी हम इस वर्ष उसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे गुणवत्ता के अन्दर सुधार आएगा। जैसा मैंने कहा, ये लर्निंग स्टूडियो, 1 करोड़ 44 लाख से हम अप्रैल माह में इसका भी उद्घाटन कर देंगे। हम घोषणाएं करने वाले लोग नहीं हैं, जो आप कहते हैं कि अध्यापकों के 54 हजार तो हो गए, बाकी की अर्थना भेजकर हम कर देंगे। प्रत्येक स्कूल में बच्चा जानता ही नहीं कि मेरा भारत क्या है, इसके लिए हर स्कूल में एक हम गैलेरी बनाएंगे भारत दर्शन गलियारा, जिसके अन्दर वह पूरे भारत को वहां देख सके, कहां है मेरी नदियां, कहां है हमारी संस्कृति, मोहनजोदड़ो कहां है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे। इस भारत दर्शन गलियारे को अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के सहयोग से हम बनाएंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

एक बात चल रही थी कि हम प्रबोधकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रबोधकों के बारे में आपने कई बार, आप तो 1200 रुपए में नियुक्त कर गए थे, यह तो फिर भी हमारी सरकार ने उनको थर्ड ग्रेड देकर के एक सम्मान उन्हें दिया, लेकिन आज हम उनको भी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय, अभी तक लेवल फर्स्ट में ही काम कर रहे हैं, उनको लेवल फर्स्ट प्रबोधक और लेवल सैकिण्ड प्रबोधक, उसको हम बनाने जा रहे हैं। जो शारीरिक शिक्षक हैं, उन्हें भी इस प्रकार का शारीरिक शिक्षक लेवल वन और शारीरिक शिक्षक लेवल टू अर्थात इनको तृतीय श्रेणी के शिक्षक के समकक्ष हम मानेंगे और इसके अन्दर जो ट्रांसफर्स की भी बात आई, इनको भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान मानकर इनके भी ट्रांसफर पर हम विधिसम्मत काम करेंगे।

जहां तक इनके प्रमोशन की बात आई, इनको एसीपी का लाभ हम दे चुके और जहां तक इनके वरिष्ठ प्रबोधकों की बात थी, इनके लिए हमने एक समिति गठित की है, जो अगले महीने-डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, चाहे वरिष्ठ प्रबोधक बनाकर आखिर उनको कहां पदस्थापित करेंगे, काडर सारा तय करना पड़ेगा, लेकिन इनके बारे में हम निश्चित रूप से उनके हित में निर्णय करने जा रहे हैं। इसके साथ में विद्यालयों में 14 फरवरी की बहुत चर्चा चलती है, उस दिन प्रेम का इजहार करने की चर्चा होती है। मैंने तय किया, वह तो मनाएं, जिसको मनाना है, लेकिन उस दिन प्रत्येक स्कूल में मातृ-पितृ पूजन के कार्यक्रम होंगे।

सबसे पहले माता-पिता से प्यार करो, फिर करना है तो किसी और से करो। माता-पिता का सम्मान करो, प्यार करो। इसलिए मातृ-पितृ पूजन दिवस उस दिन हम लोग करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्कूल में तो कम से कम गुरु पूजन कराओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): गुरु पूजन 5 सितम्बर को होता है। माता-पिता गुरु हैं, इसलिए उनको जोड़ रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह दूसरे वाला कितनी तारीख को करवा रहे हो, वह तो बताओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, बता रहा हूं। मैंने बताया कि सबसे पहली गुरु माता होती है, शायद आपको ध्यान नहीं होगा भारतीय

(श्री वासुदेव देवनानी)

संस्कृति का। पहली गुरु माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा वह स्कूल का गुरु आता है। यह मैं कोई शेर नहीं पढ़ रहा हूं। तो माता और पिता पहले गुरु हैं तो उनका पूजन साल में एक दिन स्कूल में हो। मैं बधाई दूंगा हमारे लूणी के विधायक को, मैं उनके कार्यक्रम में गया, उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों का वहां पर सामूहिक रूप से मातृ-पितृ पूजन किया। उसी तरह का एक छत्तीसगढ़ में इसका आदेश निकला हुआ है। मैंने पढ़ा, यह मेरे राजस्थान में क्यों नहीं हो। माता-पिता की पूजा होनी चाहिए। माता-पिता का सम्मान होना चाहिए। जो आज समाज में आ रहा है कि साहब, माता-पिता को कोई पूछता नहीं है तो इसलिए उनका हमने सम्मान समारोह रखा है।

23 सेवा केन्द्रों का जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी सेवा केन्द्र बनें, उसमें भी करेंगे और कम्प्यूटराइजेशन का युग है। पीओ के लिए तो हमने तय किया इसको हम लैपटाप देंगे, लेकिन जहां पर पीओ नहीं है, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं अन्य स्कूलों में, ऐसे 3092 संस्था प्रधानों को हम टैबलेट देने जा रहे हैं। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 150 जो शारदा बालिका छात्रावास हैं, प्रत्येक में डिजिटल क्लासरूम हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर 7 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह इनमें पीवीसी सिस्टम आधारित विद्युत संयंत्र भी हम छात्रावासों में सोलर हम करेंगे, उस पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए का खर्च होगा। जीवन कौशल प्रशिक्षण भी इन छात्रावासों में शुरू करेंगे। फिर लगा कि हमने आंगनबाड़ी को जोड़ा है, प्राइमरी एजुकेशन भी है, प्रत्येक स्कूल में जन सहयोग से एक खिलौना बैंक (Toys bank) की भी हम स्थापना करेंगे जो आंगनबाड़ी बालिकाओं के साथ हमारी पहली, दूसरी के बच्चों के लिए भी उपयोगी हो।

जहां पर विद्यालय में पानी का स्थान है, कई बार देखा जाता है कि पानी व्यर्थ जाता है, उस पानी के स्थान के साथ हम हरित क्षेत्र भी प्रत्येक स्कूल में वाटिका के रूप में विकसित करेंगे ताकि पानी का भी सदुपयोग हो और बच्चों में भी जल स्वावलंबन की भावना जगे, जिसका माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगाज किया है तो बच्चों के अन्दर भी पानी को बचाने का मन बने। उसके रख-रखाव, उसकी importance उन्हें समझ में आए। छात्र स्कूलों में हमने PTM कर ली, MTM कर ली, मुझे लगा कि आप और हम में से भी कई लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर के आए हैं, लेकिन स्कूल से हमारा नाता नहीं है, इसलिए सारे स्कूलों में पूरे छात्र परिषद Alumni का गठन हम प्रत्येक

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्कूल में करेंगे, ताकि जब वे अपने स्कूल से जुड़ेंगे तो अपने स्कूल के विकास में कुछ न कुछ वे सहयोग भी करेंगे।

इसके साथ जो प्रशिक्षण शिविर हम अध्यापकों के कर रहे हैं, उनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्यापक प्रशिक्षण शिविर होगा। कागज का हमने डिजिटाइजेशन किया, आप कहते हैं कि उसका लाभ क्या हुआ, उसमें जो हमने शाला दर्शन-शाला दर्पण...यह क्या है, 187 क्विंटल केवल शाला दर्शन-शाला दर्पण के कारण कागज की बचत हुई है। यह डिजिटाइजेशन का लाभ है, सब जगह कर रहे हैं। आप भी इसका अगर कहीं उपयोग कर सकते हो तो करो।

हमारे विद्यार्थी दसवीं के बाद कहां जाएं, क्या पढ़ें, इसके लिए पहले 1800 विद्यालयों में कक्षा दसवीं के पश्चात उच्च अध्ययन हेतु विषयों के चुनाव के लिए;.. महाराष्ट्र में एक शांति फाउंडेशन है, कैरियर काउंसलिंग उसके साथ प्रारम्भ की जाए, लेकिन आगामी वर्ष में 9894 में इस प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं ताकि हमारे दसवीं के बच्चे इससे लाभ लें। फिर आज का बच्चा इंटेलीजेंट हो गया है, बस आप ज्यादा चिंता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उच्च शिक्षा मंत्रीजी की आंखें छोटी हो रही हैं, थोड़ा ध्यान दो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, नहीं, मेरी बहन हैं, इनको जगा देता हूं। फिर कक्षा नवीं और दसवीं में जब बच्चा पढ़ता है, केवल पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ता है, लेकिन उसे संदर्भ के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए कक्षा नवीं और दसवीं की पाठ्य पुस्तकों में हम QR Code को छपवाएंगे। उस QR Code में जो कोई 389 QR Code लगवाएंगे, उसके आधार पर एक Hot-spot आ जाएगा, उसके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपनी समस्या के समाधान हेतु उससे संबंधित सामग्री, वीडियो चित्र आदि देख सकेंगे। यह है आधुनिकीकरण। शिक्षा को हम केवल पुरातन के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, संस्कार वही, लेकिन हम शिक्षा को युगानुकूल बनाएंगे और देश की चीज को युगानुकूल और युग की चीज को दिशानुकूल बनाएंगे, इसलिए, जैसा मैंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को हम 2 लाख 88 हजार बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, ताली तो बजाओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को शिक्षा में किए जो बजट प्रावधान हैं, उसके लिए एक बार पुन: धन्यवाद अर्पित करता हूं और शिक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और डिजिटल शिक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण वर्ष होगा। इस सत्र के बजट में 5368 करोड़ की वृद्धि जो 30 परसेंट की है, निश्चित रूप से उस पर हम आगे बढ़ेंगे।

मैं आशा करता हूं कि हम सब जन प्रतिनिधि और जन सहभागिता भामाशाहों के सहयोग से हम पूरा करेंगे। हमने राजस्थान की शिक्षा को गुणात्मक बनाने का प्रयत्न किया है, इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था, आप खुद तो सोचो, पूछना बहुत चाहिए, आपके समय में हम जब विदा हुए थे, तब राजस्थान ग्यारहवें नंबर पर था और आपके शासनकाल में 26वें पर आ गया और इस समय राजस्थान तीसरे नंबर पर है। मेरा प्रयत्न रहेगा कि राजस्थान पहले नंबर पर आ जाए। पूरा विश्व यह अनुभव कर रहा है कि हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी में प्रविष्ट हो रहा है, भारत के प्रज्ञा नेतृत्व का सम्पूर्ण विश्व में गुणगान हो रहा है। भारत के जन-जन में राष्ट्र भाव का जागरण हो, हम ऐसे बालक-बालिकाओं का निर्माण करेंगे जो विश्व को पुन: अपना नेतृत्व प्रदान कर सकें।

अंत में मैं आपको धन्यवाद अर्पित करने से पहले कुछ 2-3 कट मोशन रह गए हैं, उनके उत्तर के साथ इन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

बाधाएं आती हैं आएं
घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते-हंसते,
आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

अब केवल मैं एक का जो कट मोशन में जो आपने बातें कहीं, इनकी धारणा जगे उसके अन्दर ...(व्यवधान) उन्होंने पीपीपी मोड की चर्चा की, नहीं मेरे पास इनके एक-एक मुद्दे का जवाब है। आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की

(श्री वासुदेव देवनानी)

मान्यता समय पर नहीं होती। हमने कहा जिन्होंने गत वर्ष मान्यता के लिए पैसे जमा कराए थे, परीक्षण में देर हुई, इस बार उनको दुबारा पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आदरणीय नेता जी, अब कहो न कि हम मान गये। आप कह दो कि मान गये, सारे कट मोशन विथड़ा कर लिए। मान गये? हां, ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो माने हुए ही थे, ये तो आपको मना रहे हैं कि आप माने या नहीं मंत्रीजी को।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको बता रहा हूं। आपमें से किसी एक सदस्य ने कहा कि पीपीपी मोड या बाकी में जब माननीय कटारिया जी की अध्यक्षता में समिति बनती है तो इसका मतलब सरकार टालना चाहती है। पीपीपी मोड में भी हम अगले सत्र से पहले निर्णय करके सदन को अवगत करा देंगे। इसमें हमारे गुणावगुण पर विचार करेंगे, आपके सुझावों पर भी विचार करेंगे। इस दौरान आप में से भी किसी के सुझाव हों तो आप दें।

दूसरा, हमने ट्रांसफर पालिसी की बात कही। मैं एक-एक पर आ रहा हूं। ट्रांसफर पालिसी एण्ड काउंसलिंग सिस्टम लागू कर दिया है और बाकी भी मैंने कहा कि मैं राजनीति शिक्षा में नहीं करूंगा और न करने दूंगा इसलिए उसके आधार पर तय कर लो कि गुणावगुण के आधार पर और विधिसम्मत न्याय के आधार पर करेंगे। आप में से किसी ने कहा कि 500 तालाबन्दी हुई। आप 500 की सूची तो बता दो। तालाबन्दी आपके राज में होती थी। पहले साल यहां भी कुछ हुई लेकिन इस साल तालाबन्दी के अंगुलियों पर गिनने जितने प्रकरण हुए हैं और उनमें भी हमने पता किया तो कहीं एक शिक्षक या दो शिक्षक की कमी थी और वह भी कहीं न कहीं स्वप्रेरित नहीं थी, किसी से प्रेरित थी जिसके आधार पर किया।

बाकी कुछ ने मुझे कहा है कि हमारे स्कूल में नये विषय खोले जाएं तो इस पर निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लगभग सारी बातें और घोषणाएं आपके सामने रखी हैं। अब चूंकि आज हमारे पास कला एवं संस्कृति का भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

विषय है और माननीय मंत्री महोदया ने मुझे अधिकृत किया था कि आप इस पर बोलेंगे। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपका लम्बा भाषण सुना है।

अब इस मांग संख्या-24 में कला एवं संस्कृति विभाग है। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं के साथ यहां वर्षपर्यन्त मेले भी लगते हैं, उत्सव भी होते हैं और यह हमारी संस्कृति का परिचायक है तथा यह हमारी भौगोलिक विषमताओं के बावजूद लोक का आलोक है।

राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर एवं भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर जैसी संस्थाएं आज भी इसमें कर रही हैं और इनके आधार पर समरस जीवन होता है।

पुरातत्व संग्रहालय विभाग, इसके आधार पर 6 जिलों के अन्दर तो यह पूरा काम हो चुका है जिनमें भरतपुर, सीकर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर एवं अजमेर के संग्रहालयों के संरक्षण एवं विकास की पहल की गई है। इस बार 11 और जिले जिसके अन्दर चित्तौड़, कोटा, जोधपुर, झालावाड़, मण्डोर (जोधपुर), आहड़ (उदयपुर), डूंगरपुर, चन्द्रावती (सिरोही), शाहपुरा (भीलवाड़ा), विराटनगर (जयपुर), अलवर का विकास काम भी प्रगति पर है जिनको हम इस वर्ष पूरा कर लेंगे।

विश्व प्रसिद्ध नाहरगढ़ किला, जयपुर परिसर में सिलिकन वैक्स म्यूजियम और विरासत संग्रहालय की भी स्थापना कर उसको हमने जनता के लिए खोल दिया गया है।

इसके साथ Electric Vehicles का संचालन भी जिससे पर्यावरण सही हो तो हमने आमेर महल, हवामहल इत्यादि में शुरू कर दिया है।

लगभग तीन सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हैरिटेज सर्किट और कृष्णा सर्किट में भी हमने विकास के काम शुरू कर दिये हैं।

इसके साथ ही जो स्मारक हैं जिनके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, सफेद महल (भरतपुर), वैर किला (भरतपुर) आदि, मूसी रानी की छतरी (अलवर), गढ़ पैलेस (झालावाड़) इन स्मारकों का भी संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

एक हमारा राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण है और ये

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी पैनोरमा बना रहे हैं। इसमें भी लगभग काम प्रारम्भ हो गया है जैसे पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय, धानक्या, जयपुर, संत सुन्दर दास पैनोरमा, दौसा, संत रैदास का पैनोरमा, चित्तौड़गढ़, लोक देवता पाबूजी का पेनोरमा, कोलू (जोधपुर), नागरीदास जी का पैनोरमा, किशनगढ़ (अजमेर), कालीबाई का पैनोरमा, माण्डवा (डूंगरपुर), पन्नाधाय का पैनोरमा, कमेरी (राजसमन्द), हसन खां मेवाती का पैनोरमा, अलवर, बप्पारावल का पैनोरमा, मठाठा (उदयपुर), महाराणा राजसिंह पैनोरमा, राजसमन्द एवं मानगढ़धाम में जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आदि का निर्माण है। इन सबके डिजिटाइजेशन का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

जवाहर कला केन्द्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां भी आयोजित करने की पहल की गई है। इस समय 'वेन इज स्पेस' में 30 आर्टिस्ट्स भाग लेंगे जो आगामी 31 अगस्त, 2018 को इस प्रकार का स्थापित करने जा रहे हैं।

अब कोई 2-3 घोषणाएं हैं वो भी मैं आपके माध्यम से कर देता हूं। इन घोषणाओं में जयपुर स्थित आमेर महल में Iconic Tourism Destination के रूप में 20 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

आगामी वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा मंदिर समूह अवां (कोटा) में 5 करोड़, सूर्य मंदिर बूढ़ादीत (कोटा) में 60 लाख, प्राचीन दुर्ग माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) में 100 लाख, कोटवाली गेट (अजमेर) में 20 लाख, भवानी नाट्यशाला (झालावाड़) में 5 करोड़, छनेरी-पनेरी देवालय (झालावाड़) में 5 करोड़, मंदिर समूह किराडू (बाड़मेर) में 2 करोड़, प्राचीन मंदिर समूह ओसियां (जोधपुर) में 50 लाख, देवताओं की साल-वीरों की दलान एवं रावण की चवरी मण्डोर (जोधपुर) में 270 लाख, हर्ष देवल शिव मंदिर बिलाड़ा (जोधपुर) में 50 लाख, प्राचीन शिवालय भुंडाना, तहसील भोपालगढ़ (जोधपुर) में 50 लाख, सालिम सिंह की हवेली (जैसलमेर) में 10 लाख, सेठानी का जोहड़ा (चूरू) में 1 करोड़, मीनारयुक्त कूप बूटिया (चूरू) में 45 लाख, छतरियां देवी कुण्ड सागर (बीकानेर) में 50 लाख, रामगढ़ किला (बारां) 5 करोड़, विष्णु मंदिर काठडावन (उदयपुर) में 70 लाख, मीरा महल आहड़ (उदयपुर) में 50 लाख एवं जल महल कुम्हेर (भरतपुर) में 2 करोड़, इस प्रकार कुल 33 करोड़ 25 लाख के विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसके अलावा पैनोरमा पर भी 10 करोड़ के 6 पैनोरमा के कार्य होंगे जिनमें अलवर में राजा भर्तृहरि, भीलवाड़ा के मालासेनी में भगवान देवनारायण, राजसमन्द में महाराणा कुंभा माल्यावास मदारिया, सीकर में भक्त शिरोमणी करमेती बाई खण्डेला, अजमेर में श्री सैन महाराज, पुष्कर एवं चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया में 10 करोड़ की लागत से पैनोरमा के कार्य शीघ्र प्रारम्भ होंगे।

राजस्थान राज्य अभिलेखाकार, बीकानेर में रुपये 10.80 करोड़ की लागत से 'अभिलेख म्यूजियम' का निर्माण करके आमजन के लिए इसको खोलेंगे।

जवाहर कला केन्द्र का जैसा मैंने कहा कि दिनांक 31 अगस्त, 2018 को अन्तरराष्ट्रीय सिरेमिक्स ट्रिनाले का आयोजन हम कर रहे हैं।

इस प्रकार कला एवं संस्कृति में भी हमारी सरकार प्राचीन संस्कृति को संजोये रखना जिसके आधार पर नई पीढ़ी जान सके कि हमारी संस्कृति क्या है जिसकी तरफ आपका ध्यान कभी गया ही नहीं और हमारी सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पैनोरमा और बाकी सब पर ध्यान देकर इतनी सारी संस्कृति को संवारने का जो काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी जो दोनों मांगें थीं उन पर मैंने अपना दिया है और मैं इसको यहीं पूरा करता हूं। अब मैं आपकी अनुमति से इस मांग को पूरा करवाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: किसी को कुछ पूछना है?

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 286,59,19,42,000/- (दो सौ छियासी अरब उनसठ करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,58,83,000/- (उनहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2-मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - मंत्री परिषद के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,99,23,000/- (तेरह करोड़ निन्यानवे लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,82,97,58,000/- (दो अरब बयासी करोड़ सतानवे लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,92,36,25,000/- (चार अरब बानवे करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,32,46,000/- (दो अरब तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,32,63,42,000/- (नौ अरब बत्तीस करोड़ तिरेसठ लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,94,25,58,000/- (दो अरब चौरानवे करोड़ पच्चीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,33,86,89,000/- (आठ अरब तैंतीस करोड़ छियासी लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,21,25,80,000/- (नौ अरब इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,03,30,47,000/- (पांच अरब तीन करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,32,97,000/- (सतहत्तर करोड़ बत्तीस लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,51,63,39,000/- (छह अरब इक्यावन करोड़ तिरेसठ लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,79,19,92,000/- (एक अरब उन्यासी करोड़ उन्नीस लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,68,94,94,000/- (तेरह अरब अड़सठ करोड़ चौरानवे लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,96,99,52,95,000/- (एक सौ छियानवे अरब निन्यानवे करोड़ बावन लाख पिच्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,23,43,000/- (इक्यासी करोड़ तेईस लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 - आवास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,24,14,000/- (नब्बे करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,09,83,70,000/- (चार अरब नौ करोड़ तिरासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,70,46,92,000/- (छह अरब सत्तर करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,30,92,67,000/- (तीन अरब तीस करोड़ बानवे लाख सडसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,20,30,61,000/- (तेरह अरब बीस करोड़ तीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,08,62,98,000/- (इकसठ अरब आठ करोड़ बासठ लाख अट्ठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,61,05,81,39,000/- (एक सौ इकसठ अरब पांच करोड़ इक्यासी लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 2,76,60,81,000/- (दो अरब छिहत्तर करोड़ साठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,82,53,15,000/- (सत्तावन अरब बयासी करोड़ तिरेपन लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,64,71,54,000/- (पच्चीस अरब चौंसठ करोड़ इकहत्तर लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,76,01,01,000/- (छह अरब छिहत्तर करोड़ एक लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,56,94,000/- (एक अरब बाईस करोड़ छप्पन लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 - राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,74,000/- (एक करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,55,88,44,000/- (पचहत्तर अरब पचपन करोड़ अठासी लाख चवालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,69,70,000/- (उनतालीस करोड़ उनहत्तर लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)
राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,72,41,000/- (एक अरब सैंतीस करोड़ बहत्तर लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 - विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,82,19,97,72,000/- (एक सौ बयासी अरब उन्नीस करोड़ सतानवे लाख बहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,87,000/- (बीस लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,02,23,54,000/- (उन्नीस अरब दो करोड़ तेईस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु

(श्री उपाध्यक्ष)

विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,92,89,63,42,000/- (एक सौ बानवे अरब नवासी करोड़ तिरेसठ लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंह।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधयेक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23:41 बजे, मंगलवार, दिनांक 06 मार्च 2018 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोतर

प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम पर व्यय राशि

317. श्री रमेश (सपोटरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने एम.ओ.यू. किस-किस कम्पनी के साथ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2018 तक एम.ओ.यू. करने वाली कितनी एवं कौन-कौनसी कम्पनियों/संस्थाओं ने राज्य में कितना निवेश किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई कम्पनियों/संस्थाओं का निवेश प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से लम्बित है? यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों/संस्थाओं का एवं किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिसर्जेन्ट राजस्थान कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि का विवरण अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट-2015 के तहत विभिन्न सैक्टर्स में लगभग रुपये 3.38 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 470 एमओयू हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। विवरण अनुसंलग्नक-2 पर संलग्न है।

(3) जनवरी, 2018 तक उपरोक्त एमओयूज में से रुपये 11845.76 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 62 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा रुपये 190691.99 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 119 एमओयू निवेश की प्रक्रिया में हैं। विवरण अनुसंलग्नक-3 पर संलग्न है।

(4) 19 एम.ओ.यूज. के निवेश प्रस्ताव विभिन्न कारणों से सरकारी विभागों में लम्बित हैं, जिनका विवरण अनुसंलग्नक-4 पर संलग्न है।

(5) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक राज्य के औद्योगिक क्षेत्र

(उद्योग मंत्री)

में आर.आर. के एम.ओ.यूज के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में जो निवेश हुआ या प्रकिया में है, वह निम्नानुसार है : पैट

- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रुपये 635.73 करोड़ से अधिक का निवेश।
- भामाशाह योजना के तहत 250.84 करोड़ से अधिक का निवेश।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2010 (RIPS-2010) तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 (RIPS-2014) के तहत औद्योगिक इकाइयों में 30416.12 करोड़ का निवेश।
- राष्टीय यू ए एम पोर्टल के अनुसार एम एस एम ई इकाइयों में लगभग 21,474 करोड़ का निवेश पंजीकरण।
- रीको के औद्योगिक क्षेत्रों (इण्डस्टीयल एरिया) में कुल 14048.59 करोड़ रुपये निवेश विभिन्न चरणों में हुआ एवं महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. की परियोजना में करीब 1835 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- राजस्थान रिफाइनरी एण्ड पैटोकैमिकल काम्पलेक्स के माध्यम से 43,129 करोड़ रुपये का निवेश प्रकियाधीन है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में सोलर कम्पनियों को भूमि आबंटन के नियम

320. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सोलर कम्पनियों को भूमि का आबंटन किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी भूमियां जिन पर पहले से ही काश्तकार द्वारा पक्के मकान, पशु बाड़े व टांका इत्यादि बनाकर कब्जा काश्त हैं, उन खसरों में से सोलर कम्पनियों को भूमि आबंटन किये जाने की दशा में विस्थापित होने वाले काश्तकारों को कितना मुआवजा किस दर से दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गत चार वर्षों में इस प्रकार के प्रकरणों में कितना मुआवजा दिया गया है? काश्तकार के नाम सहित ग्रामवार एवं दी गयी राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि का आबंटन) नियम 2007 के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर की भूमि आबंटन की अनुशंसा पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति के उपरान्त विभिन्न कम्पनियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि का आबंटन) नियम 2007 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सोलर प्रयोजनार्थ हेतु आबंटन, राजकीय भूमि का आबंटन किया जाता है।

राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड की सूचना अनुसार कम्पनियों द्वारा काश्तकारों को आपसी सहमति से एक लाख रुपये प्रति परिवार अनुसार मुआवजा दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गत चार वर्षों में इस प्रकार के

(राज्य मंत्री, राजस्व)

प्रकरणों में संबंधित कम्पनियों द्वारा दिये गये मुआवजों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

321. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6 ZWM के गांव 4 ZWM व 9 ZWM को विद्युतीकृत कर दिया गया है?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6 ZWM में चक 4 ZWM व 9 ZWM में विद्युत पोल तो लगाये गये हैं परन्तु तार नहीं डाले गये हैं? यदि हां, तो उक्त चकों को किस योजना के तहत विद्युतीकृत किया गया है? योजना का नाम राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों के गरीब परिवारों को पुन: विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6 ZWM के गांव 4 ZWM को विद्युतीकृत कर दिया गया है एवं 9 ZWM का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6 ZWM के गांव 4 ZWM में विभाग की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य कर लिया गया है। इस गांव में वर्ष 2017-18 में घरेलू श्रेणी के तीन आवेदन प्राप्त हुए थे जिनके मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवायी गयी है। इसलिए विद्युत लाइन से चोरी को रोकने के लिए विद्युत पोलों से विद्युत लाइन हटा दी गयी हैं। आवेदन प्राप्त होने एवं मांग पत्र की राशि जमा होने पर विद्युत लाइन पुन: स्थापित कर विद्युत कनेक्शन जारी किये जाएंगे। चक 9 ZWM में कोई भी विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है तथा न ही वहां पर कोई विद्युत लाइन स्थापित है। गांव 9 ZWM में विभाग की दीनदयाल

(ऊर्जा मंत्री)

उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य प्रस्तावित है जो कि प्रगति पर है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6 ZWM के गांव 4 ZWM, 9 ZWM में योजना में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त गांवों का विद्युतीकरण कर आवेदन प्राप्त होने एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी उपखण्ड में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

322. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन से कृषि महाविद्यालय कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कृषि महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गंगापुर सिटी उपखण्ड में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 10 संघटक, 3 सरकारी (कृषि संकाय) व 21 निजी कृषि महाविद्यालय संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 8 कृषि से संबंधित अन्य विषयों (डेयरी, अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान, उद्यानिकी व वानिकी, प्रबन्धन व मत्स्य) पर संघटक महाविद्यालय संचालित हैं। विस्तृत विवरण संलग्न-1 पर है।

(2) प्रदेश में कृषि महाविद्यालय खोलने के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड संलग्न-2 पर है।

(3) जी नहीं। गंगापुर सिटी के नजदीक जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर कृषि संकाय युक्त शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह महाविद्यालय सवाई

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

माधोपुर पूर्व से ही संचालित है। अत: वर्तमान में गंगापुर सिटी में कृषि महाविद्यालय खोलना विचारणीय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण की राशि में कटौती

323. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान पुलिस को आधुनीकरण के लिए दी जाने वाली राशि में गत वर्षों की तुलना में भारी कटौती की है? यदि हां, तो क्यों व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्र सरकार ने आधुनीकरण के लिए राजस्थान पुलिस को दी जाने वाली राशि में गत वर्षों की तुलना में कटौती नहीं की है। इस संबंध में पुलिस आधुनीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित प्रस्ताव (केन्द्रीय अंशदान) एवं प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है-

(राशि लाखों में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लान		योग
	पार्ट-ए	पूरक प्लान	
	केन्द्रीय अंशदान	केन्द्रीय अंशदान	
2015-16	2899.00	581.00	3480.00
2016-17	2899.00	580.00	3479.00
2017-18	3816.00	763.42	4579.42

बिलाड़ा की ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण

324. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2013-14 से दिसम्बर, 2017 तक विभिन्न योजनान्तर्गत एवं स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों

(श्री अर्जुन लाल)

के निर्माण हेतु क्या कोई विशेष प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या-क्या, किस-किस योजनान्तर्गत कितने-कितने कब शौचालयों का निर्माण करवाया गया? पंचायत समितिवार, वर्षवार व ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कोई निश्चित राशि दी जा रही है? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन लोगों को दी गयी एवं कितनी राशि बकाया है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त घोषित की गयी हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जोधपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा पंचायत समिति बिलाड़ा, मण्डोर, लूणी, पीपाड शहर की ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। शौचालय निर्माण की वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से क्रमश: 7200 एवं 4800 कुल 12000 रु. प्रति शौचालय निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की कुल 51 ग्राम पंचायतों में से 51 ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुकी हैं। जिसकी सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन उद्योग नीति

325. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में कुम्हार समाज के परम्परागत व्यवसाय (मिट्टी के बर्तन एवं ईंट भट्टा) को संरक्षण प्रदान करने के लिए नई ईंट उद्योग नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा कुम्हारों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों (रिप्रेजेन्टशन्स) एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् आवा-कजावा परम्परागत तकनीक पर आधारित राज्य में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंट, कवेलू, आदि बनाने वाले कुम्हारों के लिये एक मार्ग-दर्शिका (गाइड लाइन) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल के आदेश दिनांक 12.07.2016 के द्वारा जारी की गयी, जिसकी प्रति संलग्न है।

ज्ञातव्य है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल द्वारा विभिन्न उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिये समय-समय पर मार्ग-दर्शिका (गाइड लाइन) जारी की जाती है। उपरोक्त मार्ग-दर्शिका उद्योगों के मार्ग-दर्शन के लिये जारी की जाती है, अतः इनका प्रकाशन राजपत्र में नहीं किया जाता है। इसी कारण से आवा-कजावा आधारित परम्परागत मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंट, कवेलू, आदि के निर्माण हेतु जारी मार्ग-दर्शिका का भी राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वन सुरक्षा समितियों का गठन

326. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में वन सुरक्षा समिति एवं वन प्रबन्धन सुरक्षा समितियों की मासिक बैठक करने का प्रावधान है? यदि हां, तो कोटा जिले में गत तीन वर्षों में उक्त समितियों की कितनी बैठकें की गयीं? वन मण्डलवार मासिक बैठक के प्रस्ताव की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन सुरक्षा समिति एवं वन प्रबन्धन सुरक्षा समिति का गठन एवं चुनाव किस प्रकार किया जाता है? क्या उक्त समितियों के गठन में ग्राम पंचायत को शामिल किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? समिति के गठन एवं चुनाव प्रक्रिया के नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन सुरक्षा समिति एवं वन प्रबन्धन सुरक्षा समिति के चुनाव एवं गठन की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक एवं

(श्री हीरालाल नागर)

सांसद को दी जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में ग्राम्य स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (वी.एफ.पी.एम.सी.) की मासिक बैठक करने का प्रावधान नहीं है, अपितु इस क्रम में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2000 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए) अनुसार वी.एफ.पी.एम.सी. एवं आदेश दिनांक 24.10.2002 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-बी) अनुसार वन्य जीव रक्षित क्षेत्रों (अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों) में ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) की प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें तथा कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित किये जाने के साथ ही एक तिहाई सदस्यों की मांग पर अतिरिक्त साधारण बैठक एवं आवश्यक होने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा वी.एफ.पी.एम.सी./ई.डी.सी. की कार्यकारिणी की अधिक बैठकें भी बुला सकने का प्रावधान है।

कोटा जिले में उप वन संरक्षक कोटा, उप वन संरक्षक (मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान) कोटा तथा उप वन संरक्षक (एन.सी.एस.) सवाईमाधोपुर अधीनस्थ क्षेत्र में गठित वी.एफ.पी.एम.सी. तथा ई.डी.सी. की विगत तीन वर्षों में आयोजित बैठक संबंधित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-सी 1, सी 2 एवं सी 3 अनुसार है।

(2) प्रदेश में वी.एफ.पी.एम.सी. तथा ई.डी.सी. का गठन एवं चुनाव क्रमश: राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2000 (परिशिष्ट-ए) एवं आदेश 24.10.2002 (परिशिष्ट-बी) अनुसार किया जाता है।

उक्त आदेशों में वर्णित समिति के गठन एवं कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया में संबंधित राजस्व ग्राम के समस्त व्यस्क सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया हुआ है। जिसमें संबंधित राजस्व ग्राम का सरपंच/पंच भी सम्मिलित है, परन्तु अलग से ग्राम पंचायत के सदस्यों को बुलाने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त संबंधित राजस्व ग्राम की पंचायत के सरपंच/पंच जो उस ग्राम का निवासी हो, कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें राज्य सरकार के शुद्धि पत्र दिनांक 23.05.2002 (संलग्न परिशिष्ट-डी) अनुसार कार्यकारिणी की चुनाव की स्थिति में वोट डालने का अधिकार भी है।

(वन मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रदेश में वी.एफ.पी.एम.सी. तथा ई.डी.सी. का गठन एवं चुनाव राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2000 एवं आदेश दिनांक 24.10.2002 अनुसार किया जाता है। उक्त आदेशों में वर्णित "समिति की सदस्यता एवं गठन" अन्तर्गत जिस राजस्व ग्राम की समिति बनायी जाती है उस ग्राम के प्रत्येक परिवार के सभी व्यस्क व्यक्ति समिति के सदस्य बनने के पात्र होते हैं एवं 'कार्यकारिणी का गठन' अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच, जो उस ग्राम का निवासी हो, को कार्यकारिणी का पदेन सदस्य बनाया गया है, परन्तु जन प्रतिनिधियों को पृथक से सूचना दिये जाने का राज्यादेशों में उल्लेख नहीं होने के कारण सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सिनेमाघरों में खाद्य पदार्थों की बिक्री

327. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सिनमाघरों में ग्राहकों से खाद्य पदार्थों की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जा रही है एवं ग्राहकों को खाने-पीने की वस्तुएं अन्दर ले जाने से रोका जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सिनेमाघरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के सिनेमाघरों में गत तीन वर्षो में ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की जिला स्तर पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिला उपभोक्ता अधिकारी द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? जयपुर जिले की शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिनेमाघरों में ग्राहकों को शुद्ध एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु मानदण्ड तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यदि डिब्बा बन्द वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर व्यापारी के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

ग्राहकों को खाने पीने की वस्तुएं सिनेमाघर के अन्दर ले जाने से रोकने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जिला उपभोक्ता मंचों द्वारा सिनेमाघरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के सिनेमाघरों में ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की एक शिकायत जोधपुर जिले में प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करने पर शिकायत आधारहीन पायी गयी, विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जयपुर जिले में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सिनेमाघरों में ग्राहकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सामग्री के नियमित नमूने लिए जाते हैं तथा डिब्बा बन्द वस्तुओं की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं की जाए, यह दायित्व विधिक माप विज्ञान विभाग का है। विधिक माप विज्ञान विभाग को डिब्बा बन्द वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय की जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में भूमि की चकबंदी

328. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के चक खोड़ा बारानी, खेड़ासरी बारानी एवं हरडासवाली बारानी का नक्शा उपलब्ध है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक कितने प्रकरण सीमा ज्ञान के प्राप्त हुये व उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा शेष प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी भूमि की चकबंदी होना शेष है व उक्त चकबंदी कब तक पूरी कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक सीमा-ज्ञान के कुल 261 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 247 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है एवं शेष 14 प्रकरण मौके पर फसल खड़ी होने के कारण लम्बित हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में स्थित तहसील रावतसर में 5796 हैक्टेयर क्षेत्र व तहसील पीलीबंगा में 10081 हैक्टेयर क्षेत्र में चकबंदी होना शेष है। वर्तमान में तहसील पीलीबंगा एवं रावतसर में चकबंदी का कोई कार्य नहीं चल रहा है। आगे कार्यक्रम बनाकर कार्य करवाया जाएगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत देय मुआवजा

372. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत गत 3 वर्षों में कितने प्रकरणों में मुआवजा/प्रतिकर जारी किया गया है? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने प्रकरणों में बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा/प्रतिकर जारी किया गया है? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विगत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त राशि एवं मुआवजा/प्रतिकर जारी किये जाने की वर्षवार एवं जिलेवार सूचना प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत वर्षवार एवं जिलेवार प्रतिकर एवं मुआवजा जारी करने की सूचना हेतु प्रदर्श-3 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में भर्तियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

373. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विज्ञापित भर्तियों से संबंधित कितने प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भर्ती प्रकरणों के न्यायालय में विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक

(कार्मिक मंत्री)

सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित भर्तियों से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) भर्ती से संबंधी प्रकरणों के न्यायालय में विचाराधीन होने के भिन्न-भिन्न कारण हैं। मुख्य रूप से भर्ती विशेष के नियमों, शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम प्राप्तांक, आयु सीमा में छूट से संबंधित, वर्ग परिवर्तन, प्रश्न पत्रों में विसंगति/त्रुटियों सें संबंधित, उत्तर कुंजी से संबंधित, पदो का वर्गीकरण से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, वांछित अनुभव से संबंधित, विश्वविद्यालय एवं बोर्ड आदि की मान्यता से संबंधित, परीक्षा परिणाम से संबंधित, भर्ती नियमों से संबंधित, अभिस्तावना सें संबंधित, उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित इत्यादि उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु समयबद्ध रूप से जवाब पेश कर ठोस पैरवी की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिये अनुमोदित चिकित्सालय

374. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को उनकी चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पतालों के अलावा सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त किये जाने के लिए अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो अनुमोदित निजी अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार व प्राईवेट अस्पतालों के मध्य रियायती दर के संबंध में जो करार किया गया है उस करार के अनुसार राज्य कर्मचारी/पेंशनधारक को निजी अस्पताल में चिकित्सक को दिखाए जाने के लिए कन्सलटेंट फीस निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो कितनी?

(3) राज्य कर्मचारियों से फोर्टिस अस्पताल में सेवारत चिकित्सकों द्वारा कन्सलटेंट फीस कितनी वसूल की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के निजी चिकित्सालयों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(5) सहपठित अपेंडिक्स-I के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची "परिशिष्ट-1" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्र. एफ. 6(2)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट-III दिनांक 27.06.2015 के द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा राज्य कर्मियों को उपचार उपलब्ध करवाने की दरें निर्धारित की गयी हैं। आदेश दिनांक 27.06.2015 "परिशिष्ट-2" पर संलग्न है। संदर्भित आदेश में सीजीएचएस, जयपुर की दरों को आधार बनाया गया है। सीजीएचएस, जयपुर की दरों के संबंध में जारी आदेश के संबंधित भाग की प्रति "परिशिष्ट-3" पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(4) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 4 के अन्तर्गत गठित हैल्थ बैनिफिट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में ग्रीवेंस रिड्रैसल मैकेनिज्म की स्थापना की गयी है, जो अनुमोदित चिकित्सालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिव में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

375. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शिव के तहसील मुख्यालय गडरारोड़ व उपखण्ड मुख्यालय रामसर में सहायक अभियंता कार्यालय कब तक खोले दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय खोलने का कोई निर्धारित प्रावधान नहीं है। यद्यपि विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 29.03.2011 के ऊर्जा विभाग के पत्रानुसार नया सहायक अभियन्ता कार्यालय सृजन हेतु 17500 विद्युत उपभोक्ता मानते हुए किया गया था। वर्तमान में विद्युत वितरण निगम में नया सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय खोलने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में 22,000 विद्युत उपभोक्ता एवं शहरी क्षेत्र में 28,000 विद्युत उपभोक्ता मानते हुये किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विद्युत निगमों के कार्यालयों के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव पर निर्णय के उपरान्त नवीन विद्युत कार्यालयों के सृजन हेतु निर्धारित नियमों/मानदण्डों के आधार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सन्दर्भ में उचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(3) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), जोधपुर विद्युत वितरण निगम, बाड़मेर में कुल 35509 उपभोक्ता हैं जिसमें से गडरारोड़ सहायक अभियन्ता कार्यालय हेतु 17591 उपभोक्ता प्रस्तावित हैं। गड़रारोड़ सहायक अभियन्ता कार्यालय खुलने पर सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), जोधपुर विद्युत वितरण निगम, बाड़मेर में कुल 17918 उपभोक्ता रहेंगे। गडरारोड़ में नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु चयन उसमें सम्मिलित होने वाले उपभोक्ताओं की उपलब्धतानुसार दूरी एवं विद्युत भार की साध्यतानुसार किया गया है। गडरारोड़ में सहायक अभियन्ता कार्यालय प्रस्तावित होने के कारण रामसर में सहायक अभियन्ता कार्यालय का प्रस्ताव निगम मानदण्ड अनुसार साध्य नहीं है।

प्रदेश में नेत्र सहायकों के वेतनमान संशोधन की कार्ययोजना

376. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 09 नवम्बर, 1998 को वित्त विभाग की पत्रावली संख्या एफ.14(29)वित्त/नियम/98 पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक) के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में आचार संहिता लग जाने के कारण वेतन संशोधन के उक्त आदेश जारी नहीं किये जा सके थे?

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) क्या सरकार ऑप्थेल्मिक एसिस्टेंट की वेतन विसंगति को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की मंत्री मण्डलीय उप समिति के साथ दिनांक 09 अप्रैल, 2016 की वार्ता, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02 मई, 2016 की वार्ता में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक) का वेतनमान ग्रेड पे 3600 करने एवं पदोन्नति क्रमश: ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट एवं ऑप्थेल्मिक आफिसर के पद पर करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया था? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति व उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों को वेतन विसंगतियों के प्रस्ताव सामंत कमेटी को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं? यदि हां, तो क्या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के वेतन संशोधन एवं पदोन्नति के प्रस्ताव को सामंत कमेटी को भिजवा दिया दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार चुनाव के पश्चात आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट अ)।

चुनाव पश्चात प्रकरण वेतन विसंगति निवारण समिति को जांच एवं सिफारिश हेतु प्रेषित किया गया (परिशिष्ट-ब)।

श्री वाई सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश शीघ्र ही अपेक्षित होने के कारण कोई निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं मानने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट-स)।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 लागू किये जाने के पश्चात श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति द्वारा नेत्र सहायक पद की बताई गयी वेतन विसंगति का परीक्षण कर वेतनमान (ग्रेड पे) बढ़ाये जाने को युक्तिसंगत नहीं माना गया (प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है)।

(वित्त मंत्री)

(2) जी हां (परिशिष्ट-अ)।

(3) ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में प्रकरण सातवें वेतन आयोग में रही वेतन विसंगति निवारण हेतु श्री डी.सी. सामन्त, से.नि. आईएएस की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित कर दिया गया है।

(4) जी हां (प्रति परिशिष्ट-ध पर संलग्न है)।

प्रशासनिक विभाग से नेत्र सहायक पद की वेतन विसंगति के संबंध में प्राप्त प्रकरण के संबंध में विभाग को यह सूचित किया गया था कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसकी सिफारिशें निकट भविष्य में लागू होना अपेक्षित है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में लागू करने के लिये एक कमेटी का गठन किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग नेत्र सहायकों की वेतन संबंधी मांगें उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें। नेत्र सहायकों की पदोन्नति प्रशासनिक विभाग एवं कार्मिक विभाग से संबंधित होना प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया गया (प्रति परिशिष्ट-न पर संलग्न है)।

(5) जी नहीं। श्री डी.सी. सामन्त, से.नि. आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा वेतन विसंगति के प्रतिवेदन समिति को भिजवाने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 23.11.2017/ 24.11.2017 एवं दिनांक 23.12.2917/25.12.2017 को प्रकाशित करायी गयी थी। नेत्र सहायक पद की वेतन विसंगति के संबंध में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव एवं नेत्र सहायक संघ से प्राप्त ज्ञापन वेतन विसंगति निवारण समिति को भिजवा दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में दुर्घटना सहायता के लम्बित प्रकरण

377. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कलेक्टर, पाली को गत चार वर्षों में दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री सहायता हेतु प्राप्त

(श्री केसाराम चौधरी)

हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी? सहायता प्राप्त करने वाले का नाम, गांव एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राप्त आवेदनों में काफी लोगों को सहायता राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो किन-किनको तथा उन्हें सहायता राशि अब कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्ष (01 जनवरी, 2014 से आज दिनांक 26.02.2018) में दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर कुल 957 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री सहायता हेतु प्राप्त हुए। जिनमें आज दिनांक तक 950 मृतक के आश्रितों को सहायता राशि 47440000 रुपये स्वीकृत की जा चुकी है। नाम, गांव एवं राशि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष के 7 प्रकरण अन्य जिलो में दुर्घटना से मृत्यु होने से अदेय प्रमाण पत्र के अभाव में शेष हैं, जिनमें संबंधित जिले से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही सहायता स्वीकृत कर दी जाएगी। उक्त शेष 7 प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से घटित अपराध

378. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध घटित होने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला स्तर पर आई.टी. स्पेशलिस्ट टीम गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल जलधारी)

(3) गत 4 वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से घटित अपराधों पर प्राप्त शिकायतों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध घटित होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्बन्धित थानों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बजट भाषण 2017-18 के पैरा संख्या 283 की घोषणा के अनुसार वर्तमान में 06 संभागीय मुख्यालयों यथा जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं बीकानेर में Cyber Forensic Cell कार्यरत हैं तथा एक संभागीय मुख्यालय जोधपुर में Cyber Forensic Cell स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) विगत 4 वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से घटित अपराधों से संबंधित प्राप्त 1574 शिकायतों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा के काश्तकारों को प्राकृतिक आपदाओं का मुआवजा

379. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं पर काश्तकारों को कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत पांच वर्षों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में कितना मुआवजा दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ काश्तकारों को अब तक मुआवजा वितरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, मुआवजा नहीं दिया जाता है। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत पांच वर्षों में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में दी गयी सहायता का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में रबी फसल 2015 (संवत 2071) में ओलावृष्टि से प्रभावित खसरा गिरदावरी में दर्ज प्रभावित कृषकों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान वितरण किया जा चुका है। इसके पश्चात प्राप्त एक अन्य पूरक सूची अनुसार 2854 कृषकों को सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में रबी फसल 2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की गिरदावरी रिपोर्ट (7डी) में उल्लेखित प्रभावित कृषकों के अतिरिक्त अन्य सूची में उल्लेखित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान अनुमत नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सोने-चांदी में मिलावट के दर्ज प्रकरण

380. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में सोने-चांदी में मिलावट के कितने परिवाद दर्ज किये गये? जिलेवार एवं पुलिस थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में सोने-चांदी की धातुओं में मिलावट पर रोकथाम हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में किन-किन दुकानों पर कब-कब कीमती धातुओं में मिलावट की जांच की गई एवं जांच में क्या तथ्य उजागर हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में सोने-चांदी में मिलावट की पुलिस द्वारा कोई परिवाद दर्ज नहीं किया है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त बिन्दु भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरों से संबंधित है।

(3) उक्त बिन्दु भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरों से संबंधित है।

पृथ्वीपुरा ग्राम (बस्सी) में सड़क का डामरीकरण

381. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील, जिला-जयपुर के ग्राम पृथ्वीपुरा से स्टेडियम तक ग्रेवल रोड बनी हुई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में इनके रख-रखाव पर कब-कब कुल कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षो में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की महात्मा गांधी नरेगा सहित किसी भी योजना में इस कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत डामर सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है। उक्त सड़क पर डामरीकरण कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नीतिगत निर्णय प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बांदीकुई में शौचालयों के निर्माण में अनियमितता

382. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत चार वर्षो में किन-किन ग्राम पंचायतों में कहां-कहां शौचालय का निर्माण कराया गया? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शौचालय निर्माण में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई व

(श्रीमती अलका सिंह)

कितनी-कितनी राशि का आबंटन कब-कब किया गया? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पंचायतों में शौचालय निर्माण में नियमों की अवहेलना या अनियमितता व राशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या-क्या? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राप्त अनियमितताओं की कोई जांच की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत चार वर्षो में समस्त (46) ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण करवाया गया है जिसकी ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उक्त शौचालय निर्माण में 2969.732 लाख रुपये स्वीकृत हुई है व 2224.612 लाख रुपये का आबंटन ईएफएमएस के माध्यम से किया गया है।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायत समिति बांदीकुई में शौचालय निर्माण में नियमों की अवहेलना या अनियमितता व राशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) अनियमितता व राशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में शौचालय निर्माण का लम्बित भुगतान

383. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वच्छ भारत अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र जायल में कितने शौचालयों की स्वीकृति जारी की गयी है व कितने शौचालयों का निर्माण कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्मित शौचालयों

(डा. मंजू बाघमार)

का 6 माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौनसे अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा अब कब तक उनको भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जायल में स्वीकृत एवं निर्मित शौचालयों की ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर के अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्मित शौचालयों का 6 माह से अधिक व्यतीत होने के उपरान्त किसी लाभार्थी का भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में नरेगा श्रमिकों की स्वीकृत संख्या

384. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महात्मा गांधी रोजगार योजना किस वर्ष में चालू की गयी और इसके उद्देश्य क्या थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) करौली जिले में वर्तमान में नरेगा श्रमिकों की कितनी संख्या स्वीकृत है और कितने कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारी जे.टी.ए., सहायक सचिव व अन्य को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान वर्ष 2006 में चरणबद्ध तरीके से चालू की गयी। 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में प्रारम्भ हुई। तत्पश्चात द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के 6 अन्य जिलों में तथा वर्ष 2008-09 से सम्पूर्ण राज्य में चालू की गयी।

योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक

(पंचायती राज मंत्री)

वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों की संख्या स्वीकृत नहीं की जाती है अपितु योजना मांग आधारित होने से रोजगार की मांग किये जाने पर नियमानुसार अकुशल रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। मांग के अनुरूप प्रतिदिन श्रमिकों की संख्या अलग-अलग रहती है। दिनांक 24.02.2018 की स्थिति में करौली जिले में 11098 श्रमिक कार्यरत है।

(3) जी नहीं। संविदा कार्मिकों को स्थायी करने अथवा नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ग्राम पंचायत मानका (मण्डावर) में आवास आबंटन के लम्बित आवेदन

385. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत आवास हेतु भूमि/आवास उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मानका तहसील मण्डावर जिला अलवर में गत 5 वर्षों में इंदिरा आवास योजना/प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कितने आवास आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम पंचायत के पास कितने आवेदकों के आवेदन आवास हेतु लम्बित हैं व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्राम पंचायत में कितनी भूमि व इंदिरा आवास प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि उपलब्ध न होने पर पंचायत स्तर पर आबंटन हेतु क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

(5) उक्त पंचायत में लम्बित आवेदकों को अब कब तक भूमि व आवास उपलब्ध करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 तहत अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध/आबंटित की जाती है।

(2) ग्राम पंचायत मानका तहसील मण्डावर जिला अलवर में विगत 5 वर्षो में विभिन्न आवास योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को स्वीकृत आवासों का विवरण निम्नानुसार है-

लाभार्थी का नाम	वर्ग
लाली देवी पत्नि कपूर चन्द	एस.टी.
कमला देवी रामेश्वर	एस.सी.
रजनी देवी पत्नि परसराम	एस.सी.
सोमवती पत्नि महेन्द्र	एस.सी.

(3) ग्राम पंचायत मानका में सैक 2011 की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत के पास आवेदकों के कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत मानका के पास आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। आदिनांक तक आवंटन की कार्यवाही इसलिये नहीं की गयी क्योंकि ग्राम पंचायत मानका को आबंटन की आवश्यकता ही नहीं हुई है।

(5) ग्राम पंचायत मानका के पास ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

चन्द्रसेल (कोटा) में फल सब्जी मण्डी की स्थापना

386. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चन्द्रसेल (कोटा) में प्रस्तावित फल सब्जी मण्डी की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फल सब्जी मण्डी की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण रहे?

(श्री संदीप शर्मा)

(3) उक्त प्रस्तावित फल सब्जी मण्डी की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा चन्द्रसेल में फल सब्जी मण्डी की स्थापना कब तक कर दी जाएगी।

उत्तर

(1) कोटा शहर के मध्य स्थित कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) कोटा के मण्डी प्रांगण को आम नागरिकों और फल सब्जी उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु राज्य स्तरीय भूमि चयन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2017 में चन्द्रसेल में उपलब्ध भूमि का चयन किया गया है।

(2) कोटा शहर के मध्य स्थित कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) कोटा के मण्डी प्रांगण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु राज्य स्तरीय भूमि चयन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2017 में चन्द्रसेल में उपलब्ध भूमि का चयन एवं चयनित भूमि के अभयारण्य/वन क्षेत्र से प्रभावित होने के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही मण्डी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) कोटा के वर्तमान यार्ड के व्यापार स्थानान्तरण हेतु उक्त भूमि का चयन किया गया है। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप चयनित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा सकेगी।

(4) चयनित भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही मण्डी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। चयनित भूमि का कब्जा मण्डी समिति को प्राप्त होने के उपरान्त कार्य योजना बनाकर नवीन मुख्य मण्डी प्रांगण में व्यापार प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में पशु नस्ल सुधार केन्द्र की स्थापना

387. **श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में मवेशियों की उन्नत नस्ल उपलब्ध कराने हेतु पशु नस्ल सुधार व प्रजनन केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर की 40 ग्राम पंचायतों में से 35 ग्राम पंचायतों में मवेशियों की उन्नत नस्ल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय संस्थाएं कार्यरत हैं। जिनमें से 23 ग्राम पंचायतों में पशुधन नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

पशुधन नस्ल सुधार/प्रजनन केन्द्र, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता अनुसार संचालित किये जाते हैं।

प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

388. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को किन-किन मदों एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है तथा अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों को कौन-कौनसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक झुन्झुनूं जिले में उक्त योजनाओं में कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ? कृषकवार, ग्रामवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को भारत सरकार प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों पर नियमानुसार अनुदान दिया जाता है। मदों का विभागवार तथा योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग में अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के दिशा-निर्देश, कृषि यंत्रों का विभागवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अन्तर्गत चयनित क्लस्टर क्षेत्र के कृषकों को रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर, बैटरी

(कृषि मंत्री)

स्प्रेयर, वीडर, टिलर, रीपर, स्ट्रा रीपर, पावर थ्रेसर, ग्राउण्डनट डिगर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित कृषक की भूमि चयनित क्लस्टर में होनी चाहिये तथा वह बहुकार्य समूह का सदस्य होना चाहिये। तत्पश्चात् कृषक को सम्बन्धित कृषि यंत्र हेतु जिला स्तरीय कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में मय आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, जमाबंदी की नकल सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर लाटरी प्रक्रिया द्वारा वरीयता निर्धारण कर लाभान्वित किया जाता है।

(2) झुन्झुनूं जिले में जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक उक्त योजनाओं में अनुदान से लाभान्वित किये गये कृषकों का कृषि एवं उद्यान विभाग का विवरण परिशिष्ट-4 तथा 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माचिया बायोलोजिकल पार्क में नये वन्य जीव लाने की योजना

389. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माचिया बायोलॉजिकल पार्क में जू शिफ्ट करने से पहले ओल्ड जोधपुर जू में दो साल की अवधि में कितने वन्यजीवों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बायोलॉजिकल पार्क में अब कितने नये वन्यजीव और आने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माचिया बायोलॉजिकल पार्क में जू शिफ्ट करने से पहले ओल्ड जोधपुर जू में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में वन्य जीवों की मृत्यु संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है।

(2) माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब एक जोड़ा बाघ (Tiger) तथा दो जोड़े सेही (Porcupine) जूलोजिकल पार्क, कानपुर से लाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर में आधुनिक स्तर के स्टेडियम का निर्माण

390. श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जय नारायण पूनियां)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आधुनिक स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में तारानगर में आधुनिक स्तर का स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य में आधारभूत खेल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास हेतु समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत संभाग, जिला, तहसील/पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत यथोचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पचपदरा क्षेत्र में रिफाइनरी के लिए ली गई भूमि का मुआवजा

391. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा क्षेत्र में तेल की रिफाइनरी लगाने के लिए 12 हजार बीघा लवणीय भूमि का आबंटन किया गया है व उक्त भूमि में नमक की 200 खानें 600 वर्ष पुरानी हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खान मालिकों को न तो नई खान आबंटित की गयी और न ही मुआवजा दिया गया? क्या सरकार उक्त खान मालिकों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लवणीय भूमि को राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 15/07/2013 जारी कर राजस्थान भू राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आबंटन) नियम 2007 के नियम 6 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12,034.10 बीघा भूमि को लवणीय क्षेत्र से वापिस ले लिया गया। राजस्व विभाग की उक्त अधिसूचना के क्रम में जिला कलेक्टर, बाड़मेर के आदेश दिनांक 24/07/2013 के द्वारा उक्त भूमि प्रस्तावित रिफाइनरी हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

के तहत आरक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात उद्योग विभाग के द्वारा उक्त अधिसूचना एवं आदेश के क्रम में आदेश दिनांक 19/09/2013 जारी कर उक्त भूमि को रिफाइनरी (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा आदेश दिनांक 21/09/2013 जारी कर उक्त राजकीय भूमि राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र में आबंटन) नियम 1959 में उल्लेखित प्रावधानों एवं अन्य शर्तो के तहत राज्य सरकार की जे वी कंपनी मैसर्स एच पी सी एल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आबंटित भूमि में रिफाइनरी क्षेत्र में आने वाली खानों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) रिफाइनरी क्षेत्र में आने वाले खानधारकों को विस्थापित कर शेष उपलब्ध लवणीय भूमि में आबंटित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक में सरकारी कार्यालयों के लिये भवनों का निर्माण

392. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक में माह दिसम्बर, 2017 तक कौन-कौनसे सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में कब से चल रहे हैं? उक्त कार्यालयों के लिये अब तक कितनी राशि किराये के रूप में दी जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन कार्यालयों के लिये भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक में माह दिसम्बर-2017 तक किराये के मकानों में संचालित सरकारी कार्यालयों की सूची मय संचालन दिनांक एवं किराये के रूप में अब तक दी गई राशि का वांछित विवरण सहित सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इन भवन विहीन कार्यालयों के लिए भवन

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

निर्माण हेतु बजट आबंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु ही बजट आबंटित किया जाता है। अन्य विभागों के कार्यालय के भवन निर्माण का कार्य संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आबंटित राशि

393. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कितने जिलों में लागू की गयी है? वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक इसमें कितनी राशि का प्रावधान रखा गया तथा इसके विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) उक्त योजना में कितनी राशि केन्द्र व राज्य की व्यय नहीं की गयी व इसके क्या कारण रहे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण जिलों में लागू की गयी है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 (जनवरी, 2018 तक) प्रावधान व व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	**आबंटन**		**व्यय (IFMS के अनुसार)**	
	आयोजना	**सी.ए. (केन्द्रीय)**	**आयोजना**	**सी.ए. (केन्द्रीय)**
2015-16	23051.55	11525.78	23043.63	11521.82
2016-17	42067.38	21033.69	41338.26	20669.13

नोट:- वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रावधित राशि एवं व्यय राशि में आयोजना मद के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि सम्मिलित है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

वित्तीय वर्ष	**आबंटन**		**व्यय (IFMS के अनुसार) (01अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक)**	
	राज्य निधि	**केन्द्रीय सहायता**	**राज्य निधि**	**केन्द्रीय सहायता**
2017-18	13259.92	16259.92	10003.59	10010.44

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत व्यय नहीं की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	**बचत**		**बचत का कारण**
	आयोजना	**सी.ए. (केन्द्रीय)**	
2015-16	7.92	3.96	कम खर्च का कारण संबंधितों द्वारा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
2016-17	729.12	364.56	

नोट:- वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रावधित राशि एवं व्यय राशि में आयोजना मद के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष	**बचत**		**बचत का कारण**
	राज्य निधि	**केन्द्रीय सहायता**	
2017-18	--	--	वित्तीय वर्ष 2017-18 में मार्च, 2018 तक राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता की प्रावधित राशि व्यय होना संभावित है।

सोजत में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी

394. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत वर्ष 2011 आर्थिक जनगणना में चिन्हित परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो सोजत विधान सभा क्षेत्र में कुल लाभार्थी परिवार की गांववार, नामवार, ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उज्ज्वला गैस योजना के तहत किन-किन गैस एजन्सियों द्वारा कितने गैस कनेक्शन आबंटित किये गये? लाभार्थी परिवार के गांववार, नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित परिवारों को भी उक्त योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सोजत में कुल 8362 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन आबंटित किये गये हैं। गांववार, नामवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php
https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx
https://ebharatgas.com → mylpg → Ujjwala Beneficiary

(2) सोजत विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवंटित गैस कनेक्शनों का एजेन्सीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**नाम एजेन्सी**	**आबंटित गैस कनेक्शनों की संख्या**
1	मैसर्स गिरधर इण्डेन गैस (IOCL)	3314
2	मैसर्स सोजत गैस सर्विस (IOCL)	4181
3	मैसर्स अमित एचपी गैस एजेन्सी (HPCL)	819
4	मैसर्स श्री सिद्धवी भारत गैस (BPCL)	48
	योग:-	**8362**

लाभार्थी परिवार की गांववार, नामवार सूची वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php
https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx
https://ebharatgas.com → mylpg→ Ujjwala Beneficiary

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2019 तक शेष वंचितों को (एसईसीसी अन्तर्गत) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। यह गैस कनेक्शन उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका नाम SECC 2011 लिस्ट में होना पाया जाता है, साथ ही उस परिवार में पूर्व में कोई गैस कनेक्शन नहीं होना आवश्यक है।

जहाजपुर (भीलवाड़ा) की तालाब तल की भूमियों के खातेदारी अधिकारों का निरस्तीकरण

395. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के राजस्व ग्राम जहाजपुर के पेटा तालाब चाण्डोला की किस्म पेटा तालाब तल भूमियों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किनको? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किस्म पेटा भूमियों में प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के राजस्व ग्राम जहाजपुर के पेटा तालाब चाण्डोला की किस्म पेटा/तालाब तल भूमियों में नियम विरुद्ध खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. किशनलाल, बाबूलाल, पिता भोगमाराम वगैरा नि. जाहजपुर आ.नं. 7477/2705 रकबा 01-05 बीघा।

2. छगनलाल पिता लाडु वगैरा आ.नं. 7480/2706 रकबा 02-14 बीघा

3. रंगलाल पिता पन्ना मीणा सा. सरसिया आ.नं. 7878/2705 रकबा 01-05 बीघा, 7482/2706 रकबा 02-09 बीघा।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

4. रामस्वरूप पिता सालगाराम मीणा आ.नं. 2706 रकबा 03-02 बीघा।

5. लादुलाल पिता गंगाराम मीणा आ.नं. 2706 रकबा 03-02 बीघा।

6. शान्ति पत्नि किशनलाल मीणा वगैराह आ.नं. 2706/3 रकबा 02-10 बीघा, आ.नं. 7479/2705 रकबा 0-10 बीघा।

उक्त खातेदारी अधिकार वर्ष 1982-83 में दिये गये हैं।

(2) ग्राम जहाजपुर के पेटा तालाब चाण्डोला की किस्म तालाब तल भूमि में 6 व्यक्तियों को नियम विरुद्ध खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। आ.नं. 2705/1 क (7476/2705) एवं आराजी नं. 2706 ग (7481/2706/2) रकबा क्रमश: 0.16 एवं 2.12 बीघा कुल किता 2 रकबा 3.080 बीघा भूमि की 90बी होकर नगर पालिका जहाजपुर के नाम बिलानाम आबादी दर्ज हो चुकी है तथा मकानात बन चुके हैं। उक्त नियम विरुद्ध खातेदारी के संबंध में राजस्व (ग्रुप-7) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(146)राज-7/2011 दिनांक 26.06.12 से रेफरेंस प्रस्तुत करने के समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश प्रदत्त है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा चरागाह व नाड़ी क्षेत्र की जमीन का रिजर्व प्राइस पर आबंटन

महोदय,

मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत इस बात का विशेष उल्लेख करता हूं कि दिनांक 01.02.2008 को नगर विकास न्यास, उदयपुर ने ग्राम पंचायत भुवाणा (तहसील बड़गांव) की 1,55,000 वर्गफीट चरागाह एवं नाड़ी क्षेत्र की जमीन उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पैसिफिक एजुकेशन सोसायटी, उदयपुर को रिजर्व प्राइस पर आबंटित कर दी।

चरागाह भूमि यू.आई.टी. को हस्तांतरित करने पर उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत भुवाणा के हक में दिनांक 04.12.1995 को ही स्टे आर्डर दे दिया था, जिसको वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने पुन: ग्राम पंचायत के हक में स्टे की पुष्टि कर दी।

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा किये गये उपरोक्त गैर कानूनी आबंटन के विरुद्ध ग्राम पंचायत की अगुवाई में जिला कलेक्टर ने कार्यवाही के आदेश दिये।

आबंटित भूमि आज भी ग्राम पंचायत भुवाणा के नाम राजस्थान के रेटेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा दिनाक 25.11.2011 को शासन उपसचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र में स्वीकार किया कि आबंटन से पहले भूमि न्यास के नाम दर्ज होना आवश्यक है तथा इसका पूंजीगत मूल्य भी यू.आई.टी. के द्वारा राज्य सरकार को देना अनिवार्य है। तहसीलदार ने विशेष उल्लेख किया है कि आराजी संख्या 2662 की किस्म भूमि नाड़ी है।

मैं सदन के माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी महोदय एवं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान विशेष उल्लेख की ओर आकर्षित करता हूं कि पेसिफिक एजुकेशन सोसायटी, उदयपुर को 1,55,000 वर्गफीट चरागाह एवं नाड़ी क्षेत्र की जमीन आबंटन को तुरन्त निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

सादर।

मानिक चन्द सुराना
(लूणकरणसर)

बांदीकुई की ग्राम पंचायत बसवा को नगरपालिका बनाया जाना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसवा (तह. मुख्यालय बसवा) जो कि पूर्व में वर्ष 1952 से 1957 में नगरपालिका थी इसके उपारान्त वर्ष 1978 से 1992 में नगरपालिका स्थापित रह चुकी है। वर्ष 1993 में बसवा नगरपालिका को पुन: पंचायत बना दी गई. जिसके कारण यहां की जनता को जो सुविधा नगरपालिका होने से प्राप्त थी उससे जनता को बिना किसी कारण से वंचित कर दिया गया।

बसवा कस्बे की आबादी क्षेत्र बड़ा होने के कारण यहां की सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था अन्य सभी कार्य पंचायत ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रही हैं। विधान सभा क्षेत्र बादीकुई में स्थित ग्राम पंचायत बसवा य तहसील मुख्यालय बसवा को नगरपालिका में बदलवाने हेतु माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं श्रीमान ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर से निवेदन किया था उक्त क्रम में श्रीमान विशिष्ठ सहायक श्रीयुत महेन्द्र जी पारख कार्यालय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर द्वारा श्रीमान जी को पत्राक 3676 दिनांक 17/09/14 प्रेषित करके दौसा जिले के श्रीमान कलेक्टर महोदय दौसा से 9 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही थी श्रीमान कलेक्टर महोदय दौसा द्वारा उनके पत्रांक पं.वि/2014/1345 दिनांक 17/12/14 द्वारा ग्राम: पंचायत बसवा को नगरपालिका में बदलने की अनुशंसा विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

विभागीय कार्यालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के संबंध में आयुक्त महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग सचिवालय जयपुर से भी पत्रांक एफ. 10 (क) (ग्राम) (न.पा.ग.) डीएलबी/14/5525 दिनांक 23/12/14 के द्वारा प्रति परीक्षण रिपोर्ट चाही थी। उक्त समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी थीं।

अतः सरकार से निवेदन है कि आम जनता की माग पर गम्भीर विचार करते हुए बसवा कस्बे को पुन: नगरपालिका क्षेत्र घोषित करवाने की कृपा करें।

अलका सिंह

(बांदीकुई)

प्रतापगढ़ जिले की भुड़वाई नदी पर पुल का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट में 31 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें ग्राम पंचायत रोहनीया के 5 गांव नामें

1. रोहनीया, ठाकरा, राणपुर, ममेड़ी, माडली कुल योग गांवों की आबादी 9074 है।
2. उक्त विवरण आबादी जनसंख्या को मध्यप्रदेश से आ रही भुड़वाई नदी रोहनीया पंचायत जनता को पंचायत समिति पीपलखूंट आवागमन में रोक लगा रही है। क्योंकि रोहनीया पंचायत व पृथ्वीपुरा पंचायत के बीच में होकर भुड़वाडी नदी गुजरती है।

पुल नहीं होने से रोहनीया पंचायत को जाने में घोड़ी तजपुर होकर 20-25 किमी. का चक्कर काटना पड़ता है। पुल बनने से सिर्फ 3 किमी. दूरी बनती है।

अतः आम जनता व सरकार के अधिकारियों व पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की मांग है कि भुड़वाई नदी पर गांव पृथ्वीपुरा व गांव भमेड़ी दोनों गांवों के बीच स्थान बेलनीया कऊडा नाम पेड़ के पास पुल का निर्माण कर उक्त विवरण जनता को आवागमन की सुविधा कराई जाए।

सादर।

नवनीत लाल

(घाटोल)

चाकसू के राजकीय कार्यालयों व संस्थानों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल की उपलब्धि

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू की तीनों तहसीलों क्रमश: कोटखावदा, चाकसू और फागी की ग्राम पंचायतों को बीसलपुर परियोजना से जोडकर शुद्ध पेयजल आमजन को उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार उच्च जलाशय (ओवरहैड टेक) भूतल जलाशय (GLR) बनाने और पाइप लाइनें बिछाने का कर्य प्रगति पर है। कोटखावदा और चाकसू तहसीलों में लगभग कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन फागी तहसील की मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों व अन्य सरकारी संस्थानों में भी शुद्ध फ्लोराइड मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जिससे आगामी गर्मियों में शुद्ध फ्लोराइड मुक्त पेयजल की भारी परेशानी होना तय है। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों व राजकीय संस्थानों में (PSP) पाइन्ट कनेक्शन देकर फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बीसलपुर जल परियोजना को शीघ्र पूर्ण करवाकर क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों व राजकीय संस्थानों में (PSP) पाइन्ट कनेक्शन देकर फ्लोराइड मुक्त शुद्व पेयजल उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

लक्ष्मी नारायण बैरवा

(चाकसू)

हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना से गांवों में पेयजल आपूर्ति

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सांगोद के हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना में जल के पर्याप्त स्रोत है। इस हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वे कराकर उपलब्ध जल की मात्रा इत्यादि सर्वे की रिपोर्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भिजवायी जा चुकी है। जिसमें पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता बतायी गयी है एवं डीपीआर बनकर भी तैयार हो चुकी है। वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना को बजट भाषण 2018-19 सम्मिलित करवाने की अनुशंसा की गयी है एवं हरिपुरा मांझी पेयजल योजना को वित्त विनाग द्वारा भी सक्षम स्तर पर अनुमोदित किया जा चुका है।

वर्तमान में हरिपुरा माझी पेयजल योजना से सांगोद विधान सभा के 176 गांव एवं 22 मजरे एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के 61 गांव एवं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के 44 गावों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पिछले काफी समय से सांगोद लाडपुरा एवं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्रों के कुछ गाव आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं एवं कई गांव में पेयजल की भीषण समस्या है। जिस कारण विभाग द्वारा टैंकर से सप्लाई की जा रही है। क्षेत्र में पेयजल की बढ़ती समस्या से क्षेत्र के सभी सोग परेशान हैं।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर माननीय अध्यक्ष जी एवं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सांगोद, लाडपुरा, पीपल्दा क्षेत्र के गांव में फ्लारोइडयुक्त पानी एवं पेयजल की समस्या को देखते हुये हरिपुरा

मांझी पेयजल परियोजना को बजट घोषणा में शामिल कर स्वीकृत करते हुए अनुग्रहित करने का श्रम करें।

हीरालाल नागर

(सांगोद)

लाडपुरा के मण्डाना क्षेत्र में कोटा बैराज से पानी की मांग

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मण्डाना का बड़ा इलाका डार्क जोन में आता है और यहां पर वर्ष भर पानी की किल्लत बनी रहती है। 1960 चंबल नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत कोटा बैराज एवं इसकी दायीं व बायीं मुख्य नहरों के निर्माण के बाद से ही मण्डाना क्षेत्र को कमाण्ड एरिया घोषित किया हुआ है किन्तु 58 साल बीतने के बाद भी न तो इस क्षेत्र में नहरी तंत्र विकसित हुआ है और न ही सिंचाई का एक बूंद पानी पहुंचा।

वर्तमान में मण्डाना उप तहसील में 9 ग्राम पंचायतें हैं जिनके 91 गांवों में 70 हजार लोग रहते हैं इसके पास 40 हजार बीघा जमीन होते हुए भी जब चंबल का पानी 250 किमी दूर भीलवाड़ा जा सकता है। मण्डाना का राजस्व क्षेत्र तो चंबल से 20 किमी दूर है। क्यों नहीं कोटा बैराज से लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी लिफ्ट करके नहरी तर्ज से पूरे मण्डाना के डार्क जोन में फैला दिया जाए। इसमें सरकार का खर्च भी कम लगेगा और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सम्पूर्ण मण्डाना क्षेत्र को सिंचित करने के लिए एक बड़ी लिफ्ट परियोजना की आवश्यकता है। इस हेतु बोराबास के भूखी गांव के पास से अथवा कोटा बैराज से चंबल का पानी लिफ्ट कर मण्डाना क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना का शीघ्र सर्वे करवाकर स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आधी सदी से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही मण्डाना की धरती चंबल का पानी पीकर लहलहा उठे।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

महोदय,

आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों के

निर्माण के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप परियोजना "मिसिंग लिंक सड़क" के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। इसी अनुक्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं के ग्रामवासियों द्वारा की जा रही मांग एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित गांवों में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता है:-

क्र. सं.	**ग्राम का नाम**
1.	ग्राम बिरोल से निकदास जी की बगीची होते हुए झाझड़ रोड तक
2.	ग्राम बसावा मुख्य चौक से धामाणा होते हुए लाल कुआ खिरोड़ सीमा तक
3.	ग्राम चिराना मुख्य बस स्टैण्ड से बागोरिया की ढाणी
4.	सोटवारा से जेजूसर
5.	कसेरू से डूमरा
6.	परसरामपुरा नदी से मुख्य द्वार तक
7.	बाय से पकोडी प्याउ होते हुए ओला की ढाणी तक
8.	ढिगाल से स्वामी की ढाणी तक
9.	झुन्झुनूं रोड से माताजी की ढाणी तक
10.	कोलसिया से पूजारी की ढाणी तक
11.	कोलसिया से कारी तक
12.	बडवासी से ढाका का बास होते हुए भगेरा तक
13.	कसेरू रोड से गोगामेडी मेघवाल मौहल्ले तक
14.	बडवासी से कलवानिया होते हुए कोलसिया तक
15.	जाखल सूरपा मूण्ड की ढाणी से भोडकी सीमा तक

क्र. सं.	ग्राम का नाम
16.	मानाणी ढाणी से खिरोड (बेरी) सीमा तक
17.	खिरोड गढवालों की ढाणी से थोरी वाली जोहड़ी तक
18.	खिरोड गढ़वालों की ढाणी से सेवा नगर तक

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त गांवों में "मिसिंग लिंक सड़क" निर्माण करवाये जाने की आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें।

डा. राजकुमार शर्मा

(नवलगढ़)

खातौली कस्बे स्थित राजकीय अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावास में अनियमितताएं

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के खातीली कस्बे में स्थित राजकीय अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावास में हो रही व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस छात्रावास में असुविधाओं एवं अनियमितताओं को लेकर यहां के छात्रों द्वारा बार-बार शिकायतें की जाती रही हैं एवं प्रशासन द्वारा इसकी जांच करवाये जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिनांक 19.12.2017 को नायब तहसीलदार खातौली द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान पाया कि छात्रावास में साफ-सफाई नहीं हो रही है, कमरों से बदबू आ रही है। जूते, मोजे, बिस्तर एवं चद्दरें काफी गंदी एवं घटिया स्तर की हैं। बच्चों को साबुन एवं तेल भी नहीं दिया जा रहा है, नाश्ता एवं भोजन का स्तर घटिया है एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एक बार भी नहीं कराया गया है।

निरीक्षण के बाद इस स्थिति में सुधार होना चाहिये था किन्तु बच्चों द्वारा पुनः शिकायत करने पर दिनांक 19.1.2018 को तहसीलदार द्वारा किये गये निरीक्षण में तो और भी खराब स्थिति सामने आई जिसके अनुसार बच्चों को दैनिक मीनू के अनुसार भोजन एवं नाश्ता नहीं दिया जा रहा तथा भोजन की गुणवत्ता घटिया पाई गई, सामग्री वितरण रजिस्टर में बच्चों के हस्ताक्षर हैं किन्तु तेल, साबुन व अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई। छात्रावास के

कमरों, स्नानघर एवं शौचालयों में गंदगी के कारण बदबू फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त खाना बनाने वाली महिला द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार एवं धमकियां दिये जाने का मामला भी सामने आया जिससे बच्चे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सारे प्रकरण पर समग्र कार्यवाही करने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

विद्याशंकर नन्दवाना

(पीपल्दा)

सिवाना के तीर्थ स्थलों का विकास

नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि-

बाड़मेर जिले का पहाड़ी क्षेत्र सिवाना है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। सिवाना पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पुराना कस्वा जहां पर अनेक तीर्थस्थल एवं धार्मिक स्थान हैं। जिसमें गुरु महराज की समाधियां, सिवाना का दुर्ग, मोकलसर की बावड़ियां, दुर्गादास जी की पोल, पंचतीर्थ स्थल भीमगोड़ा, हींगलाज माता मन्दिर, भीडभजन महादेव, शुक्लेश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव आदि रमणीक तीर्थ स्थल हैं।

इन सभी में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है हल्देश्वर महादेव जो कि 56 की पहाड़ियों में जमीनी तल से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर स्थित है। आने-जाने को दुर्गम रास्ता जो कि पहाड़ियों के बीच में से निकलता है। यह मन्दिर हजारों वर्ष पुराना जहां पर प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जिसका आकार विशाल है। इस शिवलिंग पर अब मन्दिर निर्माण

कार्य किया जा रहा है। जिसका कार्य प्रगति पर है। इसी पहाड़ी की तलहटी में वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की कर्मस्थली के रूप में खण्डर पोल आज भी खड़ी है। अकबर के शासनकाल में कुछ समय के लिए दुर्गादास जी इसी जगह पर रहे थे।

इस मन्दिर का विकास वर्षों पूर्व राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मन्दिर पहाड़ के ऊपरी भाग में स्थित है। जहां पर हजारों बीघा समतल भूमि भी है। आज भी वर्षा के समय उक्त मन्दिर राजस्थान का मिनीमाउंट के नाम से विख्यात है, जहां पर हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी दर्शन करने हेतु आते है। वर्षा के समय यहां पर झरने बहने के कारण स्थल बहुत ही सुन्दर हो जाता है। इस मन्दिर को जाने हेतु पहाड़ी की तलहटी तक सड़क मार्ग बना हुआ है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत की आवश्यकता है।

मेरा सदन के मार्फत निवेदन रहेगा कि वर्तमान सरकार प्राचीन धरोहर के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। हल्देश्वर महादेव मन्दिर के ऊपर जाने का रास्ता निर्माण एवं रोप-वे लगा दिया जाए तो बाड़मेर जिले का यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल विकसित हो सकेगा। जहां हजारों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आकर पर्यटन को बढ़ावा दे सकेंगे। इसके साथ ही निवेदन रहेगा कि उक्त मन्दिर अधिक ऊंचाई पर होने के कारण आज दिन तक यहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, अगर राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा का प्लांट मन्दिर के ऊपरी भाग में लगा दिया जाये तो लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र हल्देश्वर महादेव मन्दिर विकसित हो सकेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि राजस्थान घरोहर संस्कृति संरक्षण प्राधिकरण विभाग के तहत उक्त विकास कार्य करवाकर अनुग्रहित कराएं।

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

नागौर की जायल व खींवसर तहसील के किसानों की जमीन का औद्योगिक घरानों को आबंटन

महोदय,

नागौर जिले में खनिज सम्पदा के अकुल भण्डार मौजूद है। जिले के जायल और खींवसर तहसील क्षेत्र में के भूगर्भ में भू वैज्ञानिकों द्वारा लाइम स्टोन के भण्डार चिन्हित किए गए हैं। खनिज विभाग ने लाइम स्टोन के भण्डारों का पूर्वेक्षण करवाकर इन्हें आबंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइम स्टोन के ब्लाक स्वीकृत करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर ई-आक्शन की कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा अब तक लाइम स्टोन के 5 ब्लॉक की ई-नीलामी की जा चुकी है। जिसके तहत इमामी सीमेंट लिमिटेड कोलकाता. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू तथा डालमिया सीमेंट लिमिटेड को जायल व खीवसर क्षेत्र में लाइम स्टोन के टेंडर जारी किए गए हैं। नागौर जिले के मूंडवा कस्बे में भी अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस सीमेंट प्लांट को भी लाइम स्टोन खनन के लिए किसानों की विशाल जमीन अवाप्त कर अम्बुजा सीमेंट कम्पनी

को अबंटित की है। देश के इन बड़े उद्योग घरानों को लाइम स्टोन के ब्लाक आबंटित किए जा रहे हैं। इससे नागौर जिले के लोगों को क्या फायदा मिलेगा। ये कम्पनियां यहाँ कब तक खनन का काम शुरू करेंगी। लाइम स्टोन के खनन से राज्य सरकार को कितना राजस्व मिलेगा। राज्य सरकार ने खनन के दौरान नागौर जिले के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या योजना तैयार की है। लाइम स्टोन का खनन करने वाली सीमेंट कम्पनियां कितने लोगों को रोजगार देंगी और स्थानीय लोगों की खनन कार्य में क्या भागीदारी रहेगी। खनन मंत्री इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि आमजन को यह पता चल सके कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है।

हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा

(नागौर)

किशनगढ़बास के ग्राम देवता की भूमि का नगरपालिका को आबंटन

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में नगरपालिका क्षेत्र किशनगढ़बास के ठोस कचरा डालने का कोई स्थान नहीं है, जिसके कारण कचरे का निस्तारण करने में बड़ी परेशानी आ रही है। नगरपालिका किशनगढ़बास में स्थान नहीं होने से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर नगरपालिका खैरथल में कचरा डाला जा रहा है, कचरा वाहन नगरपालिका किशनगढ़बास एवं खैरथल के बीचों बीच जाता है। नगरपालिका किशनगढ़बास का कचरा डालने व कचरा वाहन कस्बे के बीच से जाने पर नगरपालिका खैरथल के निवासियों का भारी विरोध है, आये दिन विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बनी रहती है। ठोस कचरा निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास एवं तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा ग्राम देवता के खसरा नं. 70. रकबा 1.44 भूमि का मौका देखा गया गया, जो ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु उपयुक्त पाई गई।

अतः मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि खसरा नं. 70. रकबा 1.44 ग्राम देवता की भूमि को ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु नगरपालिका किशनगढ़बास को अतिशीघ्र आबंटन किया जाए, जिससे नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़बास के आम नागरिकों की समस्या का समाधान हो सके।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़बास)

श्रीगंगानगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र प्रारम्भ करना

महोदय,

श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज जल निकासी एवं ठोस कचरा निस्तारण एक विकराल समस्या बन चुकी है। सीवरेज ट्रीटमेन्ट हेतु श्रीगंगानगर में स्वीकृत तीन प्लाण्ट गुरुनानक बस्ती, पुरानी आबादी और सद्भावना नगर में में दो प्लाण्ट गुरुनानक बस्ती और सद्भावना नगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि पुरानी आबादी पलाण्ट का निर्माण कार्य तो अभी प्रारम्भ ही नहीं किया गया है। इसके क्या कारण हैं? समझ से परे हैं।

वहीं ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए नेतेवाला के पास संयंत्र लगाये जाने हेतु भूमि आबंटित की गई, यहां फिर प्रशासनिक अकर्मण्यता और अविवेकपूर्ण निर्णय से पर्यावरण नियमों को ताक में रखते हुए नहर एवं नेतेवाला गांव की आबादी भूमि के पास संयंत्र लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। फलस्वरूप पर्यावरणविदों और ग्रामवासियों का विरोध प्रारम्भ हो गया और श्रीगंगानगर में ठोस कचरा निस्तारण के प्रयास भी कागजों में सिमटते नजर आ रहे हैं। उक्त संयत्र हेतु पर्यावरण नियमों के अनुरूप नहरों एवं आबादी से दूर भूमि आबंटित किये जाने की अतिशीघ्र आवश्यकता है।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं श्रीगंगानगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट को प्रारम्भ करने एवं ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र हेतु भूमि आबंटित कर संयंत्र निर्माण प्रारम्भ किये जाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं।

कामिनी जिन्दल

(गंगानगर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विद्यालय भवनों में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कक्षा-कक्षों की कमी वाले विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) से भवन निर्माण स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय बालेसर में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने एवं विज्ञान, वाणिज्य वर्ग एवं एन.सी.सी. स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. उप खण्ड मुख्यालय शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

6. विधान सभा क्षेत्र लूणी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा (कुड़ी), मोगड़ा कलां, दुन्दाड़ा, सांगरिया, बोरानाडा में विज्ञान संकाय खोलने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मणाई में कला संकाय खोलने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाराबेरा पुरोहितान में कला संकाय खोलने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली में भूगोल एवं अंग्रेजी साहित्य का अतिरिक्त विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपरली, लूणावास खारा, मोड़ी जोशियान, कालीजाल, बड़ली, माणकलाव,

दईजर, चाली, सर व नाहरों की ढाणी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. विधान सभा क्षेत्र लूणी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेलबा, दूदियां, बम्बोर पुरोहितान, मध्यपूर्व गंगाणा, कटारड़ा, बासनी झूठा, सिंधियों की ढाणी (इमाम नगर) को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक, राजकीय माध्यमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक तथा संस्कृत विद्यालयों में भारी मात्रा में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत झंवर में नई आई.टी.आई. खोलने एवं विद्यालयों में कम पड़ रहे कक्षा-कक्षों का रमसा के माध्यम से निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

11. अलवर के कलाकारों जिनमें माटी कलां के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ओम प्रकाश गालव, भवंग वादन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जहूर खां मेवाती व परिवार एवं अन्य कलाकारों को प्रोत्साहन देकर अकादमी स्थापित करने के लिए राजकीय सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

12. शहर के पटरी पार क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु उच्च माध्यमिक (बालिका) विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

13. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के राजकीय माध्यमिक विद्यालय संस्कृत ग्राम चौमू मालाखेड़ा अलवर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा अलवर में कला महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

15. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नं. 12 टोंक में कला

संकाय में ऐच्छिक विषय हिन्दी एवं संस्कृत खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र टोंक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र टोंक में माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्षों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिए।

19. टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय यज्ञ के बालाजी टोंक को प्रवेशिका स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

20. औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में बाबा मोहनराम महाविद्यालय को सरकार अपने अधीन लेकर बाबा मोहनराम राजकीय महाविद्यालय के नाम से या नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में ग्राम पंचायत (बिरामपुर, मुण्डाना, मसीत) नगर परिषद से सम्मिलित ग्राम पंचायत मुख्यालय (साहडोद, साथलका, आलमपुर, मिलकपुर गुर्जर, खिजूरीवास व सैदपुर) व नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालय (थड़ा और मीठियावास) पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम बीनावास, बीरावास, सोवनिया, जसपाली, जालखा, हर्ष, आदर्शनगरी बिलाड़ा, वार्ड नं. 10 पीपाड़शहर, मुरकासनी बड़ी कलां एवं रावर गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों रावर की ढाणी, खातियासनी, पीथावास, जालेली दईकड़ा खारिया आनावास, राजकीय

बालिका माध्यमिक विद्यालय खारिया मीठापुर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों खारिया मीठापुर में विज्ञान वर्ग, मालकोसनी में कला वर्ग, रणसी गांव में विज्ञान वर्ग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. बिलाड़ा एवं पीपाड़शहर महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने एवं रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

27. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापुर में छात्रों की संख्या को देखते हुए गृह एवं भूगोल विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के पंचायत हैड क्वाटर पर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की संख्या को देखते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ में भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ग्राम पंचायत चिरूनी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के स्कूलों में अध्यापक लगवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

33. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कला एवं संस्कृति हेतु कला केन्द्र एवं कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पंचायत मुख्यालय के स्कूलों में कक्षा-कक्ष बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. जैसलमेर जिले में गावों की दूरियों को देखते हुए स्कूलों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

36. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैलाणा में व्यवसायिक शिक्षा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवाडा में जीव विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमारू, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय महिपालपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गामडीपाल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीथापुर को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर (मेवाड़ा), जालु कुआ, शिशोद, खेड़ा कच्छवासा, मालमाथा, मेवाड़ा में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटवाड़ा एवं भैसाकलां को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय आसियावाव को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

41. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में माध्यमिक शिक्षा विभाग के

अन्तर्गत कला कक्षों की भारी कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में एकीकरण/अनार्थिक के नाम पर 20000 के करीब विद्यालय बंद किये जाने/मर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

44. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंबावा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करदा एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढिकोड़ा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

46. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संस्कृति एवं कला के प्रतीक किलों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं):

48. प्रदेश में स्कूलों को पी.पी.पी. मोड पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. राजकीय माध्यमिक विद्यालय झुंझुनूं में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

51. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

52. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च

माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत कक्षा दसवीं में 100 का नामांकन वाले सीनियर विद्यालय में एक संकाय खोले जाने की क्रियान्विति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरू बाड़मेर में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्ष 2003 में क्रमोन्नत विद्यालय सिणरे एवं कांखी में रमसा के तहत सिवाना क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पंचायत मुख्यालय को छोड़ कर अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में गणित, सिवाना में संस्कृत, सिणधरी बालिका में भूगोल एवं महिलावास में नवीन वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

57. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बसई नवाब में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी):

61. कन्या महाविद्यालय बून्दी में समाज शास्त्र, चित्रकला विषय एवं विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के कन्या महाविद्यालय को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

64. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेमाल, नेवा तलाई, नढ़ारा पाल सराडा व अमलोछा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नव गठित पंचायत नाल हल्कार, पालसर्सिया डेलवास, खरबर B कलाता में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हाडी रानी महल, प्रताप स्मारक चावण्ड को पर्यटकों को लुभाने की दृष्टि से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

68. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. उप खण्ड मुख्यालय बायतु में कला एवं संस्कृति के विकास के लिए सांस्कृतिक कला केन्द्र की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र बायतू में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 02 किमी से अधिक दूरी के मर्ज किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डी मर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए 01 किमी से अधिक दूरी के प्राथमिक विद्यालयों को डी मर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

73. सांचौर उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

74. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में प्राधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. बारां जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. दूर किशनगंज कस्बे में होली के पावन पर्व पर लगभग 131 वर्षो से लगातार स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित फूल डोल लोकोत्सव जिसमें कला एवं संस्कृति की सजीव झाकियां प्रदर्शित होती हैं। उक्त कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं पर्यटन विभाग के कलेण्डर में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

76. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. पंचायत समिति घाटोल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय माटिया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़-अलवर):

79. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाई का बाल (लक्ष्मणगढ़) जिला अलवर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सम्मनपुर-गुर्जरपुर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

81. जोधपुर के तूरजी का झालरा की तर्ज पर अन्य प्राचीन जलाशयों का धरोहर संरक्षण के रूप में जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में योग एवं वैदिक गणित को अलग विषय के रूप में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रतापगनर, राजकीय अल्प भाषा राजमहल माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्र में बालिकाओं के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

85. तहसील मुख्यालय भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

86. मीरा की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मीरा महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

87. फलौदी मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. राजकीय महाविद्यालय फलोदी के वाणिज्य वर्ग में व्यावसायिक प्रबंधन एवं विज्ञान वर्ग में प्राणिशास्त्र विषय की पीजी कक्षा शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. राजकीय महाविद्यालय फलौदी एवं बाप में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (द्वितीय) जोधपुर को फलौदी मुख्यालय पर स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (द्वितीय) जोधपुर को फलौदी मुख्यालय पर स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

92. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

93. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लोक देवता महात्मा ईश्वरदास के पैनोरमा स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. राजस्थान संस्कृति को सहेजने एवं संवर्धन करने वाली मांगणियार जाति के विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के दो कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत जूनापतरासर, बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर मगरा मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोधिया मेघवालों की बस्ती (उण्डरवा), गेहूं, लुणु, गुड़ीसर, हाजाणियों की ढाणी, मेघवालों का तला, डूंगरों का तला को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

98. प्रदेश के एकीकरण के नाम पर बन्द किये गये ग्रामीण विद्यालयों को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्यालयों में विभिन्न विषयों की कक्षायें खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

100. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालछा तथा घणावल को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

101. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कला शिक्षा (चित्रकला एवं संगीत) अनिवार्य होने के बावजूद भी स्कूलों में अध्ययन नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

102. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कला शिक्षा (चित्रकला एवं संगीत) अनिवार्य होने के बावजूद भी स्कूलों में अध्ययन नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):

103. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय महनसर और राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंकड़ेऊ कलां को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

104. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के खेलने हेतु खेल मैदानों का अभाव व मैदानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

105. विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा कलां व चण्डावल नगर में विज्ञान संकाय विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोदेलाव, खेजड़ी बाला, पोकरीया नाडी, उपरला लाखा खेत को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र सोजत की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवली कलां, खाखरा, बुटेलावग भंवर भाटा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

108. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में कुन्हाड़ी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालिता कोटा को प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नया

खेड़ा, गोपाल मिल एवं पुलिस लाइन कोटा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. स्टफिंग पैटर्न के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा महात्मा गांधी रामपुरा कोटा व जवाहर लाल नेहरू, भीमगंजमण्डी, कोटा विद्यालयों में विज्ञान व संस्कृत विषय बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

112. विधान सभा क्षेत्र नागौर की उच्च माध्यमिक विद्यालय में झुफण्डा मुडवा नागौर में कला वर्ग खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र नागौर की राजकीय प्राथमिक विद्यालय किदवाई कालोनी नागौर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र नागौर की उच्च प्राथमिक विद्यालय बासनी बेलीया बू. झमसोता को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र नागौर तारसूर पंचायत में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र नागौर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागली व केम खामियों की ढ़ाणियां को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल):

117. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र जायल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय दुगोली/सोमणा/दुगस्ताउ/लुणसरा को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरनेल/आकोड़ा/सोनेली में कला संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

120. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने एवं स्नातक धर्म महाविद्यालय में सभी संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

121. प्रदेश में प्रबोधकों के लिये पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत चयनित उत्कृष्ठ विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र (आईटीआई) कोटा में नियमित अनुदेशक अथवा गेस्ट फेकल्टी के रूप में अनुदेशक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, संकाय परिवर्तन एवं नये संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं कम्प्यूटर लैब के लिये राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

126. विधान सभा क्षेत्र नागौर छबड़ा में छीपाबड़ौद (बारां) में चल रहे S.F.S. कालेज को सरकारी कालेज घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):

127. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानगढ़ खोखावाला को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

129. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के राजकीय विद्यालयों मे रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

130. विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालय भीम एवं देवगढ़ में चल रहे रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. राजकीय महाविद्यालय भीम में विज्ञान, वाणिज्य एवं पी.जी. संकाय खोलने जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र भीम के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

134. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई मे राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीचूपाड़ा खुर्द में कृषि विज्ञान, आभानेर में वाणिज्य संकाय एवं गुढ़ा कटला में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चल रहे स्व वित्त पोषित महिला महाविद्यालय का सरकारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नवीन ग्राम पंचायत में रमला खेड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

137. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डि-मर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंथारिया एवं करनकड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

139. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक

विद्यालयों में साइंस लैब, विषय अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में खेल मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. राजनीति में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रेवदर क्षेत्र के सरकारी अध्यापकों के विरुद्ध सरकार को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सभी स्तर के सरकारी स्कूलों में उभरते खिलाड़ियों के लिए संबंधित विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव एवं खेल विशेषज्ञों कोच की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक स्टाफ के अभाव में कमजोर परीक्षा परिणामों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

144. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. ग्राम पंचायत ढ़ोटी ब्लाक सांगोद मुख्यालय पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

148. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (चुरू) में शैक्षणिक स्टाफ अतिशीघ्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय महाविद्यालय में संकाय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

152. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के वजीरपुर उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगोल विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

156. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर चालू सत्र 2017-18 में नवस्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रारम्भ से सुचारु रूप से चलाने हेतु ठोस विभागीय क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के आर.के. पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय-किशनगढ़ (अजमेर) में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय में अध्ययन की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. किशनगढ़ (अजमेर) उप खण्ड मुख्यालय पर संचालित राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय, शिवाजी नगर को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर अविलम्ब क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. प्रदेश में लम्बे समय से तृतीय श्रेणी वर्ग के अध्यापकों के सामान्य स्थानान्तरण नहीं होने से कर्मचारी वर्ग में उत्पन्न हुए रोष के संबंध में चर्चा के लिए।

160. बजट घोषणा 2018-19 में बिन्दु संख्या 99 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के गत 04 वर्षों से क्रमोन्नति की प्रतीक्षारत ग्रामीण विद्यालयों के प्रस्तावों पर सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

161. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजकीय महाविद्यालय निवाई में पी.जी; संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूगोल विषय खुलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाय में विज्ञान संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र में निवाई तहसील मुख्यालय पीपलू पर नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

166. विधान सभा क्षेत्र कपासन में शिक्षा विभाग के संचालित सभी विद्यालयों में रिक्त चल रहे सभी श्रेणियों के अध्यापकों के पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय आकोला, मण्डपिया पहुंना को क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

168. विकास खण्ड विराटनगर (जयपुर) में सरकारी महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में संचालित सरकारी विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एक भी सरकारी ITI नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

172. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कला शिक्षा (चित्रकला एवं संगीत) अनिवार्य होने के बावजूद भी स्कूलों में अध्यापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

173. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में कला वर्ग हिन्दी एवं भूगोल विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी/गणित के विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रूप में संविदा के माध्यम से नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

176. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू की नयी पंचायत मुख्यालय में रामपुरा एवं असपुरा में विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू की नयी पंचायत मुख्यालय बसन्तगढ़ एवं ठण्डीवेरी के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

178. विधान सभा क्षेत्र आहौर के आईपुरा, बांकली, सिवणा, ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

179. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की गिरवरसर, उडवाला, बोबासर कावर सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

180. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विषय/संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र मावली में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने एवं नवीन ट्रेड चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र मावली की 62 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका फतेह नगर सनवाड़ में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र मावली की 62 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका फतेह नगर संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान एवं प्रार्थना स्थल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

185. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उप खण्ड पर I.T.I. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन उप खण्ड स्तर पर माडल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पांच पंचायत हैड क्वाटर पर वंचित रहे विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

190. प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कला शिक्षा के चित्रकला व संगीत विषय के अध्ययन करवाने व पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करवाने तथा कला शिक्षकों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. रायसिंहनगर व श्री विजयनगर में शहीद भगत सिंह कालेज एवं श्री विजय नगर में सरकारी गर्ल्स कालेज खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत डाबला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. रायसिंहनगर व श्री विजय नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

194. विधान सभा क्षेत्र आमेर में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा के लिए।

196. प्रदेश में स्कूलों की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

197. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोहेडा में विज्ञान संकाय में गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए कक्षा-कक्ष की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

201. अनूपगढ़ में PG संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. श्री विजय नगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. अनूपगढ़ राजकीय महाविद्यालय में स्टाफ पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत देसली 3/4 RSM एवं 12 KND में राजकीय विद्यालय क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

206. ब्लाक श्रीगंगानगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिहांगावाली को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के चौ. बल्लुराम गोदारा कन्या महाविद्यालय श्रीगंगागनर में एम.ए. गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर की सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

210. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवा माता मन्दिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विहिन ग्राम पंचायतों में विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

214. प्रदेश के विद्यालयों में नर्सरी, के.जी. एवं एल.के.जी. की कक्षायें प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. प्रदेश में शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्यापकों का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

216. प्रदेश में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. प्रदेश में अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

218. जहाजपुर उप खण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत कालेज को पुन: चालू कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

219. बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा का उप निदेशक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. कोलायत, बज्जू व देशनोक में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. प्रदेश में गत चार वर्षों में हटाए गए विद्यार्थी मित्रों को राजकीय सेवा में वापस लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

224. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. उप खण्ड मुख्यालय भिनाय में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

226. विधान सभा क्षेत्र आहौर के ग्राम पंचायत शंखवाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र आहौर के ग्राम पंचायत के आईपुरा, सीवणा को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र आहोर के देलदरी और काणदर गांव में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

229. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

230. योमित जांगिड़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भगत की कोठी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

231. जोधपुर संगीत नाटक अकादमी के कार्य के विस्तार को देखते हुए एवं सम्पूर्ण राजस्थान में सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु रवीन्द्र मंच की तर्ज पर 30 व्यक्तियों का स्टाफ मुहैया कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

232. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर स्थित महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में सरकारी महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्योसिंहपुरा, मोहनपुरा बालाजी एवं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नरैना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धाना का बास को माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय काल्यां (हवसपुरा) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभर लेक में वनस्पति शास्त्र एवं भूगोल विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

236. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कवाई में विज्ञान वर्ग, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बडोरा विज्ञान वर्ग, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कटावर विज्ञान वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहरोद कला वर्ग, भूगोल, चित्रकला एवं राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय कुन्जैड कला वर्ग, गृह विज्ञान, भूगोल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किसनपुरा भसालदरान को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्यागण एवं खेडली गदियान-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दीवाली, मण्डोला एवं रतनपुरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्न्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में लक्ष्मीपुरा (नगर परिषद बारां) PS अरण्या खेड़ा (अटरू) PS भोजूखेड़ी (अटरू) PS फूकर तालाब (अटरू) PS को पुन: खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

239. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में संस्कृति एवं कला के प्राचीन परिवेश के आयाम जो ग्रामीण अंचल के प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी के माध्यम से संस्कृति के विचारात्मक तुलना के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव एवं सेमारी में प्राचीन मन्दिरों में कला एवं लोक कलाकारों की वागड़ अंचल की गवरी नाट्य कला एवं ग्रामीण परिवेश की प्राचीन संस्कृति का पुन: प्रादुर्भाव एवं उन्नयन के संबंध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा जनजाति पहाड़ी दुर्गम बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने एवं क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय ऋषभदेव में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

244. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

245. प्रतिबंधित जिलों में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण गृह जिलों में करने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजकीय माध्यमिक विद्यालय आकोली, गुणसार नसोपुर, राटा खुर्द, सिवाना मिर्जापुर, खोहा व पाटन मेवान को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

248. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांखला में वाणिज्य (Commerce) संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सहाड़ा, रायपुर, सुवाणा में विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक से

माध्यमिक में व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में समायोजन अन्तर्गत बन्द किये गये प्राथमिक विद्यालय को पुन: चालू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में समायोजन के अन्तर्गत समाप्त किये गये अंग्रेजी विषय को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

252. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में रा. म. महाविद्यालय चौमूं में भौतिक शास्त्र एवं आर एल सहरिफ महाविद्यालय कालाडेरा में विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झीडा को माध्यमिक में तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय चारपोल, धोरा गुढ़ा, हीरा का बास, नृहसिंहपुरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनमानपुरा, आलीसर व सामवाली में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के कई भवन खाली होने से उनके उपयोग अन्य विभागों को करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग):

256. विधान सभा क्षेत्र डग में PG कालेज भवानीमण्डी में स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं के लिए अध्यापन के साथ-साथ सुविधाओं की उपलब्धता कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र डग के कालेज चोमहला में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र डग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र डग में विस्तुनिया माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

260. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्तियां जल्द करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

262. विधान सभा क्षेत्र वैर में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र वैर में एकीकरण के तहत बन्द किये ग्रामीण विद्यालयों को पुन: संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र वैर के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

265. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के स्कूलों में अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

266. विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत गीजगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में संचालित राजकीय महाविद्यालय को सिटी लाइट में जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

269. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, लिपिकों व प्रयोगशाला से संबंधित कार्मिकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के विद्यालयों में भवन की कमी के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित होने की शिकायत को दूर करने के लिए

SSA व RMSA के माध्यम से निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

271. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मायावाली ढाणी, टीट नवाड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बासड़ी पोसाना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाज की राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की उप खण्ड मुख्यालय उदयपुरवाटी पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की विभिन्न राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं गणित संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

276. आहौर उप खण्ड मुख्यालय पर आईटीआई खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

277. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नये विद्यालय खोलने व विद्यमान विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

278. प्रतिबंधित जिलों से शिक्षकों के स्थानान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

279. राज्य में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

280. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के राजकीय भीखाबाई महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोखरा को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़):

282. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के राजकीय विद्यालयों को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं खेल मैदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

283. भीलवाड़ा जिले में स्थित माण्डलगढ़ किला, मेनाल तिलस्वा, पार्श्वनाथ, चवलेश्वर, जोगणिया माता, त्रिवेणी संगम, बोहरी माता, कोटड़ी श्याम, सिगोली श्याम स्थलों को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय माण्डलगढ़ को स्नातकोत्तर करने एवं कोटड़ी चारभुजा उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में तिलस्वा में वेद विद्यालय खोलने व माण्डलगढ़ महाविद्यालय में संकाय विषय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

286. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजोर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. पंचायत समिति घाटोल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उडवाला को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

288. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

290. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेमन्त जैन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को डिमर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

291. विधान सभा क्षेत्र दौसा के कुन्डल, नागल बैरसी, नांगल राजावतान एवं बापी में संचालित प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बनियाना एवं मानपुरिया कोठ्या को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

292. राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

293. विधान सभा क्षेत्र दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूडियावास में कला संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुन्डल में विज्ञान विषय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छारेडा में कृषि तथा राजनीति विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र दौसा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिन्डोली एवं जोपाडा को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र दौसा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरा बंजारा ढाणी बापी एवं कालाखेता को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्मपुरा को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

296. विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

297. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

298. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विद्यालयों में कला शिक्षकों के पद सृजित कर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

299. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के पंचायत समिति झाड़ौल, फलासिया व कोटड़ा के सरकारी विद्यालयों में प्राचार्यों व्याख्याताओं व विषयाध्यापकों के लम्बे समय से रिक्त चल रहे पदों को यथाशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के राजकीय विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल की पंचायत समिति झाड़ौल, फलासिया व कोटड़ा के विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल की पंचायत समिति झाड़ौल, फलासिया व कोटड़ा में नवीन विद्यालय खोलने व पहले से स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के पंचायत समिति झाड़ौल, कोटड़ा व फलासिया के बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को ग्राम सहायक व अन्य सरकारी विभागों में समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

304. ग्राम शुभलाई (तहसील लूणकरणसर) की उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

305. राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, महाजन (तहसील लूणकरणसर) को राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

306. ग्राम पंचायत, सहनी कलां (पंचायत समिति लूणकरणसर) के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

307. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

308. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में खेलकूद के मैदानों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

310. कोटा शहर के समस्त राजकीय महाविद्यालयों व कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्टूडेन्ट फैसेलिटी सेन्टर जहां पर विद्यार्थियों एक महाविद्यालय परिसर में कैन्टीन, एटीएम, जेरोक्स मशीन, स्टेशनरी आदि की सुविधायें न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

311. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कला वर्ग में अंग्रेजी, गृह विज्ञान, उर्दू, भूगोल एवं विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित की स्नातकोत्तर की कक्षायें/कोर्स न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

312. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में उच्च शिक्षा विभाग में समस्त कालेजों में खाली पड़े शिक्षाकर्मी व मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।